

“भारतीय राजनीति और सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके विचारों की आधुनिक समय में प्रासंगिकता”

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्०

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध



निर्देशिका

डॉ० कृष्णा गुप्ता

रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

शोधकर्ता

प्रताप बहादुर पटेल

राजनीति विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

राजनीति विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2002

दिनांक -----

शोध निर्देशिका का प्रमाण-पत्र

अत्यन्त प्रसन्नता के साथ प्रमाणित किया जाता है कि प्रताप बहादुर पटेल, शोधछात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ने अपना शोध प्रबन्ध, "भारतीय राजनीति और सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके विचारों की आधुनिक समय में प्रासंगिकता" विषय में मेरे निर्देशन में सम्पन्न किया है। इनका यह अनुसंधान अत्यन्त मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। शोधकार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि तथा उपस्थिति इनके द्वारा पूर्ण की गयी है, अतः यह शोध प्रबन्ध परीक्षार्थ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

शोध निर्देशिका

डॉ० कृष्णा गुप्ता
रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

भूमिका

भारत के देश भक्तों में अमूल्य रत्न सरदार पटेल एक कर्मयोगी की भाँति बाते कम और काम अधिक करने में विश्वास रखने वाले कर्मठ व्यक्ति थे, वे भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के आधार शक्ति स्तम्भ थे। आत्मत्याग, अनवरत सेवा तथा दूसरों को दिव्य शक्ति की चेतना देने वाला उनका जीवन सदैव प्रकाश स्तम्भ बना रहेगा।

सरदार पटेल वास्तविक अर्थों में भारत के निर्माता थे। मितभाषी, अनुशासन प्रिय, कर्मठ, कुशल संगठनकर्ता के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता में उनकी अटूट निष्ठा थी। जिस अदम्य उत्साह, असीमशक्ति, और मानवीय समस्याओं के प्रति व्यवहारिक, दृष्टिकोण से उन्होंने निर्भय होकर नवजात भारत की प्रारम्भिक समस्याओं का अद्भुत सफलता समाधान के साथ किया कि उनका विश्व के राजनीतिक मानचित्र में अमिट स्थान बन गया।

सरदार पटेल मन, वचन तथा कर्म से सच्चे देश भक्त थे। वे वर्ण भेद के प्रबल विरोधी थे। संघर्ष को वे जीवन की व्यस्तता समझते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त "अदम्य साहस के साथ उन्होंने देशी रियासतों का विलीनीकरण किया तथा भारतीय प्रशासन को निपुणता एवं स्थायित्व प्रदान करने के साथ-साथ संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र की समस्याओं के समाधान में उनके द्वारा अपनाया गया व्यावहारिक दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

सरदार पटेल का व्यक्तित्व विवादास्पद रहा। उन्हें प्रायः असमझौता वादी, पूँजीवाद समर्थक, मुस्लिम विरोधी तथा साम्यवाद विरोधी कहा जाता है, जो नितान्त भ्रामक है जैसा कि उन पर ऐसा आरोप लगाने वाले समाजवादी नेता यथा मधुलिमये, जयप्रकाश नारायण तथा चन्द्रशेखर और सरदार पटेल के सहयोगी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने बाद में उनके व्यक्तित्व के बारे में अपनी भूलों को स्वयं स्वीकार कर ऐसी धारणाओं को गलत करार दिया है। प्रस्तुत शोध में भारत की राजनीति^{में प्रवेश} की भूमिका का निष्पक्ष विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है तथा उनके विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया है। अध्ययन सामग्री को सात अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम

अध्याय मे जहा सरदार पटेल के जीवन परिचय एव व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है वही द्वितीय अध्याय मे विभिन्न सत्याग्रहो मे उनके द्वारा तैयार किये गये सगठन तथा पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से उनके द्वारा किये गये प्रशासकीय निर्णयो का उल्लेख किया गया है। तृतीय अध्याय मे विभाजन के पूर्व भारतीय राजनीति मे उनके योगदानो का उल्लेख है तथा चतुर्थ अध्याय मे विभाजन के उपरान्त मन्त्रिमण्डल के सदस्य के रूप मे किये गये कार्यों का वर्णन किया गया है। पाँचवे अध्याय मे उनके विचारो का उल्लेख किया गया है तथा छठे अध्याय मे वर्तमान समय मे उनके चिंतन की प्रासंगिकता का उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया है। सातवे अध्याय मे निष्कर्ष दिया गया है।

इस शोध प्रबन्ध को निष्पक्षता के सम्पन्न करने का पूरा श्रेय पूजनीया डॉ० कृष्णा गुप्ता, रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को है। उन्ही के निर्देशन मे यह शोध प्रबन्ध लिखा गया है। जब-जब मेरे सामने कठिनाई आयी उन्होने सफल परिहार किया। यह प्रबन्ध उनके कुशल निर्देशन से ही इस रूप मे आकार ग्रहण कर सका है।

मै उनके प्रति प्रणाम निवेदित करता हूँ। राजनीति विज्ञान, विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री मो० साहिद ने भी मेरा उत्साहवर्धन तो किया ही साथ ही बहुमूल्य सुझाव भी दिये। उनके प्रति भी मै नतमस्तक हूँ। राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ० आलोक पन्त के प्रति भी मै कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होने समय-समय पर मेरी पूर्ण सहायता की। पूज्य पिता श्रीराम सजीवन पटेल, माता इन्द्रकली की प्रबल प्रेरणा ने मेरा मनोबल बठाया। पत्नी सयोगिता पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना भी आवश्यक है जिन्होने मुझे परिवारिक जिम्मेदारी से दूर रखकर शोध कार्य को पूरा करने मे पूरा सहयोग दिया। मै अपने अन्य मित्रो एव शुभचिन्तको को भी अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ जिन्होने इस शोध कार्य को पूरा करने मे सहयोग दिया।

मै विशेष रूप से 'सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक भवन', शाही बाग, अहमदाबाद के निदेशक श्री अशोक धीरूभाई देसाई का विशेष रूप से ऋणी हूँ जिन्होने मुझे अहमदाबाद प्रवास के दौरान 24 घण्टे लाइब्रेरी, नि शुल्क आवास तथा भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी, मै हरवंश पटेल, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय

वल्लभ विद्यानगर के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अहमदाबाद प्रवास के दौरान समय-समय पर मेरा मार्ग दर्शन किया।

मैं उपनिदेशक, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एव लाइब्रेरी तीनमूर्ति, दिल्ली, राष्ट्रीय अभिलेखागार एव राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली, लाइब्रेरी, गुजरात विद्यापीठ, लाइब्रेरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जहाँ से मुझे बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध करायी गयी।

अन्त में मैं उन सभी लेखकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे अपना सहयोग दिया। श्री अनिल कुमार गुप्ता (गुप्ता कम्प्यूटर्स अल्लापुर इलाहाबाद) ने शोध प्रबन्ध का टकण किया, अतः वे धन्यवाद के पात्र हैं।

शोधार्थी

Pratap Bahadur Patel

प्रताप बहादुर पटेल

अनुक्रमणिका

भूमिका

अध्याय - एक

8—23

जीवन परिचय एवं व्यक्तित्व

- (i) जन्म एवं परिवार
- (ii) बाल्यकाल एवं विद्यार्थी जीवन
- (iii) एक वकील के रूप में
- (iv) बैरिस्टर पटेल
- (v) सरदार पटेल का व्यक्तित्व

अध्याय - दो

24—75

कुशल प्रशासक एवं संगठन कर्ता के रूप में सरदार पटेल

- (i) सार्वजनिक जीवन में प्रवेश
- (ii) अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में योगदान
- (iii) गुजरात सभा के सचिव
- (iv) खेडा सत्याग्रह
- (v) नागपुर झण्डा सत्याग्रह
- (vi) बोरसद सत्याग्रह
- (vii) रौलेट ऐक्ट का विरोध
- (viii) बारदोली सत्याग्रह
- (ix) पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष
- (x) कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के पथ प्रदर्शक
- (xi) 1945-46 का चुनाव

विभाजन के पूर्व भारतीय राजनीति में योगदान

- (i) असहयोग आन्दोलन
- (ii) सविनय अवज्ञा आन्दोलन
- (iii) त्रिपुरी सम्मेलन
- (iv) क्रिप्स मिशन
- (v) भारत छोड़ो आन्दोलन
- (vi) शिमला सम्मेलन
- (vii) कैबिनेट मिशन
- (viii) आन्तरिक सरकार

विभाजन के उपरान्त भारतीय राजनीति में योगदान

- (i) विभाजन की पृष्ठभूमि
- (ii) विभाजन और सरदार पटेल
- (iii) विभाजन का क्रियान्वयन
- (iv) गृहमन्त्री के रूप में प्रशासनिक सेवाओं का गठन
- (v) देशी रियासतों का विलीनीकरण
(बडौदा, भोपाल, जूनागढ़ और हैदराबाद के विशेष सन्दर्भ में)
- (vi) संविधान निर्माण में योगदान
- (vii) केन्द्रीय समस्याओं पर नेहरू से मतभेद

सरदार पटेल के प्रमुख विचार

- (i) काश्मीर समस्या पर विचार
- (ii) नेपाल सम्बन्धी विचार
- (iii) गोवा समस्या पर विचार
- (iv) मुस्लिम लीग के प्रति दृष्टिकोण
- (v) राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ के प्रति दृष्टिकोण
- (vi) सरदार पटेल के अन्य राजनीतिक विचार
- (vii) सामाजिक विचार
- (viii) आर्थिक विचार

सरदार पटेल के विचारों की प्रासंगिकता

- (i) राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता
- (ii) सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता
- (iii) आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता

निष्कर्ष

ग्रन्थ सूची

सारणी

अध्याय - 1

जीवन-परिचय

- (i) जन्म एवं परिवार
 - (ii) बाल्यकाल एवं विद्यार्थी जीवन
 - (iii) एक वकील के रूप में
 - (iv) बैरिस्टर पटेल
 - (v) सरदार पटेल का व्यक्तित्व
-
-

जीवन एवं व्यक्तित्व

भारत देश के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात प्रान्त का काठियावाड़ जिला प्रायद्वीप के रूप में समुद्र में विस्तृत है। अरब सागर की दो शाखाओं—कच्छ एवं खम्भ की खाड़ियों के मध्य यह भाग आशीष मुद्रा में उठे हुए हाथ की तरह भारत के मानचित्र पर अलग ही दिखाई देता है। समतल उपजाऊ भूमि और समुद्री सम्पर्क ने कृषि तथा वाणिज्य दोनों ही दृष्टियों से इसे सम्पन्न बना दिया है। 1857 ई० में जब सम्पूर्ण उत्तरी भारत ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक होकर खड़ा हो गया था तो उस समय यहाँ के 200 से अधिक छोटे-बड़े नवाब अपने नाचरग और शतरज में ही व्यस्त थे। परन्तु इसी काठियावाड़ ने 19वीं शताब्दी में भारत माता की गोद में तीन ऐसे लाल डाले जिन्होंने 20वीं शदी में ब्रिटिश साम्राज्य को इस देश से सदा के लिए विदा करने में बड़ी भूमिका निभायी। ये थे—महर्षि दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। महर्षि ने राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत किया और स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज्य की आवश्यकता पर बल दिया। महात्मा गाँधी ने अहिंसा का मंत्र और सत्याग्रह का शस्त्र प्रदान किया, परन्तु इन सबका स्वतंत्रता संग्राम में सधा प्रयोग करके शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया।

जन्म एवं परिवार

स्वतंत्रता आन्दोलन में वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप से नयी दिशा देने वाले, स्वतंत्रता के उपरान्त अखण्ड भारत के निर्माता, भारत रत्न, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात राज्य के खेडा जिले में स्थित आनन्द तालुका के नाडियाद नामक ग्राम में हुआ था। नाडियाद सरदार पटेल का ननिहाल है। सरदार पटेल के जन्म के बारे में निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, जैसा कि स्वयं सरदार पटेल ने कहा था, “मेरे जन्म के बारे में जो तिथि मणि बेन ने बतायी है उसे हमने मैट्रिक परीक्षा में स्वेच्छा से अंकित की थी।”¹ मणि बेन के अनुसार सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ई० को हुआ था।

“सरदार पटेल के पिता झबेर भाई करमसद गाँव के 10-12 एकड़ जमीन धारण करने वाले साधारण किसान थे।”² अतएव कृषि द्वारा अपना जीवनयापन करते थे। वे साहसी, सयमी और वीर पुरुष के साथ-साथ धर्मपरायण व्यक्ति भी थे। वे 1829 ई० में स्वामी सहजानन्द द्वारा स्थापित स्वामी नारायण सम्प्रदाय के भक्त थे। कहा जाता है कि “भारत को आजाद करने के प्रथम पुरुषार्थस्वरूप 1857 ई० में जो विद्रोह हुआ उसमें झॉंसी की रानी लक्ष्मी बाई तथा नाना साहब घोडोपन्त की सेनाओं में भाग लेकर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था।”³ 1914 ई० में झबेर भाई स्वर्ग सिधार गये।

“वल्लभ भाई पटेल की माँ लाडबाई झबेर भाई की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी नि सतान स्वर्ग सिधार गयी। अतएव वश-रक्षा हेतु झबेर भाई ने दूसरा विवाह किया था।”⁴ लाडबाई भी अपने पति की भौति सयमी, धर्मपरायण, परिश्रमी और सरकारी महिला थी, जिनका स्वर्गवास 1932 ई० में हुआ।

वल्लभ भाई पाँच भाई व एक बहन थे। भाइयों के नाम क्रमशः सोभा भाई पटेल, नरसिंह भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल एवं काशी भाई पटेल थे। बहन डहीबा सबसे छोटी थी। पिता द्वारा शुरू किये गये स्वतन्त्रता यज्ञ को पूरा करने का सौभाग्य उनके दो पुत्रों—विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल को प्राप्त हुआ। विट्ठल भाई ने गुलाम भारत में भी अंग्रेजी शासन काल में भारत की केन्द्रीय धारा सभा के अध्यक्ष पद को गौरव पूर्ण ढंग से पूरी आन-बान के साथ योग्यतापूर्वक सम्भाला था। वे स्वाधीन भारत के लिए अपने जीवन के अन्तिम दिनों तक यातनाये बरदास्त करते रहे। जिस झड़े की शान रखने के लिए वे जीवन भर जूझते रहे और अनेक कष्ट सहन करते रहे, उसे दिल्ली के वायसराय भवन पर फहराते देखने का सौभाग्य उन्हें नसीब नहीं हुआ। सविनय कानून भंग लड़ाई के बीच ही वे स्वर्गवासी हो गये।

बड़े भाइयों सोभा भाई एवं नरसिंह भाई ने अपने पिता के कार्य में हाथ बटाया और अपने पैतृक गाँव करमसद में ही रहे। बहन डहीबा 1916 ई० में इस ससार से चल बसी। सभी भाई अत्यन्त व्यवहारकुशल एवं देशप्रेमी थे। सभी भाइयों में एक समानता यह रही कि

२ सरदार साहित्य माला राम्पुट, अहमदाबाद, 1983, पृ० 22

३ दारा, सेठ गोविन्द रारदार पटेल, दिल्ली, 1969, पृ० 6

४ रणजीत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल इलाहाबाद, 2000, पृ० 20

वे 30 से 40 वर्ष की आयु में विधुर हो गये। इसलिए आपस में “वे लोग अपने परिवार को विधुरों का परिवार कहकर आमोद-प्रमोद किया करते थे।”⁵

बाल्यकाल एवं विद्यार्थी जीवन

किसान के यहाँ जन्म लेने के कारण सरदार का लालन-पालन विशुद्ध ग्रामीण वातावरण में हुआ। इनका बाल्यकाल अपने माता-पिता के साथ करमसद में ही व्यतीत हुआ। पिता झबेर भाई, वल्लभ भाई को नित्य प्रातः काल में अपने साथ खेत पर ले जाते और रास्ते में आते-जाते पहाड़े याद कराते थे। यही से उनकी प्रारम्भिक शिक्षा प्रारम्भ हुई। सरदार पटेल बाल्यकाल से ही दृढ़ निश्चयी रहे। एक दिन इनके पिता हल चला रहे थे जिनके पीछे-पीछे वल्लभ भाई अपना कार्य करते हुए पहाड़ा याद कर रहे थे कि उनके पैर में एक डाब का काँटा चुभ गया। वल्लभ भाई पहाड़े याद करने में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। वे जब अपना कार्य करते हुए निरन्तर आगे बढ़ रहे थे तो अचानक पिता की दृष्टि उनके पैरों पर पड़ी। पैर से रक्त निकलता देखकर वे दग रह गये। उन्होंने अपने पुत्र की दृढ़ता की सराहना करते हुए काँटा निकाला और उसे महान व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया।

सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद में उस समय माध्यमिक शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी। लड़के पटेलाद पढ़ने जाते और वहाँ चार-पाँच विद्यार्थी एक साथ रहते। एक सप्ताह की रसद घर से स्वयं सिर पर उठाकर लाते और अपने हाथ से खाना बनाते। वल्लभ भाई भी उन्हीं में से एक थे। करमसद से पटेलाद के रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा था जो सबको आते-जाते अडचन पैदा करता था। बार-बार सबको उसकी ठोकर लगती थी। वल्लभ भाई ने एक बार अपने साथियों से पीछे रहकर उस पत्थर को उखाड़ कर फेंक दिया। साथियों के पूछने पर उन्होंने कहा “अपने मार्ग में आने वाले काँटे को निकालकर फेंक ही देना चाहिये।”⁶

सरदार पटेल ने जीवन भर दूसरे लोगों की और राष्ट्र की बाधाओं तथा रुकावटों को दूर करने का ही कार्य किया। प्रारम्भिक और अंग्रेजी की तीसरी कक्षा तक की शिक्षा करमसद में प्राप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए नाडियाद में दाखिला लिया जहाँ

५ पटेल, रावजी भाई मणिभाई, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ०, 7-8

६ सरदार साहित्य माला राम्पुट, पूर्वो, पृ०, 10

से उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में 1897 ई० में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किया। स्कूल में शिक्षक के अत्याचार और साथी विद्यार्थियों पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर उन्हें न्याय दिलाने, कागज, पेन्सिल, रबड़, नोटबुक आदि का व्यापार करने वाले और अपने ही पास से माल लेने की विद्यार्थियों पर जबरदस्ती करने वाले शिक्षक के खिलाफ विद्रोह करके उन अन्यायी आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करने वाले सरदार हमेशा हिम्मत, धीरज, उमंग, परिश्रम आदि उच्च गुणों का परिचय देते रहे।

सरदार पटेल विद्यार्थी जीवन से अन्याय को सहन नहीं कर रहे थे और पूरी ताकत के साथ उसका प्रतिकार करते थे। एक बार एक शिक्षक **अगरवाला** के कक्षा में समय से न जाने पर एक विद्यार्थी ने गाना शुरू कर दिया तो कक्षा में आने पर शिक्षक ने उस विद्यार्थी को डाँटना शुरू किया जिसका प्रतिकार करते हुए सरदार पटेल ने कहा, “गलती आपकी है और आप हम लोगों को डाँट रहे हैं।” परिणामस्वरूप शिक्षक ने दण्ड स्वरूप वल्लभ भाई को कक्षा से निकल जाने का आदेश दिया। वल्लभ भाई के कक्षा से निकलते ही पूरी कक्षा उनके पीछे हो ली। इस पर हेड मास्टर भरुचा ने सरदार से माफी मागने को कहा। वल्लभ भाई ने अपने उत्तर में कहा “गलती तो शिक्षक ने की है इसलिए माफी उसे मागनी चाहिये। हम क्यों माफी माँगे।”⁷ हेडमास्टर ने वस्तुस्थिति समझकर छात्रों को कक्षा में बैठने की अनुमति दे दी।

चुनौती को स्वीकार करना सरदार पटेल का जन्मजात गुण था। उनके विद्यार्थी जीवन में उनके एक शिक्षक नगरपालिका के चुनाव में उम्मीदवार थे। जिनके विरुद्ध एक दादा किस्म का दम्भी व्यक्ति उम्मीदवार था, जिसने घोषणा कर रखी थी कि यदि इस मास्टर ने मुझे चुनाव में हरा दिया तो मैं अपनी मूँछें मुड़वा लूँगा। “सरदार ने इसे पूरे विद्यालय के लिए चुनौती के रूप में स्वीकार किया और शिक्षक के पक्ष में इतना सुव्यवस्थित एवं संगठित रूप से प्रचार किया कि शिक्षक चुनाव जीत गया। फलतः मूँछ मुड़ाई के डर से वह नेता कई दिनों तक घर से लापता रहा।”⁸

इस प्रकार अपने धर्मपरायण माता-पिता के संस्कार के परिणामस्वरूप ‘परोपकाराय सता विभूतयः’ सूत्र को पटेल ने अपने जीवन में चरितार्थ किया। अपने पुरुषार्थ के बल पर

७ पटेल, रावजी भाई मणि भाई, पूर्वो, पृ० 9-11

८ रणजीत सिंह, पूर्वो, पृ० 26

अनेक कष्टों को सहते हुए भी उन्होंने करमसद, पटेलाद, नाडियाद और बडौदा में शिक्षा प्राप्त की। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त इनका इरादा कानून का अध्ययन करने का था परन्तु घर की दयनीय आर्थिक स्थिति बहुत बड़ी बाधा थी अतः अगले तीन वर्षों तक घर पर रहकर ही वल्लभ भाई ने प्लीडर की परीक्षा की तैयारी की और 1900 ई० में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए की। अध्ययन हेतु वे अपने मित्र से पुस्तकें मॉग कर पढ़ते थे। “जब वकालत की पढ़ाई के सिलसिले में वल्लभ भाई अपने एक मित्र के साथ बाकरोल में रहते थे तो बगल में एक फोड़ा निकल आया। साधनसम्पन्नता के अभाव में इलाज के लिए शहर जाना सम्भव नहीं था। गाँव में नश्वर लगाकर फोड़े को ठीक करने का एक मात्र उपचार था। अतएव इलाज के लिए नाई बुलाया गया, जो गरम सलाख लगाने के लिये साहस न जुटा सका। वल्लभ भाई ने सलाख को लेकर स्वयं फोड़े को चीर कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया।”⁹

एक सफल वकील के रूप में

सरदार पटेल की महात्वाकांक्षा ‘एक सफल वकील बनने और धन कमाने की थी। सन् 1900 ई० में गोधरा में वकालत प्रारम्भ की। वल्लभ भाई के अग्रज विट्ठल भाई ने बोरसद में अपने साथ वकालत करने के लिए आमन्त्रित किया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई किसी की छत्रछाया में रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास करना नहीं चाहते थे, अतएव बड़े भाई का आग्रह ठुकरा दिया। दो वर्ष गोधरा में वकालत करने के उपरान्त वल्लभ भाई बोरसद आ गये, पर विट्ठल भाई के साथ नहीं रहे। दोनों भाइयों में बहुत कम मुलाकात होती थी। कभी-कभी तो दोनों भाई अदालत में एक दूसरे के विरुद्ध बहस करते थे। वल्लभ भाई फौजदारी के ही मुकदमें लेते थे। वल्लभ भाई अपनी वाक्पटुता के कारण शीघ्र ही एक सफल वकील के रूप में प्रतिष्ठित हो गये। खेडा जिले की बोरसद तालुके में सबसे अधिक फौजदारी के मुकदमें थे जिसमें से अधिकतर मुकदमों में बचाव पक्ष की ओर से वल्लभ भाई वकील होते तथा वे सफल होते थे। अतः बाध्य होकर सरकार ने अदालत बोरसद से आनन्द में स्थानान्तरित कर दिया, परन्तु जब वल्लभ भाई ने आनन्द आकर वकालत प्रारम्भ कर दी तो पुनः अदालत को बोरसद में वापस आना पड़ा। “संक्षेप में अपने 10 वर्षों के वकालत काल में वल्लभ भाई एक योग्य, अनुभवी और मजे हुए वकीलों की गणना में आ गये।”¹⁰

९ पटेल रावजी भाई, पूर्वो, पृ० 7 और 8

१० दारा, सेठ गोविन्द, पूर्वो, पृ०, 19

वल्लभ भाई आरम्भ से ही निडर तो थे ही, वे किसी मजिस्ट्रेट के प्रभाव से नहीं प्रभावित होते थे। इतना ही नहीं वे विचित्र आदतों वाले या घमण्डी मजिस्ट्रेट के घमंड को उतारने की कला में भी माहिर थे। “मिस्टर हसबन्ड नामक मजिस्ट्रेट साथियों से गवाही लेते समय उन्हें आइने के सामने खड़ा होने के लिए बाध्य करते थे। मजिस्ट्रेट की इस अवाछनीय हरकत का अंत सरदार पटेल ने अपनी बुद्धि, कौशल, निर्भयता एवं समयसूचकता के कारण कराया।”¹¹

इसी प्रकार अपनी दूरदर्शिता के कारण “बोरसद के आबकारी विभाग द्वारा गैर कानूनी ढंग से शराब बनाने वाले गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वा दिया।”¹² सरदार पटेल की वाकपटुता तथा मजिस्ट्रेट की मन स्थिति को पहचानने की शक्ति “दुराचार के एक केस में देखने को मिलती है। सरदार ने इस केस में बिना किसी बहस के मजिस्ट्रेट को अपने तर्कों द्वारा प्रभावित करके अभियुक्त का बचाव किये बगैर, मुकदमे की गुण दोष की चर्चा किये बगैर, बिना किसी जाँच के तथा किसी प्रकार के गन्दे और वीभत्स प्रश्नोत्तर के बिना अपने मुक्किल को बचा लिया।”¹³

तीन वर्ष वकालत करने के बाद वल्लभ भाई की इच्छा इंग्लैण्ड जाकर बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करने की हुई। यह इच्छा इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उन्होंने देखा कि धनी व्यक्ति मुकदमे की सुनवायी के लिए अहमदाबाद से बैरिस्टर बुला लेते थे। सहायक के रूप में वल्लभ भाई को काम करना पसन्द नहीं था। सन् 1905 ई० में उन्होंने बैरिस्टरी की पढाई हेतु **तामस कुक एंड सन्स** कम्पनी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। दोनों भाईयों द्वारा अंग्रेजी में अपना नाम वी०जे० पटेल लिखने के कारण अन्तिम पत्र सयोगवश विट्ठल भाई के हाथ लग गया। इस घटना का वर्णन करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि “वकालत का पेशा करके खर्च के बराबर कमा करके विलायत जाने का इरादा किया। मगर मैंने जिस कम्पनी के मार्फत विलायत जाने का प्रबन्ध करने के लिए पत्र व्यवहार किया था, उसका आया हुआ जवाब मेरे बड़े भाई के हाथ पड़ गया, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे जाने दो तुम्हें तो मेरे आने के बाद भी जाने का मौका मिल जायेगा। लेकिन

११ पटेल, रावजी भाई, पूर्वो, पृ०, 18-19

१२ वही, पृ०, 19-20

१३ वही, पृ०, 21-22

तुम्हारे आने के बाद मेरा जाना सम्भव नहीं होगा। इस पर मैंने अपने भाई को पन्द्रह दिन का समय दिया और वे पन्द्रहवे दिन विलायत चले गये।”¹⁴

1908 ई० में विट्ठल भाई बैरिस्टर बनकर भारत वापस आ गये। बम्बई के समृद्ध गुजराती समाज के बीच उनकी निर्भयता, नैतिकता एवं प्रतिभा की धाक जमते देर न लगी।

बड़े भाई के विलायत जाने के बाद सरदार की व्यस्तता और बढ़ गयी थी। इसी दौरान वल्लभ भाई अदालत में हत्या के एक मुकदमे में गवाह से जिरह कर रहे थे। जिरह के दौरान एक सूचना का तार आया जिसे खोलकर पढ़ने के उपरान्त उसे अपनी जेब में रख लिया, जिरह जारी रही और अन्तिम क्षण तक कार्यवाही गम्भीरता से चली। जिरह पूरी होने के बाद तार की सूचना उन्होंने अपने मित्रों को देते हुए अपनी पत्नी के मृत्यु के समाचार से अवगत कराया। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि “तार पढ़ने के बाद मैं कुछ देर के लिए किकर्तव्यविमूढ हो गया था, किन्तु मृत्यु के आघात से जीवन का कर्तव्य कैसे छोड़ दूँ। यदि मैं आज दृढतापूर्वक जिरह नहीं करता तो अभियुक्त को फाँसी की सजा हो सकती थी।”¹⁵

11 जनवरी, 1909 ई० को जब पत्नी की मृत्यु हुई तब उस समय वल्लभ भाई 34 वर्ष के ही थे, जबकि पुत्री मणि बेन की आयु चार वर्ष और पुत्र डाह्या भाई की आयु तीन वर्ष थी। सत्रह वर्ष के वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी केवल छ वर्ष तक साथ रहे। जीवन के अन्तिम क्षणों में पत्नी के साथ न रह पाने का उन्हें अपार दुःख था। पत्नी की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने दोबारा विवाह न करने का निर्णय लिया।

बैरिस्टर के रूप में

विट्ठल भाई के विलायत से वापस आने से पहले ही वल्लभ भाई ने विलायत जाने की तैयारी कर ली थी। अपने छोटे भाई काशी भाई को बच्चों के पालन-पोषण का भार सौंपकर वे **10 अगस्त, 1910 ई०** को विलायत के लिए रवाना हो गये। जहाज पर पहली बार वल्लभ भाई ने अंग्रेजी वेशभूषा धारण की और भोजन में छुरी-काटे का प्रयोग सीखा।

१४ पारीख, नरहरि सरदार पटेल के भाषण (1918-1947 तक) अहमदाबाद 1950 पृ०, 25-26

१५ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली 1997

लन्दन में रहने के लिए उन्होंने एक रास्ता बोर्डिंग चुना और सितम्बर, 1910 ई० में मिडल टेम्पल में प्रवेश लिया। उन्होंने कुछ ही महीनों बाद आयोजित रोमन लॉ की परीक्षा आनर्स के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वल्लभ भाई ने लन्दन में एक आदर्श विद्यार्थी का जीवन व्यतीत किया। वे प्रतिदिन अपने निवास से अध्ययन के लिए 10-12 मील की दूरी पैदल तय करके मिडल टेम्पल के पुस्तकालय जाते थे। वे सुबह 9 बजे पुस्तकालय पहुँच जाते और साय 6 बजे वापस आते थे। कभी-कभी वे सत्रह घंटे तक अध्ययन करते थे। कड़े परिश्रम के उपरान्त बैरिस्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करके वल्लभ भाई 13 फरवरी, 1913 ई० को बम्बई आये और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बेसिल स्कॉट से अच्छा परिचय होने के नाते उनसे मुलाकात करने गये। मुलाकात के दौरान बेसिल स्कॉट ने उन्हें जिला न्यायाधीश की नौकरी का निमंत्रण दिया जिसे वल्लभ भाई ने अस्वीकार कर दिया। जिस पर स्कॉट महोदय ने बम्बई में प्रैक्टिस के साथ-साथ लॉ कॉलेज में अध्यापक बनाने का भी आश्वासन दिया, जिसे अस्वीकार कर वल्लभ भाई अहमदाबाद आ गये और वही वकालत करने लगे। वल्लभ भाई के तत्कालीन जीवन का सजीव चित्रण करते हुए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी०वी० मावलकर ने लिखा है—

“युवा बैरिस्टर पटेल ने एक प्रतिभासम्पन्न युवक के रूप में बार में प्रवेश किया। उनका अच्छे ढंग से सिला हुआ सूट और तिरछी फेल्ट, चमकीली आँखें और पैनी नजर बरबस अपनी ओर आकृष्ट करती। वे बहुत कम बोलते थे। वे अपने मुलाकातिथों का मुस्कराहट के साथ स्वागत करते थे और उन्हें इस तरह से देखते थे जैसे वे उनसे कुछ ज्यादा ज्येष्ठ, श्रेष्ठ हों।”¹⁶

सरदार पटेल फौजदारी मामलों में विशेष रुचि लेते थे। उनका गवाह से जिरह करने का ढंग अत्यन्त ही सक्षिप्त किन्तु नजर पैनी होती थी। पहली ही नजर में व्यक्ति का देखकर उसके स्वभाव को समझ लेते थे और प्रश्नों का ऐसा वार करते थे कि वह सम्भल नहीं पाता था। उनकी निर्भीकता की प्रशंसा सभी करते थे। हत्या के मामले में फँसे दो भाइयों को बिना किसी सबूत के जमानत मजूर न किये जाने पर वल्लभ भाई ने जज को उसकी मर्यादा का मान कराते हुए आवेशपूर्वक कहा कि क्या इस अदालत में खेड़ा जिले

के लोगो को बिना सबूत के ही सजा सुनाये जाने का दस्तूर है। जज ने वल्लभ भाई के आरोप से घबराकर जमानत की अर्जी को मजूर कर लिया।

इस प्रकार विद्यार्थी जीवन तथा वकालत के काल में ही सरदार पटेल के व्यक्तित्व के अनेक गुणों जैसे स्पष्टवादिता, योग्यता, निस्वार्थ, कर्तव्य-निष्ठा, त्याग की भावना, परख शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, निडर, बुद्धि चातुर्य आदि के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं।

सरदार पटेल का व्यक्तित्व

परम राष्ट्र भक्त, सतत् सघर्षरत, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्र का निष्ठावान सेवक, अखण्ड भारत के निर्माता, अनुशासनप्रिय, प्रशासक, दृढ़ प्रतिज्ञा राजनेता के रूप में सरदार पटेल का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। सरदार अदम्य साहस, अद्भुत धैर्य और सरलता के अवतार थे। वे गाँधी जी के स्वतंत्रता आन्दोलन में समर्पित सिपाही के रूप में सत्याग्रह में सक्रिय रहे। इस महान व्यक्ति को सम्पूर्ण जीवन एक कर्मयोगी की निष्काम यात्रा है। उनके व्यक्तित्व में सहगुण उजागर हुए, उन्होंने अपने जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों एवं कर्तव्यनिष्ठा की परम्परा स्थापित की।

सरदार पटेल का खुरदरा, बेमुलायम और करीब-करीब खूँखार बाह्य आवरण भयप्रद था, जिससे प्रतीत होता था कि मानो वे बिल्कुल हृदयहीन हो और मानवीय भावनाओं से उनका कोई सबंध न हो। आचरण से वे कठोर, निर्मम तथा दृढ़निश्चयी थे। वे मितभाषी थे। उनके शब्द प्रायः तीक्ष्ण तथा अकाट्य होते थे, “व्यक्तित्व के इसी पक्ष के कारण यश और प्रसिद्धि के चरमोत्कर्ष को छूने पर भी वे लोकप्रियता के उस चरम बिन्दु को नहीं पहुँच सके, जहाँ नेहरू जी पहुँचे।”¹⁷

परन्तु इस कठोर व्यक्तित्व के पीछे एक कोमल हृदय छिपा था, जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को था। ‘बापू के निवेदन’ नामक समाचार पत्र के 8 मई, 1933 के अंक में गाँधी जी ने लिखा था, “सरदार ने मुझे अपने प्रेम में जिस प्रकार सराबोर किया, उसके कारण मुझे अपनी प्यारी माँ का स्मरण हो आता था। मुझे थोड़ी भी तकलीफ होती, तो वे तुरन्त अपना बिस्तर छोड़कर उठ बैठते, मेरी सुविधा की छोटी सी बात का भी वे ध्यान रखते थे। इसके पूर्व मैं यह कभी भी नहीं जानता था कि उनमें माँ के गुण भी थे।”¹⁸ पुरुषोत्तम दास

१७ दास, सेठ गोविन्द, पूर्वो, पृ० 95

१८ पटेल, दिलावर रिह जैसवार नवोदित भारत के निर्माता सरदार पटेल, दिल्ली 2000, पृ०, 184

टडन के अनुसार—“जो उनको जानते थे वे बतलाते हैं कि वह बहुत दयावान मनुष्य थे और मौका पडने पर बहुत कोमल प्रदर्शित होते थे। उनसे बढ़कर अधिक मित्र परायण और भरोसा करने वाला साथी पाना बहुत मुश्किल था।”¹⁹

गॉंधी जी के सम्पर्क में आने पर उन्होंने उनके एकादश व्रतों को स्वीकार किया और उसके अनुसार जीवन के हर क्षेत्र में आचरण करते हुए यह सिद्ध कर दिखाया कि ये सब व्रत केवल रटने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में आचरण करने जैसे हैं। गॉंधी जी के आह्वान पर 9 जनवरी, 1918 ई० को पटेल ने अपने परिवार, अपने व्यवसाय और अपनी प्रतिष्ठा सबको त्याग कर खेड़ा के सत्याग्रह का दायित्व ग्रहण किया। पटेल ने यह निर्णय देश की पुकार और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप किया। उनके ही शब्दों में “महात्मा से अलग रहना अपराध होगा।”²⁰ पटेल ने नि स्वार्थ भाव से खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया।

सरदार पटेल ने ब्रह्मचर्य और शारीरिक श्रम की बातें ही नहीं कीं। उन्होंने महान जीवन नियमों का अपने जीवन में बड़ी कठोरता के साथ पालन किया था। 33 वर्ष की अवस्था में विधुर होने के बावजूद दूसरी शादी नहीं की तथा अपने बच्चों का पालन-पोषण स्वयं किया। सरदार ने अपने हाथों से खेती भी की थी। यही नहीं उन्होंने केले की नयी प्रजातियाँ विकसित की थीं। “उनके द्वारा केले की तैयार की गयी नयी-नयी किस्में स्टीमर द्वारा बारदोली से विदेश जाया करती थीं।”²¹ ऐसे अनुकरणीय और प्रेरणादायक कार्य सरदार पटेल कर गये हैं।

सरदार पटेल के मन में पद के प्रति कोई लिप्सा नहीं थी। राष्ट्र की आवश्यकता उनके निर्णय का एकमात्र आधार रही। बारदोली विजय के उपरान्त 1928 ई० को कलकत्ता अधिवेशन में लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “यह विजय मेरी नहीं है, गॉंधी जी की है। जो विचार और आदर्श गॉंधी जी ने दिये हैं, उनका अमल बारदोली के किसानों ने किया, इसलिए यह विजय गॉंधी जी की है और अमल करने वाले किसान हैं, इसलिए यह यश उनका है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ।”²² मोती लाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि “सरदार ने जो किया है उससे मुझे लगता है कि

१९ पटेल अभिनन्दन ग्रंथ लखनऊ, 1978 पृ० 46

२० देशाई, डे टु डे, 5, पृ० 161

२१ सरदार साहित्य माला राम्पुट, अहमदाबाद, 1986, पृ० 41

२२ वही, पृ०. 42

कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के लिए यही व्यक्ति अध्यक्ष के लिए उपयुक्त रहेगा। यदि किसी कारणवश यह नहीं आये तो जवाहर लाल आये।”²³ चौदह प्रान्तों के लोग भी सरदार को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे। 31 दिसम्बर, 1929 ई० को भारत को यह निर्णय करना था कि वह आजादी लेकर ही रहेगा। इसलिए यह अधिवेशन और उसका अध्यक्ष पद बड़ा महत्वपूर्ण था। गाँधी जी की इच्छा जवाहर लाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने की थी, अतएव उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए सरदार पटेल ने अध्यक्ष पद एक खिलाड़ी की भौति छोड़ दिया। 1936 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि “अध्यक्ष की कुर्सी पर सरदार पटेल बैठें”, किन्तु सरदार ने निस्पृह भाव से कहा कि “नेहरू को अध्यक्ष पद प्रदान किया जाय।”²⁴ 1946 ई० में तीसरी बार लोगो ने माँग की कि सरदार को अध्यक्ष बनाया जाय। इसी समय भारत को स्वराज्य मिलने वाला था अतएव जो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, यह बात सरदार पटेल जानते हुए भी गाँधीजी की इच्छा का सम्मान करते हुए एक प्रकार से प्रधानमंत्री का पद नेहरू के लिए त्याग कर एक अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। फरवरी 1949 ई० में उन्होंने कहा कि “मैं हिन्दुस्तान का एक सैनिक हूँ, जीवन पर्यन्त उसकी सेवा करने का व्रत लिया है, अगर मैं सेवा पथ से विचलित होऊँ तो मेरे जीवन का अन्त हो।”²⁵ सरदार पटेल ने राष्ट्रीय हित के आगे व्यक्तिगत हित को कभी महत्व नहीं दिया।

भारत के राजनीतिक क्षितिज पर सरदार पटेल एक विलक्षण शक्ति के रूप में उभरे, जिनके साहस, स्पष्टवादिता और दूरदर्शिता को राष्ट्र हमेशा स्मरण करता रहेगा। उनका जीवन प्रारम्भ से लेकर अन्त तक एक खुली किताब की भौति था। अपने स्पष्ट और निर्भीक वक्तव्य के लिए वे प्रसिद्ध थे। 1945 ई० में बम्बई में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा “भारत छोड़ो सकल्प में कोई बदलाव नहीं होगा, हमारा अगला प्रस्ताव होगा अंग्रेजों एशिया छोड़ो।”²⁶ एक भाषण में उन्होंने कहा कि “मैं साफ बोलने में विश्वास करता हूँ और लघु सामग्री क्या है मैं नहीं जानता।”²⁷ सरदार पटेल यथार्थवादी थे। राष्ट्रीय हित ही उनके

२३ वही पृ० 42

२४ वही पृ० 43

२५ दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 28 फरवरी, 1949

२६ हिन्दुस्तान टाइम्स, 2 जुलाई, 1945

२७ कुमार रवीन्द्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार दिल्ली 1991

लिए परम लक्ष्य रहा और उसी पर आधारित उनके विचार, निर्णय तथा नीतियाँ रही। एक दार्शनिक की भाँति वे कल्पना की उड़ान नहीं लेते थे, बल्कि भारत की धरती पर खड़े एक राष्ट्र भक्त, एक साहसी सैनिक और एक सरल किसान थे। राष्ट्रीयता उनका धर्म था। सरदार पटेल गाँधी जी की अहिंसा में उसी सीमा तक विश्वास करते थे जब तक वह व्यावहारिक है। **वी०पी० वर्मा** के अनुसार "अहिंसा एक नीति थी, न की उनका जीवन दर्शन, क्योंकि काश्मीर में, हैदराबाद के निजाम के खिलाफ वे सैनिक कार्यवाही के पक्ष में थे।"²⁸

सरदार पटेल विरोधियों के हृदय को जीतने की कला में माहिर थे। वे विरोधियों के समक्ष अपना पक्ष बड़ी दृढ़ता के साथ अत्यन्त तार्किक ढंग से रखते थे जिससे विरोधी भी उनका समर्थक बन जाता था। "1927 ई० के गुजरात बाढ़ सकट के दौरान गुजराती जनता के अनुदान हेतु उन्होंने अपने विरोधी अंग्रेज सरकार से एक करोड़ रुपये प्राप्त किया।"²⁹ सुरक्षा और समृद्धि का आश्वासन देकर विलय पत्र समझौते पर हस्ताक्षर के लिए तैयार किया। रियासतों के छिन जाने के बावजूद सरदार की मृत्यु पर अनेक राजा यह कहकर रोये कि उनका मित्र तथा रक्षक चला गया।

सरदार पटेल एक सत्यप्रिय एवं ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी राजनीति नैतिक स्तर पर आधारित थी। उनकी नैतिकता का सबसे बड़ा प्रमाण नेहरू के सबंध में गाँधी जी को दिया गया वह वचन था जिसके कारण उन्होंने नेहरू को जीवन भर अपना नेता माना। सरदार कांग्रेस संगठन के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे। भारत सरकार के उप प्रधान मंत्री, गृहमंत्री तथा रियासतों से संबंधित विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री थे लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा।

सरदार पटेल पश्चिम के समाजवाद के प्रति आकृष्ट नहीं थे। वे गाँधी जी के समाजवाद, जो इस देश की आवश्यकता से जुड़ा पर, को अधिक बल देते थे। भारत का समाजवाद भारत की धरती से उभरेगा, आपसी सहयोग पर आधारित होगा। वे देश के सतुलित विकास और सबको रोजगार दिलाने पर जोर देते थे। 26 जनवरी, 1948 ई० को पटना के नागरिकों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा- "सब राजनीतिज्ञ, पूँजीपति, किसान, मजदूर, अपने-अपने धर्म का अनुपालन करें।" 13 नवम्बर, 1949 ई० को उन्होंने

२८ रागा, वी०पी०, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, खण्ड-2 आगरा, 1961 पृ० 355

२९ पटेल, राव जी भाई मणि भाई, पूर्वो, पृ० 65-66

कहा, “राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाना होगा। खाद्य और कपड़ा हमारी मूलभूत आवश्यकता है।”³⁰ इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगो को अपने हितो को राष्ट्रीय हितो के सामने त्यागने को कहा। सरकारी तत्र, उद्योग और श्रम को एक जुट होकर राष्ट्र के विकास में सक्रिय होना होगा। हमे अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को राष्ट्रीय कर्तव्य के सामने छोड़ना होगा। कम खर्च करो, अधिक से अधिक बचत करो, पूँजी निवेश करो, ये हमारे मूलमंत्र बने।” 2 नवम्बर, 1948 को पटेल ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर रोक की बात कही, क्योंकि उनके अनुसार महगाई हमारी आजादी पर सीधा प्रहार करती है।

सरदार पटेल अपने दृढ़ सकल्प और लौह नेतृत्व के लिए विख्यात है। राष्ट्रीय हित के लिए वे कठोर से कठोर कदम उठाने से नहीं हिचकिचाये। राष्ट्र की एकता और अखण्डता उनके जीवन का लक्ष्य था। भारत की एकता एवं अखण्डता के महत्व को समझाते हुए उन्होंने 17 दिसम्बर, 1947 ई० को जयपुर में कहा था कि—“एकता के अभाव के कारण भारत ने आजादी खोई। राजपूताना के स्त्री-पुरुषों की बहादुरी और समर्पण के बावजूद सदियों पहले भारत गुलाम बना था, हम फिर से यह भूल न दोहराये।”³¹ 2 जनवरी, 1948 ई० को शिलांग में सरदार ने कहा कि “भारत एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। छ महीने पहले भारत में अनेक छोटे-छोटे स्वतंत्र रजवाड़े खड़े हो गये होते। इसके बदले हमने एकीकरण और राष्ट्रीय एकता सिद्ध की है। इसके परिणामस्वरूप उज्ज्वल भविष्य के लिए विशाल अवसर खड़े हुए हैं। हमारे अच्छे या बुरे भविष्य का निर्माण अब हमारे हाथ में है। अगर हमे अपना भविष्य सुधारना है तो वह एकता के द्वारा ही सम्भव है।”³²

सरदार पटेल एक कुशल, योग्य, अनुशासनप्रिय प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अनुशासन सरदार को बहुत प्रिय था। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी अनुशासन भंग नहीं किया तथा जो भी अनुशासनहीनता का आचरण करता था उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने से नहीं चूके। इस सदर्म में नारीमान और डॉ० खरे के विरुद्ध उनके द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रसिद्ध है। सरदार ने सरकारी सेवाओं को सदा उनके

३० भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947-50), प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1970, पृ०-133

३१ सरदार साहित्य गाला सम्पुट, अहमदाबाद, 1989, पृ०-15

३२ वही, पृ०-18

दायित्वों के प्रति सजग किया। वे स्वच्छ और सबल प्रशासन के प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने भ्रष्टाचार को मजबूती से दबाया। बिहार के गुड घपले की कड़ाई से छानबीन करवाई।

सरदार स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। सदैव स्वतंत्र चिन्तनशील कार्य पद्धति पर चले। यद्यपि उन्हें गाँधी जी का अन्धभक्त कहा जाता है, परन्तु अनेक अवसरों पर उन्होंने गाँधी जी से असहमति प्रकट की। उदाहरणार्थ, गुजरात विद्यापीठ का पुस्तकालय, जोकि गाँधी जी ने स्व० काका कालेकर की सलाह से अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी को एक पक्षीय निर्णय से दी थी, सरदार की दृढ़ता के कारण उसे वापस लेना पड़ा।

सरदार पटेल मे अद्भुत दूरदर्शिता थी। उनके जीवन के असंख्य उदाहरण उनकी दूरदर्शिता का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। सरदार पटेल काश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के खिलाफ थे। यदि इस मुद्दे पर पटेल की बात स्वीकार की गयी होती तो यह गम्भीर समस्या न बनती। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व सरदार ने नेहरू को पत्र लिखकर सूचित किया कि हिन्दी चीनी भाई-भाई की तुम्हारी धारणा गलत है। इस प्रकार सरदार ने पहले ही चीन की साम्राज्यवादी नीति को पहचान लिया था।

मुस्लिमों के प्रति सरदार पटेल का दृष्टिकोण राष्ट्रहित पर आधारित था। जिसके कारण कुछ लोगो ने उन्हें मुस्लिम विरोधी के रूप में प्रचारित किया, परन्तु वे वास्तव में सभी अर्थों में तटस्थ थे। 6 जनवरी, 1948 ई० को सरदार पटेल ने कहा था कि “मैं मुसलमानों का सच्चा मित्र हूँ पर मुझे उनका शत्रु करार दिया जाता है क्योंकि मैं स्पष्ट बात कहता हूँ।” उन्होंने मुसलमानों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें एक राष्ट्र का चुनाव करना है, दो नावों पर एक साथ सवार नहीं हो सकते।”³³

सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू ने संसद में कहा कि “आज सवेरे 9 37 को एक महान जीवन का अन्त हो गया। भारत का इतिहास उन्हें राष्ट्र निर्माता एवं कुशल संगठनकर्ता के रूप में याद करेगा। वे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायक थे, जिन्होंने हमें कठिनाइयों में सही सलाह दी, विजय के क्षणों में एक मित्र व सहयोगी रहे। शक्ति के स्रोत के रूप में गिरते मनोबल को ऊपर उठाया।”³⁴

33 भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947-50), प्रकाशन विभाग नई दिल्ली 1970, पृ०- 68

34 कृष्णा बी, इण्डियाज आयरन मैन नयी दिल्ली, 1995, पृ०-513

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि कोई अग्नि सरदार के यश को जला नहीं सकती। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा कि वल्लभ भाई प्रेरणा, आत्मबल और शक्ति का जीवन्त स्वरूप थे। मौलाना आजाद के शब्दों में पटेल की दिलेरी और वीरता पहाड़ों की तरह ऊँची थी उनका निर्णय लौह समान था।³⁵

अशोक मेहता ने सरदार को 'इस्पात का व्यक्ति' बताया जिनमें चट्टान की तरह आत्मविश्वास था।³⁶ वे जरा भी जल्दबाज नहीं थे। उनमें सयम था, वे रुकना जानते थे और रुक कर, समय और साधनों की प्रतीक्षा कर एक बार कदम आगे बढ़ा देते थे, तो बड़े हुए कदमों को पीछे खींचना तो दूर रहा, उसे रोकना नहीं जानते थे। अपने उद्देश्य मार्ग के अवरोधों को हटाने में वे एक ऐसे अभिजात आक्रमणकारी थे जिनके हृदय में लेशमात्र भी दया भाव नहीं रहता।³⁷

३५ गांधी, राजमोहन, पटेल ए लाइफ, अहमदाबाद, 1973, पृ०- 533

३६ मेहता, अशोक, सरदार पटेल, एक शब्द चित्र पटेल अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ०- 49

३७ दास, सेठ गोविन्द, पूर्वो, पृ०- 94-98

अध्याय - 2

कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता के रूप में सरदार पटेल

- (i) सार्वजनिक जीवन में प्रवेश
 - (ii) अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में योगदान
 - (iii) गुजरात सभा के सचिव
 - (iv) खेडा सत्याग्रह
 - (v) रौलेट एक्ट का विरोध
 - (vi) नागपुर झंडा सत्याग्रह
 - (vii) बोरसद सत्याग्रह
 - (viii) बारदोली सत्याग्रह
 - (x) कांग्रेस मंत्रिमंडल के पथ प्रदर्शक
 - (ix) पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष
 - (xi) 1945-46 के चुनावों के प्रमुख
-

कुशल प्रशासक एव संगठनकर्ता के रूप में सरदार पटेल

1915 ई० तक वल्लभ भाई पूरे तरीके से वकालत के पेशे से जुड़े रहे तथा राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने बैरिस्टरी की शुरुआत अहमदाबाद से की, जबकि उनके बड़े भ्राता विट्ठल भाई पटेल बम्बई में वकालत करने के साथ-साथ अपना अधिकांश समय सार्वजनिक कार्यों में व्यतीत करते थे। इसलिए वल्लभ भाई ने परिवार का खर्च उठाने की जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधों पर ले ली तथा भाई को सार्वजनिक कार्यों के लिए खुली छूट दे दी। सन् 1921 ई० में वल्लभभाई ने दोनों भाइयों के मध्य हुए समझौते की रोचक चर्चा करते हुए कहा, “हमने तय किया कि दोनों में से एक देश की सेवा करे और दूसरा कुटुम्ब सेवा करे। तबसे मेरे बड़े भाई ने अपना धड़ाके से चलता हुआ पेशा छोड़कर देश सेवा का कार्य शुरू कर दिया और मैंने घर चलाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने का कार्य किया। इस प्रकार पुण्य का कार्य मेरे बड़े भाई के हिस्से में आया और मेरे हिस्से में आया पाप का कार्य। परन्तु मैं यह समझकर मन को खुश कर लेता कि उनके पुण्य में मेरा भी हिस्सा है। वकालत का धन्धा करते हुए मेरे मन में मेरा भी हिस्सा है।¹ 1913 ई० में विट्ठल भाई के बम्बई विधान परिषद् में चुने जाने के उपरान्त वल्लभभाई राजनीति की ओर आकर्षित हुए। 1915 ई० में गुजरात सभा द्वारा आयोजित बम्बई प्रेसीडेन्सी राजनीतिक सभा में विट्ठलभाई के साथ भाग लेकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। तदुपरान्त भारतीय राजनीति में एक कुशल प्रशासक एव संगठनकर्ता के रूप में विख्यात हुए।

(i) सार्वजनिक जीवन में प्रवेश

1915 ई० में दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर आश्रम स्थापित कर वही बस गये। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गाँधी जी द्वारा चलाये गये आन्दोलन में अपनाये गये सत्य और अहिंसा का सिद्धान्त गुजरात क्लब में चर्चा का विषय बन गया। गुजरात क्लब के अधिकांश सदस्यों के आग्रह पर गाँधी जी

को क्लब में आमंत्रित किया गया। गॉंधी जी अपना विचार व्यक्त करने के लिए आये। श्री जी०डी० मावलकर ने तत्कालीन घटना की चर्चा करते हुए लिखा है, “जब गॉंधी जी क्लब में आये उस समय वल्लभ भाई अपने मित्र ठाकोर के साथ ब्रिज खेल रहे थे और मैं साथ बैठा खेल देख रहा था। जब मैं गॉंधी के पास जाने के लिए उठने लगा तो वल्लभभाई ने मुझे वहाँ जाने से रोकने के लिए मुझ पर व्यंग्य किया कि वहाँ जाकर क्या सुनोगे, वे तो गेहूँ में से ककड बीनने की ही बात कहेंगे। ऐसा करने से क्या देश स्वतंत्र होने वाला है? क्या उस समय किसी ने ऐसा सपने में भी सोचा था कि यह व्यक्ति एक दिन गॉंधी जी के दर्शन, कार्य पद्धति एवं नेतृत्व में दृढ़ विश्वास रखने वाला बनेगा।”²

उस समय देश के नेता माने जाने वाले व्यक्तियों की दिनचर्या उनके अस्पष्ट विचार अनिश्चित व्यवहार, आदि देखकर वल्लभ भाई के मन में तत्कालीन राजनीतिज्ञों के प्रति घृणा हो गयी थी। इसी बीच गॉंधी जी द्वारा गुजरात सभा का सदस्य बनने के लिए रखी गयी यह शर्त “गुजरात सभा प्रजा को सत्ताधारियों से भीख माँगने की सलाह न दे, परन्तु प्रजा को इस प्रकार शिक्षा दे कि उसमें सरकार से अपने उचित अधिकार प्राप्त करने की शक्ति पैदा हो।” वल्लभभाई को प्रभावित किया। साथ ही विट्ठल भाई की सफलता तथा राजनीति में सक्रिय लोगों से सम्पर्क के कारण वल्लभभाई ने एक साथ दो क्षेत्रों- प्रथम अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी और द्वितीय गुजरात सभा में प्रवेश किया।

(ii) अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में योगदान

प्रजातान्त्रिक मूल्यों के विरुद्ध सरकार ने 1914 ई० में म्युनिसिपल एक्ट में संशोधन करके अधिक आबादी वाले नगरों की म्युनिसिपैलिटियों में एक म्युनिसिपल कमिश्नर रखने की व्यवस्था की। म्युनिसिपल कमिश्नर पद पर आई०सी०एस अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। साथ ही उसे और अधिक अधिकार सौंपे गये। इस संशोधन के पीछे सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाना और उसके अधिकार सीमित करना था। जन विरोधी इस संशोधन का जनता ने विरोध किया। एम० ए० जिन्ना की अध्यक्षता में अहमदाबाद में हुए सम्मेलन में इस प्रतिक्रियावादी संशोधन का विरोध किया

गया तथा इसे म्युनिसिपेलिटी के सीमित आर्थिक साधनों पर अनुचित बोझ की सजा दी गयी।”³ सम्मेलन में इस सशोधन को रद्द करने की भी माँग की गयी जिसे सरकार ने अस्वीकार कर जॉन शिडली नामक म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति की, जो बहुत ही घमडी और निष्ठुर व्यक्ति था। इस पद पर नियुक्ति पाते ही उसने अपने आतंक का राज्य कायम कर लिया।

अहमदाबाद के वकील समुदाय के निवेदन पर वल्लभ भाई ने म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया। सयोगवश दरियापुर बोर्ड के म्युनिसिपल सदस्य की मृत्यु के कारण उप चुनाव हुआ, जिसमें वल्लभ भाई पटेल (17 मई, 1917) निर्विरोध चुन लिये गये। चालीस सदस्यीय म्युनिसिपल बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष सर रमण भाई मैन थे। म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य बनने के उपरान्त सरदार पटेल ने सर्वप्रथम म्युनिसिपल एक्ट के नियमों एवं उपनियमों का अध्ययन किया और प्रयास किया कि किस प्रकार से निर्वाचित सदस्यों एवं म्युनिसिपल के कर्मचारियों में सामंजस्य पैदा किया जाय और उन्हें जनता के प्रतिनिधियों के निकट लाया जाय। इसके उपरान्त वल्लभ भाई ने म्युनिसिपल कमिश्नर जॉन शिडली की अमानुषिक मनोवृत्ति पर अकुश लगाने का निश्चय किया।

म्युनिसिपल बोर्ड ने अपनी सीमा के अन्दर एक सील भरवाने का प्रस्ताव किया जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड को पचास हजार वर्ग गज भूमि विकास हेतु मिल सकती थी। परन्तु कमिश्नर शिडली ने बोर्ड के प्रस्ताव के विरुद्ध उस क्षेत्र को फतेह मोहम्मद गुशी नामक व्यक्ति को दिया सिलाई की फैक्ट्री हेतु पट्टे पर देने का निर्णय किया। पुराने अभिलेखों का अध्ययन करके वल्लभ भाई पटेल ने सिद्ध किया कि कमिश्नर में व्यक्तिगत हितों के लिए सार्वजनिक हितों की उपेक्षा की। सरदार पटेल ने बोर्ड से एक प्रस्ताव पास करवाया कि शिडली ने सील के सबंध में बम्बई सरकार को गलत सूचना दी, अतः वे अपने पद के योग्य नहीं हैं। वल्लभ भाई के प्रयासों से शिडली को अपने पद से हटना पड़ा।”⁴ यह वल्लभ भाई की सार्वजनिक क्षेत्र में पहली विजय थी।

3 मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभभाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली, 1997

शिडली की जगह मि० मास्टर कमिश्नर बनकर आये। वे स्वभाव से तो नरम अवश्य थे किन्तु काम में अत्यन्त ढीले थे। उनका एकमात्र उद्देश्य जनता का शोषण करना एवं अपनी जेब गर्म करना था। आते ही उन्होंने वेतन के अतिरिक्त कुछ भत्तो की माँग की। सरदार वल्लभभाई पटेल को जैसे ही इसकी सूचना मिली उन्होंने तुरन्त जवाब दिया कि सरकार ने जो वेतन वगैरह निश्चित करके उनकी नियुक्ति की है उन्हें स्वीकार हो तो रहे अन्यथा चले जाँय। फलतः उन्हें बाध्य होकर वापस जाना पड़ा।

उत्तरी क्षेत्र के कमिश्नर फ्रैंडरिक प्रैट जिनकी इच्छा थी कि म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ-साथ म्युनिसिपल इंजीनियर एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी अग्रेज होना चाहिए, का विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। संयोगवश उसी समय अहमदाबाद में म्युनिसिपल इंजीनियर की जगह खाली हुई। यद्यपि इस पद के लिए दो भारतीय उम्मीदवार भी खड़े किये गये जो काफी योग्य थे, परन्तु मि० प्रैट ने मेकासे नामक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया और अपनी कूटनीति से म्युनिसिपल इंजीनियर भी बना दिया। उनकी नियुक्ति होते ही म्युनिसिपैलिटी में असंतोष का वातावरण छा गया। संयोगवश उन्हीं दिनों शहर में पानी की कमी हुई जिससे जनता बहुत त्रस्त हो गयी। गुजरात सभा की ओर से महात्मा गाँधी की अध्यक्षता में एक आम सभा बुलाई गयी जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया तथा उसकी एक-एक प्रति म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष, कलक्टर तथा कमिश्नर तीनों को भेजी गयी। कमिश्नर साहब ने गुजरात सभा के मंत्रियों से मिलने की इच्छा व्यक्त की। अतः मंत्री की हैरियत से श्री शिवाभाई मोतीभाई पटेल और दादा साहब भावलकर उनसे मिलने गए। मुलाकात के दौरान मि० प्रैट ने म्युनिसिपल एक्ट को सामने रखकर तार्किक उत्तर दिये। उन्होंने कहा कि, “कानून में म्युनिसिपैलिटी शब्द है इसमें चुने हुए म्युनिसिपल अग और मनोनीत म्युनिसिपल अग का कोई भेद नहीं किया गया है। इसलिए आपको जो कुछ भी शिकायत हो उसके लिए म्युनिसिपल हाल में जाइये और आप जो चाहते हैं न मिले तो म्युनिसिपल कमेटी को चैन न लेने दीजिये। वहाँ ढोल पीटिये। इतने पर भी पानी न मिले तो, मेम्बरो के घर जाइये और उनके घरों में आग लगा दीजिये।”⁵ कुछ दिनों बाद पानी की स्थिति की जाँच के लिए सरकार के सलाहकार इंजीनियर डायर अहमदाबाद भेजे गये। सेनिटरी कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते सरदार पटेल ने भी डायर और प्रैट के साथ पानी

की वास्तविक स्थिति की जाँच के लिए शहर का भ्रमण किया। बातचीत के दौरान मि० प्रैट ने मुस्कराते हुए सरदार साहब से कहा कि परिस्थिति से मुकाबला करने का सर्वोत्तम तरीका तो यह है कि आपकी कमेटी म्युनिसिपल इंजीनियर के साथ सहयोग करे।⁶ मि० प्रैट अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाये थे कि पटेल ने गुस्से में उत्तर दिया, “उत्तम उपाय तो इस नालायक व्यक्ति को नौकरी से निकाल देना है। आपने इसे म्युनिसिपैलिटी पर थोप दिया है। इस इंजीनियर ने हमारी कमेटी से जो कहा उसे क्या हमने नहीं किया? इन्हीं से पूछिये क्या ऐसा एक भी उदाहरण दे सकते हैं? जब गुजरात सभा के मंत्री आपसे मिलने गये तब आपने उन्हें यह सलाह देने की घृष्टता की कि जाकर हमारे घर फूँक दे? हमारे घर क्यों जलने चाहिये? सारे फसाद की जड़ तो यह आदमी (मैकासे) है। इसका बगला जलना चाहिये।”⁷ सरदार पटेल का उत्तर सुनकर मैकासे को वापस बुला लिया गया। इस घटना के बाद सरदार पटेल ने महसूस किया कि उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ वकालत करना ही नहीं बल्कि अपने आपको मानव कल्याण के लिए समर्पित कर देना है।

1920 ई० में सम्पन्न हुए म्युनिसिपैलिटी के त्रिवर्षीय चुनाव में सरदार पटेल के प्रयास से उनके नेतृत्व में विश्वास करने वाले अधिकतर सदस्य चुने गये। सरदार पटेल स्थानीय स्वशासन के मार्ग में अवरोधक कानूनों को व्यर्थ मानते थे। सेनिट्ररी कमेटी के सभापति होने के कारण सरदार साहब ने पानी की उचित व्यवस्था तथा नालियों की सफाई आदि क्षेत्रों में क्रान्तिकारी सुधार किये। गाँधीजी के नेतृत्व में चलाये गये असहयोग आन्दोलन के समर्थन में अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के प्रबंध में चलने वाले विद्यालयों ने सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन का समर्थन किया। परिणामस्वरूप सरकार ने ग्राण्ट बन्द कर दिया लेकिन इसके बावजूद सरदार पटेल के प्रयासों से शिक्षातंत्र व्यवस्थित और सुचारु रूप से पुनः चलने लगा। 1921 ई० में सरदार ने म्युनिसिपल एक्ट की धारा 178 बी के आधार पर म्युनिसिपल स्कूलों का प्रबन्ध तब अपने एक हाथ में ले लिया और उसे डिप्टी इसपेक्टर ऑफ स्कूल के अधीन कर दिया तथा इम्पीरियल बैंक के खाते से भी धन डिप्टी इसपेक्टर ऑफ स्कूल के खाते में हस्तान्तरित करने के आदेश दिये। जनवरी 1922 ई० में रामस्या और विकट हो गयी जब म्युनिसिपल बोर्ड के एक सदस्य राव साहब हरिलाल भाई ने बैंक

६ पटेल, आई०जे०, वल्लभ भाई पटेल, पब्लिकेशन डिवीजन, 1986 पृ० 46

७ पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई, -भाग-एक, अहमदाबाद, 1950, पृ० 56

द्वारा धन वापस न करने पर इम्पीरियल बैंक पर मुकदमा दायर करने की धमकी दी। ऐसी स्थिति में सरकार ने अहमदाबाद और सूरत म्युनिसिपैलिटीया बंद कर दी।⁸ सरदार पटेल ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए लिखा, “स्थानीय स्वशासन की नीति पर माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रकाशित होने के बाद मई 1918 ई० में एक प्रस्ताव प्रकाशित किया था। उसमें केन्द्रीय सरकार ने जो नीति घोषित की है, उसमें बम्बई म्युनिसिपैलिटी को बर्खास्त करने का प्रस्ताव बिल्कुल विरुद्ध है।”⁹ वल्लभ भाई की नजरों में “अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी का झगडा सहयोग असहयोग के बीच नहीं था, बल्कि अन्धे सहयोग और स्वाभिमान के बीच था।”¹⁰

सरदार पटेल के प्रयासों से सस्था के कर्मचारियों एवं म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों के बीच सहकारिता का सुमेल हो गया। सरदार साहब की नजरों में असहयोग का सच्चा अर्थ पाप के साथ असहयोग एवं पुण्य के साथ सहयोग करना है। उनके अनुसार यदि पाप के साथ असहयोग करने के साथ ही यदि पुण्य कार्य के साथ सहयोग न किया जाय तो पाप के साथ किया हुआ असहयोग अपूर्ण माना जायेगा।

सरदार पटेल ने अपनी बुद्धि, चतुराई, कुशलता और शुद्ध सेवा भावना के प्रताप से अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी जैसी स्थानीय स्वराज्य की सस्था को सरकार के नागपास से मुक्त करके उसे शुद्ध प्रजातान्त्रिक सस्था बना दिया। ब्रिटिश सत्ता की फौलादी चहारदिवारी से और उस शासन के आदी बने हुए भारतीय कर्मचारियों को मानसिक गुलामी से मुक्त कराकर अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी को कार्यक्षेत्र और जनता का सेवा केन्द्र बना दिया।

वल्लभ भाई केवल प्रबन्ध कार्य में ही कुशल नहीं थे। शहर के सांस्कृतिक विकास, स्वास्थ्य सुधार, सुन्दर स्थाप्य कला तथा जनता के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की सुविधायें खड़ी करने में भी उनकी कुशलता के दर्शन होते हैं। आज का विशाल बाडी लाल साराभाई अस्पताल और सेठ चिनाई प्रसूति गृह पटेल के भागीरथ प्रयत्न के ही परिणाम हैं। शहर की घनी बस्ती छोड़कर शहर के बाहर खुले हवा, पानी का लाभ उठाने के लिए उन्होंने नागरिकों को सोसायटियों खड़ी करने की प्रेरणा दी। बदबू फैलाने वाले तालाबों के

८ . मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, पूर्वो, पृ० 20

९ . नवजीवन, 19 फरवरी, 1992

१० . वही

स्थान पर विशाल दृष्टि रखने वाले इंजीनियरो को बुलाकर आज के काकरिया जैसे रमणीय स्थल की योजना तैयार कराई। शहर के आसपास जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता था वहाँ सुन्दर बगीचे लगवाये। धनी लोगो की तिजोरी में कैद लक्ष्मी को मुक्त कराकर, उससे शिक्षा, कला तथा संस्कृति का प्रसार करने वाली संस्थाएँ खड़ी करवाई। इस प्रकार सरदार ने अहमदाबाद की जनता की शुद्ध मन से सेवा की।

सन् 1924 ई० में सम्पन्न हुए बोर्ड के चुनाव में स्थानीय कांग्रेस ने वल्लभ भाई के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। 60 सदस्यीय बोर्ड में 12 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत थे। शेष 48 में 10 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित थे। कांग्रेस ने 48 स्थानों पर चुनाव लड़ा जिसमें उसे 35 स्थानों पर सफलता मिली। वल्लभ भाई को बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। अपने अध्यक्षकाल में वल्लभ भाई ने म्युनिसिपल क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये।

6 जुलाई, 1927 ई० को सूरत में गुजरात स्थानीय निकाय के सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में पटेल साहब ने स्थानीय निकायों की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए सरकार की नीति की तीखी आलोचना में कहा, "पूरे प्रान्त में 157 म्युनिसिपैलिटीयों हैं जिसमें से लगभग सभी की आर्थिक स्थिति बुरी है।"¹¹ अहमदाबाद सुधार हेतु सरदार पटेल ने सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिये। सरदार पटेल के व्यक्तित्व के अनुसार अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी को छोड़ना उनका ही नाटकीय और महत्वपूर्ण था जितना कि उनका प्रवेश। 13 अप्रैल, 1928 ई० को पटेल साहब ने म्युनिसिपैलिटी से त्याग पत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के पीछे निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कारण थे।

1 अध्यक्ष होने के पश्चात् उनकी इच्छा अपने सहयोगियों के की सहायता से म्युनिसिपैलिटी के प्रशासन को अत्यधिक कुशल बनाने की थी लेकिन सितम्बर 1926 ई० से वे म्युनिसिपैलिटी की कार्य पद्धति से असन्तुष्ट चले आ रहे थे।

2 बारदोली सत्याग्रह तथा गुजरात प्रान्त की कांग्रेस को सशक्त बनाने हेतु भी सरदार पटेल स्थानीय स्वशासन से विमुख होने लगे।

म्युनिसिपल क्षेत्र में सरदार पटेल के नेतृत्व और उनके योगदान की चर्चा करते हुए पाठक एव सेठी ने लिखा है, "अपने प्रथम कार्यकाल (1917-1920 ई०) में पटेल ने संघर्ष

की भूमिका अपनाई और द्वितीय कार्यकाल तथा उसके उपरान्त उनका उद्देश्य सकारात्मक कार्यों द्वारा स्थानीय स्वशासन की जड़ों को मजबूत करना था।¹² स्थानीय स्वशासन के बारे में अपने अनुभवों की चर्चा करते हुए स्वयं पटेल के कहा है, “मैंने अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी की अपनी क्षमतानुसार सेवा की, नगर की सेवा करने में हमें जो सन्तोष होता था, उसे मैं दूसरे क्षेत्र में प्राप्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा नगर की गन्दगी दूर करना राजनीति में गन्दगी दूर करने से भिन्न है। प्रथम से आपको रात में अच्छा आराम प्राप्त होगा जबकि दूसरा आपको चिन्तित रखेगा तथा आपकी नींद खो देगा।”¹³

(iii) गुजरात सभा के सचिव

सन् 1917 ई० में चलाये गये चम्पारण आन्दोलन के कारण गॉंधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में विशेष प्रभाव डाला। जुलाई 1917 ई० में गॉंधीजी को सभी लोगों ने एक स्वर से गुजरात सभा का अध्यक्ष चुना। उनके सहयोगी के रूप में वल्लभ भाई सचिव पद पर, साथ ही हरिलाल देसाई भी सचिव और जी०वी० मावलकर को सयुक्त सचिव पद पर चुना गया। इसी वर्ष यह भी निश्चित किया गया कि प्रतिवर्ष गुजरात में एक राजनैतिक परिषद् की बैठक की जाये। प्रथम परिषद् के लिए सर्वसम्मति से गोआ शहर को उपयुक्त समझा गया। महात्मा गॉंधी की अध्यक्षता में प्रथम बैठक नवम्बर 1917 ई० में हुई जिसमें देश के अनेक नेताओं ने भाग लिया। गॉंधीजी द्वारा सभा में अपना भाषण अंग्रेजी में न दिये जाने के कारण जिन्ना ने गुजराती तथा बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में अपना भाषण दिया। वल्लभ भाई ने कोई भाषण नहीं दिया। गॉंधी जी ने इस परिषद् में तीन महत्वपूर्ण सुधार किये। प्रथम प्रत्येक वक्ता को या तो हिन्दी में या गुजराती में भाषण देना होगा, द्वितीय किसी भी प्रस्ताव में ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी नहीं दिखाई जायेगी, तृतीय परिषद् की ओर से एक कार्य समिति का गठन किया जाय जो दूसरे वर्ष दूसरी परिषद् के गठन तक कार्य करे।

परिषद् द्वारा बनायी गयी कार्यसमिति के अध्यक्ष महात्मा गॉंधी बने। इसके प्रधान मंत्री वल्लभ भाई पटेल बनाये गये, जबकि इन्दु लाल पारिक इसके सयुक्त मंत्री बनाये गये। समिति की केन्द्र भूमि अहमदाबाद को बनाया गया।

१२ पाठक, देवव्रत एन०, प्रवीण सेठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फ्राम सिविल टू नेशनल लीडर शिप अहमदाबाद, 1980, पृ० 361

१३ तहमनकर, डी०वी, सरदार पटेल, लन्दन 1970, पृ० 63

गोधरा परिषद् की कार्यसमिति के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी, वह थी बेगार प्रथा का उन्मूलन। बेगार प्रथा के बारे में नरहरि पारीख ने लिखा है, “उस समय जब सरकारी अधिकारी गाँवों में जाते थे तो गाँव के विभिन्न प्रकार के पेशे के लोगों से बेगार लेते थे। गाँव के कुम्हार, नाई वगैरह लोगों को अधिकारी तथा उनकी कचहरी के आदमियों की तमाम सुविधाओं के लिए अलग-अलग काम मजबूरन करने पड़ते थे और उसके लिए पूरे दाम नहीं मिलते थे और कई बार तो बिल्कुल नहीं मिलते थे। बढई को साहब के तम्बू खड़े करने के लिए लकड़ी की खूंटिया तैयार कर देनी पड़ती थी, कुम्हार को मिट्टी के बर्तन मुहैया कराने पड़ते थे और पानी भरना पड़ता था, नाई को बुहारने, झाड़ने और दिया बत्ती का काम करना पड़ता था, गाव के बनिये को जो चाहिये सो खाना सामग्री जुटा देनी होती थी और जब अफसरों का डेरा उठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था तब किसानों को तमाम सामान पहुँचाने के लिए गाड़ियाँ जोतनी पड़ती थी। इस प्रकार गाँव के हर एक आदमी को कुछ न कुछ करना पड़ता था। इन सब बातों की व्यवस्था गाँव का मुखिया पटेल करता था।”

बेगार प्रथा के दुष्परिणामों से व्यथित होकर गुजरात परिषद् ने बेगार विरोधी आन्दोलन चलाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। जिसमें कहा गया कि बेगार की प्रथा अत्यन्त अन्यायपूर्ण एवं कष्टप्रद है। इसका कोई वैधानिक आधार नहीं मालूम पड़ता। परिषद् की दृष्टि से यह विशुद्ध, गैरकानूनी है किन्तु गुजरात के कई जिलों में यह प्रथा प्रचलित है और बहुत पहले से लोग इसे मान्यता देते चले आ रहे हैं, अतः परिषद् यह निवेदन करती है कि यदि इस अमानुषिक प्रथा का कोई कानूनी आधार नहीं है तो शीघ्रातिशीघ्र इसके उन्मूलन की घोषणा की जाय। सरकार और जनता के कल्याण को दृष्टि में रखते हुए परिषद् ने यह प्रस्ताव पास किया कि बेगार प्रथा को रोक कर कानून के उल्लंघन को रोका जाय।

प्रस्ताव की एक प्रति कमिश्नर प्रैट को भेजा गया किन्तु अपनी निरकुश मनोवृत्ति के कारण मि० प्रैट ने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और क्रोधावेश में आकर कचरे की टोकरी में फेंक दिया। इसी बीच गाँधी जी चम्पाराण चले गये, अतः आन्दोलन का पूरा भार सरदार पटेल के कंधे पर आ गया। उन्होंने गाँधी जी के परामर्श से मि० प्रैट के पास दूसरा पत्र भेजा और प्रथम पत्र के मसविदे की याद दिलायी। परन्तु मि० प्रैट ने दूसरे पत्र का भी कोई उत्तर नहीं भेजा। बाध्य होकर पटेल ने अपने तीसरे पत्र में स्पष्ट किया कि बेगार

प्रथा अवैधानिक है और चेतावनी दी कि दस (10) दिन के बाद परिषद् बेगार प्रथा को पूर्णतः गैरकानूनी घोषित करने के लिए जनता को पैम्फलेट द्वारा सूचित करेगी। यदि आपको कोई आपत्ति है तो 10 दिन के अन्दर ही अपना सुझाव दे।

तीसरा पत्र पढ़ने के बाद मि० प्रैट घबराया और उसने सरदार पटेल को विचार विमर्श हेतु अपने निवास पर बुलाया पर पटेल ने इन्कार कर दिया और दस दिन के उपरान्त पैम्फलेट वितरित कर परिषद् की ओर से यह घोषणा कर दी गयी कि बेगार प्रथा अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी है जिसका जनता को खुलकर विरोध करना चाहिए। इस योजना से जनता में नयी जागृति पैदा हुई। यद्यपि इस घटना से बेगार प्रथा का पूर्ण रूप से अन्त नहीं हुआ। किन्तु जनता के हृदय पर जो आतंक की कालिमा छाई थी उसका अन्त अवश्य हो गया। जनता को अपनी शक्ति पर विश्वास हो गया। महात्मा गान्धी ने इस घोषणा से प्रसन्न होकर सरदार साहब को बधाई सन्देश भेजा। यह सरदार साहब के सार्वजनिक जीवन की प्रथम विजय थी।

(iv) खेडा सत्याग्रह

खेडा सत्याग्रह सरदार पटेल के जीवन का प्रथम सत्याग्रह था। सन् 1917 में अतिवृष्टि के कारण खेडा जिले में औसतन 30 इंच वर्षा के स्थान पर 70 इंच वर्षा हुई जिससे सारी फसल नष्ट हो गई। यहाँ तक कि मवेशियों के लिए घास-चारा आदि भी उत्पन्न नहीं हुई। सामान्यतया जब कभी वर्षा ऋतु में बरसात अधिक हो जाती है तो यह उम्मीद की जाती है कि शरद ऋतु की रबी की फसल अच्छी होगी। किन्तु इस समय चूहों ने भारी उत्पात मचाया जिससे फसलों में तमाम प्रकार के रोग लग गये और फसलें बेकार हो गयीं। इस प्रकार किसानों को पूरे वर्ष दोहरीमार झेलनी पड़ी। उनके सामने लगान चुकाने का सकट आ गया। लगान के सबंध में कानून यह था कि “हर वर्ष फसल का अनुमान लगाया जाय, यदि फसल छ आने से कम मालूम पड़ती है तो आधा लगान स्थगित कर दिया जाय और यदि चार आने से कम दिखती है तो सारा लगान स्थगित कर दिया जाय साथ ही अगर उसमें अगले वर्ष भी फसल न हो तो पिछले साल का स्थगित लगान माफ कर दिया जाय।”¹⁴

17 नवम्बर, 1917 ई० को श्री पाण्डया जी ने कठलाल गॉव के किसानों की तरफ से एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से सरकार से मॉग की, कि पूरे साल में अतिवृष्टि के कारण चार आने से भी कम फसल पैदा हुई है इसलिए लगान स्थगित कर दिया जाय। इसी प्रकार नाडियाद की होमरूल लीग शाखा ने अलग-अलग गॉवों से 18 हजार किसानों, बठलाल की शाखा ने चार-हजार किसानों के हस्ताक्षर वाला प्रार्थना पत्र बम्बई सरकार के पास भेजा और उसकी प्रतियाँ जिला कलेक्टर, उत्तरी विभाग के कमिश्नर, बम्बई प्रान्त के राजस्व सदस्यों, महात्मा गॉंधी जी, गोकुल दास पारीख, माननीय विट्ठल भाई पटेल तथा गुजरात सभा के सचिवों के नाम भेजी। सरदार साहब उस समय गुजरात सभा के सचिव थे। बम्बई सरकार ने यह जवाब दिया कि “लगान के मामले में सारा अधिकार जिला कलेक्टर को है और प्रार्थना पत्र में जो मुद्दे बताये गये हैं उस पर वे ध्यान भी दे रहे हैं।”¹⁵

सरकार की ओर से कोई सन्तोषजनक उत्तर न मिलने से मध्य दिसम्बर में विट्ठल भाई पटेल तथा गोकुल दास पारीख ने किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्टर से मुलाकात करके अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप 22 दिसम्बर 1917 ई० को जिला कलेक्टर ने “अहमदाबाद, नाडियाद और कपडबग ताल्लुके के 104 गॉवों में कुल मिलाकर एक लाख पचछत्तर हजार आठ सौ अडसठ (1,75,868 रु०) को रकम की लगान स्थगित किया जबकि जिले में कुल (23) तेईस लाख रु० लगान था यानी कुल 74 प्रतिशत लगान वसूल करना ही स्थागित किया।”¹⁶ आदेश प्रकाशित होते ही पटवारी लोग जबरदस्ती वसूली करने पर उतर आये और तरह-तरह के जुल्म डाने लगे। उनके अत्याचार से लोगो ने घर त्यागना शुरू कर दिया। “पटवारी लोग अत्याचारों के साथ-साथ बेइज्जती करने पर भी उतारू हो गये थे। महिलाओं के सामने गन्दी-गन्दी गालियाँ देते थे वे कहते थे कि घर बेचो, भूमि बेचो, पशुओं को बेचो और फिर स्त्रियों और बच्चों को बेचो लेकिन सरकारी लगान का भुगतान करो।”¹⁷ सरकार ने कठोरता की और शह भी दी, जिससे एक प्रकार का किसानों के जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो गया।

इसी समय महात्मा गॉंधी अहमदाबाद पहुँचे और गुजरात सभा के सदस्यों की बैठक

१५ पटेल, राजीव भाई, मणि भाई, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1972 पृ० 49

१६ पारीख, नरहरि, पूर्वो, पृ० 85

१७ वही, पृ० 85

सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर पर हुई। जिसमें यह तय किया गया कि जब तक बम्बई सरकार की ओर से लगान सबधी प्रार्थना पत्र का उत्तर नहीं आ जाता तब तक कमिश्नर से मिलकर लगान स्थगित करने को कहा जाय। गुजरात सभा की ओर से सर्वसम्मति के आधार पर गाँधी जी किसानों को नयी दिशा देने के लिए तैयार हुए। साथ ही अपने सहायक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया। सरदार पटेल द्वारा गाँधी के सहायक के रूप में काम करने के लिए तैयार होने पर गाँधी जी बहुत खुश हुए। इसके उपरान्त सभा ने तीन प्रस्ताव पास किये।

(1) पहली तारीख (11 1918) को गुजरात सभा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र का निर्णय होने तक सरकार से लगान स्थगित करने की प्रार्थना की जाये।

(2) निर्णय सूचना किसानों को दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

(3) कमिश्नर से मुलाकात के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल का चयन किया जाय।¹⁸

सभा की बैठक के उपरान्त गाँधी जी पुन चम्पारण चले गये। अतः सत्याग्रह का पूरा भार सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधे पर आ गया। प्रस्ताव के अनुरूप सभा की ओर से गुजरात के उत्तरी डिवीजन के कमिश्नर एफ०जी० प्रैट से मिलने एक शिष्टमंडल 10 जनवरी, 1918 ई० को गया तो कमिश्नर ने केवल दो सदस्यों (कृष्ण लाल देसाई व जी०वी० मावलकर) से मिलना स्वीकार किया तथा गुजरात सभा को अवैधानिक घोषित करने की धमकी दी। “इसी बीच गाँधी जी ने तार द्वारा सरदार पटेल को सूचित किया कि लगान स्थगित करने और वसूली का कार्य बन्द करने के लिए जबरदस्त आन्दोलन छेड़ा जाय। यह सत्याग्रह है और इसी से स्वराज्य मिलेगा। सम्भव है कि वह अभी न मिले। मौका पड़ते ही अपनी शक्ति के अनुसार सत्याग्रह की महिमा दिखाना परम धर्म है।”¹⁹ गाँधी जी की सूचना के प्रतिक्रियास्वरूप खेड़ा जिले के कलेक्टर ने 14 जनवरी, 1918 ई० को आदेश निकाल कर यह चेतावनी दी कि “लगान वसूल करने या उसको स्थगित का अधिकार पूरी तरह से जिला के कलेक्टर को है। कलेक्टर के इस आदेश की पुष्टि 16 जनवरी, 1918 ई० को बम्बई सरकार ने भी कर दी।”²⁰

१८ कुमार, रवीन्द्र, सरदार पटेल का सत्याग्रही जीवन, मुजफ्फरपुर, 1987 पृ० 17

१९ वही, पृ० 18

२० वही, पृ० 18

खेडा जिले के किसानों को उनके कष्टकारी जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए सत्याग्रह का मार्ग चुना तो उनके सहयोगी के रूप से सरदार साहब ने अंग्रेजी वेशभूषा को त्याग कर धोती कुर्ता ग्रहण किया और ग्रामों के भ्रमण पर चल दिये। गान्धी जी ने समस्या के समाधान हेतु गवर्नर का भी दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस प्रकार सारे प्रयत्न के असफल हो जाने के बाद 22 मार्च, 1918 ई० को शाम के छ बजे गान्धी जी ने नाडियाद में खेडा जिले के किसानों की विशाल सभा में सत्याग्रह का मंगलाचरण करते हुए कहा कि "असल में जो पैदावार हो उसमें लगान किया जाता है, पैदावार न होने पर भी सरकार दवाब डालकर लगान ले, यह सहन नहीं किया जा सकता, परन्तु इस देश में यह नियम ही बन गया है कि, सरकार की बात ही रहनी चाहिये। लोग कितने ही सच्चे हों, तो भी उनकी बात न मानकर सरकार को अपने ही मन की करनी है परन्तु बात तो न्याय की ही टिक सकती है। अतः उसके सामने अन्याय का फैसला बदलना ही पड़ेगा।"²¹ इसी दिन लगभग 200 किसानों ने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किये दिन प्रतिदिन यह संख्या बढ़ती ही गयी।

महात्मा गान्धी के प्रथम सहायक के रूप में सरदार पटेल ने सत्याग्रह का खूब जोर शोर से प्रचार-प्रसार किया। गान्धी जी की अनुपस्थिति में सरदार पटेल ही सत्याग्रह का नेतृत्व करते थे। यद्यपि गान्धी जी इस आन्दोलन के संचालक थे पर सरदार पटेल ने इस आन्दोलन का क्षेत्र घटाने के लिए अपने ढंग के गाँव-गाँव जाकर किसानों को हिम्मत बधाई। सरदार पटेल में तो सत्याग्रह के गुण जन्मजात थे पर गान्धी जी के सैनिक के रूप में उन्होंने जो कमान सम्भाली उससे किसानों को विशेष हिम्मत आयी। वे लगातार कुर्कियों, जारी रहने पर भी अहिंसक बने रहे। सरदार पटेल की प्रेरणा से स्त्रियों ने पुरुषों के साथ बराबर की भागीदारी करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक अखबार ने तो लिखा कि, "जिस ढंग से रैयत लड़ रही है वह अपने में आश्चर्यवान है।"²² दूसरे प्रान्तों में भी सत्याग्रह के समर्थन में सभाएँ होने लगीं और सरदार पटेल के पास बधाई सन्देश आने लगे। गान्धी जी की छत्रछाया में सरदार पटेल ने इतना संगठित आन्दोलन चलाया कि उसकी गूँज

२१ होम पोलिटिकल डिपार्टमेंट 1918 डी०एन०/ एफ० एन० 26-12-18, नेशनल आर्चिवा आफ इण्डिया न्यू, देहली

२२ पटेल, ईश्वर भाई, सरदार पटेल, आणंद 1974, पृ० 40

‘हाऊस ऑफ कामन्स’ तक सुनायी दी। सरदार पटेल ने निम्न मंत्र खेडा के किसानों को सत्याग्रह की सफलता के लिए बताये।

1 “सरदार पटेल ने किसानों से कहा कि “यदि कानून गलत हो या उसका अमल सही ढंग से सरकार न कर रही हो तो कानून का उचित ढंग से पालन कराने के लिए प्रजा को कानून के विरुद्ध जाकर भी सत्याग्रह करना पड़ता है। यह प्रजा का अधिकार है।”²³ उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर अन्याय कि विरुद्ध भी सत्याग्रह नहीं किया गया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सरदार पटेल ने कहा कि “आप जानते हैं कि एक कुम्हार भी गधे पर पहले एक मन बोझा रखता है, यदि उसे वह ले जाय तो आधा मन और बढ़ा देता है और इस तरह करते-करते उससे दो मन बोझा खिचवाता है। इसी प्रकार आप सरकार के आस-पास बोझा जैसे-जैसे सहन करते जायेंगे वैसे-वैसे सरकार आप पर ज्यादा बोझा डालती जायेगी। आपने जो बोझा अभी तक सहन किया है उसे उतार फेंकिए और निर्भीक होकर बैठिये।”²⁴

(2) किसानों का नेतृत्व वही कर सकता है जो उनके बीच रहकर उन जैसा हो जाय। इसके लिए वह अपना निवास अहमदाबाद से उठाकर नाडियाद किसानों के बीच ले गये।

(3) सरदार पटेल ने किसानों को अहिंसक रहकर कष्ट सहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि, “सरकार ने सत्ता की जोर से जमीन का लगान वसूल करने का निश्चय किया है। लोगो ने प्रतिज्ञा की है कि सरकार के अनुचित आदेशों का आदरपूर्वक वहिष्कार किया जाये और सरकार उसमें अगर सत्ता का प्रयोग करे तो आने वाले सभी दुःख सहन कर लिये जाय मगर लगान न अदा किया जाये।” किसानों ने सरदार पटेल की बातों को मानकर सरकारी क्रूरता तथा दुःखों को सहन किया, किन्तु लगान अदा नहीं किया।

(4) सरदार पटेल ने किसानों को एकता का मंत्र देते हुए कहा कि, “आपस में जो जोश है उसे न्याय के लिए लड़ने के काम में लीजिये। मारने के लिए हँसिया उठाना छोड़ दीजिये। विनय और विवेक से चलिये।”²⁵ सरदार पटेल का कथन था कि यदि जन-बल

२३ पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक), अहमदाबाद, 1950, पृ० 19

२४ वही, पृ० 23

२५ वही, पृ० 27

एकत्रित हो जाय तो कोई भी सरकार उसकी शक्ति नहीं तोड़ सकती। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि, “किसान एक है, उसका काम एक है, आदर्श एक है तथा मार्ग एक है।”²⁶

इस प्रकार आंदोलन अहिंसक मार्ग से किसानों को कष्ट सहन करने की प्रेरणा देते हुए गाँधी जी की छत्रछाया में सरदार पटेल के व्यावहारिक नेतृत्व में सफलता की ओर बढ़ चला था कि उसी बीच (3) तीन जून, 1918 ई० को गाँधी जी जैसे ही नाडियाद पहुँचे तहसीलदार उनके निवास पर पहुँच गया और उसने कहा कि, यदि अच्छी स्थिति वाले लोग लगान चुका दे तो गरीब लोगों का लगान स्थगित कर दिया जायेगा।²⁷ इस पर गाँधी जी ने लिखित रूप से ऐसा देने के लिये कहा। तहसीलदार ने ऐसा ही किया। इसके उपरान्त गाँधी जी कलेक्टर से मिले और कहा कि यदि ऐसा आदेश सारे जिले में लागू कर दिया जाय और अन्य प्रकार के दण्ड जो किसानों को कुर्की के दौरान दिये गये हैं उन्हें रद्द कर दिया जाय तो आन्दोलन का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा।” कलेक्टर ने गाँधी जी की बात मानकर आदेश जारी कर दिया। इस प्रकार सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया।

“इस सत्याग्रह से जो भी सफलता मिली उसका सेहरा गाँधी जी ने सरदार पटेल के सिर पर रखते हुए कहा कि “सेनापति की चतुराई अपनी कार्य समिति चुनने में होती है। बहुत से लोग मेरी सलाह मानने के लिए तैयार थे लेकिन उप सेनापति के रूप में मैंने वल्लभभाई को चुना। वल्लभभाई ने अपनी चलती हुई वकालत को छोड़कर मेरे विचारों की लड़ाई में शामिल हो गये। यदि वल्लभभाई न मिले होते तो जो काम आज हुआ वह कभी नहीं होता।”²⁸ खेडा आन्दोलन में अपनी प्रशासनिक क्षमता के कारण सरदार पटेल गुजरात प्रान्त की सक्रिय राजनीति में प्रवेश का अवसर दिया। सरदार पटेल 1920 से 1942 ई० तक गुजरात प्रान्त की कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस प्रकार गांधी जी गुजरात प्रान्त की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंप कर बड़े कार्यों के लिए मुक्त हो गये।

२६ वही, पृ० 28

२७ पटेल, ईश्वर भाई, पूर्वो, पृ० 42

२८ प्रभाकर, विष्णु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नयी दिल्ली, 1982, पृ० 9

रोलेट एक्ट का विरोध

प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैण्ड जर्मनी के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ रहा था। अतः वायसराय ने भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए 29 अप्रैल, 1918 ई० को दिल्ली में कुछ बड़े नेताओं से मिलकर सहायता की माँग की। सहायता सबधी वायसराय के प्रस्ताव का, 'मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल है' कहकर गाँधी जी ने समर्थन किया और अपने दिये हुए वचन के अनुसार उन्होंने सहायता के लिए सैनिक भर्ती का काम अपने हाथ में लिया। उनके इस कार्य में सरदार पटेल साथ रहे। "दोनों ने बड़ी कठिनाई से केवल सौ व्यक्तियों को ही भर्ती कर सके।"²⁹ गाँधी जी ने पूर्व में ही घोषणा कर दी थी कि पहले सेनापति के रूप में वे स्वयं और उप सेनापति के रूप में वल्लभभाई जायेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि वे युद्ध क्षेत्र में निःशस्त्र ही आगे रहेंगे। 9 नवम्बर 1918 ई० को जर्मनी द्वारा आत्म समर्पण कर देने के कारण वे दोनों सैनिक भर्ती के अपने दायित्व से मुक्त हो गये।

इन्हीं दिनों सर माण्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के नाम पर नागरिक स्वतन्त्रता पर आघात करने वाला जो रोलेट एक्ट देश के सामने आया उसने सारे देश को हिलाकर रख दिया। इस एक्ट द्वारा किसी भी सन्देहास्पद व्यक्ति को बिना किसी जाँच के जेल में डाल देने की शक्ति पुलिस को प्रदान की गयी। देश के सभी बड़े नेताओं ने इस एक्ट का विरोध किया। गाँधी जी ने इसे 'काला कानून' की संज्ञा दी और उनके मन से सरकार के प्रति श्रद्धा टूट गयी। स्वतन्त्रता, न्याय और व्यक्ति के मूल अधिकारों के विपरीत इस काले कानून का विरोध करने के लिए 24 फरवरी, 1919 ई० को गाँधी जी ने सत्याग्रह प्रारम्भ करने का निश्चय किया। सत्याग्रह शपथपत्र पर गाँधी जी के बाद दूसरे नम्बर पर सरदार पटेल के हस्ताक्षर थे। गाँधी जी ने निश्चय किया कि सत्याग्रह की लड़ाई आत्म शुद्धि की होने के कारण उसका आरम्भ उपवास और हड़ताल से किया जाय। "हिन्दू लोगों के लिए 36 घंटे तथा रोजे के कारण मुसलमानों के लिए 24 घंटे का उपवास निश्चित किया गया। 30 मार्च 1919 का दिन उपवास और हड़ताल के लिए निश्चित किया गया। लेकिन कम समय में

यह खबर सारे देश में नहीं जा सकेगी, यह सोचकर बाद में उसे 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। परन्तु इस परिवर्तन की सूचना ठीक से सबको न मिल सकी। इसलिए 30 मार्च को दिल्ली में अभूतपूर्व हड़ताल की गयी। हिन्दू मुस्लिम एक जुट हो उसमें सम्मिलित हुए। स्वामी श्रद्धानन्द तथा हकीम उल्ला ने हड़ताल का नेतृत्व किया। “स्वामी श्रद्धानन्द को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया।”³⁰

6 अप्रैल को सारे देश में काला दिवस मनाया गया। उस दिन निश्चित कार्यक्रम के अनुसार अहमदाबाद में सरदार पटेल के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया जो बाद में जनसभा में तब्दील हो गया। जन सभा को सम्बोधित करते हुए सरदार पटेल ने प्रतिक्रियावादी रोलेट एक्ट की आलोचना की। सभा विसर्जन के उपरान्त कानून भंग का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। इसके लिए सरकार द्वारा जब्त गान्धी जी की पुस्तकें ‘हिन्द स्वराज्य और सर्वोदय’ को सरदार पटेल ने सार्वजनिक रूप से बेचा तथा सरकार की अनुमति के बगैर गुजराती भाषा में सर्वोदय पत्रिका प्रकाशित की। पत्रिका का सारा कार्य वे अपने घर पर ही करते थे।

दिल्ली में हुए भीषण दंगे के कारण दिल्ली जा रहे गान्धी जी को 9 अप्रैल 1919 ई० को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया जिससे जनता भड़क उठी और देश के अन्य भागों में भी दंगे होने लगे। अहमदाबाद में भी यह आग भड़की और 10 अप्रैल, 1919 को भारी दंगा हो गया। दंगे में उत्तेजित लोगो ने पुलिस थानों, तारघर आदि सरकारी इमारतों को जलाने के प्रयत्न किये। परिणामस्वरूप अहमदाबाद में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इन दिनों सरदार साहब कुछ अन्य सहयोगियों के साथ दंगा शान्त कराने, घायलों को अस्पताल पहुँचाने, दंगा पीड़ितों को अनाज आदि मुहैया कराने का कार्य किया। उधर वल्लभ भाई के मकान पर पुलिस का सख्त पहरा बिठा दिया गया जिसके कारण उन्हें अनेक असुविधाओं एवं कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। किन्तु वे बड़ी शान्ति एवं सहिष्णुतापूर्वक परिस्थितियों का सामना करते रहे। इस दंगे के दौर में नाडियाद इलाके में रेल लाइन भी उखाड़ी गयी थी जिसके अपराध में कुछ निरपराध व्यक्तियों को पकड़ा गया था। वल्लभ भाई ने इन व्यक्तियों के बचाव में तन, मन और धन तीनों प्रकार से सहायता की। सरदार

साहब ने उनका मुकदमा लड़ा और उन्हें मुक्ति दिलाई। मधु लिमये के अनुसार, “यह अंतिम अवसर था जब कि पटेल काला चोगा पहन कर वकील के रूप में न्यायालय में उपस्थित हुए।”³¹

6 अप्रैल, 1919 को प्रारम्भ घटनाओं का अन्त 13 अप्रैल, 1919 ई० को जलियावाला बाग हत्याकांड के रूप में हुआ, जिसने सारे देश की आत्मा और उसके स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया। गंधी जी ने इस बर्बरता का अन्त करने के लिए असहयोग आन्दोलन चलाने की घोषणा की।

अहमदाबाद में दंगे के दौरान कुछ लोगो ने सरदार पटेल पर सम्पत्ति को जलाने व नष्ट करने का आरोप भी लगाया तथा सी०आई०डी० ने जॉच भी शुरू कर दी परन्तु “कलेक्टर ने स्वयं यह कहकर जॉच रोकवा दी कि सरदार ने शान्ति स्थापना में अमूल्य योगदान दिया है।”³² अहमदाबाद के पुलिस अधीक्षक मि० हेली का उन पर इतना विश्वास जम गया कि दस वर्ष उपरान्त भी उन्होंने सरकार को यह सलाह दी थी कि, “वल्लभ भाई के बिना बारदोली में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती।”³³ इस प्रकार वास्तव में अहमदाबाद के दंगे में सरदार साहब ने शान्ति स्थापित करने का ऐसा कार्य किया जो साम्राज्य की शक्ति से भी सम्भव नहीं था।

इस प्रकार सरदार वल्लभभाई पटेल ने रोलेट एक्ट के दमन के विरुद्ध अहिंसक मार्ग से गुजरात में अपने कुशल नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया तथा स्वतंत्रता सेनानियों के प्रेरणा स्रोत बन गये।

नागपुर झंडा सत्याग्रह

1923 ई० में वल्लभभाई के नेतृत्व में चलाये गये नागपुर झंडा सत्याग्रह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। यद्यपि इसका सूत्रपात जबलपुर से हुआ था। अगस्त, 1922 ई० में जब सविनय जॉच भंग समिति जबलपुर गयी तो उस समय वहाँ कि म्युनिसिपैलिटी ने एक प्रस्ताव पास कर हकीम अजमल खॉ को मानपत्र भेंट किया और

31 लिमये, मधु प्राइम मूवर्स, दिल्ली, 1985 पृ० 85

32 कुमार, रवीन्द्र, सरदार पटेल का सत्याग्रही जीवन, मुजफ्फरनगर, 1987, पृ० 27

33 पारीख, नरहरि, पूर्वो, पृ० 376

म्युनिसिपल हाल पर झंडा फहराया। सरकार ने इसे अपने झण्डे 'यूनियन जैक' का अपमान घोषित किया और राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराये जाने के लिए म्युनिलिपेलिटी पर धारा 144 लागू कर दी गयी।

18 मार्च, 1923 ई० को गॉंधी जी के कारावास का कार्यकाल एक वर्ष पूरा हो गया उस दिन प० सुन्दर लाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय झंडे के साथ एक जुलूस निकाला गया था। परिणामस्वरूप सुन्दर लाल जी बन्दी बना लिये गये तथा उन्हें 6 माह के कारावास की सजा सुनायी गयी। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप 13 अप्रैल, 1923 को जालियावाला बाग दिवस पर नागपुर में राष्ट्रीय झंडे के साथ एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसे सरकार ने सिविल लाइन्स पर रोक दिया। नागपुर में पुलिस ने धारा 144 लगाकर एक मई (1 मई) 1923 से सिविल लाइन्स में राष्ट्रीय झंडे समेत जुलूस पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस घटना के साथ ही नागपुर झंडा सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ।

नागपुर कांग्रेस प्रान्तीय कार्य समिति ने 1 मई, 1923 ई० को राष्ट्रीय झंडे के सम्मान हेतु आन्दोलन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव पास किया और सेठ जमना लाल बजाज के नेतृत्व में झण्डा सत्याग्रह चलाने की घोषणा की गयी। सेठ जमना लाल ने राष्ट्रध्वज के साथ सिविल लाइन्स जाकर सरकार की आज्ञा का उल्लंघन किया। सरकार ने अन्य लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया।³⁴ अब मध्य प्रान्त की सरकार ने राष्ट्र ध्वज के विरुद्ध मोर्चे खोल दिया। इस पर कांग्रेस कार्य समिति ने इस प्रश्न को गम्भीरता से लेते हुए राष्ट्रध्वज की लड़ाई के संचालन का कार्यभार सरदार वल्लभ भाई को सौंपा। वल्लभभाई ने कार्यकारिणी की बात मानकर इसे धर्म कार्य के रूप में स्वीकार किया और सफलता से इस सत्याग्रह का संचालन किया।

सत्याग्रह के लिए धन एवं स्वयंसेवकों हेतु पटेल ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि "नागपुर की लड़ाई अकेले मध्य प्रान्त की नहीं बल्कि सारे देश की लड़ाई है। हर प्रान्त ने सैनिक भेजकर इस लड़ाई का स्वागत किया है। अब यदि हम इस लड़ाई को व्यक्तिगत रूप से जारी न रखें तो देश की इज्जत जाती है।"³⁵

३४ पटेल, राजीव भाई मणिभाई, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ० 5

३५ नवजीवन 17 फरवरी, 1922

सरदार साहब ने सत्याग्रह हेतु नागपुर में अपना पड़ाव डाला। वहाँ की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझकर विभिन्न प्रान्तों की कार्यसमितियों को पत्र भेजकर उनसे स्वयंसेवक भेजने की अपील की। इसी समय स्वराज पार्टी का गठन हुआ जिसके सदस्य सत्याग्रह कार्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे थे। इस विषम परिस्थिति तथा गान्धी जी की अनुपस्थिति में सरदार साहब को तो सत्याग्रह कार्यक्रम चलाना ही था, उन्होंने कुशलतापूर्वक अपनी योजना तैयार की। सभी प्रान्तों से सत्याग्रही आने लगे। नागपुर और जबलपुर के अधिकारियों ने दुष्टतापूर्वक वह सघर्ष खड़ा किया था जो उन्हीं पर भारी पड़ने लगा। सारे देश से सत्याग्रहियों का प्रवाह नागपुर की ओर चल पड़ा जिसे मध्य प्रान्त की सरकार सहन नहीं कर पायी। “वल्लभ भाई ने स्त्रियों के सत्याग्रही दलों की भी व्यवस्था की। पूजनीय कस्तूरबा के नेतृत्व में गुजरात की स्त्रियों का एक दल तैयार हुआ।”³⁶ राष्ट्रध्वज सबंधी मध्य प्रान्त की सरकार की आज्ञा की अवधि 17 अगस्त, 1923 ई० को पूरी हो रही थी। अब सरकार के सामने दो रास्ते थे। प्रथम यह कि आज्ञा की अवधि बढ़ा दिया जाय और द्वितीय खामोश रहा जाय। इन दोनों स्थितियों में सत्याग्रह जारी रखना सत्याग्रहियों का काम था इसलिए सरदार पटेल ने एक निवेदन निकाला जिसके सार निम्न थे—“मध्य प्रान्त के गवर्नर साहब जैसे लोग भी यह मानते हैं कि हम राष्ट्र ध्वज के साथ ऐसे जुलूस किसी भी स्थान पर निकालना चाहते हैं जिसके कारण यात्रियों को असुविधा हो। कांग्रेस कार्यसमिति ने मुझे बताया कि यह बिल्कुल असत्य है। झंडा सत्याग्रह जनता के कानून सम्मत और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्र ध्वज की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए किया जा रहा है, जनता के किसी वर्ग की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं। मुझे इस बात की भी सूचना मिली है कि होम सेक्रेटरी का कहना है कि झंडे के साथ जुलूस ब्रिटिश यूनियन जैक का अपमान करने के लिए निकाले जाते हैं यह भी बिल्कुल झूठ है। राष्ट्र ध्वज के साथ जुलूस निकालने के पीछे सिर्फ भारतीय जनता के मूलाधिकार को सिद्ध करने का प्रश्न है।”³⁷

सरदार साहब के उपरोक्त निवेदन से सरकार बुरी स्थिति में फँस गयी। यदि वह कुछ न करे तो सत्याग्रहियों की विजय होती है और यदि कोई कदम उठाती है तो सारे

36 कुमार, रवीन्द्र, पूर्वो, पृ० 40

37 पटेल, राजीव भाई पूर्वो, पृ० 52 व 53

देश में सत्याग्रह का सामना करने को तैयार रहे। साढ़े तीन महीने की लम्बी लड़ाई के उपरान्त समझौता करना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया। होम सेक्रेटरी वल्लभ भाई से मिले जिसमें उन्होंने सिविल लाइन्स इलाके में राष्ट्र ध्वज के साथ जुलूस निकालने और सत्याग्रही कैदियों को जेल से मुक्ति की बात स्वीकार कर ली। इस प्रकार 18 अगस्त, 1923 ई० को नागपुर झंडा सत्याग्रह समाप्त घोषित कर दिया गया।

सत्याग्रह का अन्त होने पर सरदार साहब ने कहा कि राष्ट्रीय झंडे के साथ आम रास्ते पर व्यवस्थित रूप से जुलूस निकालने का अपना मूल अधिकार हमने स्थापित किया है। इसे मैं सत्य, अहिंसा और हमारे भोगे हुए दुःखों की विजय मानता हूँ।

इस प्रकार नागपुर झंडा सत्याग्रह में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व में रची गयी व्यूह रचना तथा उनके प्रशासकीय क्षमता के जो दर्शन होते हैं उससे भावी भारतीय प्रशासक तथा राजनीतिज्ञ प्रेरणा ग्रहण करके अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

बोरसद सत्याग्रह

खेडा जिले की बोरसद ताल्लुके में हत्या, लूटपाट और अपराधों की मात्रा खूब बढ़ गयी थी। डाकुओं का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। डाकू बाबर देवा और डाकू अली जैसे डाकुओं के कई गिरोह सक्रिय थे। नवम्बर 1923 ई० में सरकार ने बोरसद ताल्लुके की जनता पर अराजक, विकृत मस्तिष्क वाली और नीच कार्य करने वाले डाकुओं को आश्रय देने तथा उन्हें दंड दिलाने में सहायता न करने का आरोप लगाकर वहाँ अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति की गयी और इस पुलिस के व्यय का दो लाख चालीस हजार रुपये (2,40,000) का सारा भार बोरसद ताल्लुके से वसूल करने का आदेश जारी कर दिया गया।³⁸ इसके लिए सोलह वर्ष की उम्र के अन्दर के सभी लूले-लगड़े, अनाथ, स्त्री पुरुष पर प्रति व्यक्ति दो रुपये सात आने दंड लगा दिया गया।³⁹ इस दंड विधान के खिलाफ जनता में आक्रोश फैल गया। जनता ने सरदार पटेल के समक्ष जाकर न्याय की गुहार लगाई।

सरदार पटेल ने समस्या के समाधान हेतु प्रान्तीय कार्यसमिति की बैठक बुलाई तथा घटना की जाँच हेतु मोहन लाल पाड़्या और रवि शंकर महाराज की दो सदस्यीय समिति

३८ दारा, रोठ गोविन्द, सरदार पटेल, दिल्ली, 1960, पृ० 64

३९ कुमार, रवीन्द्र, सरदार पटेल का सत्याग्रही जीवन, मुजफ्फरपुर, 1987, पृ० 45

गठित की। जिन्होंने हर गाँव में घूम-घूम कर सही तथ्यों की जाँच की, सरदार पटेल ने इनसे भिन्न तरीके से भी सही तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ताल्लुका परिषद् का बोरसद में अधिवेशन बुलाया। अधिवेशन में रखी गयी अपनी रिपोर्ट में महाराज व पाडया समिति ने जनता के अधिकांश भाग को निर्दोष बतलाया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डाकू लोग रात में डकैती करते हैं लेकिन पुलिस वाले दिन दहाड़े लूटते हैं। पुलिस डाकुओं से मिली हुई है। वह डाकुओं को बन्दूक देती है, गोलियाँ देती है और लूट के माल में अपना हिस्सा ले कर जेबे भरती है। “सरदार पटेल ने बैठक में इस रहस्य की जानकारी दी कि डाकू अली ने सरकार को डाकू बाबर को पकड़वाने का वचन दिया है। बदले में उसे लूटपाट करने की पूरी छूट दी गयी है। इस प्रकार सरदार साहब ने पुलिस पर डाकुओं के आश्रय का आरोप लगाया।”⁴⁰

इस परिषद् के उपरान्त सरदार साहब ने बोरसद में एक दिसम्बर 1923 को प्रान्तीय समिति की बैठक बुलाई। समिति की बैठक में प्रस्ताव किया गया कि जनता की रक्षा करना तथा उसके हेतु आवश्यक पुलिस का प्रबन्ध करना यह सरकार का फर्ज है। उस फर्ज का पालन करने के स्थान पर निर्दोष जनता पर झूठे आरोप लगाकर यह जोर लगाया गया है वह सर्वथा अन्यायपूर्ण तथा अनुचित है साथ ही यह अत्याचारपूर्ण है। अतः यह समिति इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने व प्रजा को दंड न देने की तथा वैसा करने पर दुःख भी उठाना पड़े तो शांति से दुःख उठाने की, तथा अपने सम्मान की रक्षा की सलाह देती है। जनता को दंडात्मक कर न देने की सलाह देते हुए पटेल ने कहा कि, “डाकुओं के साथी कहलाकर सरकार को ढाई रुपये देने के बजाय डाकू ले जाय तो अच्छा है। हम ईमानदार और इज्जत वाले लोग हैं डाकुओं के डर से बचने के लिए हम डाकुओं के साथी होने की स्वीकृति पत्र अपने हाथों से लिख कर नहीं देंगे।”⁴¹ परन्तु पुलिस व कर अधिकारियों ने जनता से पूरी शान्ति के साथ कर वसूलना प्रारम्भ कर दिया।

सघर्ष की प्रगति के विषय में जानकारी देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि यह महात्मा गाँधी के मार्ग पर लड़ी जाने वाली लड़ाई है। यह धर्म की लड़ाई है। धर्म के खातिर दुःख

४० पटेल, राजीवभाई, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ० 58

४१ पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक), अहमदाबाद, 1950 पृ० 90

सहन करने में बड़प्पन है। लड़ाई शुरू करने के पूर्व उन्होंने स्वयंसेवकों के लिए अपील की। प्रत्येक गाँव में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की छावनियाँ तैयार की गयीं। हर गाँव में पचायतो ने प्रस्ताव पास किया कि वे नीलाम के काम में मदद नहीं देंगे। गाँव की एकता तथा शौर्य में वृद्धि हेतु बोरसद से पत्रिका भी निकाली गयी जिसमें आन्दोलन के समाचारों के अलावा सलाह एवं सूचनाएँ भी दी जाती थी।

सरकार ने कुर्की का दौरा शुरू किया लेकिन फिर भी जनता ने कर देने से इन्कार कर दिया। “सरदार पटेल के नेतृत्व में जनता सरकारी गीदडभभकी से अब डरने वाली नहीं थी। उनका सीधा जवाब होता था कि सरदार की आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते।”⁴² जब्ती का माल उठाने से लोगों ने इन्कार कर दिया। गाँव के बाहर एक नगाड़ा रखा गया। जब्ती वालों के आते ही नगाड़ा बजता और सब लोग अपने घरों में ताला मार देते। बोरसद जैसे गाँवों में दिन में सन्नाटा रहता। रात को दिये जलाकर बाजार लगाया जाता था। रात को पनीहारिन पानी भरती थी। नीलाम से बचने के लिए मिट्टी के बर्तनों में पानी भरा जाता था और रसोई की जाती थी।⁴³ किसानों ने वल्लभभाई के इस अनुसरण और उनके संगठन से सरकार हैरान और परेशान थी। डाकू बाबर देवा भी सरदार से बहुत प्रभावित था। वह रात को सभा में कभी-कभी खादी टोपी और सफेद कुर्ता पहने हुए कन्धे पर बगल में थैला लटकाये हुए उपस्थित रहता था।⁴⁴ दूसरे प्रान्तों की पुलिस भी इस आन्दोलन में जनता के साथ सहानुभूति रखने लगी थी। इसी समय वल्लभ भाई ने कोकोनाडा कांग्रेस के अधिवेशन से लौटते समय बम्बई में एक सार्वजनिक सभा में “सरकार पर एक डाकू को पकड़ने के लिए उतने ही खूखार दूसरे डाकू की मदद लेने और उसे जरूरी हथियार, बंदूक आदि मुहैया कराने तथा मनमाने ढंग से लूटपाट करने की छूट देने, प्रजा को सताने और हत्या करने आदि का खुला इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी धोखा देने का इल्जाम लगाया और न्याय की अदालत में मुकदमा चलाने की धमकी भी दी।”

४२ दारा, सेठ गोविन्द, पूर्वो, पृ० 64

४३ दारा, सेठ गोविन्द, पूर्वो, पृ० 64

४४ . पटेल, राजीव भाई पूर्वो, पृ० 59

सरदार पटेल का यह भाषण बम्बई के हर अखबारो ने मुख्य पृष्ठ पर बड़े-बड़े शीर्षका में छापा। जिससे उस पर बम्बई के नये गर्वनर सर लेस्ली विल्सन का ध्यान गया। उन्होंने होम मेम्बर को खुद जॉच के लिए भेजा और तदुपरान्त स्वयं ग्रामवासियों से मिलने का निर्णय किया। दो-तीन हजार ग्रामवासियों को साथ लेकर उनके प्रतिनिधि के रूप में राम भाई पटेल ने वार्ता की।

इस प्रकार सरदार पटेल के कुशल व्यूह रचना तथा मजबूत संगठन एवं उच्च प्रशासनिक क्षमता के सामने सरकार नतमस्तक हो गयी। पाँच माह तक चले इस आन्दोलन का अन्त सरकार द्वारा 7 फरवरी, 1924 ई० को अतिरिक्त पुलिस बल सेवा लेने और दण्डात्मक कर समाप्त कर दिये जाने के बाद हुआ।

बोरसद सत्याग्रह के विजयोत्सव के निमित्त बोरसद में हुई सभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि 'सत्य, अहिंसा और तप की' एक बार फिर विजय हुई है। हमारी लड़ाई जितनी न्याय की थी उतनी जल्दी ही यह विजय हुई है। यह विशेष आनन्द की बात है। यह विजय अपूर्व है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की विजय हुई है। सरकार ने अपनी भूल खुले दिल से और हिम्मत के साथ स्वीकार कर ली है।"⁴⁵ सरदार पटेल ने नये गर्वनर सर लेस्ली विल्सन का भी आभार प्रकट किया।

गान्धी जी अपनी अनुपस्थिति में सरदार पटेल द्वारा कुशलता के साथ उनके नेतृत्व में चलाये गये सफल आन्दोलन पर उनका स्वागत एवं अभिनन्दन 'आओ बोरसद के राजा' नामक शब्दों से किया और प्रसन्नता व्यक्त की।

बारदोली सत्याग्रह

राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में बारदोली सत्याग्रह का विशिष्ट स्थान है जिसके कुशल संचालन एवं सफलता के लिए वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि से सुशोभित किया गया। बारदोली के किसान आंदोलन के उपरान्त पटेल एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आये। विनोबा भावे के अनुसार, "पटेल के दो महत्वपूर्ण कार्यों ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बन दिया। प्रथम था बारदोली की आंदोलन और द्वितीय देशी

रियासतो का एकीकरण।⁴⁶ पट्टाभिसीतारमैया ने इसकी तुलना “इजराइलियों का मिस्र से कैनान को बर्हिगमन तथा तार्तारो का जार की निरकुशता के विरुद्ध विद्रोह से किया है।⁴⁷

बारदोली की जनता के स्वभाव एवं चरित्र के कारण 1921 ई० के असहयोग आन्दोलन के समय ही उसे मुख्य केन्द्र बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन चौरी-चौरा के हिंसक कांड के कारण उन्होंने अपना निर्णय स्थगित कर दिया। तभी से बारदोली ताल्लुका सरकार की नाराजगी का शिकार बन गया। “19 जुलाई, 1927 को बारदोली ताल्लुके का रिवीजनल सेटेलमेण्ट करके भूतकाल का बदला लेने के लिए लगान में 21-97 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी।⁴⁸ लगान में की गयी इस भारी वृद्धि से ताल्लुके में खलबली मच गयी। इस अन्याय के विरुद्ध जनता ने सरकार से शिकायत की परन्तु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। “गवर्नर जनरल ने कहा कि माल विभाग के निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसका निर्णय अंतिम है।⁴⁹

सरकार की नीतियों और नीयत से लोग तग आ गये थे अतः उन्होंने लगान वृद्धि के विरोध के लिए एक बार फिर वल्लभभाई के सहयोग की माँग की। वल्लभ भाई यद्यपि अभी बाढ़ सकट निवारण के कार्यों में लगे हुए थे, किन्तु किसानों की कठिनाइयों में निष्क्रिय बने रहना अथवा उन पर विपत्ति के समय कोई सहायता न देना, न केवल उनके स्वभाव के विपरीत था, अपितु वे इसे उपेक्षा का पाप समझते थे। एक स्थान पर अपनी अन्तर्वेदना व्यक्त करते हुए अपने भाषण में जो शब्द कहे, उनको उनकी कृषक हित परायण प्रवृत्ति का पूरा परिचय मिल जाता है। उनका कथन था कि, “किसान डरकर दुःख उठाए और जालिमों की लात खाये, उससे मुझे शर्म आती है। मेरे जी में आता है कि किसानों को कगाल न रहने देकर खड़ा कर दूँ और स्वाभिमान से सिर ऊँचा करके चलने वाला बना दूँ। इतना करके मरू तो अपना जीवन सफल समझूँगा।⁵⁰ सरदार पटेल ने किसानों का नेतृत्व ग्रहण करने के पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं-कल्याण जी मेहता, कुनबेर जी

४६ नन्दूरकर, जी०एम०, दिस वाज सरदार-दि कमोमेरेटिव वाल्यूम, अहमदाबाद, 1974, पृ 104

४७ वही, पृ०, 131

४८ बन्दोबस्त अधिकारी की टिप्पणी, होमफाइल, 178-1928, एन०ए०आई०

४९ पटेल, राजीव भाई, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ० 68

५० दास, सेठ गोविन्द, सरदार पटेल, दिल्ली, 1969, पृ० 72

मेहता तथा खुशहाल भाई मेहता से स्पष्ट कहा कि पहले वे बारदोली जाकर यह जाँच करे कि किसान सत्याग्रह करने के लिए तथा कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। बारदोली कांग्रेस के जाँच रिपोर्ट मिलने पर वल्लभ भाई स्वयं बारदोली गये। वहाँ उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में जनता से सीधा प्रश्न किया कि वे प्रतिरोध के लिए कहाँ तक तैयार हैं। उन्होंने इस सभा में सत्याग्रह की सफलता का आश्वासन न देकर किसानों के चरित्र, उनकी निष्ठा और लगन को चुनौती देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि, “मेरे साथ खेल न किया जाय। मैं ऐसे काम में हाथ नहीं डालता जिसमें जोखिम न हो। जो लोग जोखिम उठाने के लिए तैयार हों, मेरे साथ आये मैं उनका साथ दूँगा।”⁵¹

इस प्रकार बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहकर तथा उन्हें सात दिनों की मोहलत देकर वल्लभभाई अहमदाबाद लौट आये। इसके बाद उन्होंने गवर्नर जनरल को एक विस्तृत, विनम्र एवं मार्मिक पत्र लिखकर लगान वसूली स्थगित करने की माँग की पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया कि सम्भव है यह लड़ाई तीव्र रूप धारण कर ले जिसे रोकना आपके हाथ में है। इस पत्र के जवाब में गवर्नर के सेक्रेटरी ने कहा कि आपका पत्र निर्णय के लिए माल विभाग के पास भेज दिया गया है? किसानों की दी हुई सात दिन की अवधि पूरी होने के पश्चात् पटेल पुनः बारदोली पहुँचे। वहाँ उन्होंने लोगों से अलग-अलग बात कर, रायची राय मालूम कर, लोगों से घुमा-फिरा कर, तर्क-वितर्क कर उनके चेहरों, आँखों और दिलों में गहराई से झोंककर देखा तो उन्हें विश्वास और निश्चय दिखाई दिया। व लोगों के समय, उत्साह, निश्चय और दृढ़ता से प्रभावित हुए। फिर भी उन्होंने लोगों को एक बार फिर सत्याग्रह में आने वाले सकटों के प्रति अगाह करते हुए कहा कि—“यह लड़ाई जबरदस्त खतरों से भरी पड़ी है। जोखिम भरा कार्य किया जाना तो अच्छा है किन्तु किया जाय तो किसी भी कीमत पर उसे पूरा करना चाहिये। हारोगे तो देश की लाज जायेगी और जीतोगे तो आपका भविष्य बनेगा। देश की इज्जत बढ़ेगी। इसलिए सोच विचार कर जो करना चाहो सो करो।”⁵²

इस प्रकार भली भाँति जाँच परखकर जब उन्हें लगा कि किसान आन्दोलन के लिए

५१ वही, पृ० 72

५२ वही, पृ० 73

तैयार है तब सरदार साहब गॉंधी जी का आशीर्वाद लेने के लिए अहमदाबाद गये। गॉंधी जी परिस्थितियों और वल्लभ भाई के निश्चय दोनों से परिचित थे अतः उन्होंने तत्काल कहा "अब तो मेरे लिए सिर्फ इतनी इच्छा करना बाकी रह गया है कि विजयी गुजरात की जाय हो।"⁵³

गॉंधी जी का आशीर्वाद मिलने के बाद आन्दोलन का समस्त भार सरदार पटेल के कंधों पर था। अतः व्यक्तिगत जानकारी हेतु 4 फरवरी, 1928 ई० को बारदोली ताल्लुके के समस्त किसानों की एक सभा बुलाई गयी। "सभा में 80 गाँवों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।"⁵⁴ इसके अतिरिक्त सभा में बम्बई धारा सभा के तीन सदस्य भीमभाई नाईक, दादूभाई देसाई तथा डॉ० दीक्षित भी थे। सभा की अध्यक्षता करते हुए सरदार पटेल ने किसानों को सत्याग्रह का अर्थ, उसकी गम्भीरता तथा होने वाले कष्टों से अवगत कराया।

सरदार पटेल ने सत्याग्रह की शुरुआत 12 फरवरी, 1928 ई० को बारदोली ताल्लुके के समस्त प्रतिनिधियों की सभा के साथ की। सभा को सम्बोधित करते हुए पटेल ने प्रतिनिधियों को लगान न देने की सलाह दी। पटेल ने कहा "याद रखिये इस लड़ाई को छोड़कर आप कहीं हार गये तो सारे देश की नाक नीची हो जायेगी और यदि जीत गये तो सारे ससार में तुम्हारे देश का मस्तक ऊँचा होगा।"⁵⁵ सरकार के विरुद्ध एक होकर मुकाबला करने की सलाह देते हुए पटेल ने कहा कि "सरकार के पास तो तोपें हैं, बन्दूकें हैं, और हुकूमत है पर आपके पास सत्य का बल है, दुःख सहने की शक्ति है। अब इन दो शक्तियों का सामना है। यदि आपको यह निश्चय हो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उसका सामना करना हमारा धर्म है। जालिम से जालिम सत्ता भी उस प्रजा के सामने नहीं टिक सकती जिसमें एकता है।"⁵⁶ सरदार साहब ने प्रतिनिधियों को स्वयं के बल पर विश्वास करने की सलाह दी। सभा में सर्वसम्मति से लगान न देने का प्रस्ताव पास किया गया।

५३ वही, पृ० 74

५४ पटेल, राजीव भाई, पूर्वो, पृ० 70

५५ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एक विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 41

५६ वही, पृ० 41

प्रस्ताव पास होने के उपरान्त आन्दोलन की सफलता या असफलता का समस्त भार सरदार पटेल के ऊपर था। किसानों को जाग्रत करने के लिए सरदार पटेल ने बाकानेर, बराड, बड़े कुआँ, बालोड आदि अनेक स्थानों का भ्रमण किया तथा जोशपूर्ण भाषण दिये। अपने भाषणों में पटेल ने विशेष रूप से दो बातों पर बल दिया। प्रथम सरकार जनता में मतभेद करके उन्हें विभाजित करने का प्रयास करेगी जिससे जनता को सतर्क रहना होगा। और द्वितीय सरकार नेताओं को गिरफ्तार करेगी तथा भूमि कुर्क करेगी। सरदार साहब ने कहा, हमारा अनुशासन ही जीत की कुजी है। सरकार के हर गाँव में केवल दो ही आदमी एक पटेल और दूसरा तलाही होते हैं जबकि हमारे पक्ष में सम्पूर्ण गाँव है।”

सरदार पटेल ने आन्दोलन की सफलता के लिए एक सुदृढ संगठन का निर्माण किया। जिसके तहत सम्पूर्ण ताल्लुके को पाँच मुख्य भागों में बाँटा गया और उन पर एक-एक मुख्य विभागापति रखा गया। इसके अतिरिक्त सत्याग्रह छावनियों की स्थापना की गयी। प्रत्येक छावनी एक या दो मुख्य कार्यकर्ताओं के अधीन रखी गयी।”

नोट - कुछ प्रमुख छावनियों तथा उनके प्रमुखों का विवरण इस प्रकार है।

- 1 बराड गोहग लाल पाडया
- 2 बालदा—अम्बा लाल देसाई
- 3 बाकानेर—लाल भाई अमीन, शाह व अब्बास तैयब जी
- 4 स्यादला—फूलचन्द बाबू जी
- 5 बारदोली—डॉ० घिया व चीनाई
- 6 मोटा—बलवन्त राय
- 7 बाजीपुरा—नर्मदा शंकर पाडया
- 8 सीकर—कल्याण जी बाल जी
- 9 आफबा—रतन जी भगाभाई पटेल
- 10 बुहारी—नारायण भाई पटेल
- 11 सरभण—रविशंकर व्यास व डॉ० सुमन मेहता
- 12 बापजी—दरबार गोपाल दास भाई
- 13 बालोत—चन्दुलाल देसाई।

सरदार द्वारा निर्मित यह सगठन कठोर अनुशासन में बंधा था। प्रत्येक स्वयं सेवक अपने नायक या विभागापति के आदेशों का पालन करता था। जो स्वयं सेवक आचरण में शिथिल पाया जाता था उसे तत्काल हटा दिया जाता था। अनुशासन की यह कठोरता मात्र स्वयं सेवकों तक ही सीमित न होकर वल्लभ भाई तथा विभागापति को भी अपने अधीन रखती थी।

सत्याग्रह की घोषणा के साथ ही बारदोली में एक प्रकाशन विभाग की स्थापना के साथ सत्याग्रह कार्यालय की भी स्थापना की गयी। सत्याग्रह कार्यालय द्वारा अधीन गाँवों के समाचार विभागापति द्वारा जाने लगे। प्रधान कार्यालय से प्रतिदिन सूचनाएँ भेजी जाती जिसे विभागाध्यक्ष के कार्यालयों द्वारा प्रतिदिन गाँव-गाँव में पहुँचा दी जाती। प्रकाशन विभाग प्रतिदिन 'सत्याग्रह खबर तथा सत्याग्रह पत्रिका' प्रकाशित करता था जो निःशुल्क वितरित की जाती थी। प्रकाशन विभाग आन्दोलन को तीव्र गति देने का महत्वपूर्ण साधन था। सरदार पटेल तथा विभागापति गाँव-गाँव जाकर स्फूर्तिजनक भाषणों द्वारा जनता को उत्साहित करते थे।

वल्लभभाई की इस व्यूह रचना को तोड़ने के लिए सरकार ने किसानों को झुकाने हेतु कुर्की की नीतियाँ जारी किये और सर्वप्रथम यह नोटिस बनियों को दिये गये। यह चुनाव शायद इसलिए किया गया कि बनिया कमजोर और डरपोक होते हैं। जब्ती की नोटिस पाते ही वे घुटने टेक देंगे। परन्तु उन्होंने भी अन्य जातियों की भौति साहस का परिचय देते हुए घुटने टेकने से साफ इन्कार कर दिया। मात्र तीन व्यक्तियों ने लगान जमा किया जो बाद में पछताये भी। 17 फरवरी 1928 को रेवन्यू विभाग के सेक्रेटरी जे०डब्लू० स्मिथ ने सरदार पटेल को पत्र लिखा। उसने सरदार के सुझावों को अस्वीकार करते हुए कहा कि सरकार अब बड़े हुए लगान को स्थगित नहीं कर सकती और न ही वह नये बन्दोबस्त पर किसी तरह की रियासत देने के लिए तैयार है। पत्र में पटेल तथा अन्य सत्याग्रहियों पर बाहरी व्यक्ति होने का आरोप भी लगाया गया। गाँधी जी ने इस आरोप को अपमान की सज़ा दी। सरदार साहब ने सरकार को उनके गलत होने को सिद्ध करने की चुनौती दी।

जब सरकार द्वारा जारी कुर्की के आदेश की तामील नहीं हुई तो उसने सगठित रूप से भैसे या चल सम्पत्ति जब्त करना प्रारम्भ किया। जनता को आतंकित करने के लिए पठानों को बाहर से बुलाया गया। बारदोली जैसे हिन्दू बाहुल्य इलाके में मुसलमान अफसरों

तथा पठानों को बुलाकर जनता में फूट डालने का कुचक्र रचा गया। लोगों को झूठे मुकदमे में फसाये गये तथा सजाये दी गयी। इस प्रकार सरकार का दमनचक्र कठोर होता जा रहा था तो जनता में दिन प्रतिदिन नवीन उत्साह पैदा हो रहा था। सरदार पटेल के भाषण ही मुर्दों में भी जान डाल देते थे। पुरुष और स्त्रियां उन्हें अपना इष्ट देव समझने लगे थे। महादेव जोशी ने अपनी 'बारदोली की कहानी' में इन अविस्मरणीय सभाओं तथा भाषणों का वर्णन किया है। उस समय पटेल के भाषणों में सिंह जैसी गर्जना थी। एक भाषण में उन्होंने कहा कि "आज सरकार तो जंगल में घूमने वाली हाथी जैसे मदमस्त हो गयी है जो अपनी चपेट में आने वाले हर किसी को कुचल देना चाहती है। पागल हाथी मद में यह मानता है कि उसने शेर चीते को मार डाला है तो उसके सामने मच्छर की क्या गिनती। परन्तु शक्तिशाली हाथी भी मच्छर के कान में घुस जाने पर तडप-तडप कर सूढ़ पछाडते हुए जमीन पर लोटने लगता है।"⁵⁷ मैं आपकी प्रकृति का नियम बताता हूँ आप सब किसान होने के कारण जानते हैं कि जब थोड़े से बिनौले जमीन में गडकर व सडकर नष्ट हो जाते हैं तब खेत में कपास पैदा होती है।"⁵⁸ बालोड में एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि "सरकार यदि 15 रुपये के वेतन पर भाडे के सिपाही भरती करके फौज खडी करती है और वे ही सिपाही किसी समय और स्वार्थ के बिना लडाई के मैदान में जाकर टपाटप मरते हैं तो आप लोग तो हजारों रुपयों के खातेदार हैं और आपको अपने वतन के खातिर, अपने बाल बच्चों की रोटी की खातिर लडना है। कौन अभाग्य होगा, जो यह लडाई नहीं लडेगा? मैं तो चाहता हूँ कि यह लडाई लम्बी चले। यहाँ बैठे-बैठे हम सारे गुजरात को सत्याग्रह का पाठ पढाये।"⁵⁹ इस प्रकार वल्लभ भाई बारदोली की जनता को सत्याग्रह की भट्ठी में तपाया।

प्रारम्भ में वल्लभ भाई नहीं चाहते थे कि बारदोली सत्याग्रह को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया जाय। इसलिए उन्होंने किसी भी राष्ट्रीय नेता को बारदोली आने का निमन्त्रण नहीं दिया। 8 मई 1928 ई० को उन्होंने देशवासियों से धन के लिए अपील की। महात्मा गान्धी ने सरदार की अपील का समर्थन किया। परिणामस्वरूप देश, विदेश से चन्दा आने लगा। 12 जून 1928 ई० को पूरे देश में बारदोली दिवस मनाने का निर्णय किया

५७ पारीख, नरहरि सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक), अहमदाबाद, 1950, पृ० 145

५८ वही, पृ० 145

५९ पटेल, राजीव भाई, पूर्वो पृ० 76

गया। महात्मा गांधी ने लोगो से आग्रह किया कि 12 जून को आत्मशुद्धि यज्ञ करे। स्वेच्छा से अपना सामान्य काम-काज और धन्धा बन्द रखे और बारदोली की लड़ाई में सहायता देने के लिए धन का संग्रह करे। “कांग्रेस अध्यक्ष डॉ० एम०ए० अन्सारी ने समस्त प्रान्तीय कांग्रेस समितियों को अपने-अपने क्षेत्र में सार्वजनिक सभाये करने तथा चन्दा जमा करके बारदोली दिवस मनाने का परामर्श दिया।”⁶⁰ 12 जून को पूरे देश में बारदोली दिवस मनाया गया। बम्बई के समस्त बाजार बन्द रहे। सरदार पटेल के साहसिक कदम की सर्वत्र प्रशंसा की गयी और धन एकत्रित करके भेजा गया। वल्लभ भाई पटेल के आग्रह पर 11 जून तक 60 पटेलो तथा 8 तलाटियों ने अपने त्याग पत्र देकर सरकार को गम्भीर स्थिति का आभास कराया।

बम्बई धारा सभा के सदस्य के०एम० मुशी ने गवर्नर से बारदोली समस्या पर पत्र व्यवहार किया। गवर्नर के उत्तर से निराश होकर उन्होंने 17 जून को धारा सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया तथा वास्तविक स्थिति की जाँच के लिए बारदोली का भ्रमण किया। बम्बई इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स का एक शिष्टमंडल एच०पी० मोदी की अध्यक्षता में गवर्नर जनरल से मिलकर समस्या के समाधान हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। साथ में यह भी कहा ऐसे सम्मेलन में गाँधी और पटेल को अवश्य बुलाया जाय। गवर्नर ने सम्मेलन बुलाने के लिए शर्त के रूप में कहा कि पहले बड़ी हुई लगान किसी तीसरे पक्ष के पास जमा कर दिया जाय तो सम्मेलन बुलाया जा सकता है। पटेल ने गवर्नर की शर्त को अस्वीकार कर दिया। “पटेल ने बाम्बे क्रानिकल के सम्वाददाता को बताया कि निकट भविष्य में समझौते की कोई आशा नहीं है। वह बारदोली की जनता के लिए न्याय चाहते हैं और जब तक सरकार जनता के आन्दोलन को कठोरता से दबाती रहेगी कोई समझौता सम्भव नहीं हो सकता।”⁶¹

बारदोली में जैसे-जैसे लोकमत शक्तिशाली होता गया वैसे-वैसे सरकार की स्थिति नाजुक होती गयी। सरकार यदि आन्दोलन का दमन करे तो उसकी बदनामी होती क्योंकि आन्दोलनकारी अहिंसक थे। यदि वह माँग को स्वीकार कर लेती तो उसकी सार्वभौमिकता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता। तथा उसका सारा आतंक, प्रभाव एवं प्रतिष्ठा खत्म हो जाती जाता

६० बाम्बे क्रानिकल, 29 मई, 1928

६१ शिष्ट मंडल की गवर्नर से वार्ता, 22 जून 1928 विस्तृत जानकारी हेतु बाम्बे क्रानिकल 23 जून, 1928

दि टाइम्स ऑफ इंडिया के सम्वाददाता कुछ समय के लिए बारदोली में रहे। उन्होंने सूचना भेजी की बारदोली के बोलशेलिज्म का प्रयोग प्रारम्भ हो गया है। पटेल वहाँ के लेनिन है।⁶² सत्याग्रहियों के सरकारी प्रशासन को पूर्णतया पगु बना दिया है। जुलाई के मध्य तक स्थिति अत्यन्त विस्फोटक हो गयी।

18 जुलाई, 1928 ई० में सूरत को गवर्नर जनरल तथा उनके सलाहकारों और पटेल व उनके सहयोगियों के मध्य वार्ता हुई। वार्ता में सरकार की ओर से गवर्नर लेस्ली विल्सन कमिश्नर डब्लू डब्लू स्मार्ट तथा सूरत जिले के कलेक्टर हार्ट शोन उपस्थित थे। सत्याग्रहियों की ओर से सरदार पटेल के अलावा, अब्बास तैयब, शारदा बेन मेहता, भक्ति लक्ष्मी, गोपाल दास देसाई, मीठू बेन पेटिट और कल्याण जी मेहता थे। “सरकार की ओर से शर्त रखी गयी कि पुराना लगान जमा कर दिया जाय और बढ़ा हुआ लगान तीसरे पक्ष द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवा दिया जाय और वर्तमान आन्दोलन बन्द कर दिया जाय तो सरकार जॉच समिति नियुक्त करने का आश्वासन देगी।”⁶³ “जबकि वल्लभ भाई की ओर से शर्त रखी गयी कि बन्दी सत्याग्रहियों को बिना शर्त छोड़ दिया जाय, जिन लोगों के मवेशी बेचे गये हैं उन्हें मुआवजा दिया जाय, जो जमीनें कुर्क की गयी हैं उन्हें मालिकों को वापस दी जाये, जो पटेल व तलाटी नौकरी से निकाले गये हैं उन्हें नौकरी में रखा जाय तथा सरकार लगान वृद्धि के सबंध में एक निष्पक्ष जॉच समिति नियुक्त करे।”⁶⁴ सरदार द्वारा प्रस्तुत शर्तें गवर्नर ने अस्वीकार कर दी अतः वार्ता असफल हो गयी। सरदार पटेल अपनी ओर से वार्ता तोड़ने के पक्ष में नहीं थे अतः उन्होंने विनम्र भाषा का पत्र लिखकर अपनी शर्तों को दोहराया साथ ही आग्रह किया। जब उन्हें उनसे मिलने से कुछ लाभ प्रतीत हो तो मुझे सूचित करें। परन्तु पटेल को कोई सफलता नहीं मिली।

सूरत वार्ता की असफलता के लिए समाचार पत्रों ने सरकारी नीति की आलोचना की। पायनियर ने लिखा कि “किसानों द्वारा बढ़ा हुआ लगान जमा करना तथा पुनः वापस माँगना अन्यायपूर्ण है।”⁶⁵ स्वराज्य के अनुसार “गवर्नर समझौते की मनोदशा में नहीं है।”⁶⁶ हिन्दू के शब्दों में, “गवर्नर ने समझौते का एक अवसर खो दिया।”⁶⁷

इसी बीच 23 जुलाई, 1928 ई० को गवर्नर जनरल ने धारा सभा में भाषण करते हुए

६२ टाइम्स ऑफ इंडिया, 3 जुलाई, 1928

६३ बाम्बे क्रानिकल, 20 जुलाई, 1928

६४ वही, 21 जुलाई, 1928

६५ वही, 25 जुलाई, 1928

६६ वही, 25 जुलाई, 1928

६७ वही, 25 जुलाई, 1928

अपनी पुरानी शर्तों को पुन दोहराया और जनता को 14 दिनों का समय देते हुए स्पष्ट किया कि यदि ये शर्तें न मानी गयीं और समझौता न हो सका तो अपने कानून का पालन करवाने के लिए सरकार को जो उचित प्रतीत होगा। वह कदम उठाने से नहीं हिचकिचायेगी। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वह समस्त शक्ति का प्रयोग करेगी।⁶⁸ गवर्नर के भाषण का जनता तथा प्रेस में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दूसरी ओर इंग्लैण्ड में सहायक सचिव भारत मंत्री अर्थ विटरटन ने कामन सभा में कहा कि “लेस्ली ने जो शर्तें रखी हैं यदि वे पूरी न हुईं तो बम्बई सरकार को पूर्ण अधिकार होगा कि वह आन्दोलन को कुचल दे और जनता को कानून का पालन करने के लिए बाध्य करे।”⁶⁹

गवर्नर की धमकी का सत्याग्रहियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि सम्पूर्ण देश की सहानुभूति सत्याग्रहियों के प्रति बढ़ रही थी। गाँधी जी के शब्दों में “गवर्नर की धमकी और विटरटन द्वारा उसका ‘पूर्ण अनुमोदन भी बारदोली के लोगों पर कोई असर नहीं छोड़ सकेगा। इतना ही नहीं, सुनता तो यह हूँ, कि धमकी से लोग और दृढ़ हो गये हैं।” इसी बीच बम्बई के एक व्यापारी राम चन्द्र भट्ट ने बढी हुई। लगान की सारी रकम अपने खजाने से जमा करने की इच्छा प्रकट की जिस पर गांधी जी ने कहा कि यदि ऐसी भेट से सरकार के मन का समाधान हो जाय तो हमें कोई शिकायत नहीं है। देश में गरम दल के लोगों ने गवर्नर के इस धमकी भरे भाषण का हर्षपूर्वक स्वागत किया। गरम पथी लोगों में इस बात का हर्ष और उत्साह था कि अब उन्हें स्वराज्य की बड़ी लड़ाई लड़ने का अवसर मिलेगा। “सरदार शार्दूल सिंह कवीश्वर ने पत्र लिखकर गाँधी जी से आग्रह किया कि वल्लभ भाई ने बारदोली सत्याग्रह को मर्यादित रखा है जो अव्यावहारिक जान पड़ता है अतः अब सारे देश में संविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू कर देना चाहिये।”⁷⁰ गाँधी जी ने इस आग्रह को ठुकरा दिया। इसके बाद वे 2 अगस्त 1928 ई० को बारदोली गये जहाँ उन्होंने अफवाहों एवं आशंकाओं के बावजूद बारदोली निवासियों द्वारा वल्लभ भाई के आदेश का पालना करने को उत्सुक देखकर उनके मन में आत्मसन्तोष हुआ।

६८ मेहरोत्रा, एन०सी० कपूर, रजना, पूर्वो पृ० 48

६९ वही, पृ० 49

७० दास, सेठ गोविन्द, पूर्वो पृ० 84

सरकार ने सारे प्रयत्न कर लिये, सभी प्रकार के हथकड़ों का सहारा लिया लेकिन सत्याग्रही झुकने को तैयार नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में सरकार को सद्बुद्धि आयी। गवर्नर जनरल ने बातचीत के लिए सरदार साहब को आमंत्रित किया। इस बातचीत में गवर्नर ने इस आश्वासन के साथ, कि सरकार योग्य मामलों की जाँच करके बड़े हुए लगान को माफ कर देगी, यह माँग की कि सत्याग्रह बन्द कर दिया जाय और लोग पहले के समान कर देना आरम्भ कर दें। वल्लभ भाई ने गवर्नर की इस माँग को स्वीकार कर लिया किन्तु साथ ही उन्होंने आन्दोलन के दौरान बन्दी बनाये गये लोगों को रिहा करने, सरकारी कर्मचारियों को पुनः काम पर लेने, कुर्क किये गये माल और जमीन वापस करने की माँग की। सरकार ने वल्लभ भाई की सारी बातें मान ली। इस प्रकार सरकार और वल्लभ भाई के मध्य समझौता हो गया। समझौते का स्वागत करते हुए सरदार पटेल ने 11 अगस्त, को बारदोली की जनता के लिए एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा कि, “ईश्वर की कृपा से हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसका पूर्ण रूप से पालन हो चुका है। हम लोगों पर बढ़ाये गये लगान के सबंध में हम जैसी जाँच चाहते थे, सरकार ने उसी प्रकार की जाँच समिति नियुक्त करना स्वीकार कर लिया है। जब्त की हुई जमीनें किसानों को वापस मिलेगी। जेल में बन्द सत्याग्रही छोड़ दिये जायेंगे। पटेल और तलातियों को पुनः नौकरी पर रखा जायेगा और जो छोटी-मोटी माँगे हमने रखी थी, उनकी भी स्वीकृति हो गयी है।”⁷¹ इस प्रकार वल्लभभाई ने बारदोली आन्दोलन में सफलता प्राप्त की।

देश के राष्ट्रीय नेताओं ने इसे अभूतपूर्व सफलता माना। गान्धी जी ने सफलता का श्रेय वल्लभभाई, गवर्नर, सरकारी अधिकारियों तथा विधानसभा के सदस्यों को दिया। उन्होंने कहा कि “जिन्होंने शुद्ध मन से चाहा कि समझौता हो जाय वे सब इस विजय में हिस्सेदार हैं।” गान्धी के अनुसार वल्लभ भाई जैसे नेता के अथक प्रयत्नों से यह विजय मिली है। सरदार पटेल को मान पत्र देते हुए गान्धी जी ने कहा “ऐसा स्वार्थ त्यागी सरदार तुम्हें दूराँ नहीं मिलेगा। वे मेरे सगे भाई जैसे हैं किन्तु उन्हें यह प्रमाण पत्र देते हुए मुझे सकोच नहीं होता।”⁷²

७१ बाम्बे, क्रानिकल, 12 अगस्त, 1928

७२ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, पूर्वो, पृ० 51

राष्ट्रीय नेताओं में लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, सरोजनी नायडू, एम० बी० कोठारी, मौलाना शौकत अली, विश्वनाथन, राजाराम पाडया, सत्यमूर्ति आदि ने पटेल को अभिनन्दन पत्र भेजे। के०एम० मुशी ने बारदोली की घटना को भारतीय सार्वजनिक जीवन के इतिहास में महत्वपूर्ण विजय बतलाया। “बारदोली, सूरत एवं गुजरात के अन्य हिस्सों में विजयोत्सव मनाया गया।

सरदार पटेल ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि “बारदोली के लिए आप लोग मुझे श्रेय देते हैं लेकिन मैं उसका पात्र नहीं हूँ। कोई असाध्य रोग से पीड़ित बीमार पलंग पर पड़ा हो, और उसे कोई सन्यासी मिल जाये, जड़ी बूटी दे दे और उसकी मात्रा घिसकर पिलाने से रोगी स्वस्थ हो जाये ऐसी दशा हिन्दुस्तान के किसान की है। मैं तो सिर्फ जड़ी-बूटी घिसकर पिलाने वाला हूँ जो एक सन्यासी ने मुझे दी। श्रेय अगर किसी को है तो उस जड़ी बूटी देने वाले को है। दूसरे अगर कोई सम्मान के पात्र है तो वे मेरे साथी हैं। जिन्होंने चिकित्सा करने वाले अनुशासन का परिचय दिया।”⁷³

समझौते के तहत 18 अक्टूबर 1928 ई० को जॉय समिति की नियुक्ति सरकार ने कर दी। समिति ने 12 अप्रैल, 1929 ई० को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने किरानों की शिकायतों को सही माना और लगान वृद्धि की सन्तुति के आधारों को दोषपूर्ण माना। समिति ने पुराने लगान पर 60 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की।⁷⁴

इस प्रकार सरदार पटेल के कुशल संगठन, दृढ़ निश्चय और जबदस्त प्रशासकीय क्षमता के सामने शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार बौनी साबित हुई।

पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष

सात अप्रैल, 1934 ई० को कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन वापस ले लिया जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने कांग्रेस महासमिति तथा उसकी सभी शाखाओं पर से प्रतिबन्ध हटा लिया। पटना में इसी समय कांग्रेस महासमिति ने बैठक कर चुनाव के लिए एक पार्लियामेण्टरी बोर्ड का गठन किया। जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को

७३ पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक), अहमदाबाद, 1950, पृ० 160

७४ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, पूर्वो, पृ० 74

बनाया गया जो अपने स्वर्गवास तक इस पद पर बने रहे। बोर्ड के अन्य सदस्य मोलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, डॉ० असारि तथा पंडित मदन मोहन मालवीय बनाये गये। अक्टूबर, 1934 ई० के बम्बई अधिवेशन में इस बोर्ड को विधिवत मान्यता प्रदान कर दी गयी।

“1934 ई० के ब्रिटिश सरकार के साम्प्रदायिक निर्णय से बोर्ड के दो सदस्यो डॉ० असारि तथा मदन मोहन मालवीय में मतभेद पैदा हो गये।”⁷⁵ मालवीय जी का कहना था कि चुनाव के घोषणा पत्र में इस निर्णय की निन्दा की जावे जबकि डॉ० असारि की इच्छा थी कि कांग्रेस इस सबध में तटस्थ नीति अपना ले। इस मतभेद के कारण मालवीय जी ने पार्लियामेण्टरी बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया। कुछ दिनों बाद डॉ० असारि का भी देहान्त हो गया। अतः पार्लियामेण्टरी बोर्ड में कुल तीन सदस्य सरदार पटेल, मौलाना कलाम आजाद, और राजेन्द्र प्रसाद ही रह गये।

कांग्रेस पार्लियामेण्टरी बोर्ड ने सरदार पटेल के नेतृत्व में नवम्बर 1934 ई० में हुए केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव में भाग लिया। “सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व में कांग्रेस ने 44 स्थानों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस ने भी झूलाभाई देसाई को असेम्बली में अपना नेता बनाया। कांग्रेस ने कांग्रेस नेशनलिस्ट सदस्यों सहित अन्य दलों के साथ मिलकर कई बार सरकार को पराजित भी किया।”⁷⁶

ब्रिटिश ससद द्वारा पारित गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया ऐक्ट 1935 के अनुसार प्रान्तीय धारा सभाओं का चुनाव होना था। इसके लिए 1935 ई० में मतदाताओं की नयी सूची बनाने का कार्य प्रारम्भ हुआ। सरदार पटेल के निर्देशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची के निर्माण में बढ-चढ कर हिस्सा लिया। 13 अप्रैल, 1936 ई० को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए 9वें कांग्रेस के अधिवेशन में प्रान्तीय धारा सभाओं के चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। जुलाई 1936 ई० में पार्लियामेण्टरी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल तथा सचिव के रूप में गोविन्द वल्लभ पन्त नियुक्त किये गये। सरदार पटेल की प्रेरणा से प्रान्तीय पार्लियामेण्टरी बोर्डों का भी गठन किया गया। चुनाव के उम्मीदवारों का चयन बड़ा कठिन कार्य था। “उम्मीदवारों का चयन पहले

७५ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, दिल्ली, 1963, पृ० 65

७६ वही, पृ० 66

तो प्रान्तीय समिति की कार्यकारिणी करती थी परन्तु यदि कोई कार्यकर्ता प्रान्त के निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो वह उसकी अपील पार्लियामेण्टरी बोर्ड के पास करता था।⁷⁷ उम्मीदवारों के चयन में दो बातों का ध्यान रखा जाता था प्रथम-उम्मीदवार में कांग्रेस के कार्यक्रमों एवं सिद्धान्तों में निष्ठा हो और द्वितीय उसके सफल होने की सम्भावना हो। पटेल के कुशल नेतृत्व में अनेक मामलों में पार्लियामेण्टरी बोर्ड ने सन्तोष जनक हल निकाल लिया पर उम्मीदवारों के चयन के मामले में उन पर व्यक्तिगत आरोप भी लगाये गये। ऐसे आरोपों से बिना विचलित हुए सरदार पटेल ने अनुशासन बनाये रखने के अपने कर्तव्य को पूरा किया।

स्वास्थ्य अच्छा न होते हुए भी सरदार पटेल ने चुनाव में बढ-चढ कर हिस्सा लिया और चुनाव प्रचार में बहुत सक्रिय रहे। चुनाव प्रचार हेतु उन्होंने पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, महाराष्ट्र, मद्रास सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। चुनाव प्रचार में सरदार पटेल ने कार्यकर्ता से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि “यदि हम अवसर को देखकर नहीं चलेगे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को देश के आगे गौण नहीं समझेगे, तो हम जीत की बाजी हार जायेंगे और इससे हमारी सस्था की अपूर्णनीय बदनामी होगी।”⁷⁸ असन्तुष्ट सदस्यों को चेतावनी देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि “पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के नाते अपने अनुभव में एक दो बातें मेरे सामने आयीं। मैंने देखा कि जब कुछ कांग्रेसियों को उम्मीदवार नहीं चुना गया तो उन्हें लगा कि उनकी उपेक्षा की गयी है। कुछ को ऐसा महसूस होने लगा है कि उम्मीदवार चुने जाने का उनका वश परम्परागत अधिकार है। कुछ यह मानते हैं कि अगर इस मौके पर उन्हें उम्मीदवार नहीं चुना गया तो उन्हें कांग्रेस के खिलाफ बलवा करने का अधिकार है। मुझे और आपको चाहिए कि कांग्रेस की ताकत का आधार केवल लोगों की मर्जी पर नहीं है बल्कि इस बात पर है कि कांग्रेस के तमाम सदस्य और खासतौर पर कार्यकर्ता कांग्रेस के आदेशों और प्रस्तावों को खुशी से स्वीकार करें और उनका पालन करें। यदि हम लोगों में अनुशासन न हो तो धारा सभाओं

७७ मेहरत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली, 1997 पृ० 69

७८ पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक), अहमदाबाद, 1950, पृ० 328 एवं 329

मे जाने का हक नहीं है।”⁷⁹ आपसी एकता पर बल देते हुए पूना के अपने भाषण में सरदार पटेल ने कहा कि—“याद रखो जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं। उन्हें कल हमारे साथ मिलकर कार्य करना है क्योंकि वे हमसे हैं। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता एकता की है। हमारी गुलामी का कारण हमारी कमजोरी है। यह कमजोरी हमारे आपसी मतभेद से है।”

सरदार पटेल के अथक प्रयास से एव तूफानी दौर के परिणामस्वरूप फरवरी 1937 में सम्पन्न हुए चुनावों के परिणाम कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक रहे। ग्यारह प्रान्तों में से छ प्रान्तों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। स्पष्ट बहुमत प्रान्तों में संयुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त, मद्रास, बिहार, उड़ीसा और बम्बई शामिल थे। इसके अलावा असम और सीमा प्रान्त में भी कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आयी। बंगाल, पंजाब और सिन्ध में कांग्रेस अल्पमत में रही।

कांग्रेस की इस भारी सफलता का विश्वास उन दिनों सरकार को तो क्या स्वयं कांग्रेस को भी नहीं था। इस सफलता से उत्साहित कांग्रेस ने 15 से 22 मार्च 1937 तक दिल्ली में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय महोत्सव मनाया। उस अवसर पर 17 एव 18 मार्च को महासमिति की बैठक बुलाई गयी। बैठक के पूर्व राष्ट्र के नाम सदेश में सरदार पटेल ने कहा कि—“हमारे काम की पहली मजिल पूरी हो गयी है अब दूसरी मजिल पर हमें अग्रसर होना है। उसमें हमें सारा समय और शक्ति खर्च करनी होगी। चुनाव जीतने में जो निश्चय और एकता हमने दिखायी वह धारा सभाओं के कार्यक्रमों भले वह कुछ भी तय हो, अमल में लाने में दिखायेगे, तो मुझे सदेह नहीं कि हम विरोधियों को मात देंगे और स्वराज का दिन निकट ला सकेंगे।”⁸⁰

अखिल भारतीय महासमिति ने 70 के विरुद्ध 127 मतों से निश्चय किया कि “जिन प्रान्तों में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत है वहाँ गवर्नर द्वारा विशेषाधिकारों के प्रयोग न किये जाने के स्पष्ट वचन लेकर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जा सकता है।”⁸¹ इस अधिवेशन में उराके सभी सदस्यों ने कांग्रेस के विधान एव अनुशासन का पालन करने की शपथ ली।

७९ बाम्बे क्रानिकल, 22 जनवरी, 1937

८० पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई, भाग-दो, अहमदाबाद, 1956, पृ० 266

८१ शास्त्री आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 71

पद ग्रहण करने का प्रस्ताव राजेन्द्र प्रसाद ने रखा था जिसके विरोध में जय प्रकाश नारायण ने प्रस्ताव रखा था।'

इस प्रकार सरदार पटेल के कुशल प्रशासन एवं संगठन संचालन की क्षमता तथा कठोर परिश्रम की प्रान्तीय असेम्बली के चुनावों में सफलता का श्रेय दिया जाता है।

कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के पथ प्रदर्शक

प्रान्तीय असेम्बलियों के कांग्रेसी नेताओं को मन्त्रिमण्डल के गठन का गवर्नरों के निमन्त्रण 20 मार्च, 1937 ई० को दिल्ली में ही मिल गया। जिसके फलस्वरूप 6 प्रान्तों के कांग्रेसी नेताओं ने अपने प्रान्त के गवर्नरों से वार्तालाप करके कांग्रेस के इस दृष्टिकोण को रखा कि गवर्नर द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाय कि यह अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे। गवर्नर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सके अतएव 26 और 27 मार्च को कांग्रेसी नेताओं ने मन्त्रिमण्डल बनाने से इन्कार कर दिया।

6 मई, 1937 ई० को लार्ड स्नेल ने लंदन के हाउस ऑफ लार्ड्स में एक प्रस्ताव रखा कि "वायसरॉय की ओर से महात्मा गान्धी को इस आशय का आश्वासन दिलाया जाय कि विशेषाधिकार केवल अनिवार्य परिस्थितियों के लिए हैं, काम लेने के लिए नहीं और गवर्नर लोग कांग्रेस मंत्रियों के वैध कार्यों में हरगिज रोड़ा नहीं अटकायेंगे"⁸² भारत में लार्ड गेटलैण्ड ने प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा कि "वर्तमान एक्ट का आशय बिल्कुल नहीं है और इसलिए जिन कांग्रेसी प्रान्तों में अल्पमत के मन्त्रिमण्डल बनाये गये हैं वहाँ भी उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है।"⁸³ 20 जून, 1937 ई० को वायसरॉय ने एक ब्राडकास्ट भाषण में इस बात का आश्वासन दिया कि विशेषाधिकार वैधानिक हैं काम लेने के लिए नहीं। इसके बाद वायसरॉय ने अपने 21 जून के वक्तव्य पर विशेष प्रकाश डाला।

7 जुलाई, 1937 ई० को कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा में वायसरॉय के वक्तव्य को सन्तोषजनक मानते हुए छ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के गठन का निर्णय लिया। 14 से 19 जुलाई तक मध्य प्रान्त में डॉ० एन० पी० खरे ने और मद्रास में सी०वी० राजगोपालाचारी ने, संयुक्त प्रान्त में प० गोविन्द वल्लभ पन्त ने, उड़ीसा में श्री विश्वनाथ दास ने और बिहार

८२ वही, पृ० 71

८३ वही, पृ० 71

मे बाबू श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेसी मन्त्रिमण्डली का निर्माण किया। साथ ही बम्बई में श्री बालगंगाधर खेर ने कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया। कुछ समय पश्चात् पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में डॉ० खान साहिब ने अन्य दलों के कुछ सदस्यों को तोड़कर अपना मन्त्रिमण्डल बनाया। इसी प्रकार असम में कांग्रेसी पार्लियामेन्ट नेता श्री गोपीनाथ बारदोलाई ने वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर मुहम्मद सादुल्ला के कुछ सदस्यों को तोड़कर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर 17 सितम्बर, 1937 ई० को असम में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल का गठन किया।

इस प्रकार ग्यारह प्रान्तों में से आठ प्रान्तों में कांग्रेस की सरकार स्थापित हो गयी। कांग्रेसी नेताओं को सरकार चलाने का अनुभव प्राप्त नहीं था और न ही शासन की जाटिलताओं का ज्ञान था। दूसरी ओर जनता को कांग्रेसी सरकारों से बहुत आशाएँ थीं। सरकारों की किसानों को राहत, शराब बन्दी, गैर कानूनी वसूली पर रोक, उद्योग धन्धों का विकास शिक्षा का पुर्नगठन, ग्राम पंचायतों की स्थापना, सस्ता न्याय, हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों का उत्थान आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने थे। राजनैतिक बन्दी लोग कांग्रेस द्वारा मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

अतएव कांग्रेस कार्यसमिति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद व अब्दुल कलाम की एक नवीन सदस्यीय उपसमिति का गठन प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल तथा धारा सभा के सदस्यों के कार्यों को नियंत्रित, अनुशासित एवं दिशा निर्देश देने के लिए किया। यद्यपि उपसमिति में तीन सदस्य रखे गये लेकिन उपसमिति के कार्यों के संचालन का मुख्य भार सरदार पटेल को सौंपा गया। सरदार पटेल ने अपने कार्यों को निष्पक्ष एवं विवेक के साथ किया तथा अनुशासनप्रिय होने के कारण अनुशासनहीन व्यक्तियों को उनके पदों से हटाने में उन्होंने सकोच नहीं किया। कुछ विवादास्पद मामलों पर उनके निर्णय इस प्रकार रहे—

नरीमान कांड—के० एफ० नरीमान बम्बई के एक प्रतिष्ठित वकील थे जो बम्बई प्रांत की पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा वे स्वराज दल के समय धारा सभा के नेता रह चुके थे। अपने दीर्घकालीन कांग्रेसी होने के कारण वे यह आशा रखते थे कि धारा सभा के सदस्य उन्हीं को अपना नेता चुनेंगे। लेकिन 12 मार्च, 1937 ई० को बम्बई में हुई धारा

सभा की बैठक में बाला साहब खेर को सर्वसम्मति से बम्बई प्रान्त की धारा सभा का नेता चुन लिया गया। नरीमान को इस बात का आभास था, इसलिए वे धारा सभा की बैठक में उपस्थित नहीं हुए। दूसरे ही दिन बम्बई में गुजराती में निकलने वाले पारसी समाचार पत्रों तथा अंग्रेजी पत्र बाम्बे सेटीनल ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा की “नरीमान के साथ अन्याय हुआ है। धारा सभा के सदस्य नरीमान को अपना नेता चुनना चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल ने सदस्यों पर अनुचित दबाव डालकर तथा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके नरीमान को नेता चुनने नहीं दिया।”⁸⁴

इसी समय दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक 15 मार्च से शुरू हुई। इसलिए बहुत से धारा सदस्य दिल्ली पहुँच गये। बम्बई के अखबारों द्वारा सरदार पटेल के विरुद्ध मिथ्या दोषारोपण देखकर, 16 मार्च को बम्बई प्रान्त के दिल्ली में उपस्थित 47 सदस्यों ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा कि, “सरदार की तरफ से किसी भी सदस्य पर कोई अनुचित दबाव नहीं डाला गया यह बात सर्वथा निराधार एवं झूठी है।”⁸⁵ इसी बीच यह शिकायत करने वाले कुछ पत्र कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यसमिति के नाम आये कि नरीमान के साथ अन्याय हुआ है। कार्यसमिति ने मामले की पूरी जाँच करने के बाद प्रस्ताव किया कि, “समिति को विश्वास हो गया है कि धारा सभा के सदस्यों के स्वतंत्र रूप से बिना किसी अनुचित दबाव के सर्वसम्मति से अपने नेता का चुनाव किया है।” कार्यसमिति ने यह भी कहा कि धारा सभा में अनुपस्थित 47 सदस्यों ने लिखित रूप से सूचना दी है, कि उन्होंने खेर का चुनाव स्वतंत्र रूप से किया है।”⁸⁶ 23 मार्च, को नरीमान ने एक वक्तव्य द्वारा कार्यसमिति के निर्णय को स्वीकार करने तथा विवाद को समाप्त करने घोषणा की।

इतना सब होने के बावजूद बम्बई के कुछ अखबारों ने अपना विषैला प्रचार जारी रखा। इसी बीच 12 मई, 1937 ई० को नरीमान ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखकर पुनः इस मुद्दे को जीवित कर दिया। पत्र में उन्होंने कहा कि “विवाद के सबध में उन्हें कुछ नये तथ्यों का पता चला है। चुनाव के चार दिन पहले अर्थात् 8 मार्च

८४ पारीख नरहरि, पूर्वो भाग 2 पृ० 274

८५ वही, पृ० 275

८६ वही, पृ० 275 एवं 276

को धारा सभा के 30 सदस्यों ने उन्हें चुनने का निश्चय किया जो मराठी पत्र 'नवाकाल' में प्रकाशित हुआ। 9 मार्च, को सरदार साहब ने जब यह खबर पढ़ी तो उन्होंने अहमदाबाद से शंकरराव देव तथा गंगाधर राव को तार देकर अच्युत के साथ 11 मार्च, को बम्बई बुलाया।⁸⁷ ये तार अभी हमारे हाथ लगे हैं हमारी वल्लभ भाई के अनुचित व्यवहार का प्रमाण हमारे हाथ लगा है और इसकी तरफ आपका ध्यान खींचता हूँ। बम्बई के समाचार पत्रों ने इन तारों के आधार पर तरह-तरह के आरोप सरदार पटेल पर लगाने प्रारम्भ कर दिये। 17 जून के नेहरू ने नरीमान को पत्र का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि जिस दिन उन्होंने तार दिये थे उस दिन उन्होंने मुझे भी पत्र लिखा था कि महाराष्ट्र में कुछ और जिम्मेदराना चर्चाये हो रही है और उन्हें रोकने के लिए मैंने गंगाराव देशपांडे वगैरह को बम्बई बुलाया है।⁸⁸

5 से 8 जुलाई तक वर्धा में हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में नरीमान के आरोपों को निराधार पाया। कार्य समिति की बैठक समाप्त हो जाने के बाद गाँधी जी की सलाह पर सरदार पटेल ने निम्न वक्तव्य निकाला—

“उन्होंने कहा कि अभी तक मैं जान बूझकर मौन रहा परन्तु अब जनता को जानकारी देना आवश्यक है। उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नेता के चुनाव पर असर नहीं डाला। सरदार पटेल ने नरीमान पर आरोप लगाया कि वे स्वयं 4 मार्च, 1937 को उनसे मिले थे तथा नेता चुने जाने में सहायता माँगी जिसे उन्होंने इन्कार कर दिया।⁸⁹ पत्रों में वक्तव्यों की छड़ी लगा दी और 13 जुलाई को एक कठोर पत्र नेहरू को लिखा। नेहरू ने जवाब में कहा कि यदि आप को कांग्रेस कार्यसमिति पर विश्वास नहीं है तो जिस पर आपका विश्वास है उसके पास जायें। अन्त में नरीमान ने गाँधी जी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि “पार्लियामेण्टरी कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते सरदार को विशाल और निरंकुश अधिकार प्राप्त हैं। अतः धारा सभा के सदस्य साक्ष्य देने में घबरायेगे। नरीमान ने गाँधी जी की निष्पक्षता पर शक करते हुए लिखा कि मेरा नाम आपको पत्रों से मुझे लगता है कि

८७ पटेल, पेपर्स, नरीमान फाइल्स, अहमदाबाद,

८८ मेहरोत्रा, एन०सी० कपूर, रजना, पूर्वो पृ० 72

८९ पटेल, पेपर्स, नरीमान फाइल्स अहमदाबाद,

आपके मन में मेरे प्रति पूर्वाग्रह है।”⁹⁰ नरीमान किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि सरदार पटेल ने सुझाव दिया कि मामले की जाँच किसी निष्पक्ष पारसी नेता से करायी जाय। बाद में यह कार्य विश्वविख्यात पारसी विधान शास्त्री डी०एन० बहादुर को सौंपा गया। श्री बहादुर को दो विषयों पर अपनी जाँच रिपोर्ट देनी थी। प्रथम नवम्बर 1934 ई० में केन्द्रीय धारा सभा के लिए हुए चुनाव को नरीमान बने अपने आचरण से कांग्रेस को धोखा दिया था या नहीं। और द्वितीय इस आरोप में सच्चाई है या नहीं कि मार्च 1937 के बम्बई धारा सभा के नेता के चुनाव में सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया और नरीमान को नेता नहीं चुनने दिया।

प्रथम प्रश्न पर पटेल का आरोप था कि 1934 के चुनाव में कांग्रेस पार्लियामेण्टरी बोर्ड ने नरीमान और डॉ० जी०बी० देशमुख को बम्बई से केन्द्रीय धारा सभा के लिए प्रत्याशी बनाया था। परन्तु नरीमान ने जानबूझ कर मतदाता सूची में सही पता न होने के आधार पर अपना नाम वापस लेकर कांग्रेस की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कार्य किया। यही नहीं उन्होंने चुनाव वाले दिन दूषित प्रचार करके एक अन्य पारसी प्रत्याशी सर कावसजी की परोक्ष रूप से सहायता कर, के०एम० मुशी को पराजित करवा दिया।

श्री डी०एन० बहादुर ने भली-भाँति जाँच करने के उपरान्त अपने निर्णय में कहा कि—

(i) “1934 ई० के केन्द्रीय धारा सभा के चुनाव में सरदार पटेल ने जो आरोप लगाये हैं वे सही हैं।

(ii) 1937 ई० के बम्बई धारा सभा के नेता के चुनाव में नरीमान ने जो आरोप सरदार पटेल पर लगाये हैं वे सिद्ध नहीं होते।”

नरीमान के विरुद्ध बहादुर द्वारा दिये गये निर्णय का गाँधी ने भी अनुमोदन कर दिया। नवम्बर 1937 ई० के कलकत्ते अधिवेशन में “कांग्रेस कार्य समिति ने नरीमान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नरीमान को भविष्य में कांग्रेस में कोई भी जिम्मेदारी के पद और विश्वास के अयोग्य ठहरा दिया।” परन्तु 10 वर्ष पश्चात् 1947 ई० में नरीमान

द्वारा अपने व्यवहार के लिए सरदार से खेद प्रकट करने के उपरान्त पुन उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया गया।

मध्य प्रान्त का सकट - प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल के संचालन में सबसे अधिक गम्भीर समस्या मध्य प्रान्त में हुई। मध्य प्रान्त एक मिश्रित इकाई थी। 1937 ई० में डॉ० एन० वी० खरे को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। खरे मराठी क्षेत्र से संबध रखते थे। मन्त्रिमण्डल का गठन सरदार पटेल की सहमति से हुआ था। मन्त्रिमण्डल में बरार क्षेत्र के पी०वी० गोले तथा आर०आर० देशमुख तथा महाकौशल क्षेत्र के आर०एस० शुक्ला, डी०पी० मिश्रा, और डी०के० मेहता मंत्री बनाये गये। जबकि यूसुफ शरीफ को मुसलमान प्रतिनिधि की हैसियत से मन्त्रिमण्डल में रखा गया। मन्त्रिमण्डल में प्रारम्भ से ही आन्तरिक मतभेद था। यद्यपि खरे सभी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने व्यक्तियों को नियुक्त किया तथा डी०पी० मिश्रा के महत्व को घटाने का कार्य किया। फरवरी 1938 ई० में मुख्यमंत्री खरे के खिलाफ शरीफ प्रकरण, उमरी की हत्या, जबलपुर के दगे को लेकर असन्तोष फैल गया जो 1938 के अन्त तक विस्फोट रूप धारण कर लिया।

असतोष की शुरुआत कानून और न्याय मंत्री यूसुफ के व्यवहार को लेकर हुआ। यूसुफ ने 13 वर्षीय हरिजन लड़की के बलात्कारी कैदियों को एक तिहाई सजा पूरी होने के पूर्व ही गवर्नर की अनुमति से माफ कर दिया। कैदी मुसलमान थे इसलिए परिणामस्वरूप धारा सभा के बाहर तथा मंत्री कक्ष के सामने हिन्दू जनता ने नारे लगाये। सरदार पटेल को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने शरीफ से स्पष्टीकरण माँगा तथा प्रान्त की सरकार को तत्काल इस मामले को अपने हाथ में लेने को कहा। खरे शरीफ को बचाना चाहते थे। मुस्लिम लीग ने प्रचार किया कि मंत्री तथा कैदी के मुसलमान होने के कारण हिन्दू संगठन मंत्री के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यसमिति ने सम्पूर्ण मामले की जाँच कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर मन्मथ नाथ मुखर्जी को सौंप दी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में शरीफ को दोषी पाया तथा शरीफ को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया।

अभी शरीफ कांड सुलझ नहीं पाया था कि 7 मई, 1938 ई० को डी०पी० मिश्रा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जबलपुर दगे में उनकी भूमिका पर असन्तोष व्यक्त किया।

तथा 8 मई को गोके, शुक्ल, मिश्र तथा मेहता ने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की। त्यागपत्र का प्रमुख कारण खरे द्वारा संचालित गृह विभाग की कमजोरियाँ, जबलपुर दंगे में नरमी का व्यवहार, खरे की नौकरशाही पर निर्भरता, महत्वपूर्ण मामलों पर परामर्श न करना, तथा शरीफ कांड की जाँच आदि बताये गये।⁹¹ इसके अलावा सरदार साहब के पास कई मंत्रियों के रिश्वत में लिप्त होने तथा सगे सबंधियों के साथ पक्षपात करने की खबर आयी। इन सब बातों से प्रान्त में कांग्रेस की प्रतिष्ठा तेजी से गिर रही थी। अतः सरदार पटेल ने सक्रियता से 24 मई, 1938 ई० को पंचमढी में धारा सभा के सदस्यों एवं मंत्रियों की बैठक बुलायी जिसमें समझौता हो गया। इस अवसर पर सरदार पटेल ने वक्तव्य प्रकाशित करते हुए कहा कि—

“शरीफ मामले में सरकार ने अभी-अभी निपटारा किया है। हमने सब मंत्रियों के साथ अलग-अलग बातें की और फिर एक साथ बातें की। सारे समाधान करने में कठिनाई तो हुई लेकिन यह बताते हुए आनन्द होता है कि सारे मतभेद मिट गये हैं। मंत्रियों ने हमें आपस में सहयोग करने का विश्वास दिलाया है।”⁹² मंत्रियों पर रिश्वत के आरोप पर बोलते हुए सरदार साहब ने कहा कि इसका सबूत हमें नहीं मिला।

समझौते के कुछ समय बाद सरदार पटेल के पास शिकायतें आने लगीं की खर समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। 13 जुलाई, 1938 को यह समाचार प्रकाशित हुआ कि खरे समर्थक दो मंत्री गोले तथा देशमुख ने त्यागपत्र दे दिया है। 20 जुलाई, 1938 को खरे ने पत्र लिखकर मिश्र एवं मेहता को त्यागपत्र देने की सलाह दी। उनका तर्क था कि वह स्वयं त्यागपत्र देने जा रहे हैं इसलिए परम्परा के अनुसार सभी मंत्रियों को त्यागपत्र दे देना चाहिए। मंत्रियों ने त्यागपत्र देने से इकार कर दिया। 20 जुलाई को दोपहर के समय खरे ने अपना त्यागपत्र गवर्नर को सौंप दिया तथा जिन मंत्रियों ने त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया था उन्हें मन्त्रिमण्डल से मुक्त कर दिया गया।

23 तारीख को वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई जिसमें खरे को भी बुलाया गया। कार्यसमिति ने निर्णय लिया कि चूंकि दल के नेता ने त्यागपत्र दे दिया है इसलिए

९१ वही, पृ० 75

९२ वही, पृ० 76

नये नेता के चुनाव के लिए 27 तारीख को धारा सभा की बैठक बुलायी जाय। डॉ० खरे को परामर्श दिया गया कि वे दुबारा नेता पद पर के चुनाव में शामिल न हो जिसका खर ने विरोध किया। कार्यसमिति ने डॉ० खरे को पुन बुलाकर 25 तारीख को चुनाव न लड़ने का स्पष्ट आदेश दिया। पर डॉ० खरे को पुन बुलाकर 25 तारीख को चुनाव न लड़ने का स्पष्ट आदेश दिया। पर डॉ० खरे नहीं माने। बाध्य होकर कार्यसमिति ने खरे पर अनुशासन भंग का आरोप लगाया तथा उन्हें कांग्रेस सगठन में किसी जिम्मेदारी के अयोग्य ठहरा दिया गया।

डॉ० खरे ने कांग्रेस अध्यक्ष सुभाषचन्द्र बोस को पत्र लिखकर कार्यसमिति के निर्णय से असहमति प्रकट की। उन्होंने यह कहा कि—“मैं इस विचार से पूरी तरह असहमत हूँ कि कांग्रेस कार्यसमिति या पार्लियामेण्टरी बोर्ड धारा सभा के कांग्रेस दल को अपने नेता के चुनाव के मामले में कोई आदेश दे सकती है। मेरा विचार है कि धारा सभा के सदस्यों को अपना नेता चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है।”

27 जुलाई को मध्य प्रान्त की कांग्रेस धारा के सदस्यों ने रविशंकर शुक्ला को अपना नेता चुना लिया। पार्लियामेण्टरी उपसमिति के परामर्श के बाद 29 जुलाई, 1938 को रविशंकर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। डॉ० खरे ने अपनी प्रतिक्रिया में सरदार पटेल पर निरकुशता और पक्षपात का आरोप लगाया और कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्णय की आलोचना करते हुए उसे ‘फासीवाद’ की सजा दी। खरे ने ‘अपने बचाव’ नामक पुस्तिका प्रकाशित कर पाठकों को इस बात से अवगत कराने का प्रयास किया कि सरदार पटेल ने उनके साथ अन्याय किया है। डॉ० खरे को आरोपी के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चन्द्र बोस ने एक लम्बा वक्तव्य प्रकाशित कर सरदार पटेल को उचित ठहराया। इसके बाद डॉ० खरे हिन्दू महासभा में शामिल हो गये।

इस प्रकार इस कांड में भी सरदार पटेल के कठोर अनुशासन की झलक मिलती है।

बिहार तथा संयुक्त प्रान्त के राजनीतिक कैदियों की रिहाई - 1937 के प्रान्तीय धारा सभाओं के चुनावों के समय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित घोषणा पत्र में यह वचन दिया गया था कि यदि कांग्रेस सत्तारूढ़ होगी तो वह तमाम राजनीतिक कैदियों को छोड़ देगी। सत्त

मे आने के बाद बम्बई तथा मद्रास में राजनीतिक कैदी छोड़ देगी। सत्ता में आने के बाद बम्बई तथा मद्रास में राजनीतिक कैदी छोड़ भी दिये गये। संयुक्त प्रान्त के 15 और बिहार के 21 राजनीतिक कैदी थे जिनको रिहा करने को लेकर सरकार और गवर्नर में विवाद उत्पन्न हो गया। जब संयुक्त प्रान्त और बिहार ने इन कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव किया तो दोनों प्रान्तों के गवर्नरों ने आपत्ति उठाई कि यदि इन कैदियों को रिहा कर दिया जायेगा तो पंजाब और बंगाल में विषम समस्या उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि ये क्रान्तिकारी गतिविधियों से संबंधित हैं। अपने पक्ष में गवर्नर ने तर्क रखा कि काकोरी कांड के कुछ कैदियों को छोड़ देने पर उन्होंने अवांछनीय हरकतें करते हुए जनता के बीच उत्तेजनात्मक भाषण दिये। वायसराय ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट धारा को लागू करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी की कैदी छोड़े न जा सकें। मंत्रीगण सरदार वल्लभ भाई और गांधी जी से मिले। जिन्होंने सलाह दी कि यदि गवर्नर कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार न हो तो मंत्रियों को त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस पर दोनों प्रान्तों के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र गवर्नरों को दे दिया। जिसे गवर्नरों ने स्वीकार नहीं किया।

1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने एक लम्बा और विस्तृत प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि "मार्च, 1937 ई० में कांग्रेस ने भारतमंत्री, वायसराय और विभिन्न प्रान्तों के गवर्नरों के इस वक्तव्य के कारण मंत्रिमंडल का गठन किया कि गवर्नर से रोजमर्रा के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः गवर्नर जनरल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट की धारा 126(5) लागू करके व्यर्थ की दखलदाजी की है।"⁹³ प्रस्ताव पर बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा कि "हमने पर स्वीकार कर लिया है इसलिए हमारा धर्म हो जाता है कि हम जनता की इच्छानुसार शासन करें। जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहा है, उन्हें हम जेल में कैसे रख सकते हैं। वे देश की आजादी के लिए अपने प्राण देने को तैयार थे भले ही उनका कार्य करने का तरीका गलत रहा हो। जनमत द्वारा चुनी हुई कोई भी सरकार ऐसे देश भक्तों को जेल में नहीं रख सकती।" इस प्रकार कैदियों की रिहाई न होने की स्थिति में त्यागपत्र का प्रस्ताव कार्यसमिति द्वारा पास किया गया।

प्रस्ताव पास हो जाने के बाद दोनों प्रान्तों के मंत्री अपने-अपने प्रान्तों में गये। तो

1 “प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र से अपनी रिपोर्ट में केवल एक ही नाम सूचित किया हो और यदि कांग्रेसजनों में उस नाम पर कोई विवाद न हो, तो सरदार पटेल को कमेटी का प्रस्ताव स्वीकार करने की सत्ता दी जाती है।

2 दूसरे मामले में उम्मीदवारों के नाम सरदार की सिफारिश से ही बोर्ड के अन्य सदस्यों के पास उनकी राय के लिए भेजे जायेंगे।”⁹⁶

इस समय सरदार पटेल दुःसाध्य रोग से पीड़ित थे और पूना प्राकृतिक चिकित्सालय में चिकित्सा करा रहे थे। स्वास्थ्य लाभ न होने के बावजूद चुनावों को सगठित करने की सारी जिम्मेदारी सरदार पटेल पर डाली गयी जिन्होंने इस जिम्मेदारी को उत्तम ढंग से पूरी की। वे फण्ड वसूल करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे चुनाव में पैसे की कमी नहीं आने दी।

दिसम्बर 1945 ई० में चुनावों हेतु कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। 1945-46 का चुनाव 1937 के चुनावों से भिन्न था, पिछले चुनावों में कांग्रेस को केवल ब्रिटिश सरकार के समक्ष शक्ति प्रदर्शन करना था परन्तु इस चुनाव में उसे ब्रिटिश तथा मुस्लिम लीग दोनों के समक्ष अपनी स्थिति का प्रदर्शन करना था। साथ ही अन्य छोटे-छोटे राजनीतिक दल भी थे जिनके साथ कांग्रेस के मतभेद थे। इस चुनाव में सरदार पटेल की मुख्य चिन्ता केन्द्रीय तथा प्रान्तीय असेम्बली के साथ-साथ उसके उपरान्त सविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर थी।

चुनावों के संचालन हेतु सरदार पटेल ने बम्बई के कांग्रेस भवन की ऊपरी मजिल पर एक विशिष्ट कार्यालय की स्थापना की। “प्रत्याशियों के चयन के मामले में उन्होंने एकाधिकार का परिचय दिया। प्रत्याशियों के चयन के मामले में उन्होंने व्यक्तिगत मजबूत प्रत्याशी की बात करते थे।”⁹⁷

किसी दूसरे दल के साथ समझौता करते समय भी वे प्रत्याशी की सफलता को ध्यान में रखते थे। “उन्होंने डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के इस परामर्श को कि चुनाव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ समझौता कर लिया जाय, ठुकरा दिया क्योंकि उनकी नजर में

९६ शंकर, वी०, पूर्वो, पृ० 9

९७ दास, दुर्गा, सरदार पटेल, कोरेसपाण्डेन्स, खण्ड दो, अहमदाबाद, 1973, पत्र संख्या, 27

‘कांग्रेस हिन्दू महासभा पूरे देश में एक भी सीट नहीं जीत सकती थी अतः ऐसे समझौते से लाभ के बजाय हानि अधिक है।’⁹⁸ 14 दिसम्बर, 1945 ई० को सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को परामर्श दिया कि उन्हें अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देना चाहिये क्योंकि चुनावों में उनकी पार्टी एक भी स्थान प्राप्त नहीं कर सकेगी।⁹⁹

प्रत्याशियों के चयन के मामले में अन्य योग्यताओं के रूप में सरदार पटेल अनुशासित अनुदारवादी, सादगी जीवन पसन्द व्यक्ति को वरीयता दी। इसी आधार पर उन्होंने नेहरू की सस्तुति होने पर भी धर्म यश देव के नाम को अस्वीकार कर दिया। अपने पत्र में तर्क देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि “उनसे बातचीत कर मैंने अनुभव किया कि उनका रहन-सहन खर्चीला है उनकी पत्नी खर्चीली आदतों की एक सोसाइटी गर्ल है।”¹⁰⁰ प्रत्याशियों के चयन में सरदार पटेल ने क्षेत्रीय आधारों को भी महत्व दिया “जब आजाद ने जी०वी० देशमुख को प्रत्याशी बनाने की आलोचना की तो पटेल ने तर्क दिया कोणकी मतों को प्रभावित करने के लिए उनका प्रत्याशी बनाना आवश्यक है।”¹⁰¹

उम्मीदवारों के नाम की अन्तिम स्वीकृति की शक्ति केन्द्रीय चुनाव बोर्ड को थी जो अपने कार्यों में विलम्ब कर रही थी क्योंकि इसके अध्यक्ष मौलाना आजाद बीमार थे, शासक अली, राजेन्द्र प्रसाद और पत आदि सदस्य चुनावों और दूसरे कार्यों में सलग्न थे। अतएव बोर्ड की मीटिंग समय से नहीं हो पाती थी। इसलिए इस सन्दर्भ में पटेल ने आजाद से कहा कि “मीटिंग न होने की स्थिति में मेरे पास इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि कमेटी का उत्तर न मिल सके तो मैं अपने विवेक से उम्मीदवारों के बारे में निर्णय दूँ।”¹⁰²

कुछ प्रत्याशियों के चयन को लेकर सरदार पटेल का मौलाना आजाद से गम्भीर मतभेद हो गया। मौलाना आजाद, जी०वी० देशमुख (बम्बई), विश्वनाथ दास (कटक),

९८ वही, पत्र सख्या, 18

९९ नन्दूरकर, जी०एम०, सरदार लेटर्स मोस्टली अननोन, खण्ड एक, अहमदाबाद, 1927, पत्र सख्या, -12

१०० दास, दुर्गा, पूर्वो, पत्र सख्या 4

१०१ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 117

१०२ दास, दुर्गा, पूर्वो, पत्र सख्या, 22

ठाकुरदास भार्गव (पंजाब), पाण्डे (महाकौशल) आदि के नामों पर पुर्नविचार चाहते थे जिसे सरदार ने अस्वीकार कर दिया”¹⁰³ इसके अलावा सरकार के सिन्ध एंव लाहौर की प्रस्तावित दौरे पर आजाद ने आपत्ति की जिसके उत्तर में सरदार पटेल ने, “केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड तथा कांग्रेस कार्यसमिति से त्याग पत्र देने की इच्छा व्यक्त की।”¹⁰⁴ सरदार के इस निर्णय से “आजाद घबराये और उन्होंने तत्काल सरदार से क्षमा याचना की।”¹⁰⁵

इस प्रकार 1945-46 के चुनाव में सरदार पटेल ने प्रत्याशियों के चयन के मामले में एकाधिकार प्राप्त कर योग्य, कर्मठ, सादगी पसन्द तथा जिताऊ प्रत्याशियों को खड़ा करके, रात दिन चुनावी सभा उसके पक्ष में माहौल बनाने का कार्य किया।

1945-46 के चुनावों में कांग्रेस ने केन्द्रीय असेम्बली के 57 स्थानों पर विजय प्राप्त की जबकि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर विजय प्राप्त करके मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के रूप में अपने आपको पेश किया। प्रान्तों में कांग्रेस 923 सीटों पर विजय प्राप्त की जबकि मुस्लिम लीग ने 425 सीटें जीतीं। इस प्रकार इन नतीजों से सरदार पटेल को धक्का लगा और उन्हें मुस्लिमों से निराशा हुई और उनकी यह धारणा मजबूत हुई कि मुसलमान राष्ट्रीय नेताओं की अपेक्षा मुस्लिम लीग के साथ है।

१०३ वही, पत्र संख्या 30 एवं 31

१०४ वही, पत्र संख्या, 68

१०५ वही, पत्र संख्या, 71

अध्याय-3

विभाजन के पूर्व भारतीय राजनीति में योगदान

- I असहयोग आन्दोलन
 - II सविनय अवज्ञा आन्दोलन
 - III त्रिपुरी कांग्रेस
 - IV क्रिप्स मिशन
 - V भारत छोड़ो आन्दोलन
 - VI शिमला सम्मेलन
 - VII कैबिनेट मिशन
 - VIII आन्तरिम सरकार
-
-

असहयोग आन्दोलन

रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल, 1919 को वैशाखी के दिन जालियावाला बाग में आयोजित जन सभा जनरल डॉयर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाकर सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। उसके इस कृत्य की निन्दा पूरे देश में हुई। “डॉयर के इस कृत्य की प्रतिक्रियास्वरूप रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने, ‘सर’ की उपाधि लौटाकर अंग्रेजों के मुँह पर करारा तमाचा मारा, तो महात्मा गाँधी ने भी ‘कैसे हिन्द’ का सम्मान लौटा दिया और असहयोग का प्रस्ताव किया।”¹ यह प्रस्ताव सरदार पटेल के हाथों गुजरात राजकीय परिषद् की बैठक में रखा गया। जिसका कुछ नरमपथियों ने जोखिम की बात कह कर विरोध किया। सरदार पटेल ने उनका उत्तर देते हुए कहा कि “यह बात सही है कि असहयोग में जोखिम तो है, मगर दुनिया के किस देश को सरलता से आजादी प्राप्त हुई है। चुप बैठे रहने में क्या कम जोखिम है। जोखिम के भय से क्या प्रजा की उन्नति के महान कार्यों को किसी ने छोड़ा है? इतने विशाल साम्राज्य को गठित करने वालों ने खतरों का डर मन में रखा होता तो उनका कोई अस्तित्व न होता।”²

“4 सितम्बर, 1920 ई० को कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गाँधी जी ने द्वारा प्रस्तुत असहयोग सबंधी प्रस्ताव 884 के मुकाबले 1886 मतों से पारित कर दिया गया।”³ इस प्रस्ताव में दो प्रमुख भाग थे। प्रथम नकारात्मक और द्वितीय सकारात्मक। नकारात्मक भाग के अन्तर्गत धारा सभाओं, न्यायालय तथा शिक्षण संस्थाओं का परित्याग और सकारात्मक भाग में पचायतो, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं आदि की स्थापना सम्मिलित थी। दिसम्बर, 1920 ई० के नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गयी। इस अधिवेशन में यह भी निर्णय लिया गया कि, “कांग्रेस का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य के

१ ताराचन्द, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग-तीन, प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, 1982, पृ० 507

२ पटेल, ईश्वर भाई, सरदार वल्लभाई पटेल, आनन्द, 1974, पृ० 44

३ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 29

स्थान पर शान्तिमय उपायो से स्वराज्य प्राप्त करना है।⁴ नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज्य के नारे ने एक वर्ष में जोर पकड़ लिया। जनता को लगातार कार्यक्रम देने के उद्देश्य से नागपुर कांग्रेस के बाद महासमिति की बैठक में निश्चित किया गया, कि, 'तिलक स्वराज्य फण्ड' में 30 जून, 1921 तक एक करोड़ रुपये जमा किया जाय तथा चार आने वाले एक करोड़ सदस्य बनाये जाय। देश में बीस लाख चरखे बाँटे जाय। इसमें से गुजरात के हिस्से में आये 10 दस लाख रुपये, तीन लाख सदस्य बनाना और एक लाख चरखों के बारे में सरदार पटेल ने गाँधी जी को निश्चिन्त होने के लिए कहा। अपने अथक प्रयास और प्रभाव के कारण बहुत ही जल्दी दस लाख के बजाय पन्द्रह लाख रुपये एकत्रित कर दिये और सदस्यता तथा चरखों का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया। 30 जून तक तिलक स्वराज्य फण्ड में एक करोड़ रुपये एकत्रित हो गया।

तिलक स्वराज्य फण्ड का लक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त लोकमान्य तिलक की पहली बरसी के दिन (1 अगस्त, 1921 ई०) महात्मा गाँधी ने वस्त्रों की होली जलाने का निश्चय किया। गाँव-गाँव में इस पर अमल हुआ। इस अवसर पर जलाई गयी होलियों में बम्बई और अहमदाबाद की होली शायद सबसे बड़ी थी। वल्लभ भाई ने अपनी बैरिस्ट्री के गाउन के अलावा दर्जनो सूट, नेक टाईया, कॉलर और बूटे जलाये। लोगों में अपरिमित जोश था। होली शुरू होते ही वे अपने शरीर के ऊपर से विदेशी कपड़े उतारकर वस्त्रों की वर्षा सी कर दी। विदेशी वस्त्रों की होली के साथ-साथ अहमदाबाद में सरदार पटेल ने स्वयंसेवाओं के साथ विदेशी वस्त्रों की मड़ी एवं दुकानों पर घरना भी दिया। "सरदार वल्लभ भाई के प्रयासों से अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी ने भी सरकार से असहयोग किया। परिणामस्वरूप म्युनिसिपैलिटी भग कर दी गयी। इस पर सरदार पटेल के प्रयासों से अहमदाबाद के नागरिकों ने तत्काल 'सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा मंडल' की स्थापना की।"⁵ असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रमों को और तेजी से पूरा करने के लिए वल्लभ भाई ने अपने सैकड़ों सहयोगियों के हस्ताक्षरों का एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा कि-

"हिन्दुस्तान की सार्वजनिक आकाशाओं को कुचल डालने वाली इस शासन तंत्र में कोई भी हिन्दुस्तानी असैनिक और खास तौर पर सैनिक की हैसियत से नौकरी करे, यह

४ दास, सेठ गोविन्द, सरदार पटेल, दिल्ली, 1969, पृ० 41

५ वही, पृ० 42

हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय सम्मान को धक्का पहुँचाने वाली बात है। प्रत्येक भारतीय का फर्ज है कि वह नौकरियों से नाता तोड़ ले और अपने गुजारे के लिए कोई अन्य उपाय ढूँढ़ ले।”⁶

सरदार पटेल ने 1921 ई० की गर्मियों से खादी पहनना आरम्भ किया है और 1927 ई० से मणि बहन द्वारा कात कर तैयार की गयी खादी के कपड़े सरदार जीवन भर पहने। सरदार ने जगह-जगह जाकर आन्दोलन में सहयोग और सरकार से असहयोग का बिगुल बजाने का आह्वान किया। अपने आह्वान के पक्ष में उन्होंने और जोरदार तर्क रखे। उनका सक्षिप्त विवरण निम्न है।

1 सरदार ने किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति का सर्वप्रथम आह्वान किया तथा कहा कि “क्या कभी किसी ने खतरे के डर से जनता की उन्नति के महान प्रयोग छोड़ दिये हैं? यदि यह डर इतना बड़ा साम्राज्य बनाने वाले लोगों को होता तो आज उनका कोई अस्तित्व न होता।” रेलवे और जहाज के सफर में दुर्घटनाओं का डर रहता है तो क्या इस भय से कोई सफर करना छोड़ देगा? यदि नहीं तो आप भी भय त्याग दें।” यदि आप ऐसा करते हैं तो स्वराज्य प्राप्ति में जरा भी देर नहीं लगेगी।”⁷

2 सरदार ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जिसका आधार भयकर शस्त्र है, का प्रतिकार केवल गान्धीवादी मार्ग से ही सम्भव है। 28 सितम्बर 1921 को अहमदाबाद के विद्यार्थियों की सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि—“महात्मा गान्धी आये तक राजनीतिक जीवन में सत्य का प्रवेश हुआ खेडा सत्याग्रह में उन्होंने माँग की कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिये जो आज ही अपना तमाम धन्धा छोड़कर नाडियाद में रहे और लडाई का काम अपने सिर पर ले ले। मैंने वह कार्य सिर पर ले लिया। तब उनके साहस से मुझे विश्वास हो गया कि अब तक भारत उल्टे रास्ते पर चल रहा है। उनके बताये हुए मार्ग पर चलने से ही भारत का उद्धार होगा।”⁸ अतः असहयोग युद्ध की जो दुदुम्भी बज रही है, लडाई छिड़ गयी है, ऐसे समय में “मैं क्या करूँगा” “मेरा क्या होगा।” इस तरह के नामर्दी वाले विचारों को त्याग कर मैदान में कूद पड़ना चाहिए तथा यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए।”⁹

६ वही, पृ० 43

७ प्रभाकर, विष्णु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दिल्ली, 1982, पृ० 13

८ पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक), अहमदाबाद, 1950, पृ० 116

९ वही, पृ० 27

3 उड़ीसा में एक सभा को सम्बोधित करते हुए पटेल ने 'वर्तमान परिस्थितियों और सहयोग' पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि "हमें किसी दूसरे पर राज्य नहीं करना है परन्तु जैसे फ्रान्सीसी लोग फ्रांस पर राज्य करते हैं, जर्मन लोग जर्मनी में और इटली वाले इटली में करते हैं उसी प्रकार हम हिन्दुस्तान के लोग सिर्फ हिन्दुस्तान पर राज्य करें।" पटेल ने लोगों से सरकारी शिक्षण संस्थाओं, अदालतों, धारा सभाओं तथा विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की भी सलाह दी।¹⁰

31 मई, व 1 जून, 1921 को भडौच में गुजरात राजनीति परिषद के अध्यक्षीय भाषण में स्वराज्य के वास्तविक अर्थ की चर्चा की और कहा कि "हमारे स्वराज्य में थोड़े से विदेशियों की सुविधा के लिए विदेशी भाषा में राजकाज नहीं होगा, शिक्षा का महत्व विदेशी भाषा नहीं होगी, विद्यालयों को आचार्य विदेशी नहीं होंगे।"¹¹

18 सितम्बर, 1921 ई० को अहमदाबाद में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गयी इस अवसर पर सरदार पटेल ने कहा कि "विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने से निश्चित ही लकाशायर में खलबली मच गयी होगी।"¹² जनता के शुद्ध मन से विदेशी कपड़ों का हमेशा के लिए बहिष्कार करना होगा क्योंकि स्वराज जनता की इच्छा शक्ति, त्याग और समय पर निर्भर करता है।"¹³ दिसम्बर 1921 ई० में हुए अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष के रूप में बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा कि यह समय जनता के परीक्षा की घड़ी है।

देश भर में असहयोग आन्दोलन की सफलता देखकर और खासतौर पर वल्लभ भाई के प्रयासों से जो पूरे गुजरात में असहयोग की लहर चल रही थी, उसे देखकर गाँधी जी ने असहयोग आन्दोलन को विस्तृत करके इसके कार्यक्रम में करने देने की लड़ाई के लिए बारदोली ताल्लुके का चुनाव किया। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के चौरा-चौरा कांड के कारण 5 फरवरी, 1922 ई० को गाँधी जी ने आन्दोलन वापस ले लिया। गाँधी जी के इस निर्णय ने उस समय लगभग सभी प्रमुख नेताओं को क्रुद्ध कर दिया। गाँधी जी के इस निर्णय का समर्थन सिर्फ वल्लभ भाई और डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने ही किया।

१० वही, पृ० 28-29

११ वही, पृ० 32

१२ वही, पृ० 41

१३ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, पूर्वो, पृ० 30

इस प्रकार आन्दोलन स्थगित हो गया और लोगो मे निराशा फैल गयी। गॉंधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दे दी गयी। सरदार ने गॉंधी जी की अनुपस्थिति मे प्रजा को रचनात्मक कार्यों द्वारा तैयार करने का कार्य किया जो वाद मे राजनीतिक चेतना की लहर के रूप मे बोरसद सत्याग्रह, बारदोली की सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह मे देखने को मिली। इस प्रकार सरदार ने गुजरात मे राज्यनीतिक चेतना का विकास किया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन

1928 ई० मे साइमन कमीशन के वहिष्कार आन्दोलन की सफलता से उत्साहित होकर महात्मा गॉंधी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने की घोषणा कर दी। आन्दोलन चलाने से पूर्व गॉंधी जी ने वायसराय के ग्यारह शर्तो का प्रस्ताव भेजा जिस पर कोई सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर गॉंधी जी ने यह घोषणा की कि वह 12 मार्च, 1930 ई० को नमक कानून भंग करने के लिए दाण्डी मार्च करेगे।

दाण्डी मार्च की पूर्व तैयारी के लिए सरदार पटेल 7 मार्च को बोरसद ताल्लुके के रास गॉंव गये। जहाँ उनको सुनने के लिए हजारो लोग इकट्ठा हुए। “जब वल्लभ भाई इस प्रकार गॉंधी जी के आगे-आगे चल रहे थे के तो सरकार ने समझा “यह तो 1900 वर्ष पहले का ईसा मसीह का दूत जान बैपटिस्ट है।”¹⁴ अतः सरकार ने वल्लभ भाई के भाषण करने पर प्रतिबन्ध लगाते हुए उन्हें भाषण न करने की नोटिस दी। जिस पर सरदार ने अमल न करने की इच्छा जाहिर की और तुरन्त ही पुलिस ने सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया और “उन पर मुकदमा चलाकर तो तीन सप्ताह की अधिक जेल की सजा दे दी।”¹⁵ यह सरदार पटेल की पहली गिरफ्तारी थी।

सरदार पटेल की गिरफ्तारी के समाचार से सम्पूर्ण गुजरात मे तीव्र प्रतिक्रिया हुई। वहाँ का बच्चा-बच्चा सरकार के विरुद्ध हो गया। अहमदाबाद के साबरमती के रेतीले तट पर गॉंधी जी की अध्यक्षता मे एक विशाल सभा हुई। जिसमे 75,000 स्त्री पुरुषो ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमे उन्होंने सकल्प लिया कि, “हम अहमदाबाद के नागरिक यह सकल्प करते है कि जिस मार्ग पर वल्लभ भाई गये है हम भी उसी पर जायेगे और

१४ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 55

१५ होम पालिटिकल डिपार्टमेन्ट, 1930 एफ०एन० 33/39/30, नेशनल आर्चिब्स ऑफ इण्डिया, न्यू देल्ही

ऐसा करते हुए स्वाधीनता को प्राप्त करके छोड़ेंगे। हम देश को स्वतंत्र किये बिना न तो चैन से बैठेंगे और न ही सरकार को चैन से बैठने देंगे। हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं, कि जिस मार्ग पर वल्लभ भाई गये हैं हम भी उसी पर जायेंगे और ऐसा करते हुए स्वाधीनता को प्राप्त करके छोड़ेंगे। हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष का उद्धार सत्य एव अहिंसा से होगा।”¹⁶ इसके उपरांत 300 सौ लोगो ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया।

सरदार की गिरफ्तारी पर अहमदाबाद के वकीलो का मत था कि सरदार ने भले ही कहा हो कि मैं स्वीकार करता हूँ परन्तु उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया केवल भाषण देने की इच्छा प्रकट की। इसलिए यह गिरफ्तारी गैर कानूनी है।

केन्द्रीय असेम्बली में मदन मोहन मालवीय ने सरदार की गिरफ्तारी तथा सजा पर स्थगन प्रस्ताव रखा जो पारित न हो सका। जिन्ना ने गिरफ्तारी के सन्दर्भ में कहा कि “अलबत्ता विचार स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो सकता है और कई बार इसका दुरुपयोग हुआ भी है। परन्तु उससे भी ज्यादा खतरनाक तो यह है कि सरकार विचारों को दबा लेने का अधिकार धारण कर ले।”¹⁷

सरदार पटेल को गिरफ्तार करके साबरमती जेल में रखा गया। जेल में प्रवेश करते ही उन्होंने कभी भी बीड़ी और सिगरेट न पीने का सकल्प लिया और उसे सदा के लिए छोड़ दिया। जेल में उन्हें एकान्त मिला जहाँ वे भगवत गीता और तुलसी कृत रामायण का नियमित पाठ करने लगे। साथ ही कुछ मनपसंद पुस्तकें भी पढ़ने की मिली। अपने जेल प्रवास के दौरान सरदार ने अपने जीवन में सर्वप्रथम 7 3 30 से 29 4 30 तक की जीवन डायरी लिखी। इस डायरी के आन्दोलन से स्पष्ट होता है कि वह स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति पूरी तरह समर्पित थे तथा गुजरात के प्रति उनकी अटूट ममता तथा बापू के प्रति भक्ति भाव का परिचय मिलता है।”¹⁸

अपनी जेल डायरी में उन्होंने लिखा है कि जेल में क वर्ग और ख वर्ग के कैदियों को अलग-अलग भोजन मिलता था। सरदार ने सभी के लिए एक-सा भोजन की माँग की।

१६ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 55

१७ पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई, भाग दो, अहमदाबाद, 1956, पृ० 16 17

१८ वही, पृ० 18-32 (डायरी का वर्णन)

जिसे जेल अधिकारियों ने ठुकारा दिया तो सरदार पटेल ने उपवास शुरू कर दिया अतः जेल अधिकारियों को झुकना पड़ा।

पौने चार महीने जेल में रहने के बाद 26 जून, 1930 ई० को सरदार पटेल जेल से बाहर आये। उस समय देश का राजनीतिक वातावरण गरम था। गाँधी जी ने 12 मार्च, 1930 को दाण्डी कूँच करके 5 अप्रैल, 1930 को नमक कानून तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के कारण कांग्रेस के समस्त महत्वपूर्ण नेता जेल में डाल दिये गये थे। सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में बन्द कर दिया था। इसी कड़ी में जवाहर लाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस अध्यक्ष का पद भार मोती लाल नेहरू के कंधे पर आ गया और जब 30 जून, 1930 को सरकार ने मोती लाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया।

इस प्रकार महत्वपूर्ण नेताओं की गैर मौजूदगी में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का समस्त भार सरदार पटेल के कंधों पर आ गया। उन्होंने सम्पूर्ण राष्ट्र में सत्याग्रह की लड़ाई छेड़ने का विचार बनाया। उनके प्रति जन समर्थन को देखकर सरकार ने दमनकारी कदम उठाते हुए राष्ट्रीय विचारधारा के समाचार पत्रों एवं पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया। कांग्रेस को गैर कानूनी सस्था घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के समस्त कार्यालयों में ताला लगा दिया गया। सरकार की इस उक्त कार्यवाही से आन्दोलन ने और गति पकड़ लिया। मदन मोहन मालवीय जो अभी तक शान्त थे कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनने की माँग की जिसे सरदार ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस को गैर कानूनी सस्था घोषित करने पर सरदार पटेल ने प्रतिक्रियास्वरूप कहा कि, “देश का हर घर कांग्रेस का कार्यालय बन जाय और हर व्यक्ति कांग्रेस सस्था बन जाय।”¹⁹

इस दौरान जयकर और तेज बहादुर सप्रू द्वारा समझौते के प्रयत्न पर सरदार पटेल ने कहा कि-“इस प्रकार के जोड़तोड़ से जाने अनजाने में प्रजा का सम्मान भग होता है यह देश की कुसेवा है। जब सरकार का हृदय परिवर्तन होगा और समझौते का वक्त आयेगा तो सरकार स्वयं यरवाद जेल के ताले को खोलकर गाँधी जी से बात करेगी।”²⁰ कांग्रेस

१९ पटेल, ईश्वर भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आनन्द, 1974, पृ० 104

२० वही पृ० 104

का कार्य तेजी से चलाना ही लड़ाई का शीघ्र अंत है यह नहीं भूलना चाहिए। बम्बई के खानूभाई वाडी में छात्रों की एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए छात्रों से आग्रह किया कि, "जब युवको का युवराज जवाहर लाल जेल में है तथा सैकड़ों माताओं पर पुलिस ने अमानुसिक व्यवहार किया है तो तुम गणित तथा इतिहास पढ़ने में व्यस्त हो।"²¹

31 जुलाई, 1930 ई० को तिलक की पुण्यतिथि के दिन एक विराट जुलूस निकाला गया जिसमें सरदार पटेल ने भी भाग लिया। बोरी बदर स्टेशन के पास जुलूस रोक दिया गया। और उसे अवैध घोषित कर दिया गया जुलूस में शामिल हजारों लोग वहीं बैठ गये। मूसलाधार वर्षा हुई। सब लोग भीग गये। लेकिन सरदार सहित सभी लोग वहाँ बैठे रहे। प्रातः होते ही सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके उपरान्त तीन महीने की सजा के तौर पर यरवदा जेल भेज गये।

5 नवम्बर 1930 ई० को सजा की अवधि समाप्त होने के उपरान्त सरदार जेल से छोड़ दिये गये। इस समय कर्नाटक और गुजरात में कर बन्दी लड़ाई शुरू हो जाने के कारण सरकार दमन की अधिक सख्त कार्यवाही करने लगी थी। जनता को सरदार के भाषणों के प्रभाव से दूर रखने के लिए सरकार ने अनेक भाषण देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। सरदार ने सरकार के प्रतिबन्ध की अनदेखी करते हुए बम्बई खादी भंडार का उद्घाटन करते समय अपने भाषण में कहा "मेरी वाणी पर दुनिया में कौन प्रतिबन्ध लगा सकता है। मैं जेल में भी बैठा रहूँ तो भी यह आपके पास तक पहुँच जायेगी और आपके हृदय में समा जायेगी।"²² प्रतिबन्ध के बावजूद भाषण देने के आरोप में उन्हें पुनः दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह में गिरफ्तार कर लिया गया, और नौ महीने जेल की सजा दी गयी।

इसके उपरान्त सरकार सत्याग्रहियों की माँग के आगे झुककर भारत के भावी शासन के सबंध में लन्दन में गोलमेज सम्मेलन करने की घोषणा की। "12 दिसम्बर, 1930 ई० को आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सम्मानपूर्ण स्थान न मिलने के कारण कांग्रेस ने भाग नहीं लिया।"²³ इस सम्मेलन के सबंध में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि, "यह दूल्हे के बिना सम्पन्न होने वाला विवाह था।" 19 जनवरी, 1931 ई० को इंग्लैण्ड के तत्कालीन

२१ बाम्बे, क्रानिकल, 7 जुलाई, 1930

२२ पटेल, ईश्वर भाई, पूर्वो, पृ० 105

२३ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 57

प्रधानमंत्री रमजे मैकडानाल्ड ने गोलमेज सम्मेलन में घोषणा की कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य तक दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री की घोषणा से कांग्रेस कार्यसमिति पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया, और 25 जनवरी को महात्मा गान्धी और सरदार पटेल सहित 26 कांग्रेसी सदस्यों को जेल से छोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप गान्धी जी और वायसराय के मध्य 5 मार्च, 1931 ई० को समझौता हो गया जिसे गान्धी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते द्वारा आन्दोलन स्थगित कर गान्धी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया। 8 मार्च, 1931 ई० को अहमदाबाद में एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करते हुए समझौते के बारे में सरदार पटेल ने कहा, कि यदि हमने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपनी माँगों की स्पष्ट घोषणा की तो यह समझौता हानिकारक न होगा। कांग्रेस को आमंत्रित करके सरकार ने कांग्रेस की शक्ति को स्वीकार किया है।²⁴ सरदार पटेल के समक्ष मुख्य समस्या गुजरात सरकार द्वारा किसानों की ज़ब्त की हुई जमीन वापस दिलाने की थी जिस पर सहयोग करना वायसराय ने स्वीकार कर लिया था, अतः किसानों को ढाढस बंधाने के लिए गान्धी, पटेल ने एक साथ एक सप्ताह तक दौरा किया।

कांग्रेस अध्यक्ष—गान्धी इरविन समझौते के उपरान्त 31 मार्च, 1931 ई० को कराची अधिवेशन में सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। यह समय अत्यन्त ही गम्भीर और दुःख भरे वातावरण का था। इस समय दो प्रमुख समस्याएँ देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी।

1 प्रथम गान्धी इरविन समझौता और

2 द्वितीय भगत सिंह व उनके साथियों को फाँसी

गान्धी इरविन पैक्ट अधिवेशन के कुछ समय पूर्व ही हुआ था। युवा वर्ग और जनसाधारण को इस समझौते के प्रति अत्यधिक असन्तोष था जिसका मुख्य कारण यह था कि पैक्ट की शर्तों के अनुसार जिन कैदियों की रिहाई होनी चाहिए वह नहीं हो पायी थी क्योंकि नौकरशाही जान-बूझकर ऐसा कर रही थी। साथ ही बंगाल तथा कुछ अन्य प्रान्तों में बड़ी संख्या में जिसे कैदी नजरबन्द थे जिनका पूर्व सविनय अवज्ञा आन्दोलन से तो समझौते में कोई प्रावधान नहीं था।

भगत सिंह, राजगुरु और गुरुदेव को 'पंजाब के एक अधिकारी की हत्या के लिए 1928 के लाहौर षडयंत्र कांड अभियोग में 23 मार्च, 1931 ई० को फाँसी की सजा दी गयी थी। युवा वर्ग सहित सम्पूर्ण राष्ट्र की माँग थी कि फाँसी की सजा न दी जाय। लेकिन फाँसी दी गयी जिससे इन युवा देश भक्तों के श्रद्धाजलि हेतु देश भर में हड़ताले की गयी और परिस्थितियाँ ऐसी हो गयीं कि "यह कहना असंभव न होगा कि उस समय गाँधी जी की अपेक्षा भगत सिंह का नाम अधिक प्रसिद्ध हो गया था।"²⁵ इन दो घटनाओं की विषम परिस्थितियों के साथ सरदार को कांग्रेस के संचालन का भार उठाना पड़ा। सर्वप्रथम उसका स्वरूप तभी प्रदर्शित हो गया था जब सरदार महात्मा गाँधी के साथ कराची स्टेशन पर पहुँचे थे तो युवा वर्ग ने काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत किया। यहाँ एक समस्या गाँधीवाद को लेकर खड़ी हो गयी। युवा वर्ग का कथन था कि जब गाँधी जी भगत सिंह का एक साधारण सा मामला नहीं तय कर पाये तो क्या उनकी अहिंसा स्वराज्य प्राप्ति हेतु उचित रहेगी।"²⁶

सरदार पटेल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सर्वप्रथम युवा वर्ग में व्याप्त दोनों समस्याओं पर विचार व्यक्त करते हुए उनका निदान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा—“नवयुवक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को थोड़े ही दिन पहले फाँसी दी गयी है इसलिए देश के गुस्से का पार नहीं है। इन नवयुवकों की कार्यपद्धति से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि किसी और उद्देश्य से हत्या करने की अपेक्षा देश के लिए हत्या करना कम पाप है। फिर भी भगत सिंह और उनके साथियों की देश भक्ति और बलिदान के आगे नतमस्तक हूँ। लगभग सारे देश ने यह माँग की कि उनकी फाँसी की सजा को बदलकर देश निकाला दिया जाय, फिर भी सरकार ने उन्हें फाँसी दे दी। जो यह प्रकट करता है कि मौजूदा शासन प्रणाली कितनी हृदयहीन है।”²⁷

गाँधी इरविन समझौते के सबंध में सरदार पटेल ने कहा कि “कांग्रेस का मत रहा है कि यदि सम्मान के साथ देश के हितों के प्रति कोई समझौता हो सके और बिना किसी शर्त के कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की माँग करने का अधिकार हो, तो कांग्रेस गोलमेज

२५ कुमार, रवीन्द्र, सरदार वल्लभ भाई जवाहर भाई के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार (थीसिस), दिल्ली, 1991 पृ० 101

२६ वही, पृ० 101

२७ पारीख, नरहरि, पूर्वो, पृ० 59

सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर ले। साथ ही यदि कोई ऐसा शासन, विधान जो सभी दलों को मान्य हो, को तैयार करने में सहयोग दे। इस सबध में यदि सफलता प्राप्त नहीं होती तो हमारे संघर्ष का मार्ग खुला है और उस मार्ग से विचलित करके बाकी कोई शक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है।”²⁸ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही कराची में साम्प्रदायिक दंगा हो गया जिसमें कुछ मुसलमान परिवारों को बचाने के प्रयत्न में संयुक्त प्रान्त के कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी मारे गये। इस समाचार को सुनते ही अधिवेशन में जबरदस्त शोक छा गया। कांग्रेस ने संवेदना प्रकट करते हुए अपने प्रस्ताव में कहा कि,-

“जो लोग खतरों में पड़े हुए थे उनको बचाने के लिए और शान्ति स्थापित करने के लिए हमारे प्रमुख कार्यकर्त्ता ने अपने प्राणों की जो आहुति दी है उस पर हमें गर्व है।”²⁹

इन सबके अलावा कांग्रेस का यह अधिवेशन मौलिक के अधिकारों तथा आर्थिक व्यवस्था संबंधी प्रस्तावों के कारण अधिक महत्वपूर्ण है। 7 व 8 अगस्त को बम्बई में हुई कार्य समिति में 14 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गयी जिनमें से कुछ प्रमुख मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं।

- 1 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- 2 शान्तिपूर्ण इकट्ठा होने या सभा की स्वतंत्रता
- 3 संघ बनाने की स्वतंत्रता
- 4 आजीविका की स्वतंत्रता
- 5 धर्म की स्वतंत्रता
- 6 भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण
- 7 बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कानून के समक्ष समस्त नागरिकों की समानता
- 8 सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग की समान व्यवस्था

इसी समय श्रमिकों, भूमि तथा भूराजस्व, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के लिए 17 नियम भी स्वीकार किये गये। इसके पूर्व जून 1931 ई० में पटेल की अध्यक्षता में कार्यसमिति की बैठक बम्बई में हुई जिसमें यह प्रस्ताव किया गया कि, “यदि आवश्यकता

२८ वही, पृ० 59-60

२९ वही, पृ० 63

हो तो स्थिति के अनुसार गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गान्धी द्वारा किया जाना चाहिये।”³⁰ इसी बीच 18 अप्रैल, 1931 ई० को लार्ड इरविन का कार्यकाल पूरा होने के बाद मद्रास सभा बम्बई के गवर्नर रह चुके, स्वभाव से कठोर और कांग्रेस विरोधी लॉर्ड विलिंग्डन वायसराय बनकर आये। जिन्होंने गान्धी इरविन समझौते पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि “वह भला इरविन किस नटखट बनिये के चक्कर में फँस गया है।” मैं होता तो उसे हाथ नहीं रखने देता।”³¹ अतः अपने स्वभाव के अनुसार नये वायसराय ने जगह-जगह पर समझौते की शर्तों को तोड़कर जो मिठास का वातावरण बना था, उसे कड़ुवाहट में बदल दिया। पटेल ने 21 जुलाई 1931 ई० को गान्धी को शिमला में तार भेजकर कहा कि, “पुलिस का जुल्म असह्य होता जा रहा है। किसानों की भीड़ शिकायत करने के लिए आश्रम में उमड़ पड़ती है। बारदोली के कोने-कोने पर पुलिस लगा दी गयी है और पुलिस तथा स्त्रियाँ सताये जाने की और न सुनने जैसी गालियों की शिकायत करते हैं। यदि इस कांड का इलाज हो ही न सके तो भगवान के लिए अब तो लड़ाई शुरू कर देने दीजिये।”³²

अविश्वास के इस वातावरण में भारत के लिए बिना किसी उपलब्धि की आशा से एक सच्चे सत्याग्रही के कारण गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गान्धी 29 अगस्त, 1931 ई० को लंदन के लिए प्रस्थान किया।” गान्धी जी की अनुपस्थिति में सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता के साथ जटिल परिस्थितियों में संघटन का काम सम्भाला। उस समय उन्होंने पूरे देश में अनुशासनप्रिय अध्यक्ष के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों जैसे-सरकार की नीतियों के प्रति दृष्टिकोण और कार्यकर्त्ताओं के मध्य सामंजस्य बैठाने का अद्वितीय कार्य किया।

गान्धी जी को लंदन जाने से पूर्व वायसराय ने आश्वासन दिया था कि बारदोली में लगान वसूली के समय पुलिस ज्यादातियों की सरकार जाँच करेगी। जाँच का काम मिस्टर गार्डन को सौंपा गया। गार्डन द्वारा की जा रही जाँच को सरदार पटेल के एकतरफा कहकर

३० वही, पृ० 66

३१ मेहरोत्रा, एन०सी० कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 66

३२ वही, पृ० 77-78

इसका विरोध किया। इसी समय सरकार ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाकर मामले को और बिगाड़ने का कार्य किया कि वह संयुक्त प्रान्त में किसानों को लगान न देने के लिए उत्साहित कर रही है। सीमा प्रान्त में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पुनः सक्रिय सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने की तैयारी चल रही थी। बंगाल की स्थिति भयंकर थी। इन विषम परिस्थितियों का वर्णन करते हुए सरदार पटेल ने 8 नवम्बर, 1931 ई० को गाँधी जी को तार भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि “यहाँ स्थिति अधिकाधिक नाजुक बनती जा रही है। सरकार का रवैया बहुत खराब है। बंगाल में स्थिति खराब होती जा रही है। सरहद प्रान्त में जुल्म बढ़ रहे हैं। संयुक्त प्रान्त में लगानबन्दी की लड़ाई जल्दी शुरू करना अनिवार्य जान पड़ता है। बारदोली में जॉच की कार्यवाही सन्तोषजनक ढंग से न होने के कारण और दूसरे कारणों से भी मामूल होता है कि उससे हट जाना पड़ेगा। आपका जल्दी आना वाछनीय है यदि आप आने में देरी करेंगे तो काम बिगड़ जायेगा।”³³

एक तरफ सरकार भारतीयों के साथ कड़ाई से पेश आ रही थी तो दूसरी तरफ लंदन में अग्रेजों ने कम्यूनल अवार्ड के माध्यम से इस कार्य में अम्बेदकर को भी शामिल कर लिया था। अतएव इस विषय में निराशाजनक परिस्थितियों में सरदार का पत्र पाते ही गाँधी जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड एवं श्री निवास शास्त्री के बार-बार आग्रह के बावजूद सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर 28 दिसम्बर 1931 ई० को भारत वापस आ गये। इस प्रकार द्वितीय गोलमेज असफल रही। कांग्रेस ने पुनः 1 जनवरी, 1932 को सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ने की घोषणा कर दी। परिणामस्वरूप 4 जनवरी, 1932 ई० को गाँधी जी और सरदार पटेल गिरफ्तार कर लिए गये। जवाहर लाल नेहरू, पुरुषोत्तर दास टंडन तथा शेरवानी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। कांग्रेस की अवैध सस्था घोषित कर दिया गया।

गिरफ्तारी के बाद सरदार पटेल को गाँधी जी के साथ यरवदा जेल में रखा गया जहाँ दोनों ने 16 महीने तक (जनवरी 1932 से 1933 तक) साथ रहे। साबरमती में सिंगरेट पहले ही छोड़ दी थी। “यहाँ सरदार ने चाय भी छोड़ दी।”³⁴ 8 मई, 1933 ई० को गाँधी

33 मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली 1997,

जी को 21 दिन के उपवास के कारण जेल से छोड़ दिया गया तो गाँधी जी ने लिखा कि जेल में वे "बारदोली और खेडा जिलों के किसानों की जैसी चिन्ता करते थे उसे मैं भूल नहीं सकता।"³⁵

पहली अगस्त को सरदार को यरवदा जेल से हटाकर नासिक जेल भेज दिया गया जहाँ से उन्हें 4 जुलाई 1934 ई० को मुक्त किया गया। ढाई वर्ष की इस जेल यात्रा के दौरान सरदार के व्यक्तिगत जीवन तथा देश की राजनीति में निम्न प्रमुख घटनाएँ घट चुकी थीं।

1 16 अगस्त, 1932 ई० को सरकार ने साम्प्रदायिक घोषित करके अश्वपृथ्वी जातियों को सामान्य हिन्दुओं से पृथक् करके उन्हें पृथक् निर्वाचन करने का अधिकार दे दिया। जिसके विरोध में गाँधी जी ने 20 सितम्बर, 1932 से आमरण अनशन शुरू कर दिया परिणामस्वरूप 24 सितम्बर, 1932 की पूना समझौता हो गया।

2 1 नवम्बर, 1932 ई० को सरदार की माता जी का देहान्त हो गया। सरकार की शर्तों को स्वीकार न करने के कारण वह अपनी माँ के अन्तिम सस्कार में भाग नहीं ले सके।

3 नासिक जेल में आने के दो महीने बाद 20 अक्टूबर, 1933 ई० को उनके अग्रज बिट्ठल भाई का यूरोप में देहान्त हो गया। लोगो ने आग्रह किया कि उनका अन्तिम सस्कार सरदार के हाथों होना चाहिए लेकिन जेल से छूटने की सरकार की शर्त सरदार को मजूर नहीं थी इसलिए अन्तिम सस्कार में शामिल नहीं हुए।

4 इसी बीच उनकी पुत्र वधू (डाह्याभाई की प्रथम पत्नी) का भी देहान्त हो गया।

5 15 मार्च, 1933 को सरकार ने एक श्वेतपत्र जारी करके भारत के भावी संविधान की रूप रेखा प्रस्तुत की।

जेल मुक्ति के उपरान्त 12 जुलाई, 1933 ई० को पूना में कांग्रेस कार्यकारिणी ने बैठक कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह दबाने का निर्णय किया। इस सत्याग्रह में भी सरदार पटेल बन्दी बनाये गये तथा उन्हें खान अब्दुल गफ्फार के साथ अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया गया। बीमारी के कारण 14 जुलाई, 1934 को सरदार को जेल से छोड़ दिया गया।

त्रिपुरी कांग्रेस

1938 ई० में हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते सुभाष चन्द्र बोस का चुनाव हुआ तो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया लेकिन दूसरे ही वर्ष उन्हें एक अप्रिय कर्तव्य निभाना पड़ा। 1939 ई० के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए तीन नाम सुझाये गये। 1 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 2 दूसरा सुभाष चन्द्र बोस और 3 तीसरा पट्टाभि सीता रमैया। कांग्रेस कार्यसमिति ने मौलाना आजाद के नाम का अनुमोदन करते हुए दोनों उम्मीदवारों से नाम वापस लेने का अनुरोध किया। चुनाव अवश्य भावी देखकर मौलाना आजाद ने अपना नाम वापस ले लिया तो कांग्रेस कार्यकारिणी ने पट्टाभि सीता रमैया के नाम का प्रस्ताव किया। और सुभाष बाबू से नाम वापस लेने की विनती की। जिसे सुभाष बाबू ने ठुकरा दिया। अतएव कांग्रेस के आज तक के इतिहास में पहली बार चुनाव होने का मौका आया। ऐसी स्थिति में सरदार पटेल ने एक वक्तव्य निकालकर कहा कि, “कांग्रेस में यह परम्परा चली आ रही है कि किसी विशेष असाधारण परिस्थितियों के सिवा एक ही व्यक्ति लगातार दो बार कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के लिए पसन्द नहीं किया जाता। प्रश्न तो केवल बरसों से चली आ रही परम्परा का है जिसे तोड़ना जरूरी नहीं है।”³⁶ आगे उन्होंने कहा कि, “इस पद के गौरव की शोभा बढ़ाते हुए जिस ढंग से अध्यक्ष का चुनाव हमेशा सर्वसम्मति से होता है उसे ध्यान में रखकर नीति और कार्यक्रम में विरोध होने के बावजूद बाद विवाद उचित नहीं है। डॉ० पट्टाभिसीतारमैया अध्यक्ष पद के लिए योग्य व्यक्ति है इसलिए हम सुभाष बाबू से अनुरोध करते हैं कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए डॉ० सीता रमैया को सर्वसम्मति से चुनने में सहयोग करें।”³⁷ सरदार पटेल के वक्तव्य का जवाब देते हुए सुभाषचन्द्र बोस ने कहा कि—

“पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता रहा है। इस समय व्यापक मान्यता है यह है और अगले वर्ष भी संभव है कि कांग्रेस के नरम दिल के लोग सघ शासन की योजना के बारे में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर ले। ऐसी परिस्थिति में यह बहुत जरूरी है कि कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जो पूरे दिल से सघ शासन

३६ पटेल, ईश्वर भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आनन्द, 1974, पृ० 159

३७ पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई भाग - दो, अहमदाबाद, 1956, पृ० 512

का विरोध करने वाला हो, ऐसा कोई दूसरा उम्मीदवार मिल जाय तो मुझे अध्यक्ष बनने की कोई अभिलाषा नहीं है।”³⁸

सुभाष बाबू के उत्तर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि मुझे दुःख इस बात का है कि सुभाष बाबू हम लोगो पर जो आरोपण कर रहे हैं उसके जबाब में “मैं इतना ही कहूँगा” कि मैं किसी ऐसे सदस्य को नहीं जानता जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की सघ शासन की योजना का समर्थक हो।”³⁹ मैं इस विचार से भी सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष को निर्णय लेने का अधिकार है वह ऐसा कोई निर्णय कार्यसमिति की स्वीकृति से ही ले सकता है।”⁴⁰

गोंधी जी और नेहरू ने भी सुभाष बाबू को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने। परिणामस्वरूप 29 जनवरी, 1939 ई० को चुनाव हुआ जिसमें सुभाष बाबू ने गोंधी और पटेल समर्थित पट्टाभि सीता रमैया को 85 मतों से हरा दिया। पट्टाभि सीता रमैया को ८५ मतों से हरा दिया। पट्टाभि सीता रमैया की हार को अपनी हार स्वीकार करते हुए गोंधी ने इस्तीफा दे दिया और कार्यकारिणी के 15 में से 13 सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया। बीमारी के कारण सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस के खुले अधिवेशन में नहीं आ पाये इसलिए उनके स्थान पर मौलाना आजाद ने अध्यक्षता की, जिसमें कार्यकारिणी ने दो प्रस्ताव रखा जिसे गोविन्द वल्लभ पन्त ने पढ़कर सुनाया।

1 पहले प्रस्ताव में यह कहा गया कि गोंधी जी की प्रेरणा, सलाह और मार्गदर्शन से जो बल कांग्रेस ने प्राप्त किया है उसे बनाये रखने में ही सस्था का कल्याण है और

2 दूसरे प्रस्ताव में कहा गया कि गोंधी जी जिस रास्ते से पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस को चलाया है उसी रास्ते पर चलकर वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। इसलिए कार्यसमिति गोंधी जी पर विश्वास रखते हुए अध्यक्ष से निवेदन करती है कि कार्यसमिति का चुनाव गोंधी जी की इच्छा से करे।

ये दोनों प्रस्ताव सुभाष चन्द्र बोस को स्वीकार नहीं थे अतः उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद राजेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गये। इसके

३८ वही, पृ० 513

३९ वही, पृ० 513

४० पटेल, ईश्वर भाई, पूर्वो, पृ० 161

उपरान्त सुभाष बाबू प्रान्तों के मंत्रियों के कार्यों में हस्तक्षेप करके अनुशासन भंग करने का कार्य करने लगे। पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल ने उनसे ऐसा न करने की विनती की जिसे सुभाष बाबू ने अस्वीकार कर दिया। बाध्य होकर कांग्रेस कार्यकारिणी ने उन्हें “बंगाल कार्यकारिणी अध्यक्ष पद के अयोग्य घोषित कर दिया साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अगले तीन वर्ष तक वे कांग्रेस के किसी भी चुनाव को लड़ने के योग्य नहीं हैं।”⁴¹ इसके उपरान्त सुभाष बाबू ने कांग्रेस से अलग होकर फारवर्ड ब्लाक नामक पार्टी का गठन किया और कांग्रेस के विरुद्ध खुला प्रचार किया।

सुभाष चन्द्र बोस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उनके समर्थकों ने सरदार पटेल को जिम्मेदार ठहराया। जिसका कारण बताते हुए डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि-

“सरदार साफ-साफ बात करने वाले व्यक्ति थे। मीठी-मीठी बातें करके किसी को खुश करने की कला उन्होंने नहीं सीखी थी।”

क्रिप्स मिशन

1 सितम्बर, 1939 ई० को छिडे द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय ने बिना कांग्रेस से सलाह लिए 3 दिसम्बर, 1939 ई० को भारत को मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्धरत देश घोषित कर दिया। साथ ही वायसराय ने निम्न दो बातों की भी घोषणा की।

1 प्रथम यह कि हिन्दुस्तान में संघ शासन की स्थापना का उद्देश्य तो छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जब तक युद्ध चल रहा है तब तक इस पर किसी तरह का विचार-विमर्श नहीं किया जायेगा। और

2 द्वितीय यह कि 1935 के संविधान में यह संशोधन किया गया कि समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वायसराय जब चाहेगा, प्रान्तीय सरकार के अधिकार अपने हाथ में ले लेंगे।

वायसराय की इस घोषणा से पूरे देश में खलबली मच गयी। कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा में बैठक कर वायसराय की घोषणा के विरोध में प्रस्ताव पास किया तथा जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद एवं सरदार पटेल की उपसमिति बनाई ताकि ये लोग समयानुकूल अन्य कार्यकर्ताओं को कोई सुझाव दे सकें। उपसमिति ने प्रांतीय सरकारों को त्यागपत्र देने की सलाह दी फलतः सभी प्रान्तों की सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया।

इसी बीच जापान भी युद्ध में जर्मनी की ओर से शामिल हो गया। जापान के युद्ध में शामिल होने से धुरी राष्ट्रों की ताकत एकाएक बढ़ गयी। जापानी सेनाये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसने सिंगापुर, मलाया आदि पर अधिकार कर लिया और वह भारत की सीमाओं तक पहुँच आयी तथा कुछ बम कलकत्ता में गिराये। इस प्रकार युद्ध में इंग्लैण्ड की स्थिति नाजुक होती गयी।

अब भारतीय नेताओं की मनोवृत्ति देखकर अमेरिका, चीन एवं अन्य मित्र राष्ट्रों ने चर्चिल पर भारतीयों की सहायता प्राप्त करने के लिए दबाव डाला। तो चर्चिल ने कूटनीति का सहारा लेते हुए भारत के मित्र समझे जाने वाले तथा उसकी स्वतंत्रता के समर्थक सर स्टेफर्ड क्रिप्स को समझौता करने के लिए एक प्रस्ताव के साथ भारत भेजा।

23 मार्च 1942 ई० को क्रिप्स भारत आये। भारत में तीन सप्ताह प्रवास के दौरान उन्होंने महात्मा गाँधी, सरदार पटेल सहित तमाम राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की। तत्पश्चात् समस्या का वैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट की ओर से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे क्रिप्स योजना के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का सारांश निम्न था।

- 1 भारत को तत्काल औपनिवेशिक दर्जा दे दिया जायेगा, जो किसी अन्य ब्रिटिश उपनिवेश से दर्जे में कम न होगा।
- 2 युद्ध समाप्ति के उपरान्त एक संविधान सभा का निर्वाचन सभी दलों की सहमति से किया जायेगा।
- 3 पहले प्रान्तीय धारा सभा सदस्यों का चुनाव किया जायेगा और फिर वह संविधान सभा का चुनाव करेगी।
- 4 देशी रियासतों को भी अपनी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा।
- 5 ब्रिटिश सरकार संविधान सभा के निर्णयों को स्वीकार करने का उत्तरदायित्व लेगी किन्तु उसमें निम्नलिखित बातों का समावेश करना होगा।
 - (i) किसी भी प्रान्त या देशी रियासत को संघ से पृथक होने का अधिकार होगा। तथा
 - (ii) ब्रिटिश सरकार से एक सन्धि द्वारा उसके द्वारा दिये हुए वचनों का सम्मान करना होगा।

- 6 भारत का सेना विभाग युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार के निरीक्षण में कार्य करेगा और शेष विभाग लोक प्रतिनिधियों के हाथ में होंगे।

क्रिप्स के उपरोक्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में हुई जो तीन दिनों तक चली। काफी विचार विमर्श के बाद उपरोक्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। गान्धी जी की उपस्थिति में कार्यसमिति ने सर्वाधिक आपत्ति रक्षा विभाग के संबंध में की। 2 अप्रैल, 1942 ई० को पास किये हुए अपने प्रस्ताव को 11 अप्रैल, 1942 ई० को प्रकाशित करते हुए कांग्रेस कार्यसमिति ने क्रिप्स मिशन को असफल घोषित कर दिया। क्रिप्स मिशन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि—“क्रिप्स मिशन तो एक खोटा सिक्का था। उसे बनाने वाले की नीयत खराब थी। उसमें अप्रामाणिकता एवं धोखेबाजी थी। जाते-जाते क्रिप्स खुद ही बदल गये और उसका दोष कांग्रेस के मध्ये मढ़ गये। यह सारा मिशन अमेरिकी लोकमत को खुश करने के लिए नियोजित किया गया था।” आगे उन्होंने कहा कि “क्रिप्स मित्र भाव से हलाहल भरा हुआ विष प्रस्ताव के रूप में लाये थे। इसके जैसी झूठी और धोखेबाज योजना आज तक कोई नहीं आई। इस योजना में ऐसी प्रपंचपूर्ण सुविधा छिपी हुई है कि युद्ध के उपरान्त भारत में ब्रिटिश सत्ता कायम रहे।”

भारत छोड़ो आन्दोलन

क्रिप्स मिशन की विफलता ने देश को राजनीति में एक गतिरोध पैदा कर दिया। कांग्रेस के समक्ष जापानी आक्रमण से देश की रक्षा करने की विकट समस्या उत्पन्न हो गयी। जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था उसने हांगकांग, मलाया और सिंगापुर पर अधिकार करने के उपरान्त वर्मा पर भी अधिकार कर लिया तथा भारत के कोकानाडा और विशाखापट्टनम पर बम गिराये। ब्रिटिश सरकार इन स्थानों और अन्य संभावित स्थानों जहाँ आक्रमण का भय था जनता को हटाने लगी। ऐसे में गान्धी जी तथा कांग्रेस कार्यसमिति के लिए जनता की रक्षा का प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया। एक साम्राज्य से संघर्ष करते-करते मुक्ति नहीं मिली और दूसरे के आने की आशा बलवती हो गयी। देश का भविष्य अन्धकार में हो गया। अब गान्धी जी के विचारों में परिवर्तन आ चुका था। 26 अप्रैल, 1942 को ‘हरिजन’ में लिखा कि देश में अंग्रेजों के बने रहने से जापानियों को हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का प्रोत्साहन मिलता है अतः देश के सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि “अंग्रेज

तत्काल व्यवस्थित रूप से इस देश को छोड़ दे।⁴² इसके बाद समस्या पर विचार करने हेतु 27 अप्रैल से 2 मई तक इलाहाबाद में कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई। इस बैठक में महात्मा गाँधी नहीं आये लेकिन उन्होंने अपना सन्देश भेजा। जिसमें भारत की स्वतंत्रता के लिए इसे ईश्वर के सहारे छोड़ देने की बात कही ताकि वह स्वयं अहिंसा के मार्ग से स्वतंत्रता ले सके। इस बैठक में “सरदार पटेल ने अंग्रेजों चले जाओ का प्रस्ताव रखा”⁴³ जिस पर नेहरू और मौलाना आजाद ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। अतः मतभेद होते हुए इस सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव पारित किये गये।

- 1 ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से देश छोड़ दे।
- 2 ब्रिटिश साम्राज्य के कारण भारत युद्ध क्षेत्र बन गया है।
- 3 इस देश की स्वतंत्रता के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है।
- 4 यदि जापान आक्रमण करता है तो उसका अहिंसा से प्रतिकार किया जायेगा।
- 5 भारत का किसी देश के साथ झगडा नहीं है।⁴⁴

इस प्रकार गाँधी जी द्वारा प्रस्तावित अधिकांश बातें स्वीकार कर ली गयीं। इसके उपरान्त 6 जुलाई, 1942 ई० को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक वर्धा में हुई जो नौ दिन के लम्बे समय तक जारी रही। इस बैठक में “एक लंबा प्रस्ताव पारित किया गया जिस पर सदस्यों में कोई मतभेद नहीं था।”⁴⁵ वर्धा में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि “न केवल भारत के हित में अपितु सम्पूर्ण विश्व की रक्षा हेतु और नाजीवाद, फासीवाद, सैन्यवाद या किसी अन्य प्रकार की साम्राज्यवादी शक्ति से बचने के लिए, मलाया और सिंगापुर आदि के अनुभवों से बचने के लिए केवल भारत की स्वतंत्रता ही एक मात्र रास्ता है। और इसी से भारत अन्य देशों या सम्पूर्ण विश्व की जनता हेतु स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सहयोग कर सकेगा। इसी के साथ अन्य विभिन्न प्रस्तावों के बाद यह भी स्पष्ट किया गया कि स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण अथवा हर क्षेत्र में स्वतंत्रता होगी अन्त में यह कहा गया कि यदि यह उपरोक्त अपील असफल रही तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर संघर्ष करेगी और इस संघर्ष में अहिंसक रूप

४२ दि इण्डियन एन्युअल रजिस्टर, भाग-एक, 1942, पृ० 237 से 254

४३ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 84

४४ पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई, भाग-दो, अहमदाबाद, 1956, पृ० 616-17

४५ वही, पृ० 626

से चलाये गये 1920 से अब तक के समस्त सघर्षों का समावेश होगा। 7 अगस्त, 1942 ई० को विचार हेतु महासमिति पुन बम्बई में मिलेगी।⁴⁶ इतना करके महासमिति स्थगित हो गयी।

वर्धा अधिवेशन के बाद सरदार पटेल ने निश्चित रूप से यह मान लिया था कि अब ब्रिटिश सरकार के साथ जीवन मरण का संग्राम होना अनिवार्य है। अतः जनता को जागृत करने हेतु वर्धा से वे सीधे अहमदाबाद गये और 26 जुलाई, 1942 ई० को लोकल बोर्ड के मैदान पर एक लाख जनसमूह को सम्बोधित करते हुए 'अग्रेज चले जाओ' की रूपरेखा बतायी। आन्दोलन के कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि,—

“ऐसा समय फिर नहीं आयेगा। आप अपने मन से भय निकाल दें। यह प्रसंग फिर नहीं आयेगा। उन्हें यह कहने का अवसर न दें कि गाँधी जी अकेले थे। जब वे 74 वर्ष की आयु में आन्दोलन का भार उठाने के लिए निकल पड़े हैं तब हमें समय का विचार करना चाहिये। आपसे माँग की जाय या न की जाय, समय आये या न आये परन्तु आपके लिए कुछ पूछने की बात नहीं रह जाती। अब कार्यक्रम क्या है यह पूछकर बैठें मत रहिये। 1919 के रोलेट एक्ट के विरोध से लेकर आज तक जितने भी कार्यक्रम रहे हैं उन सबका समावेश इसमें हो जायेगा। कर मत चुकाओ आन्दोलन, कानून भंग और इसी तरह दूसरी लड़ाइयाँ, जो सीधे रूप से सरकारी शासन से बन्धन तोड़ने वाली हैं उन्हें कांग्रेस अपना लेगी। रेलवे वाले रेल बन्द करके, तार वाले तार विभाग बन्द करके, डाकखाने वाले डाक का काम छोड़कर, सरकारी नौकर नौकरियाँ छोड़कर और स्कूल कॉलेज बन्द करके सरकार कि तमाम यंत्रों को स्थगित कर दें। यह लड़ाई इस किस्म की होगी। इसमें आप सब भाई साथ दीजिये। इस लड़ाई में आपका हार्दिक सहयोग होगा तो यह लड़ाई थोड़े ही दिन में खत्म हो जायेगी और अग्रेजों को यहाँ से चले जाना होगा। काम करने वालों को सरकार पकड़ भी ले, तो भी हर एक हिन्दुस्तानी अपने आप को कांग्रेसी समझे और उसी तरह अपना फर्ज अदा करे और पुकार होते ही लड़ने को तैयार हो जाय तो स्वतंत्रता दरवाजा खटखटाते हुए आकर खड़ी हो जायेगी।”⁴⁷

४६ वही, पृ० 626-628

४७ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 86

28 जुलाई को सरदार पटेल ने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दिया इसके बाद अहमदाबाद के कालेज विद्यार्थियों को भी इस आन्दोलन की रूपरेखा से परिचित कराया। 30 जुलाई को महिलाओं की एक सभा में इस पर प्रकाश डालकर आन्दोलन के पक्ष में माहौल तैयार करने का कार्य किया।

देश की सम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि, “इस लड़ाई में भाग लेने का सभी धर्म के लोगों का कर्म है जिन्होंने हिन्दुस्तान में जन्म लिया है।” उन्होंने सभी धर्म और जाति के लोगों से आन्दोलन में शामिल होने की अपील की। मुसलमानों के बारे में विशेष रूप से विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि “मुसलमान यह समझ ले कि यह लड़ाई कांग्रेस या हिन्दुओं के लिए सत्ता लेने की नहीं अपितु गुलामी नष्ट करने के लिए है।” आपसी विवादों को हम लोग बैठकर सुलझा लेंगे, ऐसा होगा तभी आजादी मिलेगी। यदि यह चाहे कि अंग्रेजों के रहते समझौता हो जायेगा तो हरगिज ऐसा सम्भव नहीं होगा क्योंकि वे समझौता न होने देने के लिए ही बैठे हैं।”⁴⁸

पहली अगस्त को सरदार अहमदाबाद से बम्बई चले गये जहाँ पर उन्होंने 2 अगस्त, 1942 ई० को चौपाटी में भाषण देते हुए कहा—“आपको यह समझकर लड़ाई छेड़नी होगी कि महात्मा गाँधी और नेताओं को पकड़ लिया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो आपके हाथ में ऐसी ताकत है कि 24 घंटे में शासन खत्म हो जाय।”⁴⁹ अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए सरकार पटेल ने आरोप लगाया “कहा जाता है कि ब्रिटेन और अमेरिका लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं मगर इनके लोकतंत्र का अर्थ है काले लोगों को लूटना। यह लूट के बँटवारे की लड़ाई है।”⁵⁰ ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्युनिस्टों पर से प्रतिबन्ध हटाकर उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने की भी सरदार ने आलोचना की और कहा कि वह आशा करते हैं कि कम्युनिस्ट देश भक्ति का सच्चा प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।”⁵¹ कांग्रेस की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि “जिस दिन हिन्दुस्तान आजाद हो जायेगा, उस दिन कांग्रेस अपने आप विसर्जित हो जायेगी। उस दिन कांग्रेस का नाम पूरा हो जायेगा। कांग्रेस अपने लिए नहीं अपितु देश के लिए सत्ता माँगती है।”

४८ पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918-1947), अहमदाबाद, 1950 पृ० 516

४९ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 87

५० मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 112

५१ द्वितीय, विश्वयुद्ध को कम्युनिस्टों ने ‘लोक युद्ध’ कहकर अंग्रेजों का साथ दिया

पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार 7 एव 8 अगस्त को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बम्बई में की गयी जिसमें महात्मा गान्धी ने 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 7 अगस्त को अपने भाषण में सरदार पटेल ने अहिंसा द्वारा अंग्रेजों को भारत छोड़वाने की। वकालत की उन्होंने कहा "लडाई में हमारा कार्यक्रम हमेशा गान्धी जी ने तैयार किया है जब तक वे बैठे हैं हुक्म देगे वही हम मानेंगे।" सरदार ने गान्धी जी की गिरफ्तारी के बारे में चेतावनी देते हुए कहा "अगर सरकार गान्धी जी को पकड़ लेती है तो हम सब भारतीयों का यह फर्ज होगा कि तुरन्त आजादी हासिल करने के लिए उसे जो समझ में आये वही कर डालें।"

"भारत छोड़ो" आन्दोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्यसमिति में जवाहर लाल नेहरू ने रखा तथा सरदार पटेल ने उसका समर्थन किया। इस प्रस्ताव के विरोध में कुल 13 मत पड़े। कम्युनिस्टों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। 8 अगस्त को मध्यरात्रि में महासमिति ने कहा अंग्रेजों चले जाओ और यदि न जाय तो उनके विरुद्ध अहिंसक परन्तु प्रचण्ड और देशव्यापी विद्रोह छेड़ दिया जाय। इस पर बम्बई पुलिस ने मध्य रात्रि को ही (8 अगस्त) बम्बई के समस्त टेलीफोन काट दिये। इसके उपरान्त गान्धी और पटेल सहित 14 सदस्यों को जोशीले भाषण के आरोप में (9 अगस्त को प्रातः) गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में बन्द कर दिया गया। महात्मा गान्धी अपनी गिरफ्तारी के समय 'करो या मरो' को नारा दिया। महात्मा गान्धी की आगा खॉ जेल में रखा गया।

वल्लभ भाई को अहमदनगर किले में 9 अगस्त की दोपहर को बहुत गुप्त तरीके से ले जाया गया। लगभग तीन सप्ताह तक उनको बाध्य सत्तार के सम्पर्क से दूर रखा गया। सरदार पटेल को जब गिरफ्तार किया गया उस समय उनकी पुत्री मणि बहन तथा कांग्रेस के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी श्री जे०बी० कृपलानी भी सरदार के साथ गिरफ्तार हुए। मणि बहन को सरोजनी नायडू के साथ यरवदा जेल में रखा गया। इस बीच सरदार पटेल के पुत्र "डाह्या भाई ने इस अवसर पर दिये गये गान्धी और पटेल को भाषणों के प्रतियों छपवाकर व्यापक रूप से जनता के मध्य वितरित किया तथा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य किया।"⁵² जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने डाह्या भाई

को भी (19 नवम्बर, 1942 ई० को) गिरफ्तार कर लिया। “दोनों भाई बहनों को सरकार ने बिना मुकदमा चलाये लगभग दो वर्षों तक नजरबंद रखा।”⁵³

“अहमदनगर जेल में सरदार पटेल के साथ अन्य बन्दियों में जवाहर लाल नेहरू, डॉ० हरेकृष्ण महताब, शंकर राव देव, प्रफुल्ल बाबू, गोविन्द वल्लभ पटेल, डॉ० सैयद महमूद, आसफ अली, मौलाना आजाद, जे०बी० कृपलानी, नरेन्द्र देव और डॉ० पट्टाभि सीता रमैया थे।⁵⁴ जेल में अक्सर ये सभी आन्दोलन के विषय में चर्चा कर रहे थे। इस लम्बे कारावास में आँतों के पुराने रोग ने उन्हें अत्यधिक कष्ट दिया। 1943 की गर्मियों तक उनका वजन 20 पाउंड तक घट गया।⁵⁵ इसके बावजूद भी सरकार ने उन्हें जेल से मुक्ति नहीं दी। 25 जून 1945 को वायसराय ने सभी पक्षों की शिमला में एक परिषद् बुलाई। परिषद् में भाग लेने हेतु जेल में बन्द सरदार पटेल सहित सभी नेताओं को 15 जून, 1945 को मुक्त कर दिया गया। गाँधी जी की बीमारी के कारण पहले ही 6 मई, 1945 को रिहा कर दिया गया था। सरदार जब जेल में थे तो निम्न प्रमुख राजनैतिक घटनाएँ घटित हुईं।

1 20 अक्टूबर, 1943 को लॉर्ड बेवेल, लिनलिथगो के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल बने।

2 9 से 27 सितम्बर, 1944 तक महात्मा गाँधी ने जिन्ना से राजगोपालाचारी फार्मूले पर असफल वार्ता की।

3 गाँधी-जिन्ना वार्ता की असफलता के बाद समस्या के समाधान हेतु तेजबहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक निर्दलीय समिति गठित की गई। जिसका सहयोग करने से जिन्ना ने इकार कर दिया। अप्रैल, 1945 ई० में इस समिति ने देश विभाजन को अस्वीकार कर दिया।

4 जनवरी, 1945 ई० में अन्तरिम सरकार के गठन के सबंध में लियाकत अली और झूलाभाई देसाई के मध्य समझौता हुआ। जिसे देसाई-लियाकत अली समझौते के नाम से जाना जाता है। जेल में बन्द कांग्रेसी नेताओं ने इस समझौते का विरोध किया।

5 मई, 1945 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया।

५३ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 90

५४ वही, पृ० 90

५५ वही, पृ० 93

शिमला सम्मेलन

14 जून, 1945 ई० को वायसराय लॉर्ड बेवेल ने अपने एक ब्राडकास्ट भाषण में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए और अन्तरिम सरकार के गठन के लिए शिमला में एक सम्मेलन करने की घोषणा की। उनका प्रस्ताव था कि वायसराय की कार्यकारिणी में “कास्ट हिन्दू (सर्वर्ण हिन्दू) और मुसलमानों की बराबर-बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाय।”⁵⁶ तथा वायसराय के प्रधान सेनापति के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय थे। वैदेशिक कार्य भी भारतीयों को दे दिया जायेगा। कार्यकारिणी वर्तमान विधान के अधीन ही कार्य करती रहेगी जब तक कि नया विधान न बन जाय। वायसराय केवल वैधानिक प्रमुख बना रहेगा।

17 जून, 1945 को सरदार पटेल ने कास्ट हिन्दू शब्द पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा “यदि यह शर्त रही तो सम्मेलन में कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस कोई वर्गीय संगठन नहीं है।”

वायसराय के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक मौलाना अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में बम्बई में हुई। 21 व 22 जून को सम्पन्न इस बैठक में निर्णय लिया कि 25 जून, 1945 ई० को प्रस्तावित वायसराय की (शिमला) बैठक में कांग्रेस शामिल होगी।

25 जून, 1945 ई० को सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन के पहले ही दिन जिन्ना के इस वक्तव्य से सम्मेलन की सफलता सदिग्ध हो गई कि—“कांग्रेस 10 प्रतिशत हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती है जबकि मुस्लिम लीग 90 प्रतिशत या उससे अधिक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है।” तथा यह कहना गलत है कि कांग्रेस का समस्त समुदायों पर प्रभाव है।”⁵⁷ 27 जून को जिन्ना ने वायसराय से स्पष्ट कह दिया कि वह केन्द्रीय कार्यपालिका में किसी अन्य दल के मुसलमान को स्वीकार नहीं करेंगे। अतः कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद 29 जून की स्पष्ट हो गया।

30 जून 1945 ई० को सरदार पटेल ने अपने भाषण में कहा कि, “कांग्रेस अपना राष्ट्रीय स्वरूप नष्ट नहीं कर सकती और न ही वह अपने सम्पूर्ण देश के प्रतिनिधित्व के दावे से पीछे हट सकती है। जिन्ना भले ही दावा करे कि देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व

५६ बाम्बे, कार्मिकल, 18 जून, 1945

५७ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली, 1997,

मुस्लिम लीग करती है। कांग्रेस ऐसे दावों को मानने की बजाय अलग रहा ही पसंद करेगी।⁵⁸ कांग्रेस लीग गतिरोध के कारण 28 जून, 1945 को 15 दिन के लिए स्थगित सम्मेलन पुनः 14 सितम्बर, 1945 को शुरू हुआ। कांग्रेस ने अपने द्वारा दिये गये नामों में सभी दलों के नाम दिये थे जबकि मुस्लिम लीग ने कोई नाम देने से इन्कार कर दिया। वायसराय ने इस पर सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए भग कर दिया।

कैबिनेट मिशन

भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लारेन्स ने ब्रिटिश लोक सदन से घोषणा की कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने भारत के वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन नामक प्रतिनिधिमण्डल भेजने का फैसला किया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि "भारतीय समस्या का हल करने के लिए यह ब्रिटिश सरकार का अंतिम प्रयास है।"⁵⁹ सरदार का तर्क था कि "भारतीय समस्या का एकमात्र हल सत्ता का तत्काल हस्तान्तरण है। इस कार्य में जितना विलम्ब होगा, मुस्लिम लीग उतनी ही मार्ग में बाधक बन जायेगी।"⁶⁰ सरदार के अनुसार सत्ता हस्तान्तरण में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य होंगी। "भारत जैसे विशाल देश में सत्ता का हस्तान्तरण एक कठिन कार्य है। इसके क्रियान्वयन में कुछ स्थानों पर झगड़ों को गम्भीरता से नहीं लेना चाहिये।"⁶¹

इसके पूर्व जनवरी, 1946 ई० में पटेल ने घोषणा की थी कि साम्प्रदायिक झगड़ों का भ्रम कांग्रेस को उसके लक्ष्य तक पहुँचने से नहीं रोक सकता। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि—

"यदि पाकिस्तान का निर्माण किया जाता है तो इससे हिन्दू व मुसलमान के झगड़े बढ़ेंगे। गृह युद्ध भी हो सकता है।"⁶² मुस्लिम लीग के नेता खलील उल जमा की नजरों में यह धमकी सरदार पटेल ने ब्रिटिश सरकार को भ्रम में डालने के लिए दी।

५८ वही, पृ० 115

५९ बाम्बे, क्रानिकल, 23 मार्च, 1946

६० वही,

६१ वही,

६२ दि टाइम्स ऑफ इंडिया, 15 जनवरी, 1946 (अहमदाबाद में 14 जनवरी, को दिया गया भाषण)

12-15 मार्च, 1946 ई० को कांग्रेस ससदीय दल ने कैबिनेट मिशन से वार्तालाप हेतु एक तदर्थ समिति नियुक्त की जिसके सदस्य सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरू और मौलाना आजाद बनाये गये। एक प्रेस कान्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि "कांग्रेस तत्काल सत्ता हस्तान्तरण चाहती है यद्यपि वह अल्पसंख्यकों की उचित माँगों की सुरक्षा का वचन देती है लेकिन जिन्ना के भारत विभाजन की माँग को स्वीकार नहीं करती।"⁶³ उन्होंने कहा कि देश विभाजन की माँग स्वीकार करने से पंजाब और बंगाल के हिन्दू और सिक्खों के लिए घातक होंगे और देश की सुरक्षा संकट में पड़ जायेगी।⁶⁴ सरदार पटेल ने कहा कि कांग्रेस दो आधारों पर कैबिनेट मिशन से वार्ता करेगी।

1 प्रथम अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर सत्ता का अधिकार और इसके साथ ही सरदार पटेल ने "अन्तिम सरकार के गठन का समर्थन किया और कहा कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन से अच्छे व्यवहार की आशा रखती है।" सरदार पटेल की इस सक्रियता पर उनकी आलोचना करते हुए गाँधी जी ने कहा कि वह कांग्रेस में एक शक्तिशाली व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सरदार पटेल ने इसकी चिन्ता नहीं की।

इसी बीच 23 मार्च, 1946 ई० को सर स्टैफर्ड क्रिप्स, मि० ए० वी० एलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लारेन्स कैबिनेट मिशन के सदस्य की हैसियत से भारत आये। कैबिनेट मिशन ने 23 मार्च से लेकर 12 मई, तक कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य राजनैतिक दलों से गहन मन्त्रणा की। किन्तु किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाये। अतएव मिशन ने 16 मई, 1946 को एक वक्तव्य निकालकर निम्न प्रस्ताव किये।

1 ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाय जिसके हाथ में विदेशी मामले, रक्षा तथा आवागमन के साधन हों। उसको उन विभागों पर अपना व्यय निकालने के लिए कर लगाने का भी अधिकार हो।

2 संघ की एक कार्यकारिणी तथा धारा सभा हो जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य दोनों के प्रतिनिधि हों।

3 शेष सभी विषय प्रान्तों के पास रहेंगे।

६३ दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 23 मार्च, 1946

६४ वही,

4 प्रान्तों को अपने गुट बनाने का अधिकार होगा वह चाहे तो अपने वर्ग की सरकार तथा धारा सभा भी बना सकेंगे।

5 10 वर्ष बाद इस विभाग पर दुबारा विचार किया जायेगा।

6 सविधान सभा का निर्वाचन प्रान्तीय धारा सभाओं के नवनिर्वाचित सदस्य इस प्रकार करेंगे कि 10 लाख जनसंख्या का एक प्रतिनिधि होगा। प्रान्तों के प्रतिनिधियों की संख्या उनके जनसंख्या के अनुपात में होगी। प्रत्येक सम्प्रदाय को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा।

7 हिन्दू, मुस्लिम और सिख केवल यही तीन सम्प्रदाय स्वीकार किये जायेंगे।

8 मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों तथा परिगणित क्षेत्रों के सबंध में पृथक-पृथक उपसमितियों विचार करेंगी।

9 केन्द्र में अविलम्ब एक राष्ट्रीय अस्थायी सरकार की स्थापना की जायेगी। उपरोक्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गयी जिसमें कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया जा सका। अपने प्रस्ताव में कांग्रेस ने कहा "पूरी स्थिति के अभाव में कांग्रेस इस समय कोई अंतिम निर्णय लेने में असमर्थ है।"⁶⁵ सरदार पटेल ने समिति की बैठक में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "उनकी नजर में इस योजना से देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। वह यह अनुभव करते हैं कि यदि मुस्लिम लीग को अन्तरिम सरकार में मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया तो ऐसी सरकार किसी भी प्रकार नहीं चल सकती।"⁶⁶

जिन्ना ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को इस विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस उसे अस्वीकार कर देगी अतएव शासन तंत्र उसके हाथ में रहेगा। सरदार पटेल जिन्ना की नीयत समझ गये अतः इसके उपरांत वे वार्तालाप में दिलचस्पी के साथ अंतिम रूप से भाग लेने लगे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य मुख्य विवाद सरकार के गठन को लेकर था। मुस्लिम लीग समानता पर बल देते हुए 5 सदस्य कांग्रेस के और 5 मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल में शामिल करने पर बल दे रही थी। जबकि कांग्रेस (5 5 2) के सिद्धान्त

६५ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 104

६६ वही, पृ० 104

की विरोधी थी। सरदार पटेल ने अपना विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि “जिन्ना का उद्देश्य देश को विभाजित करके इतिहास में पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध होने का है।”⁶⁷ बेवेल ने सरदार पटेल को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन ने उन्हें सतुष्ट नहीं कर पाये अतः ये वार्ता असफल हो गयी।

सरदार के साथ वार्ता असफल हो जाने के बाद वायसराय ने 16 जून, 1946 ई० को आन्तरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी। जिसमें 14 सदस्यीय मन्त्रिमण्डल के निर्माण की बात कही गयी। इन सदस्यों में कांग्रेस के 6 (जिसमें एक दलित प्रतिनिधि भी होगा) मुस्लिम लीग को 5, सिक्ख 1, भारतीय ईसाई 1 और पारसी 1 होंगे। वायसराय ने आन्तरिम सरकार के सदस्यों के नामों की भी घोषणा कर दी। साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी एक दल की असहमति होने पर भी आन्तरिम सरकार का गठन किया जायेगा जिसमें उन लोगों को सम्मिलित किया जायेगा जो 16 जून की योजना स्वीकार करते हैं। 9 जून से 25 जून को अपनी बैठक में कांग्रेस ने अपना दृढ़ निश्चय प्रगट किया कि एक राष्ट्रीय मुसलमान भेजने को कांग्रेस का अधिकार है और यह अधिकार छोड़ा नहीं जायेगा। 23 जून को वायसराय ने सरदार पटेल को सुझाव दिया कि वह राष्ट्रीय मुसलमान को शामिल करने पर बल न दे। इस पर सरदार ने कहा कि “ऐसा करने पर मुसलमान कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे जिससे साम्प्रदायिक समस्या हल करने में जिन्ना को वीटो का अधिकार मिल जायेगा।”⁶⁸ इस प्रकार इस बैठक में कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय चरित्र का बलिदान करने का निर्णय नहीं लिया साथ ही संविधान सभा में जाकर स्वतंत्र और अखण्ड भारत के संविधान को बनाना स्वीकार कर लिया।”⁶⁹

“24 जून को सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा सुधीर बोस ने मिशन के तीनों मंत्रियों के साथ भगी बस्ती में गाँधी जी के साथ इस विषय पर मन्त्रणा की। सोमवार का दिन होने के कारण वार्ता लिखकर हुई जिसकी सारी चिट्ठे सुधीर दास के पास सुरक्षित रखी गयी।” 26 जून 1946 को काफी सोच-विचार के बाद कांग्रेस ने 16 जून के प्रस्तावों को अस्वीकार

६७ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार दिल्ली, 1997, पृ० 123

६८ वही, पृ० 123

६९ पाण्डेय, बी०एन०, सेलेक्टेड डाक्यूमेण्ट्स, खण्ड 7, मैकमिलन, 1979, पृ० 195

करके भी सविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लगभग तीन माह बाद यह मामला शांत हुआ और कैबिनेट मिशन वापस चला गया।⁷⁰

6 जुलाई 1946 ई० को बम्बई में कार्य समिति की बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेहरू ने अपने समापन भाषण में राज्यों के समूहीकरण के सबंध में ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जिससे समस्या और गम्भीर बन गयी। नेहरू ने कहा कि—“प्रान्तीय असेम्बली की मजूरी की योजना का अर्थ केवल इतना है कि हम सविधान निर्मात्री सभा में प्रवेश को इच्छुक हैं इसके सिवा कुछ नहीं है।” एक प्रेस वक्तव्य में नेहरू ने कहा— हम असेम्बली में जाकर क्या करेंगे इस विषय पर हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। सरदार पटेल ने नेहरू के प्रान्तीय वर्ग संबंधी भाषण को भावात्मक मूर्खता की सजा दी। सरदार पटेल ने कहा कि मेरी राय में कोई भी प्रान्त अपनी प्रान्तीय स्वायत्ता को त्यागने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि यह मानवीय प्रकृति के विरुद्ध है।⁷¹

नेहरू के वक्तव्य पर जिन्ना ने उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 27 जुलाई, 1946 को वासयराय पर कांग्रेस के हाथों खेलने का आरोप लगाया और मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके पहले कैबिनेट मिशन को दी गयी स्वीकृति वापस ले ली। 2 अगस्त के 13 अगस्त 1946 की कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक वर्धा में हुई। “इस समिति की बैठक में सरदार पटेल ने सिखों से सविधान सभा के वहिष्कार न करने की अपील की। सिख पथ ने सरदार पटेल की अपील को स्वीकार कर लिया।”⁷² इसी बीच 12 अगस्त, 1946 ई० को वासयराय ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू को अन्तरिम सरकार बनाने का आमत्रण दिया। कांग्रेस कार्यसमिति ने इस आमत्रण को स्वीकार करने का अधिकार जवाहर लाल नेहरू को दे दिया तथा इस विषय पर भावी कार्यवाही के लिए जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और राजेन्द्र प्रसाद की एक उपसमिति बनायी गयी।

७० शास्त्री, आचार्य चन्द्र शेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल (दिसम्बर 1956) सोसाइटी फॉर

पार्लियामेण्टरी स्टडीज, नयी दिल्ली, 1963, पृ०, 106

७१ लिमये, मधु, प्राइम मूवर्स, दिल्ली, 1985, पृ० 128

७२ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 107

अन्तरिम सरकार

12 अगस्त, 1946 ई० को वायसराय का सरकार गठन करने का निमन्त्रण पाने के उपरान्त तथा वर्धा कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद 16 अगस्त, 1946 ई० को जवाहर लाल नेहरू ने बम्बई में जिन्ना से मुलाकात कर मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल होने का निमन्त्रण दिया। जिसके जवाब में जिन्ना ने कहा कि वह अपनी शर्तों पर ही सरकार में शामिल होंगे। इसके पश्चात् सरकार बनाने हेतु नेहरू अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के नामों को अन्तिम रूप देने में व्यस्त हो गये। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या एवं नामों को लेकर सरदार पटेल और मौलाना आजाद के मध्य मतभेद उभरकर सामने आये। "मौलाना आजाद 6 मुसलमानों को मन्त्रिमण्डल में रखना चाहते थे। जिसमें 5 मुसलमान प्रतिनिधि की हैसियत से और 6वें वह स्वयं राष्ट्रीय मुसलमान प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होना चाहते थे। जिसका विरोध सरदार पटेल ने किया फलतः आजाद मन्त्रिमण्डल में शामिल नहीं हुए।"⁷³ "जब मौलाना आजाद मुसलमान कोटे से पाँचों नाम देने में देरी कर रहे थे तो सरदार पटेल ने कहा-यदि वे पाँच नाम न तय कर पाये तो तय किये गये तीन नाम दे देंगे। दो नामों का समायोजन बाद में कर लिया जायेगा।"⁷⁴ इस प्रकार कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में 2 दिसम्बर, 1946 ई० को अन्तरिम सरकार का गठन किया जिसमें 11 सदस्य शामिल किये गये। मन्त्रिमण्डल में शामिल सदस्यों में, 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, 3 शरत चन्द बोस, 4 राज गोपालाचारी, 5 जगजीवन राम, 6 जॉन मथाई, 7 सरदार बलदेव सिंह, 8 श्री सी० एच० भाभा, 9 आशिफ अली, 10 सर शराफत अहमद खॉं और सर सैयद जहीर थे। इनमें से जगजीवन राम अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के तौर पर, सरदार बलदेव सिंह सिख प्रतिनिधि के रूप में, जॉन मथाई भारतीय ईसाई के प्रतिनिधि के तौर पर तथा सी० एच० भाभा पारसी प्रतिनिधि के रूप में मन्त्रिमण्डल में शामिल किये गये। वल्लभ भाई को गृह के साथ सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय का भार भी सौंपा गया।

७३ पटेल, मणिबहन सरदार जी के विशिष्ट एवं अनोखे पत्र, भाग-दो, अहमदाबाद, 1976, पृ० 73 (सरदार का पत्र बाबू के नाम 20-08-46)

७४ पटेल मणिबहन, सरदार श्री के विशिष्ट एवं अनोखे पत्र, भाग दो, पृ० 74 अहमदाबाद (1976) वही, पृ०, 74

“1937 के प्रान्तीय चुनावो मे 1583 स्थानो मे से 704 स्थान जीतने वाली कांग्रेस पार्टी ने मार्च अप्रैल, 1946 मे सम्पन्न चुनावो मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए 930 सीटें जीत ली। 18 प्रान्तो मे कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला जबकि तीन प्रान्तो बंगाल मे उसकी सदस्य संख्या 52 से बढ़कर 86 पंजाब, मे 19 से बढ़कर 58 तथा सिंध मे 7 से बढ़कर 21 हो गयी।”⁷⁵ सभी प्रान्तो मे गवर्नर का दफा 93 का शासन समाप्त कर जुलाई 1946 ई० मे निर्वाचित मंत्रिमंडल बन गये। बाद मे इन्ही प्रान्तीय धारा के सदस्यो ने सविधान सभा के सदस्यो का चुनाव किया।

कांग्रेस की इस भारी सफलता से मुस्लिम लीग बिल्कुल खीझ गयी और मई 1946 ई० से ही देश के कई भागो मे साम्प्रदायिक दंगे करा दिये। 16 अगस्त को उसने पूरे भारत मे सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दौर मे बंगाल की सुहरावर्दी सरकार ने बंगाल मे खुल्लमखुल्ला दंगा कराने की प्रेरणा दी। परिणामस्वरूप चार दिनो तक कलकत्ता मे जबरदस्त साम्प्रदायिक दंगा हुआ जिसमे लगभग 4000 हिन्दुओ को मार डाला गया और करोडो की सम्पत्ति लूट ली गयी। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दुओ ने भी दंगा किया जिसमे मुसलमानो को भारी क्षति उठानी पडी। गॉंधी जी ने हस्तक्षेप कर दंगे को शान्त कराया। लेकिन 26 दिसम्बर को पुन कलकत्ता मे दंगा भड़क उठा। 23 अक्टूबर को पूर्वी बंगाल के नोआखाली स्थान पर मुसलमानो ने हिन्दुओ का कत्लेआम किया।⁷⁶ जिसका बदला लेने के लिए 26 अक्टूबर को हिन्दुओ ने मुसलमानो का कत्लेआम किया। महात्मा गॉंधी ने उपवास की धमकी देकर लोगो को रुकवाया और 6 नवम्बर को नोआखाली की यात्रा पर गये।

साम्प्रदायिक दंगो मे केन्द्रीय सरकार की अक्षमता स्वीकार करते हुए सरदार ने आरोप लगाया कि इस षडयंत्र मे ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल है। उनके अनुसार “बंगाल के गवर्नर ने बंगाल की घटनाओ को नही रोका परिणामस्वरूप लोगो ने अपनी रक्षा की बागडोर अपने हाथो मे ले ली।”⁷⁷

सरदार का आरोप था कि सरकारी अधिकारी पीछे से छूरा भोक रहे है। सरदार

७५ वहीं, पृ० 74 (बापू का पत्र सरदार के नाम 28-8-46)

७६ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 109

७७ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली 1997, पृ० 126-27

पटेल ने स्पष्ट कहा कि—“जब तक लीग जहर उगलना बन्द नहीं करेगी तब तक शान्ति नहीं हो सकती। सरकारी अफसर यदि ठीक से काम करना चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं आपसे अपील करता हूँ कि धोखे में पाकिस्तान लेने की बात मत करो। हों यदि तलवार से लेना है तो उसका मुकाबला तलवार से किया जा सकता है।”⁷⁸ सरदार ने गोंधी की बगाल की नोआखाली यात्रा पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि “बगाल में उस समय तक शान्ति नहीं स्थापित हो सकती जब तक कि मुस्लिम लीग पर न मान जाय कि उससे भी बदला लिया जा सकता है।”⁷⁹

इस बीच 13 अक्टूबर 1946 ई० को वयातराय लार्ड बेवेल तथा नवाब भोपाल के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अन्तरिम के मन्त्रिमण्डल में शामिल होने की तैयार हो गयी। मुस्लिम लीग के मन्त्रियों के लिए 15 अक्टूबर, 1946 को शरदचन्द बोस, शफात अहमद खॉ और सैयद अली जहीर ने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। वायसराय ने मुस्लिम लीग के पाँच मन्त्रियों 1 लियाकत अली, 2 चुन्दरीगर, 3 अब्दुर रब, 4 गजनफार अली और, 5 जोगेन्द्र नाथ मण्डल को 25 अक्टूबर, 1946 को मन्त्रिपद की शपथ दिलायी। मन्त्रिमण्डल में शामिल होने के लीग के ध्येय का उल्लेख करते हुए गजनफार अली ने कहा कि “यह अन्तरिम सरकार में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि हमारे अभीष्ट ध्येय पाकिस्तान के लिए वहाँ हमको पैर टिकाने का मौका मिल जायेगा।”⁸⁰ जब लीग मन्त्रिमण्डल में शामिल हुई तो बेवेल ने सुझाव दिया कि कोई महत्वपूर्ण विभाग विशेषकर गृह विभाग लीग को दे दिया जाय। मौलाना आजाद भी इस मत से सहमत थे। परन्तु सरदार पटेल ने वायसराय की सलाह मानने से इन्कार कर दिया और कहा “यदि आप लोग जिद करेंगे तो हम मन्त्रिमण्डल छोड़ देंगे पर गृह मन्त्रालय नहीं छोड़ेंगे।”⁸¹ वायसराय जानते थे कि सरदार के त्यागपत्र का अर्थ होगा सभी कांग्रेसी सदस्यों का त्यागपत्र अतः उन्होंने मुस्लिम लीग को गृह विभाग न देकर वित्त विभाग दिया। इस सदर्थ में “प्रोफेसर हुमायूँ कबीर ने आजाद के नाम अपने

७८ व्यास, दीनानाथ, वल्लभ भाई पटेल, पृ० 450

७९ मेहरोत्रा एव कपूर, पूर्वो, पृ० 127

८० ताराचन्द्र, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग-तीन, प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, 1982, पृ० 467

८१ आजाद, मौलाना, आजादी की कहानी, कलकत्ता 1965, पृ० 185

लिखे पत्र में सरदार की आलोचना की कि उन्होंने वित्त विभाग जैसा विभाग गृह विभाग के बदले मुस्लिम लीग को देने की गलती की।”⁸² किन्तु मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग ने सरदार के निर्णय की उपयुक्तता सिद्ध कर दिया। यदि गृह विभाग सरदार के पास न होता तो देशी राज्यों की समस्या का इतना जल्दी समाधान न हो पाता। मंत्रीपद सम्हालने के बाद 5 दिसम्बर को सरदार पटेल ने घोषणा की कि दफ्तर में कर्मचारी राष्ट्रीय पोशाक कुर्ता धोती पहनकर आ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की साम्प्रदायिकता के मार्ग से हटाने के लिए उन्होंने उस पर प्रतिबंध भी लगाया। गृह मंत्रालय के अलावा सरदार के पास सूचना प्रसारण विभाग भी था। मुस्लिम लीग के मंत्रियों के उन पर आरोप लगाया कि ऑल इंडिया रेडियो पर हिन्दी का अधिक प्रयोग किया जाता है तथा कांग्रेसी नेताओं की अपेक्षा लीगी नेताओं को कम समय दिया जाता है। सरदार ने इसका खण्डन किया। उन्होंने एक गुप्त व अवैधानिक पाकिस्तान रेडियो पर आपत्ति की जो प्रतिदिन अपने कार्यक्रम को प्रारम्भ तथा अन्त में पाकिस्तान जिन्दाबाद कहता था।”

3 नवम्बर, 1946 को मेरठ कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व हुए दंगों के संबंध में सरदार पटेल ने जो भाषण दिया वह अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा उसमें इतनी स्पष्टवादिता थी कि कुछ राष्ट्रीय मुसलमानों ने भी इस भाषण को बुरा माना और इस्लाम के हिमायतियों ने कहा कि ‘इस्लाम खतरे में है।’ उन्होंने नेहरू से कहा कि सरदार मुसलमानों पर संदेह करते हैं और उनके विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यों की उपेक्षा करते हैं।” किन्तु सरदार के ऊपर ऐसे अनर्गल आरोपों का कोई फर्क नहीं पड़ा और अपनी बातों को स्पष्टता और निर्भीकता से सदैव रखा।

14 फरवरी, 1947 ई० को सरदार पटेल ने लार्ड बेवेल को एक पत्र लिखकर अन्तरिम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली के लाहौर में दिये गये वक्तव्य पर रोष प्रकट किया जिसमें गजनफर अली ने कहा था कि “मोहम्मद बिन कासिम तथा महमूद गजनी ने केवल कुछ हजार सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया था और लाखों हिन्दुओं को पराजित किया था। खुदा ने चाहा तो कुछ लाख मुसलमान करोड़ों हिन्दुओं को पराजित कर देंगे। अन्तरिम सरकार में लीग और कांग्रेस के मध्य विवाद इतना तीव्र हो गया कि सरदार को

धमकी देनी पड़ी कि यदि मुस्लिम लीग के मंत्रियों को सरकार से नहीं हटाया गया तो कांग्रेस त्याग पत्र दे देगी।

अपनी उपरोक्त भावनाओं के कारण मुस्लिम लीग ने इन दिनों सम्पूर्ण देश में साम्प्रदायिकता का विष फैला रहा था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक अनुमान के अनुसार 4 मार्च, 1947 ई० तक साम्प्रदायिक दंगों में अकेले पंजाब में 2049 व्यक्ति मारे गये और 1103 भयंकर रूप से घायल हुए। बंगाल, बिहार और पंजाब आदि के साम्प्रदायिक झगड़ों से निपटने में सरदार पटेल और गाँधी जी में मतभेद रहे।

अध्याय 4

विभाजन और उसके उपरान्त भारतीय राजनीति में योगदान

- (i) विभाजन की पृष्ठभूमि
 - (ii) विभाजन और सरदार पटेल
 - (iii) विभाजन का क्रियान्वयन
 - (iv) गृहमन्त्री के रूप में प्रशासनिक सेवाओं का गठन
 - (v) देशी रियासतों का बिलीनीकरण (एकीकरण)
(बडौदा, भोपाल, जूनागढ़ एवं हैदराबाद के विशेष सन्दर्भ में)
 - (vi) संविधान निर्माण में योगदान
 - (vii) सरदार पटेल और नेहरू मतभेद
-
-

विभाजन की पृष्ठभूमि

भारत का विभाजन इस शताब्दी की महान घटनाओं में से एक है तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। विभाजन माउण्ट बेटेन योजना के तहत हुआ। 22 मार्च, 1947 ई० को लार्डमाउण्ट बेटेन भारत के गवर्नर जनरल एव वायसराय बन कर भारत आये। देश की परिस्थितियों की स्वदृष्टि से अवलोकन करने के उपरान्त उन्होंने एक योजना बनायी, जिसमें भारत की स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ-साथ उसको दो भागों में विभक्त करने का भी प्रस्ताव था। उन्होंने अपनी योजना के लिए सरदार बल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गाँधी, जिन्ना के साथ-साथ अन्य लोगों तथा कांग्रेसी नेताओं से विचार-विमर्श करके और उनकी सहमति लेकर 3 जून, 1947 ई० को घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य 15 अगस्त, 1947 ई० को अस्तित्व में आयेगे। बाद में विभाजन के साथ स्वतंत्र अधिनियम 1947 भी पारित हुआ और विभाजन के साथ भारत स्वतंत्र हुआ। भारत के लिए विभाजन अत्यन्त दुःखद प्रसंग था जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव आज तक देखने को मिलता है। भारत का विभाजन क्यों और किन परिस्थिति में हुआ तथा भारत को कांग्रेसी नेता इसे स्वीकार करने को क्यों तैयार हुए इसको समझने के लिए विभाजन के इतिहास को निम्न तीन भागों में बाँटा जा सकता है।

(1) 1933 तक का काल, (2) 1939 तक का काल, (3) 1947 तक का काल

(1) प्रथम काल 1933 तक—सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राष्ट्र के बीज इस शताब्दी के प्रारम्भ में इंग्लैण्ड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उच्चवर्गीय मुस्लिम युवा छात्र रहमती अली के विचारों से प्राप्त होते हैं। इन सुपर वर्गीय मुस्लिमों के विचार में कांग्रेस की स्थापना के बाद यदि उसके नेतृत्व में देश आजाद होता है तो शासन की बागडोर बहुसंख्यक हिन्दुओं के हाथ में चली जायेगी जो मुसलमानों पर आतंक कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों में से समीउल्ला एव आगा खॉं आदि ने मिलकर 1906 ई० में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। चूँकि मुस्लिम लीग की स्थापना कांग्रेस के समानान्तर मुस्लिमों के संगठन के रूप में की गयी इसलिए यहीं से देश विभाजन के बीज देखने को मिलते हैं।

तद् उपरान्त अंग्रेजी सरकार ने 1909 ई० के मोरले मिण्टो सुधारों में “फूट डालो और राज करो” की नीति अपनाते हुए हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग प्रतिनिधियों के चुनाव की व्यवस्था की। इस व्यवस्था में विभाजन के बीज को विकसित कर पौधा बना दिया तथा कांग्रेस और लीग के सबंधों में कटुता उत्पन्न कर दी। पर सौभाग्य से 1916 ई० में भूला भाई देसाई और लियाकत अली के मध्य सहयोग का समझौता हो गया परिणामस्वरूप प्रथम राज्य के पौधे का विकास रुक गया। इसी बीच महात्मा गाँधी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में आये जिन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। उनकी नजर में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दोनों सम्प्रदायों में सहयोग अति आवश्यक था। इसी कारण 1920 के असहयोग आन्दोलन में मो० अली जिन्ना को अपने साथ रखा तथा खिलाफत आन्दोलन में अली बन्धुओं का साथ दिया। इस समय तक कोई ऐसा मुस्लिम नेता नहीं था जो राष्ट्रीय स्तर का हो। असहयोग आन्दोलन में महात्मा गाँधी ने प्रथम बार मौलाना मोहम्मद अली को राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रचारित किया। लेकिन शीघ्र ही मौलाना की मृत्यु हो गयी। परिणामस्वरूप 1933 के काल तक बिना किसी राष्ट्रीय नेता के मुस्लिम समुदाय रहा। इस दौरान मुस्लिम लीग की भी स्थिति गौण रही।

द्वितीय काल 1933 से 1939 तक :- 1933 ई० में जिन्ना अपने चार वर्षों के विदेश प्रवास के बाद वापस भारत आये और 1934 ई० में केन्द्रीय असेम्बली में चुन लिये गये तब भी मुस्लिम समुदाय बिना राष्ट्रीय नेता के रहा। जिन्ना का आगमन देश विभाजन की दिशा में एक विशेष घटना थी। क्योंकि जिन्ना जब विदेश गये तो उसके पूर्व कांग्रेसी थे लेकिन जब वापस आये तो निश्चित तौर पर सक्रिय उच्चवर्गीय मुस्लिमों के बुलावे पर जिनका पृथक्ता का पौधा अभी पनपा था और बढ़ने का मार्ग ढूँढ़ रहा था और जिन्ना चूँकि विदेश प्रवास के दौरान साम्प्रदायिकता के रंग में रंग गये थे अतः जब वे इस वर्ग के साथ हुए तो मुस्लिम लीग का पुनरुद्धार प्रारम्भ हुआ। इस दौरान मुस्लिम लीग ने बिल्कुल से कांग्रेस विरोधी नीति अपना ली थी। ऐसे समय में जिन्ना लीग के अध्यक्ष चुने गये और विकल्प के अभाव में लम्बे समय तक अपने पद पर रहे। 1937 ई० के प्रान्तीय चुनाव में मुस्लिमों के एकमात्र राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद मुसलमानों का बहुमत उनके पक्ष में नहीं गया। “मुस्लिम लीग को कुछ सीटें संयुक्त प्रान्त में मिली वह थी जमीयत-उल-उलेमान के समर्थन के

कारण। जिसने मुस्लिम लीग को यह सोच कर समर्थन दिया था कि चुनावों के बाद मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी।”¹

चौधरी खालिकुज्जना और नवाब इस्माइल खॉं संयुक्त प्रान्त में लीग के नेता थे। जो सरकार में भागीदारी के इच्छुक थे। जवाहर लाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के एक सदस्य को मंत्री बनाने के लिए तैयार थे लेकिन मुस्लिम लीग उपरोक्त दोनों प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहती थी। उसका कथन था कि यदि दोनों की मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता तो वह सरकार में शामिल नहीं होगी। सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग के तर्क का विरोध करते हुए सरकार निर्माण में लीग का समर्थन न लेने की घोषणा की। सरदार पटेल की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग की इस अनुचित माँग के समर्थन में मौलाना आजाद ने कहा कि “यदि यह माँग मान ली जाती तो व्यावहारिक रूप से मुस्लिम लीग पार्टी कांग्रेस में लीन हो जाती।”² जिन्ना ने मंत्रिमंडल में लीग को शामिल न करने के मुद्दे को अलग राष्ट्र के निर्माण के मुद्दे से जोड़ दिया। 1937 के चुनाव के बाद बनी कांग्रेस सरकारों को पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सम्बोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि—

“प्रान्तों में सरकार निर्माण के बाद सम्पूर्ण भारत में हिन्दू मुस्लिम एकता की प्राचीन परम्परा को पुनर्स्थापित करने का यह एक अच्छा मौका है।”³

जिन्ना ने इस घटना के उपरान्त और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू हो जाने के बाद भयभीत होकर पृथक राज्य की माँग तेज कर दी। संयोग से अंग्रेजों ने भी लीग का प्रयोग अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किया तथा उसे अलग राज्य की माँग को और तीव्र करने के लिए प्रेरित किया।

तृतीय काल 1939 से 1947 तक :- सितम्बर, 1939 ई० में छिड़े द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय ने बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप प्रान्तों की कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसम्बर, 1939 ई० को ‘मुक्ति दिवस’ मनाया। भारत मंत्री जैटलैण्ड और

१ आजाद, मौलाना, आजादी की कहानी, कलकत्ता, 1965, पृ० 179

२ वही, पृ० 180

३ नन्दूरकर, जी०एम०, सरदारसँ लेटर्स मोस्टली अननोन, अहमदाबाद, 1977, पृ० 67

वायसराय जिनलित्थगो ने अपने वक्तव्यो से मुस्लिम लीग को बढावा दिया। जैटलैण्ड ने अपने वक्तव्य मे “काग्रेस को हिन्दू सगठन घोषित किया और मुस्लिम लीग को मुस्लिमो की एक मात्र प्रतिनिधि सस्था माना।”⁴

पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के नाते सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग के भ्रामक और मिथ्या प्रचार का खडन करते हुए कहा “मुक्ति दिवस की योजना केवल इसलिए की गयी की तमाम दुनिया और खासकर अग्रेज लोग यह देख ले कि भारतीयो मे एकता का पूर्ण अभाव है और हिन्दू तथा मुसलमान एक दूसरे के सख्त विरोधी है।”⁵ सरदार पटेल ने तर्क दिया कि “काग्रेस के मन्त्रीगण हटाये नही गये है अपितु सैद्धान्तिक मतभेद के कारण त्याग पत्र दिये है। यदि हम चाहते तो मुक्ति दिवस के दिन फिर मन्त्रिमण्डल की स्थापना कर सकते थे लेकिन यह काग्रेस के सिद्धान्त का सवाल था इसलिए हमने वैसा किया जैसा मतदाताओ से वादा किया था कि यदि हम अपने देशवासियो के हितो की रक्षा नही कर पायेगे तो अपने पदो से उसी समय हट जायेगे।”⁶

1929 ई० के लाहौर अधिवेशन जि सभे भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग की गयी थी के ठीक 11 वर्षो उपरान्त 1940 ई० मे मुस्लिम लीग ने जिन्ना की अध्यक्षता मे पृथक पाकिस्तान की माँग की तथा प्रत्येक मुद्दे पर काग्रेस का विरोध जारी रखा। 1940 के प्रस्तावित व्यक्ति सत्याग्रह और 942 ई० के भारत छोडो आन्दोलन का भी मुस्लिम लीग ने विरोध किया। और मुसलमानो से आन्दोलन मे सहयोग न करने की अपील की। इसके बावजूद महात्मा गाँधी जिन्ना की तरफ दोस्ती का हाथ बढा रहे थे और बार-बार उन्हे कायदेआजम की उपाधि दे रहे थे। महात्मा गाँधी द्वारा दिये जा रहे इस विशेष सम्मान का जिन्ना ने पूरा-पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया। जिन्ना ने गाँधी जी के लिए अपशब्दो का प्रयोग करते हुए जून 1942 मे लुई फिशर को लिखा “होमरूल सोसाइटी के दिनो मे गाँधी और नेहरू ने मेरे अधीन कार्य किया।”⁷

४ दि इण्डियन एन्युअल रजिस्टर, खण्ड दो, 1939, पृ० 409-418

५ व्यास, दीनानाथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पृ० 388

६ वही, पृ० 386

७ दास, एम०एन०, पार्टीसन एण्ड इण्डिपेण्डेन्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली, 1982, पृ० 62

यही नहीं जिन्ना ने पत्र में आगे महात्मा गाँधी को हिन्दू मुस्लिम एकता का शत्रु बताते हुए लिखा “जब मैं कांग्रेस का सक्रिय सदस्य था वे तो मेरा उद्देश्य हिन्दू मुस्लिम एकता था। जिसे गाँधी नहीं चाहते थे इसलिए मुझे अप्रसन्नता हुई।”⁸

सरदार पटेल गाँधी जी द्वारा लीग और जिन्ना को आवश्यकता से अधिक महत्व दिये जाने से खुश नहीं थे। 1942 ई० के आन्दोलन में गिरफ्तारी के बाद जब वे जेल में थे तो अनेक बार उन्होंने पत्रों के माध्यम से लीग व जिन्ना की खुशामदी के विरुद्ध चेतावनी दी थी। उन्होंने मौलाना आजाद की भी एक कांग्रेसी के नाते लीग के प्रति सहानुभूति की अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग की थी। इस प्रकार यदि सरदार पटेल की बात गम्भीरता से ली जाती तो जिन्ना तथा लीग के प्रति खुशामदगरी रुक जाती तो विभाजन के जो दावे जिन्ना के व्यक्तिगत रूप से पेश किये शायद न पेश न कर पाते। मुस्लिम लीग की स्थिति कर चर्चा करते हुए सरदार ने कहा कि “वह आखिर चाहती क्या है? बार-बार कांग्रेस ने यही कोशिश की कि दोनों दलों में सम्मानपूर्ण समझौता हो जाय पर हर बार जिन्ना साहब ने हमें झोंसे ही दिये। कांग्रेस ने समझौते की खातिर अपने पुराने और आदरणीय नेता प० मदन मोहन मालवीय तक की बात टाल दी और साम्प्रदायिकता को ठुकराया नहीं मुस्लिम लीग हमेशा हमारी देन को ठुकराती रही और कभी भी अपनी माँगे पेश ही नहीं की।” पटेल ने स्पष्ट किया कि “कांग्रेस यह कभी स्वीकार नहीं करेगी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र सस्था है।”⁹

1944 ई० में राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला रखा जिसे राजगोपालाचारी फार्मूले के नाम से जाना जाता है। इसमें मुस्लिम लीग के साथ एक काम चलाऊ सहयोग पर आधारित था तथा इससे भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, पर विचार व्यक्त करते हुए जिन्ना ने गाँधी जी पर आरोप लगाया कि “जादुई रूप से गाँधी जी के होठों पर विभाजन है।”¹⁰ इस प्रकार विभाजन की प्रक्रिया में राजा जी फार्मूला भी शामिल हो गया। 1946 ई० के प्रारम्भ में नौ सेना के विद्रोह और ब्रिटेन में एटली के नेतृत्व में मजदूर दल की सरकार के चलते भारत से जाने का निर्णय ब्रिटेन ने कर लिया और भारतीय राजनीतिक समस्या के हल के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसने भारत विभाजन के

८ वही, पृ० 62

९ व्यास, दीनानाथ, पूर्वो, पृ० 388-389

१० मिश्रा, डी०जी०, लिविंग इनधरा, दिल्ली, 1975, पृ० 450

प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 2 सितम्बर, 1946 ई० को नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव किया। प्रारम्भ में लीग मन्त्रिमंडल में शामिल नहीं हुई लेकिन बाद में 15 अक्टूबर, 1946 को लीग मन्त्रिमंडल में शामिल हो गयी। जहाँ उसने सरकार को परेशानी में डालने का कार्य ही किया।

साम्प्रदायिक दंगे—नेहरू के नेतृत्व में अस्थायी सरकार के गठन के बाद ही लीग ने अपना रोष साम्प्रदायिक दंगों से उतारा। वह यह सिद्ध करना चाहती थी कि दोनों समुदायों में कोई समझदारी नहीं है। 16 अगस्त, 1946 को लीग ने 16 अगस्त, 1946 को सीधी कार्यवाही का आह्वान करते हुए देश के उन क्षेत्रों को साम्प्रदायिक दंगों की आग में झोकने का कार्य किया वे लीग द्वारा प्रस्तुत पाकिस्तान के दावे पर असर डालने वाले थे। ये क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के माग तथा पश्चिमी सीमा प्रान्त। साम्प्रदायिक दंगों की शुरुआत पूर्वी बंगाल से हुई। बंगाल में इन दिनों सुहरावर्दी की सरकार थी जिसे शहीद अर्थात् इस्लाम पर अपने को न्योछावर करने वाला घोषित किया गया। सुहरावर्दी की लीगी सरकार ने 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया तथा मुसलमानों की एक भारी सभा में खुल्लमखुल्ला दंगा करने की प्रेरणा दी। चार दिनों तक कलकत्ता में गुण्डों का आतंक रहा। फिरोज खॉं नून ने एक सभा में कहा कि “मुसलमान ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे की नेता लोग चगेज खॉं तथा हलाकू खॉं के हत्याकांडों को भूल जायेंगे।”¹¹ कलकत्ते के यह हत्याकांड दिल्ली में नादिर शाह के हत्याकांड के बाद सबसे भयंकर हत्याकांड था। पुलिस में प्रायः मुसलमान ही थे अतः वे इस दंगे में केवल मूकदर्शक बने रहे। उन्होंने अपना मौन तोड़ दिया जब हिन्दू भी बदला लेने के लिए उदन्त हो गये। कलकत्ते की नालियों में खून बहने लगा। “इन दंगों में कम से कम 4000 लोग मारे गये तथा सहस्रों घायल हुए। करोड़ों की सम्पत्ति लूट लिया गया अथवा जला दिया गया।”¹²

इसकी प्रतिक्रिया दूसरे वर्गों में भी हुई तथा बिहार व दिल्ली आदि स्थानों पर इसका बदला लिया गया। किन्तु पुनः पूर्वी बंगाल के नोआखाली में दंगे हुए जहाँ स्वयं महात्मा गान्धी शान्ति स्थापना के लिए गये। इस प्रकार कलकत्ते में शान्ति हो गयी लेकिन सितम्बर

११ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 109

१२ वही, पृ० 109

1946 ई० में मुजफ्फरपुर (बिहार) में दंगा शुरू होगया नोआ खाली का बदला लेने के लिए 26 अक्टूबर को बिहार के छपरा, पटना और भागलपुर में व्यापक रूप से दंगा हुआ। इसके अलावा बम्बई, अलीगढ़, सिलहट, क्वेटा, आरा तथा दिल्ली में भी दंगे हुए। साथ ही बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद, गढ़ मुक्तेश्वर, अहमदाबाद तथा ढाका भी दंगे, से प्रभावित हुये इन दंगों में सरकार मूकदर्शक बनी रही। इन क्षेत्रों में दंगों की सम्भावनाये पहले से ही थी। सरदार पटेल ने इसी आशका के कारण कैबिनेट मिशन के सदस्यों से कहा था कि—

“यदि मुस्लिम लीग के साथ समझौता नहीं होता है तो बंगाल और सिन्ध में साम्प्रदायिक दंगों की काफी सम्भावना है।”¹³ सरदार पटेल की आशका पर मिशन के वरिष्ठ सदस्य क्रिप्स ने कहा कि—

“आपको बंगाल का भय नहीं रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक ऐसे गवर्नर है जो गम्भीर उत्पात खड़ा होने पर तत्काल सेक्शन 93 लागू कर देगे।”¹⁴

परन्तु जब उत्पात सचमुच खड़ा हुआ तो कोई कदम नहीं उठाया गया और सरदार की कड़ी टिप्पणी के अनुसार वह इन सारी घटनाओं के समय दार्जलिग में विश्राम करते रहे। बंगाल दंगे के उपरान्त देश के तमाम भागों में छिटपुट दंगे होते रहे।

नेहरू मन्त्रिमंडल के सदस्य “गजनफर अली ने 2 दिसम्बर, 1946 ई० को करँची में एक चुनावी सभा में कहा कि “मुस्लिम लीग अन्दर से सीधी कार्यवाही करने के लिए ही मन्त्रिमंडल में शामिल हुई है। मैं घर से निकलते समय सोचता था कि मुझे जेल में रहना होगा। किन्तु मुझे आन्तरिक सरकार में स्थान मिला। अब केवल दो ही मार्ग हैं या तो कांग्रेस झुकेगा या मारकाट के लिए तैयार रहे।”¹⁵

अपनी इन्ही भावनाओं के अनुरूप मुस्लिम लीग ने उन दिनों देश भर में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाया। जनवरी 1947 के प्रारम्भ में मुस्लिम लीग ने आसाम में जबरदस्ती जमीनों पर अधिकार करने के लिए मुसलमानों के दल भेजना आरम्भ किया। हजारा में उपद्रव हो गया। प्रान्तीय सरकार ने जब इन गैरकानूनी अधिकार रखने वालों को बेदखल करना शुरू कर दिया तो मुस्लिम लीग ने सत्याग्रह करने की घोषणा की।

१३ शंकर, वी०, सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार, खण्ड-एक अहमदाबाद, 1976, पृ० 385

१४ वही, पृ० 385

१५ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 114

ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1948 तक भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा के बाद लीग ने साम्प्रदायिक स्थिति को तेजी से बिगाड़ने का कार्य किया। उसे यह विश्वास हो गया कि वह अधिक से अधिक जितने प्रान्तों को अपने प्रभाव में ले लेगी उन सब का अधिकार अंग्रेज उसे सौंप देगे। बंगाल तथा सिन्ध पर तो उसका नियंत्रण था ही, अतएव उसने सीमा प्रान्त तथा पंजाब में नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाई जहाँ पर क्रमशः डॉ० खान साहिब का कांग्रेसी मंत्रिमंडल और खिजर खयाज खॉ का सर्वदलीय युनियनिस्ट मंत्रिमंडल था।

सीमा प्रान्त में कांग्रेस और खुदाई हिक्मत यारों के विरुद्ध उन्हें भला बुरा कहने और बदनाम करने का आन्दोलन चलाया गया। वहाँ अल्पसंख्यक हिन्दुओं और सिखों के विरुद्ध साम्प्रदायिक दुर्भावनाये फैलायी गयी जिसके परिणामस्वरूप लूटपाट, अग्निकांड और हत्या आदि की घटनाये हुई। आतंक के भय से हिन्दू और सिख वहाँ से भागने लगे। कांग्रेस और हिक्मतयारों ने उनकी सहायता का प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हुए।

आसाम तथा सीमा प्रान्त के पश्चात् मुस्लिम लीग ने पंजाब में अपना आन्दोलन प्रारम्भ किया। जहाँ सगठित प्रदर्शनी के माध्यम से इसकी शुरुआत की। पंजाब प्रान्त के गवर्नर और अंग्रेज अधिकारी थे। इस आन्दोलन में लीग का साथ दे रहे थे। जिससे पंजाब के प्रधानमंत्री खिजर खयात खॉ ने घबराकर 3 मार्च, 1947 ई० को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। किन्तु मुस्लिम लीग फिर भी सरकार न बना सकी। क्योंकि हिन्दुओं तथा सिक्खों ने मंत्रिमंडल में उसके साथ शामिल होने से इन्कार कर दिया फलतः गवर्नर ने प्रान्त में दफा 93 लागू कर दिया।

हिन्दुओं तथा सिक्खों ने 4 मार्च को लाहौर में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किया। इस पर मुसलमानों ने उन पर आक्रमण कर दिया। परिणामस्वरूप पूरे प्रान्त में हिंसा का बोलबाला हो गया। हत्याये, अग्निकांड, अपहरण, बलात्कार खिलवाड हो गये। लाहौर, अमृतसर तथा मुल्तान सभी बरबाद हो गये। लाहौर से चलने वाली सभी 22 पैसेन्जर गाड़ियाँ बन्द कर दी गयीं। लाहौर से अन्य नगरों के टेलीफोन कनेक्शन तोड़ दिये गये। 6 मार्च को जालंधर, स्यालकोट तथा रावलपिंडी में भी दंगे हुए।

पंजाब की इस भयानक स्थिति पर विचार करने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में 5 से 8 मार्च तक हुई। जिसमें पंजाब को दो भागों में विभाजित करने की

आवश्यकता महसूस की गयी जिससे मुस्लिमबाहुल भाग को गैर मुस्लिम भाग से अलग किया जा सके, फलतः दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे के भय और आतंक से मुक्त हो जायेंगे। कांग्रेस ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया। लेकिन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

कांग्रेस कार्यसमिति पर इस मार-काट की भयंकर प्रतिक्रिया हुई। उसने माउण्ट बेटेन के आगमन के पूर्व ही भारत विभाजन की माँग कर दी। जिसका नेहरू और पटेल ने समर्थन किया।

भारत विभाजन

भारतीयों को सत्ता सौंपने के विषय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने अस्पष्ट विचार प्रकट करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि “सम्राट की सरकार यह स्पष्ट करती है कि वह जून 1948 तक समस्त सत्ता का उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथों में सौंप देगी परन्तु यदि सविधान निर्मात्री सभा सभी पार्टियों की सहमति से सविधान बनाकर नयी सरकार गठित नहीं कर लेती तो ब्रिटिश सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत में केन्द्रीय सत्ता जिसको सौंपी जाय और क्या यह नयी केन्द्रीय सरकार को या कुछ क्षेत्रों में प्रान्तीय सरकारों को या किसी और तरीके से भारतीय जनता के सर्वोच्च हित को दी जाय।”¹⁶ साथ ही बेवेल के स्थान पर लार्ड माउण्टबेटेन को भारत का वायसराय बनाने की घोषणा की गयी।

प्रधानमंत्री के उपरोक्त वक्तव्य का मुस्लिम लीग ने यह अर्थ लगाया कि यदि वह जून, 1948 ई० तक सविधान निर्मात्री सभा का वहिष्कार करती रहेगी तो ऐसी स्थिति में सरकार विवश होकर सरकार उन प्रान्तों को लीग को सौंप देगी जहाँ मुसलमानों का बहुमत है।

24 मार्च, 1947 ई० को लार्ड माउण्ट बेटेन भारत के वायसराय का पद ग्रहण किया और अपनी योजना के अनुसार कहा—“मैं एकदम घिर आयी वास्तविक समस्या को महसूस करता हूँ। यदि हमने शीघ्रता से काम नहीं किया तो वह गृह युद्ध का रूप ले लेगी। इसके पीछे विभाजन ही बहुत अधिक समधान कर देगा। मैं कोई दूसरा विकल्प सपने में भी नहीं देखता।”¹⁷

१६ दि इंडियन एन्युअल रजिस्टर, खण्ड-एक, 1942, पृ० 142-143

१७ बेटेन, लार्ड माउण्ट, पिल लाइफ ऑफ टाइम्स, ब्रिटेन, 1960, पृ० 152

इसके लिए माउण्टबेटेन ने विभिन्न भारतीय राजनीतिज्ञों से मुलाकात की। माउण्ट बेटेन ने भारतीय राजनीतिज्ञों के बारे में जो विचार व्यक्त किए वे बड़े रोचक हैं। उनके अनुसार नेहरू स्पष्टवादिता और औचित्य भावना से प्रभावित थे। वे नेहरू के अच्छे मित्र थे। जबकि सरदार पटेल दृढ़, धीर, स्पष्टवादी, व्यावहारिक और वास्तविकता को मानने वाले थे और नौकरशाही पर विश्वास करते थे। जिन्ना के संबंध में उनका मत था कि जिन्ना का दिमाग तेज था। वह कानूनी बारीकियों को समझते थे परन्तु वे अभिमानी थे। इस प्रकार उनकी नजर में कांग्रेस में नेहरू और पटेल ही प्रमुख व्यक्ति थे।

माउण्टबेटेन का विचार था कि यदि सरदार पटेल को अपनी योजना से सहमत कर लिया जाय तो कांग्रेस इस योजना को स्वीकार कर लेगी, अतएव उन्होंने सबसे अधिक विभाजन के बारे में सरदार पटेल को ही समझाने का कार्य किया जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। सरदार पटेल माउण्ट बेटेन योजना से सहमत हो गये। सरदार पटेल का दृष्टिकोण स्पष्ट था। उनके अनुसार “हमने हिन्दुस्तान के टुकड़े किये जाना कबूल कर लिया है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया और यह गलती थी। मैं अभी तक नहीं मानता कि हमने कोई गलती की। और मैं यह भी मानता हूँ कि यदि हमने हिन्दुस्तान का टुकड़ा करना मजूर नहीं किया होता, जो आज जो हालात हैं उससे भी बुरी हालत होने वाली थी और हिन्दुस्तान के दो नहीं अपितु अनेक टुकड़े होने वाले थे। मेरे सामने यह चित्र है कि हमने किस प्रकार एक वर्ष सरकार चलायी और यदि हमने यह बात कबूल न की होती तो क्या होता? आप इतना विश्वास रखें कि जब मैंने और मेरे भाई नेहरू ने यह कबूल न की होती तो क्या होता ? आप इतना विश्वास रखें कि जब मैंने और मेरे भाई नेहरू ने यह कबूल किया कि अच्छा है, यदि टुकड़ा जरूर करना है और इसके मुसलमान लगान नहीं मानते, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। क्योंकि हम जब तक परदेशियों को हटा न दें, विदेशी हुकुमत न हटा दें, तब तक दिन प्रतिदिन ऐसी हालात होती जाती थी कि हमें साफ तौर से दिखाई दिया कि हमारे हाथ में हिन्दुस्तान का भविष्य नहीं रहेगा और परिस्थिति काबू से बाहर चली जायेगी। इसलिए हमने सोचा कि अभी दो टुकड़े करने से काम ठीक हो जाता है तो वैसा ही कर लें। हमने मान लिया कि ठीक है, अपना अलग घर लेकर यदि यह भाई शान्त हो जाता है और अपना घर सम्भाल लेता है तो हम अपना सम्भाल लेंगे

लेकिन हमने यह बात इसी उम्मीद से मानी थी कि हम शान्ति से अपना काम करेंगे तो उसमें हमारी गलती हुई क्या?"¹⁸

इस प्रकार उपरोक्त अवधारणा से सरदार पटेल तथा नेहरू ने सर्वप्रथम विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। महात्माँ गॉंधी इससे सहमत नहीं थे परन्तु जब सरदार पटेल ने उनको समझाया कि यदि दो भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं तो अपना अपना घर लेकर अलग हो जाते हैं, तब गॉंधी जी ने सहमति दी। यद्यपि गॉंधी जी ने विभाजन रोकने के लिए जिन्ना से कहा था कि वह प्रधानमंत्री बन जाय लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं हुए, वह सिर्फ विभाजन चाहते थे।

के० एम० मुशी ने विभाजन के सबध में सरदार पटेल की मानसिक स्थिति की चर्चा बने सुन्दर ढंग से की है। मुशी के अनुसार 1947 ई० में वे और सरदार पटेल बिडला भवन नयी दिल्ली में साथ-साथ रहते थे और साथ-साथ टहलने जाते थे। मुशी के अनुसार सरदार पटेल जो अखंड भारत के समर्थक थे, भारत विभाजन के समर्थक बन गये। मुशी ने लिखा है कि "मुझे स्वाभाविक धक्का लगा क्योंकि सदैव राजा जी की विभाजन का समर्थन करने की कड़ी आलोचना करते थे।"¹⁹ पटेल जी ने विभाजन के पक्ष में दो तर्क दिये। प्रथम यह कि कांग्रेस अहिंसा में विश्वास करती है वह हिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती। यदि कांग्रेस अपने सिद्धान्त को भी बदल दे तो वर्तमान स्थिति में हिंसा का सहारा लेकर कांग्रेस अपने को समाप्त कर देगी क्योंकि इसका अभिप्राय मुस्लिम लीग से एक लम्बा संघर्ष होगा जबकि ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पुलिस और सेना के बल पर शासन कर रहे हैं। पटेल जी ने दूसरा कारण यह बताया कि अगर विभाजन को स्वीकार कर लिया गया तो शहरों और गाँवों में साम्प्रदायिक झगड़े होंगे और यहाँ तक कि सेना और पुलिस की साम्प्रदायिक आधार पर बँट जायेगी। एक मजबूत संगठन के आभाव में हिन्दुओं को नुकसान होगा क्योंकि हिन्दू स्वभाव से उदारवादी होते हैं। जबकि दूसरी तरफ यदि संघर्ष होता है तो वह संगठित सरकारों के द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, "क्योंकि दो सरकारों के बीच

१८ भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947 से 1950 तक) प्रकाशन विभाग दिल्ली, 1970, पृ० 103

१९ मुशी, के०एम०, इंडियन कान्सीट्रियुशनल डाक्यूमेन्ट्स, वाल्यूम-1, बम्बई, 1967, पृ० 126

समझौता करना पूरे देश में फैले हुए दो सम्प्रदायों के बीच समझौते से आसान है।”²⁰
इसके अलावा सरदार पटेल विभाजन के अन्य कारणों में मानते थे कि—

1 मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिए विभाजन आवश्यक है और

2 सरदार पटेल का विचार था कि स्वतंत्र इकाई के रूप में पाकिस्तान अधिक दिन नहीं टिकेगा। वह थोड़े समय पश्चात् पुनः भारतीय संघ में सम्मिलित हो जायेगा और जिन्ना शीघ्र ही उनके साथ आ जायेंगे।

3 विभाजन के उपरान्त एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना हो सकेगी।

विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार न करने वाले लोगों में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद प्रमुख थे। जिन्होंने सरदार पटेल द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर लिखा कि—

“यह इतिहास का एक सत्य है कि हिन्दुस्तान में जो आदमी लार्ड माउण्ट बेटेन का सबसे पहले शिकार हुआ वह सरदार पटेल थे। कार्य परिषद् में जो स्थिति पैदा हो गयी थी सरदार उससे बहुत चिढ़ गये थे, वे बँटवारे में विश्वास करने लगे। वित्त विभाग लीग को सौंप देने का दायित्व सरकार का ही था इसलिए लियाकत के सामने अपनी असहोयता सबसे अधिक रोष उन्हें ही आता था। इसलिए माउण्ट बेटेन ने जब विभाजन की योजना सुझायी तो सरदार पटेल के मन में यह बात पक्की हो गयी कि यह लीग के साथ कार्य नहीं कर सकते।”²¹

इस प्रकार विभाजन संबंधी निर्णय को मान्यता प्रदान करने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक 14 जून, 1947 ई० को सविधान क्लब में प्रारम्भ हुई। गान्धी जी विशेष निमन्त्रण पर अधिवेशन में उपस्थित हुए। आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभाजन का प्रस्ताव प० गोविन्द वल्लभ पंत ने रखा जिसका अनुमोदन मौलाना आजाद ने किया हालांकि वे प्रस्ताव के कट्टर विरोधी थे। प्रदीर्घ साधन बाधक चर्चा के बाद प्रस्ताव 15 जून, 1947 ई० को 15 के विरुद्ध 157 मतों से पारित कर दिया गया। समिति की बैठक में सरदार

२० वही, पृ० 126-127

२१ आजाद, मौलाना, आजादी की कहानी, कलकत्ता, 1965, पृ० 204-205

पटेल ने कहा "यदि एक अगूठा विषपूर्ण हो जाय तो उसे अलग ही कर देना चाहिये अन्यथा सम्पूर्ण शरीर को अत्यधिक हानि उठानी पडती है।"²²

सरदार पटेल को विभाजन का बड़ा दुःख हुआ जिसे उन्होंने स्वयं स्वीकार करते हुए कहा कि-

"मैं जीवन भर भारत की एकता के लिए प्रयत्नशील रहा हूँ आप सबको इस प्रस्ताव से जो दुःख हुआ है, उससे कम मुझे नहीं हुआ है परन्तु मेरे दिल में यह बात बैठ गयी है कि इस पिछले नौ महीने से देश की शासन व्यवस्था हम लोग चला रहे हैं। इस अरसे में मुझे दुःखद अनुभव हुए हैं। मैंने देखा और अनुभव किया कि यदि हम यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे और पिछले नौ मास से देश का शासन जिस तरह चला है, और ब्रिटिश सल्तनत ने जिस तरह उसे चलने दिया है वैसा ही यदि वह अधिक दिनों तक चलता रहा, तो मुझे निश्चित भय है कि समूचा भारत ही पाकिस्तान बन जायेगा।

इसलिए यदि सारे भारत को पाकिस्तान बनने से बचाना हो तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करके, देश के विभाजन का खतरा उठाकर भी अंग्रेज सरकार को भारत से हटाने में कुछ हानि नहीं है। इसमें देश का सुख निहित है। भविष्य में बहुत बड़ी बुराइयों को रोकने के लिए इस बुराई को स्वीकार करके अंग्रेजों को इस पाप को भारत से हमें विदा करना चाहिये। इस दृष्टि से मैं दुःख और वेदना से रुदन करने वाले मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस कड़वे घूँट को पी जायें।"²³

विभाजन का क्रियान्वयन

विभाजन की योजना 3 जून, 1947 को स्वीकृति कर ली गयी तो इसको कार्यान्वित करने के लिए दो प्रकार के उपाय आवश्यक थे। प्रथम विधेयक द्वारा इसे कानूनी अधिकार प्रदान करना और द्वितीय विभाजन के प्रशासनिक परिणामों का सामना करना। लॉर्ड माउण्ट बेटेन ने 'विभाजन के प्रशासनिक परिणाम' नामक एक 32 पृष्ठीय दस्तावेज राजनीतिक दलों के समक्ष पेश किया तथा इस हेतु एक विभाजन समिति की नियुक्ति की गयी जो 5 जून, 1947 ई० को विभाजन परिषद् में परिवर्तित हो गयी। माउण्ट बेटेन इस परिषद् के अध्यक्ष

२२ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 132

२३ पटेल, राव जी भाई म०, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ० 205

थे तथा इसमें प्रत्येक डोमिनियन के दो-दो प्रतिनिधि थे। कांग्रेस की ओर से इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ० राजेन्द्र प्रसाद थे। राजगोपालाचारी को वैकल्पिक सदस्य के रूप में रखा गया था तथा मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना और लियाकत अली थे। अब्दुल खनिश्तर को वैकल्पिक सदस्य के रूप में रखा गया था। काम के सुगम बनाने के लिए दो सदस्यीय एक संचालन समिति तथा अधिकारियों की 10 विशेषज्ञ उप समितियाँ भी बनायी गयी। विशेषज्ञ उप समितियों के अधीन प्रशासन का सम्पूर्ण क्षेत्र जैसे- परिसीमन, परिसम्पत्ति एवं दायित्वों का विभाजन, राष्ट्रीय ऋण का विभाजन, सगठन, सेना आदि का विभाजन था। इसके अतिरिक्त एक मध्यस्थ परिषद् बनाई गयी जो उन मामलों पर निर्णय करेगी जो विभाजन परिषद् के समक्ष विवादास्पद होंगे।

“विभाजन परिषद् की प्रथम बैठक 27 जून, 1947 ई० को हुई तथा दूसरी बैठक 30 जून को, तीसरी 5 जुलाई, चौथी 10 जुलाई, पाँचवी 15 जुलाई, छठी 17 जुलाई, सातवी 19 जुलाई, आठवी 22 जुलाई, नवी 24 जुलाई, दसवी 26 जुलाई, ग्यारहवी 29 जुलाई, बारहवी 31 जुलाई, तेरहवी 2 अगस्त, चौदवी 4 अगस्त, पन्द्रहवी 5 अगस्त और सोलहवी बैठक विभाजन के पूर्व 6 अगस्त, 1947 में हुई। सरदार पटेल तथा जिन्ना प्रत्येक बैठकमें उपस्थित रहे।”²⁴ विशेषज्ञ समितियों ने इतनी सद्भावना से कार्य किया कि बहुत ही कम मामले संचालन समिति के पास गये। के०एम० मुशी के शब्दों में “प्रत्येक मामले में पटेल और जिन्ना एक स्वीकार्य फार्मूले पर सहमत हो जाते थे। जब कभी मतभेद होता था तो माउंट बेटेन सुलह के लिए आ जाते थे।”²⁵

यद्यपि विभाजन परिषद् ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझा लिया लेकिन चल अचल सम्पत्ति तथा सेना को लेकर कुछ समस्याएँ आयी। युद्ध के कारण ब्रिटेन अपने पीछे पाँच बिलियन डॉलर का ऋण छोड़ गये थे। नकद सम्पत्ति के रूप में स्टेट बैंक में धन तथा सोना था। काफी विवाद के पश्चात् तय हुआ कि पाकिस्तान को 17.5 प्रतिशत नकदी मिलेगी तथा उसी अनुपात में वह ऋण का बोझ अदा करेगा। चल सम्पत्ति का बँटवारा 80 और 20 के अनुपात में हुआ। सरदार पटेल पाकिस्तान को नकदी भुगतान स्थगित करना

२४ मेहरोत्रा एवं कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली 1997, पृ० 134

२५ मुशी के०एम०, इंडियन कान्सीड्यूशनल डाक्यूमेण्ट्स, वाल्यूम 1, बम्बई, 1967, पृ० 131

चाहते थे ताकि काश्मीर युद्ध में पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके। परन्तु गाँधी जी के उपवास के कारण यह सम्भव न हो सका। लियाकत अली 6 में से एक मुद्रणालय पाकिस्तान को स्थानान्तरित करवाना चाहते थे जिसका सरदार पटेल ने यह कहकर विरोध किया कि “किसी ने पाकिस्तान को अलग होने के लिए नहीं कहा। हमें इस बात की चिन्ता नहीं है कि वे अपने साथ सम्पत्ति ले जाय, परन्तु हम भारत की कार्य प्रणाली में इस कारण व्यवधान सहन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के पास साधन नहीं हैं।”²⁶

सेना का विभाजन एक कठिन कार्य था। भारतीय सेना एक सस्था के रूप में विकसित हुई थी। विभाजन परिषद् सेवा का विभाजन 15 अगस्त, 1947 के पूर्व चाहती थी जबकि सेनाध्यक्ष सर क्लाड आचिन लेक इसके विभाजन के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार सेना जैसे संगठन को विभाजित करना उसको नष्ट करना है। परन्तु माउण्टबेटेन ने विभाजन पर बल दिया। यह कार्य आचिन लेक ने अनिच्छा से किया। विभाजन परिषद् की अन्तिम बैठक में सरदार पटेल ने कहा कि “भारत चाहता है कि पाकिस्तान एक सम्पन्न पड़ोसी के रूप में उभरे। उन्होंने आशा प्रगट की कि विभाजन परिषद् के अन्दर वार्तालाप ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के प्रति सद्भावना के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता है।”²⁷

दोनों उपनिवेशों के बीच सीमा निश्चित करने के लिए दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गये कि पूर्वी और पश्चिमी प्रदेशों के लिए दो आयोग बना दिये जाय। जिसके अध्यक्ष सर सीरिल रैडक्लिफ हो। बंगाल, और पंजाब प्रान्तों के मध्य भौगोलिक विभाजन की रेखा खींचते के लिए रैडक्लिफ की रेखा खींचने के लिए रैडक्लिफ की नियुक्ति इसलिए की गयी कि वे इस क्षेत्र से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। लॉर्ड माउण्टबेटेन के साथ-साथ नेहरू और जिन्ना ने भी अनभिज्ञ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया था। माउण्टबेटेन ने इस नियुक्ति के बारे में कहा कि उन्हें कोई खुशी नहीं हुई क्योंकि वे जानते थे कि यह कार्य बड़ा जटिल है और इसमें वे किसी पक्ष को पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं कर पायेंगे। सीमांकन के लिए नियुक्त रैडक्लिफ कमीशन में भारत की ओर से सरदार पटेल तथा पाकिस्तान की ओर से जिन्ना अपना पक्ष रखने के लिए अधिकृत किये गये।

रैडक्लिफ को भौगोलिक एवं वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी। उनको

२६ मेहरोत्रा एव कपूर पूर्वो, पृ० 134

२७ मुशी, के०एम०, पूर्वो, पृ० 132

इस कार्य के लिए जो नक्शे दिये गये वे अधूरे थे तथा उपलब्ध कराये गये, साधन अपर्याप्तता थी तथा विभाजन चन्द हफ्तों में करना था यानी समय की अपर्याप्तता थी। अतएव स्वाभाविक था कि ऐसी परिस्थितियों में खींची जाने वाली विभाजन रेखा को लेकर रैडक्लिफ कठिनाइयों में थे। रैडक्लिफ कलकत्ता को लेकर भारी उलझन में थे क्योंकि जिन्ना ने उस पर दावा ठोका था। आर्थिक रूप से सहमत होने के बावजूद बहुसंख्यक हिन्दुओं की आबादी के कारण रैडक्लिफ ने उसे भारत में ही रहने दिया। बंगाल विभाजन रेखा दोनों राष्ट्रों के लिए समान रूप से आर्थिक विनाश का पर्याय थी। विश्व का 85% जूट उत्पादन वाला भू भाग पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। भारत के हिस्से में जूट का सामान बनाने वाले 100 से भी अधिक कारखाने आये। पर जूट की फसल उगाने वाला एक भी खेत न था और जूट का सामान निर्यात करने वाला कलकत्ता बदरगाह भी भारत के हिस्से में आया। वायसराय के आदेशानुसार दोनों राष्ट्र स्वतंत्रता समारोही तक इस विभाजन को गुप्त रखा। इसके अलावा जल्दबाजी में किये गये इस विभाजन से पंजाब में अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गयी। वहाँ के कुछ घर बीचोबीच से विभाजित हो गये जैसे कुछ घरों का दरवाजा भारत में खुलता था तो छत पाकिस्तान में थी फलतः खिड़कियाँ और बरसात में छतों का पानी पाकिस्तान में गिरता था। एक ही गाँव के कुछ घर पाकिस्तान में चले गये तो कुछ भारत में आ गये। जल्दबाजी में किये गये इस विभाजन में अनेक त्रुटियाँ थी फिर भी दोनों देशों ने इस विभाजन को स्वीकार कर लिया। सर रैडक्लिफ विभाजन के उपरान्त त्रासदी के लिए उत्तरदायी थे पर अनिच्छा से क्योंकि उन्होंने अन्त में कहा कि—“जैसा कि मुझे आभास हो गया था जल्दबाजी से खींची इस विभाजन रेखा से उत्तर भारत रक्त रंजित हो उठा था।”²⁸

इस प्रकार इस अनियोजित विभाजन के परिणामस्वरूप पंजाब में भीषण दंगा हो गया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 लाख निर्दोष लोग इस दंगे में मारे गये और अपार सम्पत्ति का विनाश हुआ। अतएव जब यह देखा गया कि दोनों राष्ट्रों के अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रह सकते थे तो जनसंख्या के अदला-बदली का प्रस्ताव किया गया। इस प्रकार लगभग एक करोड़ जनसंख्या की अदला-बदली की गयी।

इस समय भारतीय मुसलमानों का पाकिस्तान जाने का मार्ग अमृतसर ही था किन्तु

२८ पटेल, दिलावर सिंह जैसवार, नवोदित भारत के निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 2000 पृ०

अमृतसर के सिख पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा किये गये सिखों पर अत्याचार, सामूहिक हत्याकांड और स्त्रियों के अपमान से इतना क्षुब्ध थे कि उन्होंने स्पष्ट घोषणा की अमृतसर से किसी मुसलमान को जीवित नहीं जाने दिया जायेगा। अतएव मुसलमानों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की जिम्मेदारी थल सेनाध्यक्ष तिमैया को सौंपी गयी। इस समस्या के समाधान के लिए सरदार पटेल स्वयं मेनन के साथ अमृतसर गये और सिखों को समझा बुझाकर मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का मार्ग प्रशस्त किया। 30 सितम्बर, 1947 ई० को अमृतसर में सिख नेताओं को सम्बोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि—

“मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप कम से कम एक सप्ताह के लिए आक्रमणों के इस व्यापक प्रसार को रोक दें और फिर देखें कि क्या इसका उत्तर सन्तोषजनक मिलता है की नहीं यदि आपको निराश होना पड़ा, तो इस बात को सारा ससार जान जायेगा कि वास्तविक अपराधी कौन है।”²⁹

गृह मंत्री के रूप में प्रशासनिक सेवाओं का गठन

1946 की अन्तरिम सरकार में सरदार गृह मंत्री के साथ-साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे। 1947 ई० में देश विभाजन के उपरान्त जवाहर लाल नेहरू ने पुनः मन्त्रिमंडल में शामिल होने का निमन्त्रण देते हुए लिखा कि “चूँकि कुछ हद तक औपचारिकताये निभानी होगी, इसलिए मैं आपको नये मन्त्रिमंडल में सम्मिलित होने का निमन्त्रण देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। यह पत्र किसी हद तक अनावश्यक है, क्योंकि आप तो मन्त्रिमंडल के मजबूत से मजबूत स्तम्भ हैं।”³⁰

“मन्त्रिमंडल के मजबूत से मजबूत आधार स्तम्भ” शब्द मन्त्रिमंडल में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण स्थिति का वर्णन करते हैं। जब सरदार ने इस बार मन्त्रिमंडल में स्थान ग्रहण किया तो इस बार उन्हें उप प्रधान मंत्री के साथ-साथ गृह एवं सूचना विभाग सौंपे गये। इसके साथ नव निर्मित देशी राज्यों का विभाग भी 5 जुलाई 1947 ई० को भी सरदार को सौंप दिया गया। एक इतिहासकार ने सरदार के कार्यों का विवरण सार रूप में निम्न प्रकार से किया।

२९ शास्त्री,, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 205

३० दास, दुर्गा, सरदार पटेल के पत्र व्यवहार, खण्ड-एक, अहमदाबाद, 1976, पृ० 537

“भारत के आन्तरिम मामले में सरदार वास्तव में सर्वोपरि थे, यद्यपि दिखाई ऐसा देता था कि कोई भी निर्णय वे नेहरू को सूचना दिये बिना और कम से कम उनकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना नहीं करते थे। आन्तरिक सत्ता के सारे सूत्र पटेल के नियंत्रण में थे क्योंकि वे न केवल गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सम्भालते थे, बल्कि सूचना एवं प्रसारण विभाग भी सम्भालते थे। इसके साथ कांग्रेस संस्था में भी पटेल का प्रमुख स्थान था। वे दो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सम्भालने के कारण पटेल विभाजन के बाद भी अनिश्चितता, अव्यवस्था और अराजकता की गड़बड़ी से देश को बाहर निकालकर भारत के व्यवस्थित, संगठित और सुस्थिर राज्य के सच्चे निर्माता कहे जाते हैं।”³¹

1 मन्त्रिपद ग्रहण करने के बाद सरदार के समक्ष प्रशासन के साम्राज्यवाद के स्थान पर लोकतन्त्रीय शासन के अनुरूप बनाने तथा अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना जनहित की ओर मोड़कर उसे चुस्त बनाने की थी, इसके अलावा अधिकारियों में विश्वास की भावना पैदा करने के साथ-साथ तमाम अन्य समस्याएँ थीं। जिनका सामना सरदार पटेल को करना था। सरदार के समक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी वह केन्द्र तथा प्रान्तों में प्रशासनिक तथा पुलिस विभाग सेवाओं सबंधी पदों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की थी। पहले इन पदों पर भारत मंत्री की सेवाओं इंडियन सिविल सर्विस तथा इंडियन पुलिस के अधिकारी रखे जाते थे परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोगों की भर्ती बन्द हो चुकी थी। जिसका कारण 1945 ई० में नवनिर्वाचित ब्रिटिश मजदूर दल की सरकार का भारत छोड़ने का निर्णय था। लेकिन अधिकारियों की रिक्तता ने समस्या का रूप ले लिया। सरकार के संस्थापकीय तंत्र का निर्माण और देश की कठिन परिस्थितियों में कर्मचारियों को यथाशक्ति राष्ट्र की उत्तम सेवा करने की प्रेरणा सरदार पटेल ने दी तथा उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए निम्न प्रावधान किये।

1 स्वतंत्रता के बाद आनुपातिक पेंशन पर सेवा निवृत्त होने तथा कैरियर खोने के लिए मुआवजा प्राप्त करने का विकल्प यूरोपियों के साथ-साथ भारतीयों को भी प्रदान किया।

2 जहाँ तक भारतीयों का प्रश्न था, सरदार का मत था कि उनका कर्तव्य नई राष्ट्रीय सरकार को अपनी सेवाएँ देते रहने का है अतिरिक्त इसके कि किसी कारण से किसी अधिकारी की सेवाओं की जरूरत उसे न रहे।

3 इस कारण लोगो को सरदार ने पूरा अश्वासन दिया कि उनकी सेवा की शर्तो पर कोई हानिकारक प्रभाव नही पडेगा तथा सेवाये बनी रहेगी।

4 सरदार ने ये गारण्टी केवल अखिल भारतीय स्तर की सेवाओ को ही देना स्वीकार किया प्रान्तीय सेवाओ को नही। वे प्रान्तीय सरकार की सेवाओ के सदस्यो को देशी राज्यो के सन्दर्भ मे कुछ हद तक देखते थे।

सरदार पटेल ने कहा कि यदि कोई अधिकारी इससे अधिक गारण्टी माँगता है तो उसका कारण केवल हमारी आँखो मे अविश्वास तथा हमारी सद्भावना की चुनौती ही हो सकती है ऐसे व्यक्ति को मैं सरकारी सेवा मे सहायक नही मानूँगा बल्कि चाहूँगा कि और अधिक रियायत माँगने वाला व्यक्ति इस सेवा को छोड दे।³²

उपरोक्त प्राथमिक प्रावधानो के बाद सरदार पटेल ने समस्या के समाधान हेतु निम्न कदम उठाये।

1 सरदार ने प्रातीय सरकारो के परामर्श से प्रशासनिक सेवा के दो स्तरों का निर्माण किया। आई० सी० एस० के स्थान पर इण्डियन एडीमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) तथा आई०पी० के स्थान पर इडियन पुलिस सर्विस (भारतीय पुलिस सेवा) का गठन किया। ये दोनों सेवाये अपनी पूर्ववर्ती सेवाओ के समान प्रान्तीय स्तर की थी, परन्तु भर्ती, सेवा की शर्तो तथा अनुशासनिक कार्यवाहियों का नियमन केन्द्रीय सरकार और सघ लोक सेवा आयोग द्वारा होता था। इन सेवाओ मे भर्ती का कार्य 1947 ई० मे ही प्रारम्भ कर दिया गया।

2 जब तक उच्च पदों पर रिक्तता बनी रही सरदार ने रिक्तता को भरने के लिए तथा अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों की प्राप्ति हेतु आयु सीमा को समाप्त कर दिया।

3 विभाजन के पूर्व के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वे विदेशी थे तथा आजादी की लडाई मे वर्तमान प्रशासको के खिलाफ अमानुषिक कार्यवाही मे शामिल थे अतः ऐसे अग्रेज अधिकारियों पर भारतीय प्रशासको से विश्वास उठ गया था। वे नही चाहते थे कि अग्रेज यहाँ रहे। अतएव अग्रेज अधिकारियों ने जब यहाँ रुकने की दो शर्तो प्रथम अग्रेज सरकार द्वारा प्राप्त अधिकार के अनुसार एक निश्चित अवधि के बाद सवेतन छुट्टी लेकर इंग्लैण्ड

जाने की और द्वितीय भारत सरकार उनका अधिकार सुरक्षित रखे और वे अंग्रेज नागरिक के रूप में ही भारत में रहने की शर्तों रखी तो सरदार ने शर्तों को मानने से इकार कर दिया।³³ और बिखरे हुए असमामजस्य पूर्णता के शिकार प्रशासन तंत्र को और भी कदम उठाकर सुदृढ़ किया।

देशी रियासतों का एकीकरण

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों की समस्या का स्थायी हल एक महत्वपूर्ण एवं गम्भीर चुनौती थी। ब्रिटिश भारत में न केवल गवर्नरों के अधीन थे वरन् छोटी बड़ी 565 रियासतें थी, “जिनका क्षेत्रफल प्रान्त 715, 964 वर्गमील था तथा जनसंख्या 1941 की जनगणना के अनुसार 93,189,233 थी।”³⁴ जनसंख्या तथा आकार की दृष्टि से एक रियासत दूसरे रियासत से भिन्न थी। कुछ रियासतों का क्षेत्रफल हजारों वर्ग मील था जबकि अधिकांश रियासतें अत्यधिक छोटी थी। “काठियाबाद की एक रियासत बिजानोनेस, का क्षेत्रफल मात्र 0 29 वर्ग मील तथा जनसंख्या 206 थी तथा वार्षिक आय 500 रु० थी।”³⁵ सम्पूर्ण राज्य का अवैज्ञानिक आधार पर छोटे बड़े खण्डों में विभक्त रहना आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में बाधक था। राजनैतिक शक्ति के मामले में एक रियासत दूसरी रियासत से पृथक् थी। परन्तु कोई भी रियासत राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र सार्वभौमिकता का प्रयोग नहीं कर सकती थी और ब्रिटिश सरकार की अधिसत्ता पूर्ण थी।

भारत औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्रदान करने की ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की 12 मई, 1947 की घोषणा का कई देशी राज्यों ने यह अर्थ लगाया कि वह भी पूर्णतया स्वतंत्र हो जायेंगे। इस प्रसंग में द्रावनकोर ने स्वतंत्र रहने की अपनी इच्छा की घोषणा 11 जून को ही कर दी। बाद में निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा की। इस पर प० नेहरू तथा सरदार पटेल ने माउण्ट बेटेन द्वारा बुलायी गयी। 13 जून, 1947 की बैठक में इस मामले को उठाया। इस बैठक में नेहरू और पटेल के अलावा कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आचार्य जे०बी० कृपलानी तथा मुस्लिम लीग की ओर से मो० अली जिन्ना, लियाकत अली और

३३ प्रभाकर, विष्णु, सरदार वल्लभ भाई, नयी दिल्ली, 1982, पृ० 56

३४ मेहरोत्रा एवं कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली, 1997, पृ०, 140

३५ वही, पृ०, 140

अब्दुल रब-निश्तर, सिखों की ओर से सरदार बलदेव सिंह तथा राजनीतिक परामर्शदाता सर-कानराड कारफील्ड ने भी भाग लिया।

“नेहरू तथा पटेल के देशी राज्यों की अलग रहने की नीति का विरोध करने पर जिन्ना ने उनकी अलगगँव की नीति का समर्थन किया।”³⁶ अन्त में काफी वाद-विवाद के बाद यह निश्चय किया गया कि देशी राज्यों से सम्पर्क रखने के लिए भारत सरकार एक नये विभाग की स्थापना करे। इस सबध में गवर्नर जनरल के विधान सबधी परामर्शदाता राव बहादुर वी०पी० मेनन को एक नोट प्रस्तुत करने को कहा गया। श्री मेनन के नोट के अनुसार 25 जून, 1947 के अन्तरिम सरकार के मन्त्रिमण्डल ने रियासती विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई की अधीनता में करने का निर्णय किया। 5 जुलाई को इस विभाग की स्थापना हो जाने पर सरदार पटेल ने श्री वी०पी० मेनन को इसका सेक्रेटरी बनाया। इसी दिन सरकार वल्लभ भाई पटेल ने देशी राज्यों के नाम एक सन्देश में उनसे अनुरोध किया कि वह भारत सरकार के साथ शीघ्र ही तथा पूर्ण समझौते करके अपने रक्षा, विदेश तथा यातायात के विषय केन्द्रीय सरकार को सौंप दें। 10 जुलाई को कई राजाओं तथा देशी राज्यों के मन्त्रियों ने सरकार के निवास पर उनसे भेट की। भेट करने वालों में ग्वालियर तथा पाटियाला के राजा भी शामिल थे। उन्होंने सरदार के साथ दिल खोलकर वार्ता की और यह स्वीकार किया कि देश भक्ति के दृष्टिकोण से भी देशी राज्यों तथा शेष भारत का एक प्रकार का सहयोग वाछनीय है। जिन्ना ने इस योजना का सार्वजनिक तौर पर विरोध किया। 25 जुलाई को कई राजाओं ने सरदार पटेल से मुलाकात कर जिन्ना के वक्तव्य से असहमति प्रकट की। 5 जुलाई, 1947 ई० को देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि—

“कांग्रेस रजवाड़ों की दुश्मन नहीं है, वह देशी राज्यों एवं उसकी प्रजा का हित चाहती है। रियासती विभाग राज्यों के साथ अफसराना व्यवहार नहीं करेगा। सम्मिलित पुरुषार्थ से ही हम इस देश को महान बना सकेंगे, लेकिन एकता की कमी होगी तो नयी आपत्तियों का मुकाबला करना होगा। आम लोगों के हित के लिए यदि सबका सहयोग नहीं होगा तो अधाधुन्धी फैल जायेगी और वह हम छोटो-बड़ों को तबाह कर देगी। चलिए हम

सब एक साथ सगठित रूप से पुरुषार्थ करे और इस पवित्र भूमि को दुनिया के देशों में योग्य स्थान दिलाकर भारत को शान्ति और समृद्धि की भूमि बना दे।”³⁷

सरदार की इस घोषणा ने उष्मा भरे वातावरण का निर्माण किया। राजाओं और देशी राजा की प्रजा ने उसका उमंग और उत्साह से प्रत्युत्तर दिया। काश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे अपवादों की छोड़कर अन्य तमाम राजाओं ने भारत के सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। पटियाला और बीकानेर सर्वप्रथम प्रवेश पत्र की पूर्ति कर भारत अधिराज्य में शामिल हुई इसके पश्चात् धौलपुर, भरतपुर, विलासपुर, ग्वालियर, नाभा आदि रियासते शामिल हुई। सरदार पटेल, वी०पी० मेनन ने कई रियासतों का तूफानी दौरा किया। द्रावण कोर, जोधपुर, भोपाल और इन्दौर के शासक कुछ आनाकानी के उपरान्त भारत अधिराज्य में शामिल हुए। 14 अगस्त, 1947 ई० तक हैदराबाद, काश्मीर, जूनागढ़ और काठियावाड़ की दो रियासतों को छोड़कर लगभग सभी रियासतें भारत राज्य में सम्मिलित हो गयीं। इस प्रकार 15 अगस्त, 1947 के दिन एक सगठित राष्ट्र का निर्माण हुआ।

भारत संघ में सम्मिलित सभी रियासतें केवल रक्षा, विदेश नीति और यातायात विभाग के सबंध में ही समझौता प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये थे अतः यह समस्या का समाधान न होकर उसका मात्र सूत्रपात्र था समाधान होना तो अभी बाँकी था। देश की सुरक्षा, उसकी अखण्डता के साथ ही देश में कानून व्यवस्था एवं प्रगति की दृष्टि से भी जिस व्यावहारिक तालमेल की आवश्यकता थी वह इस समझौते से अथवा रियासतों की वर्तमान स्थिति में सम्भव नहीं थी। सभी राज्यों के वायदे कानून अलग-अलग थे। शासन पद्धति, आबकारी, न्याय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, संरक्षण, रास्ते नहरें, विद्युतीकरण, औद्योगिक विकास कहीं-कहीं दो-दो, चार-चार मील पर बदलती सरहदे आदि के प्रश्न सम्पूर्ण विकास में बाधक थे फलतः सार्वभौम अखण्ड लोकशाही प्रजातंत्र की भावना फलीभूत नहीं हो पा रही थी।

इसका एक मात्र उपाय था देशी राज्यों का विलीनीकरण। विभाजन के फलस्वरूप खड़े हुए निराश्रितों का प्रश्न, शासन तंत्र की स्थिरता, कानून और व्यवस्था की पुनः स्थापना जैसे तत्कालीन ध्यान देने वाले प्रश्नों के हल होने पर सरदार ने देशी राज्यों का प्रश्न फिर हाथ में लिया और विलीनीकरण की शुरुआत उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से की।

उन दिनों उड़ीसा तथा छत्तीस गढ़ राज्यों में प्रजामंडलो ने उत्तरदायी शासन प्राप्त करने के लिए वन प्रयोग करना आरम्भ कर दिया था। शासकों ने भी राजभक्तों का दल बनाकर गुरखों की भर्ती की तथा धेनकतल के राजा से सहायता की याचना की। इस पर अक्टूबर के अन्त तक आदिवासियों ने इन राज्यों में विद्रोह कर किसानों की भूमि तथा अन्न भंडार पर अधिकार करना आरम्भ कर दिया। इसके उपरान्त गाँवों पर आक्रमण करके लूटपाट भी शुरू कर दी।

बिहार सरकार से इन मामलों की शिकायत पाने पर सरदार ने बिहार सरकार के द्वारा बालासोर के कलेक्टर को नीलगिरि राज्य पर अधिकार करने का आदेश दिया फलतः 14 नवम्बर, 1947 ई० को नीलगिरि पर अधिकार कर लिया गया।

इस समय बिहार के हीराकुण्ड बाँध के लिए सरकार किसानों की भूमि पर अधिकार कर रही थी। पटना के राजा ने किसानों की सरकार के विरुद्ध सक्रिय कदम उठाने के लिए भड़काया।

उन्हीं दिनों यह भी पता चला कि बस्तर के शासक वहाँ की खनिज सम्पत्ति हैदराबाद के पास गिरवी रख रहे हैं। सरदार पटेल ने इसका कागजी सबूत पाने पर बस्तर के अन्य वयस्क राजा को दिल्ली बुला कर ऐसा न करने की चेतावनी दी।”

उड़ीसा के मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब से इन राज्यों के विरुद्ध इस प्रकार की अनेक शिकायतें पाने पर सरदार ने उन सब राज्यों के सबंध में 20 नवम्बर 1947 को अपने अधिकारियों से परामर्श कर यह अनुभव किया कि राज्यों का आकार छोटा होने के कारण वह उत्तरदायी शासन के व्यय का भार सहन नहीं कर सकते। सरदार ने यह भी अनुभव किया कि प्रजा के सहयोग के बिना राज्यों में कानून तथा व्यवस्था की स्थापना भी नहीं की जा सकती और ऐसी दशा में भारत सरकार को उन राज्यों का शासन अपने हाथ में लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसका अंतिम हल यही दिखलाई पड़ता है कि शासक गुजारा लेकर अपना-अपना राज्य भारत सरकार को सौंप दे।

गुजारे के प्रश्न पर अनेक दृष्टिकोणों से विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि रियासत की वार्षिक आय के आधार पर गुजारे की रकम इस प्रकार निश्चित की

जाये कि “प्रथम एक लाख वार्षिक आय पर 15 प्रतिशत, अगले चार लाख की आय पर 10 प्रतिशत तथा 5 लाख से अधिक की समस्त आय पर 7 1/2 प्रतिशत दिया जाये। यह भी निश्चय किया गया कि 10 लाख रुपये से अधिक किसी को भी न दिया जावे। इसके लिए वर्ष 1945-46 की आय को आधार माना गया। राजाओं की व्यक्तिगत सम्पत्ति आदि के विषय में भी उचित निर्णय किया गया।

इन सब तैयारियों के पश्चात् सरदार पटेल ने वी०पी० मेनन को साथ लेकर 13 दिसम्बर को कटक पहुँचे और 14 दिसम्बर को प्रथम छोटे-छोटे राजाओं की मीटिंग बुलाकर उनके सम्मुख एक प्रभावशाली भाषण दिया जिसमें उन्होंने बतलाया कि—“राज्यों की अन्तरिम अशान्ति को दूर करने का उपाय केवल यही है कि या तो उनके शासन को भारत सरकार हस्तगत कर ले, अथवा वे स्वेच्छा से गुजरात लेकर अपना-अपना राज्य भारत सरकार को सौंप दे।”³⁸ इस समय राजाओं को विलय सन्धि पत्र की प्रतियाँ भी दी गयीं। पर्याप्त वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर के बाद उन सब राजाओं ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके पश्चात् सरदार पटेल ने बड़े राजाओं को बुलाकर उनसे भी वार्तालाप किया। वार्ता लम्बी चली लेकिन अन्त में उन सभी राजाओं ने भी सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। इस प्रकार 14 दिसम्बर, 1947 ई० को 23 राज्यों का उड़ीसा में विलीनीकरण करके सरदार पटेल ने अपने अभियान का श्री गणेश किया।

दूसरे दिन 15 दिसम्बर, 1947 ई० को नागपुर पहुँच कर सरदार पटेल ने छत्तीसगढ़ के 38 राजाओं से मुलाकात करके तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए उड़ीसा राज्य का उदाहरण रखकर विलीनीकरण की सन्धि पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया जिसे स्वीकार कर राजाओं ने विलीनीकरण पर हस्ताक्षर कर दिये। ये सारा काम शीघ्रतापूर्वक समाप्त करने के बाद सरदार 16 दिसम्बर, 1947 को दिल्ली लौट आये और उसी दिन राज्यों की समस्या को सुलझाने के सबध में एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने बतलाया कि “इस बात को सभी समझते हैं कि लोकतन्त्र और लोकतंत्री सस्थाएँ कुशलतापूर्वक तभी काम कर सकती हैं जबकि जिस देश में इनका प्रयोग किया जाय वह काफी हद तक आत्मनिर्भर हो किन्तु अधिकांश राज्य इतने छोटे हैं कि वह उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की सस्थाओं का व्यय

वहन नहीं कर सकते। ऐसी दशा में उत्तरदायी शासन के लिए प्रजा का आन्दोलन इतना बढ़ सकता है कि राज्य के अस्तित्व तक को समाप्त होने की सम्भावना है।³⁹ तद् उपरान्त सरदार पटेल ने राज्यों के विलयन की स्वीकृति गाँधी, माउण्टबेटेन और मन्त्रिमंडल से भी ले ली। इस विलीनीकरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महात्मा गाँधी ने कहा कि—

“सरदार ने तो बड़े सस्ते में ही यह सौदा निपटा दिया।”⁴⁰ अपने अनुभव के आधार पर सरदार ने सभी छोटी बड़ी रियासतों को निपटारा तीन आधारों पर किया। प्रथम कुछ को प्रान्तों में मिला दिया, द्वितीय कुछ को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखा और तृतीय कुछ को आपस में मिलाकर एक सघ का निर्माण कर दिया।

उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों के प्रान्तों में विलय से सरदार पहले को वह मार्ग मिल गया, जिस पर चलकर देशों राज्यों की गम्भीर समस्या को सदा के लिए सुलझाया जा सकता था। अतएव उन्होंने निश्चय कर लिया कि भारत के किसी भी देशी राज्य की स्वतंत्र सत्ता न रहने दी जाय।

सौराष्ट्र सघ का निर्माण—उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ की सफलता के बाद सरदार पटेल ने काठियावाड़ की रियासतों की ओर ध्यान दिया जो न केवल भौगोलिक दृष्टि से वरन् धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। यह अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली है। “काठियावाड़ में 14 सलामी वाले राज्य, 17 गैर सलामी राज्य, 191 छोटी रियासतें तथा 449 ऐसी रियासतें थी जिन्हें जमींदारों से अधिक, किन्तु राजाओं से कुछ कम अधिकार थे। इनमें से कई राज्यों के भाग दूसरे के भाग में सम्मिलित थे। जिससे काठियावाड़ का मानचित्र 860 भागों में बटा था।”⁴¹ प्रत्येक कुछ मील पर अधिक क्षेत्र बदल जाने के कारण व्यापार, चुगी, न्याय तथा प्रशासन आदि की गम्भीर समस्याएँ थी। “सरदार के अनुसार इस विभाजन से क्षेत्र का विकास पूर्णतया प्रभावित था।”⁴² इस प्रकार की स्थिति राज्य और जनता दोनों के लिए

३९ भारत की एकता का निर्माण, सरदार वल्लभ भाई के भाषण, (1947 से 1950) प्रकाशन विभाग, दिल्ली, 1970, पृ० 141

४० शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 145

४१ वही, पृ० 145

४२ नन्दूरकर, जी०एम०, सरदार पटेल, इन दि टियुन विद दि मिलियन्स, खण्ड 1, अहमदाबाद 1976, पृ० 77

अहितकर थी। अतएव उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए सरदार पटेल ने काठियावाड़ की छोटी बड़ी सभी इकाईयों को मिलाकर एक संयुक्त काठियावाड़ की योजना बनायी। जिस पर सभी राजाओं ने 13 जनवरी, 1948 ई० को हस्ताक्षर करके इसका नाम सौराष्ट्र संघ रखा। 15 फरवरी, 1948 को भावनगर में इसका उद्घाटन करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि “गोंधी जी का सपना था कि काठियावाड़ को एक किया जाय और मुझे प्रसन्नता है कि आज गोंधी जी का सपना साकार हुआ।”⁴³

राजस्थान राज्य का निर्माण—राजस्थान में 19 सलामी और 3 गैर सलामी रियासते थी। इन रियासतों का विलय पाँच चरणों में हुआ। प्रथम चरण में अलवरपुर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली रियासतों को सम्मिलित कर ‘संयुक्त मत्स्य’ की स्थापना हुई। द्वितीय चरण में कोटा, बासवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, भालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोक रियासतें मिलकर संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण किया। तीसरे चरण में उदयपुर को राजस्थान में सम्मिलित किया गया और चतुर्थ चरण में शेष बची हुई जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर की रियासतें सम्मिलित हुई और 15 मई, 1949 को मत्स्य क्षेत्र को विस्तृत राजस्थान में शामिल किया गया। विस्तृत राजस्थान के निर्माण में सरदार पटेल की बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा बीमारी ने उनकी कठिनाइयों को और बढ़ा दिया। 14 जनवरी को उदयपुर में भाषण करते हुए सरदार ने कहा था कि “बहुत समय से हम तथा अनेक नरेश विस्तृत राजस्थान की कल्पना कर रहे थे। एक सामान्य भावना थी कि वर्तमान स्थिति में अलग-अलग रहने से लाभ के बजाय हानि ज्यादा है। राजस्थान तथा भारत की भलाई के लिए संयुक्त राजस्थान अनिवार्य हो गया था।”⁴⁴

विन्ध्य प्रदेश—सरदार पटेल ने विन्ध्य प्रदेश की स्थापना हेतु मेहनत को बुन्देलखंड भेजा। उनके समझाने पर बुन्देलखंड तथा बघेलखंड के सभी 38 रियासतों के राजा ने 2 अप्रैल, 1948 के संयुक्त विन्ध्य प्रदेश की स्थापना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। इसका उद्घाटन वी०एन० गाडगिल ने किया। इस अवसर पर अपने लिखित सन्देश में सरदार पटेल ने कहा कि—

४३ वही, पृ० 83

४४ वही, भाग दो, पृ० 35-39

“एकता तथा प्रजातान्त्रिक ढाँचा व्यर्थ है। यदि वह सामान्य जनता के जीवन में परिवर्तन नहीं लाता या पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास नहीं करता।”⁴⁵

मध्य भारत—सरदार पटेल ने इन्दौर और ग्वालियर के प्रतिनिधियों को समझाकर, इस क्षेत्र की 25 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर 28 मई, 1948 ई० को सबसे विस्तृत सघ मध्य भारत का निर्माण किया गया। दोनों राजघरानों में मतभेद के कारण पूर्व में दो सघ बनाने का प्रस्ताव था। 4 दिसम्बर, 1948 को मध्य भारत की धारा सभा का उद्घाटन करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि—

“उन्हें अनुभव नहीं करना चाहिये कि उन्होंने अपनी शक्तियों को त्याग कर कोई भूल की है। बल्कि उन्हें एक अच्छा कार्य करने पर गर्व करना चाहिये।”⁴⁶

पाटियाला तथा पूर्वी पंजाब सघ (पेप्सू)—अनेक प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त यह तय किया गया कि पूर्वी पंजाब तथा हरियाणा को छुए बिना पाटियाला सहित सभी राज्यों का एक सघ बना दिया जाय। जिसका नाम ‘पाटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य’ रखा गया। इस क्षेत्र की सभी रियासतें पाटियाला, सिन्ध, नभा, फरीदकोट, मलेर कोटला तथा कपूरथला के अतिरिक्त दो गैर सलामी रियासतें कलसिया व नालागढ़ ने 5 मई, 1948 को हस्ताक्षर कर दिये। 15 जुलाई को सघ का उद्घाटन करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि—

“वहाँ की जनता का उत्तरदायित्व अधिक है क्योंकि उनका पड़ोसी एक ऐसा देश है जिससे भारत के सबंध “विश्वास तथा मैत्री के नहीं हैं।”⁴⁷

द्रावनकोर तथा कोचीन संघ—13 अप्रैल, 1949 को द्रावनकोर तथा कोचीन दोनों रियासतों के मंत्रियों ने सरदार पटेल से भेंट कर एक सघ बनाने की अनुमति माँगी। द्रावनकोर के राजा को इसका प्रमुख बनाया गया। सरदार की अस्वस्थता के कारण इसका उद्घाटन 1 जुलाई, 1949 को भी मेनन ने किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर सरदार पटेल ने अपने सन्देश में कहा कि—

४५ वही, भाग एक, पृ० 94-96

४६ वही, पृ० 122-123

४७ वही, पृ० 107

“आज इस सुखद अवसर पर संपूर्ण भारत को गर्व है क्योंकि रियासतों के एकीकरण की नीति का वह अंतिम चरण है जिसका श्री गणेश अठारह माह पूर्व शुरू हुआ था।”⁴⁸

इस प्रकार काश्मीर को छोड़कर जिस पर उन्होंने जवाहर लाल की अस्वीकृति, सहमति के कारण तथा नेहरू द्वारा समस्या को अपने हाथ में ले लेने के कारण हाथ नहीं डाला। देश में स्थित सभी 562 रियासतों को जो ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों और अंग्रेजी राज्य की सुदृढ़ चौकियाँ थी, तोड़कर स्वराज्य और स्वाधीनता की सुदृढ़ नींव रखते हुए अखण्ड भारत का निर्माण किया।

राज्यों के विलीनीकरण की भावना का वास्ता देते हुए नवानगर के जान साहब, जो कठियावाड़ संघ के राज प्रमुख बने और चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के अध्यक्ष थे। सौराष्ट्र की ईकाई की रचना के वक्त कहा था कि—

“कठियावाड़ के राजाओं की ओर से मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम राज्य करते-करते थक नहीं गये थे। यह बात भी नहीं थी कि धाक-धमकी या दबाव डालकर सरदार पटेल ने हमसे गद्दी का त्याग कराया हो, बल्कि हमने स्वयं अपनी मर्जी से अपनी सर्वोपरिता का त्याग किया है और नये राज्य का निर्माण किया है।”

शागध्रा नरेश के कथनानुसार—

“सरदार जी की शान्त प्रकृति और असाधारण नम्रता ने देशी राजाओं के दिल पर इतना प्रभाव डाला कि वे इतने महान स्वार्थ त्याग के लिए तत्पर हो गये और उनके एकीकरण कार्य में उन्होंने सहयोग दिया।

विलयन का परिचय—अपने रियासतों के एकीकरण अभियान के समय विलीनीकरण के लिए राजाओं को प्रेरित करते हुए सरदार पटेल ने इसके बदले प्रतिफल के रूप में प्रिवीयर्स, निजी सम्पत्तियों को रखने की छूट तथा कुछ वैयक्तिक अधिकार और प्रतिष्ठा वापस रखने की स्वतंत्रता का वायदा किया था। एकीकरण के बाद कांग्रेस के अन्दर वामपंथी इसके विरुद्ध थे और उन्होंने सरदार पटेल से सालियाना का करार रद्द करने या उसे बदलने का आग्रह किया तो सरदार ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि—“स्वराज्य का आरम्भ मैं अप्रामाणिकता नहीं करना चाहता हूँ।”⁴⁹ आगे उन्होंने कहा कि—

४८ वही, भाग-दो, पृ० 74

४९ पटेल, बाबू भाई जश भाई, व्याख्यान, उद्धृत सरदार साहित्य माला सम्पुट, 1983, पृ० -14

“यदि सलाह सम्मति से समाधान न हुआ होता तो आज की अपेक्षा उस समय सघर्ष करने की शक्ति राजाओं में अधिक थी। उन्हें न्याय देना उचित है। उनकी जगह अपने आप को रखें और तब उनके त्याग का मूल्यांकन करें। राजाओं ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। उन्होंने अपनी सत्ता और अधिकार छोड़ दिये हैं और राज्यों के विलीनीकरण की सम्मति ही है। करार के अनुसार हमने जो उत्तरदायित्व लिया है तथा उन्हें जो विश्वास दिलाया है उसे सालियाना अदा करके पूरा निभाना है। इसे पूरा न करने में हमारी विफलता और विश्वास भग गिना जायेगा।”⁵⁰

सालियाना का निश्चय अलग-अलग रियासतों के साथ हुआ। इसके लिए एक विशेष सिद्धान्त भी निकाला गया। 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाली रियासतों के शासकों को 1,30,000 रुपये वार्षिक सालियाना देना निश्चित हुआ 450 रियासतें इसके तहत आयीं। 11 रियासतों में निश्चित सीमा से 10 लाख रु० अधिक सालियाने का प्रबन्ध किया गया और प्रत्येक का निश्चय अलग-अलग निम्न प्रकार से हुआ।⁵¹

“ग्वालियर (25 लाख), इन्दौर (15 लाख), पटियाला (17 लाख), बडौदा (26.5 लाख), जयपुर (18 लाख), जोधपुर (17.5 लाख), बीकानेर (17 लाख), ट्रावनकोर (18 लाख), भोपाल (11 लाख), मैसूर (26 लाख), और हैदराबाद (50 लाख)। ये सालियाना रियासतों की मुद्रा में दिए गये। 91 शासक ऐसे थे जिनका सालियाना एक लाख या उससे अधिक वार्षिक था। जबकि 47 शासक एक लाख से दो लाख के बीच, 31 शासक 2 लाख से 5 लाख में बीच तथा 13 शासक 5 लाख में 10 लाख के बीच सालियाना पाने के हकदार हुए। 50 हजार से अधिक और एक लाख के कम पाने वाले 56 शासक तथा 50 हजार से कम सालियाना पाने वाले शासकों की संख्या 396 थी।”⁵²

इसके अलावा शासकों को वे निजी सम्पत्तियाँ भी उन्हें दी गयीं जो समझौता करने की तिथि को उनके वैयक्तिक नाम से थीं। राज्य प्रमुखों की निजी सम्पत्ति का निश्चय अधिकांश सरदार पटेल द्वारा ही किया गया। यह सालियाना क्रमशः घटने वाला था।

५० मेनन, वी०पी०, दि स्टोरी ऑफ दि इटीग्रेशन ऑफ दि इंडियन स्टेट्स, कलकत्ता, 1956, पृ० 488

५१ मेहरोत्रा एव कपूर, पूर्वो, पृ० 161

५२ वही, पृ० 161

अक्टूबर 1949 ई० में संविधान सभा में सरदार जी ने बताया था कि “भारतीय स्वतंत्रता के कानून ने राज्यों को तमाम बन्धनों से मुक्त कर दिया था। राष्ट्र के हित के लिए घातक सिद्ध होने वाले, स्वतंत्र होने का निर्णय यदि राजाओं ने किया होता तो इस देश के हित शत्रु अनेक तत्वों का साथ उन्हें मिल गया होता। राजाओं ने अपनी शासन सत्ता सौंप कर भारत में शामिल होने का करार स्वीकार करके अपने कर्तव्य का पालन किया है राजा सम्मानपूर्वक हट गये हैं।”

1950 के श्वेत पत्र के उपोद्घाटन में सरदार जी ने बताया कि जो सिद्धि प्राप्त हुई है वह क्रान्ति से कोई कम नहीं है। हैदराबाद में कुछ किस्से ऐसे हुए जो मन को चुभें। इसे छोड़ दें तो यह क्रान्ति इतनी सरलता और शांति से हुई है कि इस महान सिद्धि का स्पष्ट ख्याल आना कठिन है क्योंकि हम इन घटनाओं के अत्यन्त निकट रहे थे।

राजाओं के दिल में इस सन्धि के विषय में जो भावना थी उसे वास्ता देते हुए अल्बर नरेश ने कहा कि—

“सरदार साहब हमारे बुजुर्ग रहे। माता-पिता जैसे उन्होंने हमारे साथ प्रेम का बर्ताव किया। उन्होंने हमें प्रेम और वात्सल्य भाव से जीत लिया। हमारे हृदय में हमारे हित की बात उतरी। सरदार साहब ने हम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला। हमें ऐसा लगा था कि हमारे दिल दुःखा कर, सत्ता के बल पर हमें सतायेगे तो सन् 57 का विद्रोह जैसे हुआ था वैसा विद्रोह भी भारतीय सरकार के खिलाफ राजा करेंगे। लेकिन सरदार साहब ने सत्ता का डंडा नहीं चलाया उन्होंने अपनी प्रेम गंगा हमारे जीवन में बहाई। हमें अपना सच्चा स्वार्थ समझाया और माता-पिता जिस प्रकार अपने लड़कों को सतुष्ट करते हैं उस प्रकार उन्होंने हमें सतुष्ट किया। सरदार साहब ने तो हमारी मिलकत और राजसत्ता दोनों का हमसे देश को समर्पण कराया ऐसा समर्पण देश प्रेम और उदारता के सिवाय नहीं हो सकता।”⁵³

20 मार्च, 1948 को ‘मत्स्य सघ’ का उद्घाटन करते हुए बी०एन० गाडगिल ने कहा था कि—

यदि महात्मा गॉंधी हमारी स्वतंत्रता के निर्माता है तो वल्लभ भाई पटेल भारतीय सघ के विश्वकर्मा है।⁵⁴

सरदार जी की सिद्धियों को अजलि देते हुए पूर्व राष्ट्रपति श्री वी०वी० गिरि ने नवम्बर, 1973 ई० में कहा था कि—

“यह अत्यन्त उपयुक्त है कि सरदार भारत की एकता के सर्जक माने जाते हैं। उनकी राजनीतिक सूझ-बूझ, प्रखर राष्ट्र भावना, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और जबरदस्त प्रबन्ध कुशलता ने उन्हें दुनिया के बड़े से बड़े महापुरुषों में एक सिद्ध कर दिया है। सरदार अपनी सम्पूर्ण योग्यता का उपयोग भारत को एक और अखंड राष्ट्र बनाने में किया है।”⁵⁵

श्री बी० शंकर के कथना अनुसार—

“इतने कम समय में सरदार ने जो जादू कर दिखाया वह इतिहास के पृष्ठ में अमिट रूप से लिखा जायेगा। इस घटना से महान घटना सारे विश्व में आज तक नहीं हुई।”⁵⁶

कुछ लोग सरदार की इस सिद्धि की तुलना जर्मनी के विस्मार्क द्वारा प्राप्त सिद्धि से करते हैं। यह तुलना करने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि विस्मार्क ने तो सेना के बल पर धाक जमायी और अत्याचार से कुछ छोटे राज्यों को दबाकर जर्मनी का एकीकरण किया जिससे सरदार की तुलना कदापि नहीं हो सकती। सरदार ने जिन 562 रियासतों को एक किया उसमें से एक रियासत तो फ्रांस से भी बड़ी थी। बड़ौदा, ट्रावनकोर और मैसूर इन राज्यों को ही मिलाये तो समग्र जर्मनी से भी अधिक बड़ा प्रदेश बनता है। ऐसे राज्यों को सरदार ने प्रेम से जीता। केवल हैदाबाद में ही थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ा। इस सबध में मोरार जी देसाई का कथन है कि “विस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया परन्तु अधिक समय लिया और वह भी एक छोटे देश में जहाँ कुछ ही राज्य थे। एक ही धर्म के लोग थे। परन्तु पटेल ने यह कार्य एक विशाल देश जहाँ विभिन्न धर्म तथा भाषा के लोग थे और देश प्रति अधिक देश भक्ति भी नहीं थी, वहाँ किया।”⁵⁷

५४ मेहरोत्रा, एव कपूर, पूर्वो, पृ० 163

५५ वही, पृ० 163

५६ वही, पृ० 163

५७ वही, पृ० 163

बडौदा—बडौदा के महाराज सर हर प्रताप सिंह गायकवाड सुप्रसिद्ध महाराज सर सयाजी राव गायकवाड के पुत्र थे जिन्होंने 1939 ई० में गद्दी सम्भाली। यद्यपि भारतीय संविधान की रचना होने पर देशी राज्यों की ओर से सर्वप्रथम उन्होंने ही अपना प्रतिनिधि भेजा था, साथ ही उन्होंने अगस्त, 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर भी भारत के साथ सम्मिलित होने के समझौते पर हस्ताक्षर करके अन्य राजाओं का मार्ग प्रशस्त किया था, किन्तु बाद में जब भारत, पाकिस्तान और जूनागढ़ के कारण समस्या में पड़ गया तो उन्होंने भारत के साथ सौदेबाजी करके अपने सभी किये कराये पर पानी फेर दिया। वह अपने राज्य का विस्तार तो चाहते ही थे साथ ही अपनी सेना को भी विस्तृत करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वह गुजरात तथा काठियावाड़ के 'किंग' बनना चाहते थे। अपनी यह इच्छाये उन्होंने 2 सितम्बर, 1947 ई० को सरदार पटेल को लिखे हुए पत्र में प्रकट की थी। पत्र में उन्होंने लिखा कि—

“मेरे दीवान कल आये और मुझसे मिले। उन्होंने जूनागढ़ की सारी बातें सुनायी। ऐसे नाजुक समय में गुजरात और काठियावाड़ में सम्पूर्ण शान्ति बनी रहे और कानून तथा व्यवस्था टिकी रहे। इसकी पूरी जिम्मेदारी बडौदा राज्य निम्न शर्तों पर लेने को तैयार है—

1 महीकठा, साबरकाठा, रेवाकठा, पालनपुर, पश्चिमी भारत के राज्यों और गुजरात के राज्यों पर भारत सरकार आज जो सत्ता भोग रही है वह सारी सत्ता बडौदा राज्य के हाथ में दे दे।

2 भविष्य में किसी समय असाधारण परिस्थितियों में जरूरत खड़ी हो तो भारत सरकार बडौदा राज्य को जरूरी सैनिक सहायता दे।

3 गुजरात और काठियावाड़ पर बडौदा की सार्वभौम सत्ता स्वीकार करने के अर्थ में बडौदा के महाराजा समस्त गुजरात के महाराज माने जाय।

4 बडौदा राज्य सदा भारत सरकार का वफादार मित्र रहेगा और सुरक्षा, देश विदेश के सबधों तथा आन्तरिक व्यवहार के विषय में सम्पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य पूरा करेगा अर्थात् बडौदा राज्य भारत सरकार का अंग बना रहेगा।”⁵⁸

इस पत्र के जवाब में सरदार पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि—

“राज्य को बढ़ाने की अपनी महात्वाकांक्षा से वे खतरे में पड़ जायेंगे, साथ ही भारत सरकार को उनकी मदद की जरूरत नहीं है।”⁵⁹

जनवरी 1948 में उनकी प्रजा ने उत्तरदायी शासन के लिए आन्दोलन आरम्भ किया, जिसके लिए वह हारे मन से अप्रैल, 1948 में तैयार भी हो गये। मई, 1948 ई० में डॉ० राज वाण मेहता को अपना दीवान बनाकर यूरोप चले गये।

डॉ० जीव राज मेहता को चार्ज लेने पर पता चला कि महाराजा ने राज्य के सुरक्षित कोष से बहुत बड़ी रकम निकाली थी और वह अनेक रत्नों को भी बेच चुके थे। उधार की रकम 220 लाख रुपये थी। 29 मई, 1948 को उन्होंने 105 लाख रुपये खजाने से और भी लिये। इस पर प्रजा के प्रतिनिधियों ने दीवान की अध्यक्षता में एकत्रित होकर दो प्रस्ताव पास किये। एक में उन्होंने घोषणा की कि सर प्रताप सिंह राज्य करने योग्य नहीं हैं और उनको अपने बड़े पुत्र के पक्ष में राज्य त्याग कर देना चाहिए। इस विषय पर भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि राज्य में रिजेसी कौंसिल बनाकर अल्पवयस्क शासक के स्वत्वों की रक्षा करें। और दूसरे प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह राज्य के हिसाब की विस्तृत जाँच पड़ताल करके सुरक्षित कोष की रक्षा करें और महाराजा से उसकी क्षतिपूर्ति करवायें।

सर प्रताप सिंह उपरोक्त प्रस्तावों को सुनकर यूरोप से लौट आये और दिल्ली आकर सरदार पटेल से मुलाकात की। अब वह अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए सहमत हो गये और इस बात पर भी सहमत हो गये कि “राज्य के शासन का संचालन एक रिजेसी कौंसिल करे जिसमें महारानी शान्ता देवी, दीवान जीवराज मेहता तथा न्यायमन्त्री हों।”⁶⁰ वह इस बात से भी सहमत हो गये कि भारत सरकार राज्य के सुरक्षित कोष की जाँच पड़ताल करे, जिसके समस्त ऋण चुकाने का उन्होंने वचन दिया। “भारत सरकार ने अपनी जाँच रिपोर्ट में कहा कि 1943 से 1947 तक के बीच खजाने से 6 करोड़ रुपये निकाले गये थे। साथ ही अनेक बहुमूल्य रत्न, प्रसिद्ध लडवाला मोतियों का हार, हीरो का हार तथा तीन अमूल्य रत्न हटाकर इंग्लैण्ड भेज दिये थे।”⁶¹ बाद में महाराज

५९ वही, पृ० 278

६० शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 153

६१ वही, पृ० 163

तथा उनके मंत्रियों के मध्य मतभेद बढ़ गये। इस पर सरदार पटेल स्वयं जनवरी 1949 में बड़ौदा जाकर पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात् बम्बई प्रान्त में बड़ौदा का विलय करने का निश्चय किया। राज्य की कौंसिल ने 28 फरवरी, 1949 को सरदार के निश्चय को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बड़ौदा राज्य का विलीनीकरण बम्बई प्रान्त में हो गया। लेकिन 1950 ई० में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद एक बार पुनः बम्बई के विलय विरोधी राजाओं का सघ बनाने का असफल प्रयास किया।

भोपाल - भोपाल का नवाब सर हमीद उल्ला खॉ 1926 ई० में गद्दी पर बैठा था। अंग्रेजों के भारत छोड़ते समय नवाब भोपाल नरेन्द्र मडल का चासलर था। भारत में अन्तरिम सरकार बनने पर, तथा उसमें मुस्लिम लीग के न शामिल होने पर नवाब को बहुत दुःख हुआ। उन्होंने वायसराय लार्ड बेवेल से जोड़-तोड़ करके मुस्लिम लीग के अन्तरिम सरकार में पिछले दरवाजे से प्रवेश कराया। 25 जुलाई, 1947 ई० में जब राज्यों के भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी एक में सम्मिलित होने के लिए मीटिंग की गई तो वह उसमें सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि वह सम्मिलन के विरुद्ध थे। नवाब की इच्छा भारत तथा पाकिस्तान दोनों से सबंध स्थापित करने की थी। अधिकांश राज्यों के सम्मिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के बाद भी वह यही सोचते रहे कि वह सम्मिलन पत्र पर हस्ताक्षर किये बिना केवल यथापूर्व समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। "बहुत सोचने विचारने के बाद दोनों पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने इस बात का अनुरोध किया कि इस घटना को 10 दिन तक गुप्त रखा जावे।"⁶²

अप्रैल 1948 ई० में प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन के लिए आन्दोलन आरम्भ कर दिया। इस पर नवाब सरदार साहब से परामर्श किया। इस परामर्श में बहुत समय लगा। नवाब ने समझौते की एक-एक धारा पर वकीलों की भोंति बहुत अधिक वाद-विवाद किया। उसने इस बात पर भी बल दिया कि उसके राज्य के विलय की बात को अभी गुप्त रखा जाय। इस समय यह भी तय किया गया कि भोपाल के मध्य भारत में विलीन न करके चीफ कमिश्नर के प्रान्त के रूप में उसका प्रथम राज्य बनाया गया। बाद में भोपाल 1 जून, 1949 को अधिगृहीत कर लिया गया और मध्य प्रदेश में मिला दिया गया।

भोपाल के नवाब ने कहा "सरदार साहब, मैंने तुम्हारा विरोध किया पर अब मैं तुमसे हार गया हूँ और अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ।"⁶³ तब सरदार ने एक खिलाड़ी की भोंति जवाब देते हुए कहा कि "यह न मेरी जीत है और न ही तुम्हारी, बल्कि यह सत्य की जीत है। जिसमें हम दोनों ने योग किया। तुमने साहसपूर्वक कदम उठाया, इसके लिए तुम अभिनन्दनीय हो। तुम्हारी प्रामाणिकता, हिम्मत और धैर्य की मैं सराहना करता हूँ।"⁶⁴

जूनागढ़ का विलय :- जूनागढ़ काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी जो कराची से 300 किमी० दूर ऐसी रियासतों के मध्य बसा था, जो सभी भारतीय संघ में सम्मिलित हो चुकी थी। रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राम आदि सेवाएँ जो जूनागढ़ में थी, वे सब भारतीय संघ द्वारा संचालित होती थी। 1941 की जनगणना के अनुसार जूनागढ़ रियासत की जनसंख्या 6,70,719 थी। जिसमें से 80 प्रतिशत हिन्दू थे, वहाँ हिन्दुओं और जैनियों के अनेक धर्मस्थल थे, तथा उसकी सीमा कहीं से भी पाकिस्तान से नहीं मिलती थी।⁶⁵

जूनागढ़ की विशेष स्थिति को देखते हुए भारत के राज्य विभाग ने प्रवेश लिखित पूर्ति हेतु भेजा। "जूनागढ़ का शासक महावत खॉं रसूल खॉं को कुत्ता पालने का इतना शौक था कि वह निर्धन जनता को भूखा रखकर कुत्तों के लिए विशेष भोजन तथा गोश्त का आयात करता था।"⁶⁶ कुत्तों की शादी सरकारी खजाने से होती थी तथा उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता था। इस प्रकार मौज मस्ती में व्यस्त रहने के कारण रियासत का सब कार्य उसने अपने दीवान सर शहनवाज हट्टो को दे दिया था जो जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रभाव में था। 13 अगस्त, 1947 ई० को सर शहनवाज भुट्टो ने उत्तर दिया कि वह मामला विचाराधीन है। इसी बीच साम्प्रदायिक प्रवृत्ति का होने के कारण भुट्टो ने 15 अगस्त, 1947 ई० को गुप्त रूप से जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में कर दिया तथा बाबरिया बाढ़ व मंगरोल रियासतों को भी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बाध्य करने लगा। इस प्रकार भारत को अधरे में रखकर लिये गये इस निर्णय की जनता में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उसने विद्रोह कर दिया। नवानगर के शासक जाम साहब ने अपने वक्तव्य में इसकी

६३ पटेल, बाबू भाई जश भाई व्याख्यान, उद्धृत सरदार साहित्य सम्पुट माला, अहमदाबाद 1986 पृ० 18

६४ वही, पृ० 18

६५ पटेल, राव जी भाई, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ० 240

६६ तहनकर, वी०पी०, सरदार पटेल, पृ० 226

भर्त्सना की तथा काठियावाद की एकता पर बल दिया। भावनगर, मोरवी, गोंडल, पोरबन्दर तथा वनमानकर के शासकों ने इस निर्णय की आलोचना की। नवाब ने भौगोलिक बाध्यता के तर्क का खंडन करते हुए पाकिस्तान के विलय के पक्ष में कहा कि—

“भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में एक शासक के लिए विलय संबंधी निर्णय के पूर्व जनता से परामर्श लेने का प्रावधान नहीं है।”⁶⁷ जाम साहब दिल्ली आये तथा सरदार पटेल और राज्य विभाग की जनता की भावनाओं, हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार तथा हिन्दुओं के वहाँ से पलायन से अवगत कराया। साथ ही यह सुझाव भी दिया कि यदि शीघ्र कार्यवाही न की गयी तो काठियावाद क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना कठिन हो जायेगा।

17 सितम्बर, 1947 ई० को भारतीय मंत्रिमंडल ने जूनागढ़ को चारों ओर से घेर लेने का निर्णय किया। इसी बीच मुम्बई में सामलदास के नेतृत्व में एक छः सदस्यीय अस्थायी सरदार गठित हो गयी। काठियावाद की अनेक रियासतों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। 28 सितम्बर को अस्थायी सरकार ने अपना मोर्चा बम्बई से हटाकर राजकोट में स्थापित कर लिया।

इधर जूनागढ़ ने बाबरिया बाढ़ में सेना भेजकर हस्तक्षेप किया तथा 51 ग्रामों के मलागिरावासियों को पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए बाध्य किया। मंगोल के नरेश को भी भारत संघ में विलय के समझौते को तोड़ने के लिए बाध्य किया। तद् उपरान्त जूनागढ़ के दीवान ने भारत को सूचित किया कि—

“बाबरिया बाढ़ तथा मंगोल जूनागढ़ के अभिन्न भाग हैं और उनका भारत संघ में प्रवेश असंवैधानिक था।”⁶⁸

भारत ने उपरोक्त क्षेत्रों से सेना वापस बुलाने की जूनागढ़ से माँग की जिसे दीवान ने अस्वीकार कर दिया। इस पर सरदार पटेल ने जूनागढ़ की उपरोक्त कार्यवाही को आक्रमण की संज्ञा दी तथा उसके विरुद्ध शक्ति प्रयोग का निर्णय किया जिसका “माउण्ट बेटेन ने विरोध करते हुए इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजने पर बल दिया।”⁶⁹

६७ मेनन, वी०पी०, दि स्टोरी ऑफ दि इंडीग्रेशन ऑफ दि इंडियन स्टेट्स, कलकत्ता, 1956, पृ० 128

६८ वही, पृ० 137-138

६९ वही, पृ० 138

मन्त्रिमंडल के निर्णयानुसार सरदार पटेल ने गुरुदयाल सिंह के नेतृत्व में सेनाये जूनागढ़ के समीप भेज दी तथा संचार व्यवस्था का विच्छेद कर दिया साथ ही आर्थिक नाकेबन्दी कर दी। 25 अक्टूबर को अस्थायी सरकार की सेना की चार टुकड़ियों ने अमरपुर गाँव पर अधिकार कर लिया तथा दूसरे दिन 23 अन्य गाँवों पर भी अधिकार कर लिया। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होते देखकर नवाब अपने परिवार, कुत्तों तथा गहने तथा एक करोड़ आदि लेकर कराची भाग गया। “भागते समय उसके प्रधानमंत्री ने 7 नवम्बर को कहा कि मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वह राज्य के शासन को अपने हाथ में लेकर व्यवस्थित करे।”⁷⁰

परिणामस्वरूप 7 नवम्बर, 1947 ई० को वहाँ का शासन सम्भाल लिया तथा सामलदास गाँधी सहित तीन प्रतिनिधियों की सरकार अपने प्रशासक की अधीनता में स्थापित कर दी। 13 नवम्बर, 1947 को सरदार पटेल जूनागढ़ गये जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को परामर्श देते हुए कहा कि “जो लोग अब भी राष्ट्र के सिद्धान्त को मानते हैं और सहायता के लिए बाह्य शक्ति की ओर देखते हैं, उनके लिए काठियावाड़ में कोई स्थान नहीं है।”⁷¹ और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि—

“जो लोग भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं, या पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखते हैं उन्हें नवाब का रास्ता अपनाना चाहिये, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिये।”

साथ ही पाकिस्तान को भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी भी दी।

प्रारम्भ में जनमत संग्रह के पक्ष में सरदार पटेल नहीं थे परन्तु बाद में मेनन से विचार के बाद जनमत संग्रह की बात स्वीकार कर ली। फलतः 20 फरवरी, 1941 ई० को जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ जिसमें भारत में पक्ष में 1, 19, 729 मत तथा पाकिस्तान के पक्ष में 91 मत पड़े। 20 फरवरी, 1949 ई० को जूनागढ़ सहित ग्यारह रियासतों का सौराष्ट्र में विलय कर दिया गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जूनागढ़ की समस्या सरदार पटेल की सूझ-बूझ तथा

७० शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 147

७१ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 148

निर्णय लेने की क्षमता, अदम्य साहस के कारण समाप्त हो गयी। यदि वे माउण्ट बेटेन के इस विचार को कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सच को सौंप देना चाहिए स्वीकार कर लेते तो काश्मीर की भाँति वह समस्या भी भारत के लिए सरदर्द बनी रहती।

हैदराबाद का बिलय :- भारत के बीचो-बीच स्थित है हैदराबाद राज्य देशी राज्यों में सबसे बड़ा था। निजाम की गिनती दुनिया के धनाढ्य व्यक्तियों में होती थी। इसे भारत का हृदय कहा जा सकता था। इसके उत्तर में मध्य प्रान्त दक्षिण में मद्रास प्रान्त, तथा पूर्व में उड़ीसा राज्य थे। इस राज्य की जनसंख्या में हिन्दू 85 प्रतिशत थे लेकिन उनकी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा गया था। नागरिक सेवाओं, पुलिस तथा सेना में मुसलमान ही रखे गये थे। उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी तथा उनको अन्य बातों से भी वंचित किया गया था। यहाँ तक कि 1946 ई० में बनाई हुई विधान सभा के कुल 132 सदस्यों में से 71 सदस्य मुसलमान थे जबकि हिन्दुओं की संख्या 61 थी। अतएव हिन्दुओं में असन्तोष की भावना थी।

वर्तमान निजाम उस्मान अली खॉं 29 अगस्त, 1911 ई० को गद्दी पर बैठा था। 3 जून, 1947 ई० को ब्रिटिश सरकार की भारत को राजनीतिक सत्ता सौंपने की घोषणा के बाद निजाम ने स्पष्ट किया कि वह भारत अथवा पाकिस्तान किसी की भी सविधान परिषद् में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेगा और 15 अगस्त, 1947 को सर्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्र कहलायेगा। किन्तु भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 7 उसकी इस इच्छा में बाधक थी। अतएव 11 जुलाई को उसने एक प्रतिनिधि मंडल नवाब छतारी की अध्यक्षता में भारत सरकार के पास वार्ता हेतु दिल्ली भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने भारत सरकार के सम्मुख माँग रखी कि नगर निजाम को वापिस किया जाय तथा हैदराबाद को औपनिवेशिक स्वतंत्रता दी जाय। वह सम्मिलित समझौते पर हस्ताक्षर किये बिना केवल यथापूर्व समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता था। किन्तु सरदार का रुख स्पष्ट था। उन्होंने सम्मिलित समझौते पर हस्ताक्षर करने का जोर दिया और 25 जुलाई, 1947 को नवाब छतारी को नरेन्द्र मंडल की वार्तालाप समिति में सम्मिलित कर लिया। किन्तु नवाब छतारी ने उसमें भाग नहीं लिया और हैदराबाद प्रतिनिधि मंडल बिना किसी समझौते के वापस आ गया। सरदार ने "हैदराबाद को अपने निर्णय पर पूर्वविचार करने के लिए दो महीने का समय दिया।"⁷²

भारत सरकार और निजाम के मध्य 29 नवम्बर, 1947 ई० को एक 'यथास्थिति समझौता' हुआ। जिसके अनुसार यह तय हुआ कि "15 अगस्त, 1947 के पूर्व तक हैदराबाद से पारस्परिक सबंध की जो व्यवस्था थी वह बनी रहेगी। सुरक्षा, परिवहन और वैदेशिक सबंध पर कोई नयी व्यवस्था नहीं की जायेगी।"⁷³ समझौते का पालन हो रहा है कि नहीं इसकी देखभाल के लिए दिल्ली में हैदराबाद के तथा हैदराबाद में दिल्ली के एक-एक प्रतिनिधि रखे जायेगे। सरदार पटेल ने के०एम० मुशी को भारत सरकार का प्रतिनिधि बनाकर हैदराबाद भेजा। समझौता करते वक्त सरदार पटेल ने आशा व्यक्त की थी कि—

"एक वर्ष के काल में हम दोनों के बीच निकट सबंध स्थापित हो जायेगे और आशा है कि इसके परिणामस्वरूप स्थायी रूप से भारतीय सघ में हैदराबाद शामिल हो जायेगा।"⁷⁴

समझौते के तुरन्त बाद से ही निजाम ने "इसका उल्लंघन शुरू करते हुए दो अध्यादेश जारी कर दिया तथा पाकिस्तान से 20 करोड़ रुपये ऋण के तौर पर लिये तथा भारत सरकार से पूछे बगैर पाकिस्तान में एक जनसम्पर्क अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी।"⁷⁵

इसी बीच हैदराबाद में 'इन्निहादुल मुसलमीन' नामक एक साम्प्रदायिक सगठन ने साम्प्रदायिक विष फैलाना आरम्भ कर दिया। सैयद कासिम रिजवी इस सगठन का अध्यक्ष था। उसने 'रजाकर नाम से एक स्वयंसेवी सैनिक सगठन भी बनाया हुआ था।"⁷⁶

इन लोगो के आतंक तथा साम्प्रदायिक अत्याचारों से हैदराबाद के हिन्दुओं में असन्तोष बढ़ता जा रहा था यह सगठन खुलेआम भारत सरकार व हिन्दुओं से घृणा का प्रचार करता था। "28 फरवरी, 1948 को के०एम० मुशी ने निजाम के प्रधानमंत्री लायक अली को पत्र लिखकर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया।"⁷⁷ 15 मार्च, 1948 को एन० वी० गाडगिल ने ससद को सूचित किया कि हैदराबाद शर्तों का पालन नहीं कर रही है। अतः सकट बरकरार है। 16 अप्रैल, 1948 ई० को सरदार ने लायक अली से रिजवी के इस भाषण पर आपत्ति की जिसमें रिजवी ने कहा था कि—

७३ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 149

७४ वही, पृ० 149

७५ वही, पृ० 149-150

७६ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 161

७७ नन्दूरकर, जी०एम०, सरदार पटेल, इन दि टियुन विद दि मिलियन्स, खण्ड-एक, अहमदाबाद, 1974, पृ० 168-169

“यदि भारतीय सघ हैदराबाद में हस्तक्षेप करेगा तो उसे वहाँ 1 50 करोड़ हिन्दुओं की हाड़डियों और राख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।”⁷⁸ साथ ही सरदार ने लायक अली को चेतावनी देते हुए कहा कि “मैं आपको असमजस की स्थिति में नहीं रखना चाहता। हैदराबाद की समस्या उसी प्रकार हल होगी जैसी कि अन्य रियासतों की। कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम कभी भारत के अन्दर एक स्वतंत्र राज्य के लिए सहमत नहीं हो सकते जिससे भारतीय एकता भग हो जिसे हमने खून पसीने से बनाया है। हम मैत्रीपूर्ण ढंग से एव सहयोग से समस्या को सुलझाना चाहते हैं, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम कभी भी हैदराबाद की स्वतंत्रता पर सहमत हो जायेंगे। हैदराबाद का स्वतंत्र अस्तित्व का प्रयास सदैव असफल रहेगा।”⁷⁹

“इसके पूर्व 23 से 25 अक्टूबर तक निजाम की अध्यक्षता में व्यवस्थापिका समिति ने अपने 9 सदस्यों में से 6 के विरुद्ध तीन मतों से निर्णय लिया था कि सम्मिलन करार पर हस्ताक्षर कर दिये जाय। निजाम ने 25 अक्टूबर, 1947 ई० के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया था और कुछ मामूली सुधारों की सूचना के साथ उस पर दस्तखत करने का वचन दिया।”⁸⁰ और यह निश्चित हुआ कि 27 अक्टूबर, 1947 ई० को प्रतिनिधि मंडल निजाम के हस्ताक्षरों वाला करार लेकर नयी दिल्ली जायेगा। परन्तु “27 अक्टूबर को सुबह कासिम रिजवी ने 20 से 25 हजार रजाकारों को हैदराबाद की सड़कों और गलियों में कूच करने का आदेश दिया। वे सड़कों, गलियों, कूचों और खास तौर पर छतारों के नवाब सर रॉबर्ट और सर सुल्तान अहमद के बगलों के आस-पास भाले और नगी तलवारें लेकर घूमने लगे और ‘डेलीगेंस को नयी दिल्ली न भेजा जाय’ के नारे लगाने लगे।”⁸¹ अन्ततः कासिम से डरकर निजाम ने भारत सरकार के साथ समझौता करने से इन्कार कर दिया था।” कम्युनिस्टों के सहयोग से कासिम ने हिन्दुओं पर भयकर अत्याचार किये।”⁸² हैदराबाद की समस्या दिन-प्रतिदिन भयकर होती जा रही थी। पाकिस्तान से चोरी छिपे हथियार भेजे जा रहे थे। सीमाओं पर गड़बड़ी पैदा की जा रही थी। हजारों काग्रेसी कार्यकर्ताओं को

७८ मेहरोत्रा एव कपूर, पूर्वो, पृ० 150

७९ वही, पृ० 150

८० पटेल, राव जी भाई म०, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ० 316-317

८१ वही, पृ० 318

८२ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 171

जेल में डाल दिया गया था। इस बीच सीमा सघर्ष और बढ़ गये तथा मद्रास से बम्बई जाने वाली एक रेलगाड़ी पर हैदराबाद राज्य के अन्दर गगापुर में आक्रमण करके दो लोगो को मार डाला गया। इस काण्ड में 11 अन्य व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए तथा 13 लापता हुए जिनमें 4 महिलाओं तथा दो बच्चे भी शामिल थे। जब घटना हो रही थी तो उस समय एक पुलिस अफसर भी बन्दूक लिये हुए प्लेटफार्म पर उपस्थित था किन्तु इस आक्रमण को वह चुपचाप देखता रहा। सरदार उस समय मसूरी में थे।

13 जून, को लार्ड माउण्टबेटेन, नेहरू और मेनन सरदार पटेल से मिलने देहरादून गये। इस मुलाकात में सरदार साहब ने माउण्टबेटेन को हैदराबाद से समझौता करने का अधिकार दिया। माउण्ट बेटेन तथा निजाम के सलाहकार सर वाटर माकटन ने समझौते का प्रारूप तैयार कर लिया तथा निजाम ने प्रधानमंत्री लायक अली की स्वीकृति की प्राप्त कर ली। तद् उपरान्त समझौते के कुछ प्रावधानों से असहमत होते हुए भी सरदार पटेल ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी, परन्तु निजाम ने समझौते को अस्वीकार कर दिया। यह समझौता भारत सरकार ने झुककर किया था। फलतः उसे घोर निराशा हुई।

21 जून, 1948 को माउण्टबेटेन के स्थान पर राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। हैदराबाद की स्थिति और बिगड़ गयी। कांग्रेस सस्था को अवैध घोषित किया जा चुका था तथा उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। कासिम ने उन मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार शुरू कर दिया था जो उससे सहमत नहीं थे। कासिम ने अपने एक भाषण में कहा कि—

“जो मुसलमान उनके विरुद्ध हाथ उठायेगे उनके हाथ काट लिये जायेगे।”⁸³ भारत सरकार द्वारा रजाकारों के खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने की सर्वत्र निन्दा हो रही थी। इसी बीच 28 सितम्बर, 1948 ई० को हैदराबाद सरकार के प्रतिनिधि ने मामले को संयुक्त राष्ट्र सघ में ले जाने की सूचना दी। इस दौरान भारत सरकार के रजाकारों के आतंक के सबध में कई पत्र निजाम को लिखे और उसके माध्यम से रजाकारों पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग की। निजाम ने रजाकारों के अत्याचारों की घटना को कोरी कल्पना बताते हुए प्रतिबन्ध लगाने से इन्कार कर दिया।

८३ मुन्शी, के० एम०, इण्डियन कान्स्टीट्यूशनल डाक्यूमेन्ट्स, वाल्यूम -1 बम्बई, 1967, पृ० 170

अगस्त के अन्त तक हैदराबाद की स्थिति बड़ी विस्फोटक हो गयी। अतः सरदार ने अतत बल प्रयोग का फैसला किया और कहा कि निजाम को बता दिया जाय कि भारत सरकार के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है। “नेहरू ने मन्त्रिमण्डल की रक्षा समिति की बैठक में सरदार के निर्णय का विरोध किया। समिति की बैठक में वाद विवाद इतना उग्र हो गया कि सरकार पटेल ने क्षुब्ध होकर अपना त्यागपत्र दे दिया और रक्षा समिति की बैठक से उठकर चले गये। दूसरे दिन तत्कालीन गवर्नर जनरल राजागोपालाचारी ने मना कर सरदार को पुनः बैठक में वापस लाये। इसी दिन कनाडा के राजदूत ने नेहरू से रजाकारो द्वारा ईसाई महिलाओं के ऊपर आक्रमण किये जाने की शिकायत की तब जाकर नेहरू ने भारी मन से बल प्रयोग की सहमति सरदार पटेल को दी।”⁸⁴

सरदार पटेल ने सेनाओं को आज्ञा दी कि 13 सितम्बर को हैदराबाद पर चढ़ाई कर दी जाय। अतः अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मेजर जनरल जे०एन० चौधरी के कमान में सेनाओं ने हैदराबाद पर दो ओर से कूच कर दिया। “एक दल शोलापुर से हैदराबाद की ओर चला यह दूरी 186 मील की थी तो दूसरा दल वेसवाडा से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। यह दूरी 106 मील थी।”⁸⁵ 13 और 14 सितम्बर को कुछ हल्का फुल्का प्रतिरोध हुआ। 108 घंटे की सैनिक कार्यवाही के बाद 17 सितम्बर को हैदराबाद की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरान्त 18 सितम्बर को भारतीय सेना जनरल चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद में प्रवेश किया। इस कार्यवाही में भारतीय सेना को मामूली नुकसान हुआ जबकि रजाकारो के 800 सैनिक मारे गये।

1 अक्टूबर, 1948 ई० को सरदार पटेल ने सेना के अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए इन आरोपों का खंडन किया कि भारतीय सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण किया। उन्होंने कहा इस प्रकार की बात करने वाले आक्रमण शब्द की परिभाषा नहीं जानते। उन्होंने कहा कि—

“हम अपने लोग पर कैसे आक्रमण कर सकते हैं। हैदराबाद की जनता तो भारत का हिस्सा है।”⁸⁶

८४ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 172

८५ पटेल, राव जी भाई, पूर्वो, पृ० 321

इस प्रकार सरदार पटेल के दृढ़ निश्चय से हैदराबाद समस्या का समाधान हुआ। यदि पंडित जवाहर लाल नेहरू की चलती तो यह समस्या भी भारत के लिए काश्मीर से कही अधिक कष्टदायी होती और इसकी एकता और अखण्डता में विघ्न डालती।

संविधान निर्माण में योगदान

आजादी की लड़ाई के समय संविधान सभा के माँग सर्वप्रथम 1934 में महात्मा गाँधी ने की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि मुक्त रूप से चुने हुए भारत के लोगो की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाया जाना चाहिए। 1936 में सम्पन्न हुए, फैजपुर कांग्रेस की सभा में उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा था कि—

“कांग्रेस एक पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन की माँग करती है। जिसमें राजनीतिक शक्ति पूरी तरह से लोगो को प्रदान की जायेगी।”⁸⁷ ऐसी स्थिति तभी आ सकी जब कैबिनेट मिशन के तहत देश में संविधान सभा का गठन हुआ और उसकी बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 ई० को सम्पन्न हुई जिसमें आचार्य जे०वी० कृपलानी ने डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा से अस्थायी अध्यक्ष का पद ग्रहण करने का अनुरोध किया। जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। 13 दिसम्बर, 1946 ई० को सभा ने इसके लिए डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया जिसका समर्थन सरदार पटेल ने किया। इस प्रकार राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिये गये। 13 दिसम्बर, 1946 ई० को जवाहर लाल नेहरू ने इसके उद्देश्यों एवं अवरोधों पर प्रकाश डाला। डॉ० एम०आर० जयकर ने इन प्रस्तावों में सशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा था कि इस तरह के संविधान के निर्माण में मुस्लिम लीग और भारतीय राज्यो का भी सहयोग लिया जाना चाहिए और इस प्रकार अपने प्रस्ताव को और मजबूत बनाना चाहिये। यह सभा दोनों प्रतिनिधियों के सहयोग देने के लिए अगली तारीख तक स्थगित कर दी जानी चाहिये। सरदार पटेल ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि बैठक में प्रस्तुत की गयी इन रियासतों को श्वेत पत्र से परे माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि “इन्हे न केवल अस्वीकार किया जायेगा बल्कि 16 मई को बनाये गये नियमों में न तो कोई परिवर्तन किया जायेगा और न ही परिवर्धन

८६ मुन्शी, के० एम०, पूर्वो, पृ० 175

८७ देसाई धीरू भाई का व्याख्यान उद्धृत सरदार साहित्य माला सम्पुट शाहीबाग अहमदाबाद, पृ० 86

किया जायेगा। तालियो की गडगडाहट के बीच उनका यह मत स्वीकार कर लिया गया।⁸⁸ मुस्लिम लीग द्वारा सविधान सभा का वहिष्कार तथा अन्य दलो और निर्दलीयो की कमजोर स्थिति के कारण सविधान पर कांग्रेस का प्रभाव सर्वोपरि था। यद्यपि डॉ० भीमराव अम्बेडकर जैसे बुद्धिशील व्यक्ति, गोपाला स्वामी आयर, अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, के०एम० मुशी तथा जॉन मथाई जैसे विधिशास्त्री आदि का योगदान सविधान निर्माण में कम न था। परन्तु कांग्रेस में जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल के बहुमुखी योगदान की प्रशंसा करते हुए एच०बी० कामथ ने लिखा है कि—

“जवाहर लाल नेहरू ने सविधान सभा को एक नई चेतना और सम्भवत विश्व व्यापी रूप दिया और सरदार पटेल ने उसे वास्तव में व्यवहारवादी एवं यथार्थवादी मार्गदर्शन किया।”⁸⁹

सरदार सविधान सभा की तीन महत्वपूर्ण उप समितियों, मौलिक अधिकार उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति और प्रान्तीय सविधान उप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों के विकास में भी सरदार पटेल की भूमिका निर्णायक रही है। विशेषकर शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना, सविधान की सकटकालीन व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन, देशी राज्यों के विलीनीकरण तथा एकीकरण, सरकारी सेवाओं से सम्बद्ध धाराये, जम्मू काश्मीर राज्य से संबंधित विशेष अनु० 370 के प्रावधान तथा भाषा नीति।

सरदार पटेल द्वारा सविधान में दिये गये प्रमुख योगदानों का विवरण निम्न प्रकार से किया गया है।

1. मौलिक अधिकारों से संबंधित योगदान :- सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में मौलिकारों अधिकारों से संबंधित उप समिति का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनु० 20 के तहत किया गया था। इस समिति के सदस्य के रूप में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री के०एम० मुशी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पी०एस० देशमुख, श्री महावीर त्यागी, श्री एस०ए० लाहिणी, श्री हरि विष्णु कामथ, श्री आर०आर० दिवाकर, श्री वी० दास, रायबहादुर चौधरी सूरजमल, सरदार पृथ्वी सिंह आजाद, श्री अनन्तेश्वरम् आयर, श्री मीनू मसानी

८८ वही, पृ० 87

८९ मेहरोत्रा एवं कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्तित्व एवं विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 164

और श्री के० टी० शाह जैसे विभिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया था। जिससे समिति की बैठक में जोरदार तर्क वितर्क होता था। सरदार पटेल ने इन उदारवादी, समाजवादी और रूढ़िवादी विद्वानों में सामंजस्य बैठाने का अद्भुत कार्य किया। समिति ने मूल अधिकारों से संबंधित अपने कार्यों को सम्पन्न करने के उपरान्त 23 अप्रैल, 1947 ई० को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश की। जिसमें न्यायोचित मूल-भूत अधिकारों का एक परिशिष्ट दिया गया था।

सरदार पटेल ने 29 अप्रैल, 1949 को रिपोर्ट के सबंध में अपना एक प्रस्ताव विचारार्थ रखा था। उन्होंने इस प्रस्ताव में न्यायोचित और गैर न्यायोचित अधिकारों के सबंध में लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा कि—“हम इन मूल अधिकारों को संविधान के अन्तर्गत न्याय योग्य बनाने पर अधिकतम महत्व दे जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं नवीनतम प्रजातान्त्रिक संविधानों में विशेष उपायों सहित नागरिक अधिकार संविधान की छवि प्रदर्शित करते हैं।”⁹⁰ परिणाम स्वरूप संविधान के अनु० 32 द्वारा सवैधानिक उपचारों के अधिकार को सम्मिलित किया गया।

नागरिकता वाले अनुच्छेद पर विचार करते समय केन्द्रीय मुद्दा वह बन गया था कि क्या कोई भी व्यक्ति भारत में मात्र जन्म लेने के कारण भारतीय नागरिक कहलायेगा, उसके माता-पिता विदेशी हों? इस पर हस्तक्षेप करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि—

“ऐसी स्थिति में कितने ही विदेशी स्त्री-पुरुष भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए बच्चे को जन्म देने हेतु भारत आ सकते हैं? यह एक विचारणीय मुद्दा है और इसके लिए क्या आप भारतीय संविधान में आनुवांशिकता की परम्परा का विकास करना चाहते हैं।”⁹¹ उन्होंने कहा था कि “यह याद रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि संसार में नागरिकता के सबंध में पुर्नसमीक्षा की जायेगी। पूरा विश्व हमारी ओर नजरे लगाये बैठा है। हम इसे स्थगित करके एक खतरा मोल लेगे और वैधानिक विषयों को जन्म देगे। शब्दों की आलोचना करने पर भी इसका अभी अन्त नहीं होगा। यह एक साधारण समस्या है। हमारे यहाँ हमेशा विदेशी आते रहते हैं। जन्म लेने के संयोग के कारण यदि कोई विदेशी यहाँ आता है और

९० कस्टीदियेन्ट असेम्बली डिबेट्स, वाल्यूम-4 फरीदाबाद, 1966, पृ० 304

९१ वही, वाल्यूम-3, पृ० 423

बस जाता है, तो सवैधानिक नियमों के द्वारा दोहरी नागरिकता को हम नियंत्रित कर सकते हैं।⁹²

सरदार के प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर नागरिकता का प्रावधान सविधान में किया गया।

जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, लिंग रंग आदि भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए सरदार पटेल ने प्रस्ताव करते हुए कहा कि इन आधारों पर किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जायेगा और साथ ही सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के ऐसे कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों तथा मनोरंजन स्थलों आदि का प्रयोग करने की पूरी छूट दी जायेगी जिनका निर्माण पूरी तरह या आंशिक रूप से सार्वजनिक फंड से किया गया हो। इस उपनियम के सबंध में चर्चा करते समय 'राजनीतिक प्राणी' शब्द रखने का प्रस्ताव सरदार ने किया था जिसके अनुसार राजनैतिक दलों के सदस्यों का राजनीतिक विचारों की भिन्नता के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखकर किया था पर सविधान निर्मात्री सभा इससे सहमत नहीं हुई। इस पर सरदार पटेल ने कहा था कि राजनैतिक मान्यताओं के आधार पर लोगों में इस प्रकार का अन्तर करना बहुत बुरा है।

सविधान के अनु० 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है। मूल अधिकार समिति ने इसे बहुत महत्वपूर्ण माना और तय किया कि मूलभूत अधिकार वाले अध्याय में ही अस्पृश्यता उन्मूलन को रखा जाय। इस सबंध में किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति को कानून अपराध माना जायेगा और हर तरह की अस्पृश्यता प्रतिबंधित कर दी जाय।

इस सबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि "यदि अस्पृश्यता निवारण मुख्य मुद्दा है और अस्पृश्यता का प्रचलन कानूनी अपराध है, तो स्वतंत्र भारत में मानवीय अस्पृश्यता के कलक को दूर करने के लिए विधान हर तरह से उचित है।"

इस अधिनियम को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया था।

सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर प्राप्त करने वाले अधिनियम को प्रस्तुत करते समय सरदार पटेल को महावीर त्यागी के इस सशोधन का कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को महत्व दिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, का सामना करना पड़ा। इस सशोधन के समर्थन में कहा गया था कि जहाँ तक सम्भव हो अपने ही प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रशासन चलाया जाना चाहिए। सरदार पटेल ने इस सशोधन को अस्वीकार करते हुए कहा कि राज्य की सभी नौकरियों और नियुक्तियों में सबके समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। धर्म, प्रजाति, लिंग, जाति, जन्म स्थान और निवास आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।

यह अधिनियम भी सरदार की इच्छानुसार पास हो गया।

सभी उपाधियों को समाप्त करने सबधी अधिनियम को पेश करते हुए सरदार ने कहा कि "सघ उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली उपाधियाँ प्रदान नहीं करेगा। इस अधिनियम को प्रस्तुत करते हुए बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि उत्तराधिकार शब्द बहुत विवादास्पद हो गया है और इसे हटा दिया जायेगा और इसका औपचारिक सशोधन भी कर दिया जायेगा। इस अधिनियम के अनुसार "सघ के द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जायेगी।" सरदार पटेल ने कहा कि "इन उपाधियों के द्वारा देश के लोगों का सार्वजनिक जीवन भ्रष्ट होता है। इसलिए इसे मूलभूत अधिकारों में रखना बेहतर रहेगा।"⁹³

अनु० 19 में उल्लिखित सभी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का अधिनियम प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे से छठे अधिनियम तक औचित्यपूर्ण प्रतिबन्ध राज्य द्वारा लगाये जा सकते हैं। अतएव उन्होंने अनेक प्रकार की स्वतंत्रताओं और गारंटियों का उल्लेख करने वाले अनु० 30 को प्रस्तुत किया। तेरह अध्याय का यह अनुच्छेद नागरिकों को भारत में किसी भी क्षेत्र में व्यापार तथा व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करता है। सरदार पटेल की दृष्टि में भारत के किसी भी हिस्से में लोगों के उद्योग, व्यापार आदि करने की स्वतंत्रता प्रदान करना नितान्त आवश्यक था क्योंकि राज्य मुक्त व्यापार पर पाबन्दी लगा सकते थे। अन्तर्राज्यीय और राज्य के अन्दर मुक्त व्यापार तथा सगठित उद्योग भारत के लिए नितान्त

आवश्यक थे। इस पहलू पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा था कि सविधान में इस बात की गारण्टी होनी चाहिये कि राज्य कानून बनाकर मुक्त व्यापार में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करेगा।

सरदार पटेल को 'सम्पत्ति विषयक अधिकारों के संरक्षण पर सर्वाधिक सक्रियता एवं उत्साह से भाग लेना पड़ा। सरदार की दृष्टि में ऐसा संरक्षण देश के भविष्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण था क्योंकि यह आन्तरिक और बाह्य पूँजी के आकर्षण को जन्म देने में सहायक होगा। परन्तु कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन के वचन एवं नीति के साथ इस संरक्षण का तालमेल बैठाने में सरदार पटेल को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविन्द वल्लभ पन्त का तर्क था कि उचित मुआवजा तय करने की अन्तिम शक्ति विधानसभा के पास हो। मुआवजा का औचित्य राज्य की क्षमता तथा सम्पत्ति ग्रहण करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाय। कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के लोग किसी भी प्रकार का मुआवजा न देने के पक्ष में थे। परन्तु सरदार किसी की भी व्यक्तिगत भूमि का अधिग्रहण बिना मुआवजा दिये 'चोरी तथा डकैती मानते थे।'⁹⁴

काफी वाद विवाद के बाद सविधान सभा ने सम्पत्ति के अधिकार को सविधान द्वारा संरक्षित बनाया तथा मुआवजे हेतु उसे विधि न्यायालय में अपील की परिधि में रखा। एक मध्यम मार्ग निकालकर जमींदारी उन्मूलन संबंधी धारा को सम्पत्ति के मूल अधिकार संबंधी धारा से अलग कर दिया गया।

अल्पसंख्यक समिति—

देश की एकता एवं अखण्डता के लिए सरदार पटेल की एक अन्य उपलब्धि उनके अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाह की गयी भूमिका से दृष्टिगोचर होते हैं। वे अल्पसंख्यकों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते थे। उनके उत्थान के लिए विभिन्न कार्य, सामाजिक एवं आर्थिक दोनों क्षेत्रों में किये। अल्पसंख्यकों के लिए नौकरियों और चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा के साथ अलग चुनाव क्षेत्र रखने की मांग पर सरदार पटेल ने 25 अगस्त, 1947 ई० को सविधान निर्मात्री सभा के समक्ष विचारार्थ एक प्रस्ताव प्रस्तुत

किया। “जिसमे उन्होंने अलग चुनाव क्षेत्र की माँग अस्वीकार कर दिया था पर विधान सभाओं के चुनाव में जनसंख्या के आधार पर दस वर्ष तक सम्मिलित आरक्षित चुनाव क्षेत्रों की स्वीकृति प्रदान की थी। दस वर्षों के बाद इस व्यवस्था की पुनर्समीक्षा किये जाने की व्यवस्था की गई थी।”⁹⁵

अल्पसंख्यकों को तीन वर्गों में बाँटा गया था। वर्ग ए में एंग्लो इंडियन, पारसी, असम के मैदानी भागों की जनजातियों को रखा गया था। जो देश की आबादी का आधा प्रतिशत थी। वर्ग बी में सिक्ख, भारतीय ईसाइयों को रखा गया जो देश की आबादी का आधे से अधिक पर डेढ़ प्रतिशत से कम थे। वर्ग सी में मुसलमानों और अनुसूचित जातियों को रखा गया। समिति ने यह सिफारिस की थी कि सभी चुनाव सम्मिलित रूप से कराये जायेंगे और जनसंख्या के आधार पर उपर्युक्त अल्पसंख्यकों को सीटें आरक्षित कर दी जायेंगी तथा अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों को अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ने की छूट होगी। मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों को आरक्षण की माँग को समिति ने नामजूर कर दिया पर इस बात की मजूरी दे दी, कि 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के आठवें पैराग्राफ के अनुसार व्यवस्था की जायेगी।

सरकारी सेवाओं में आरक्षण की माँग के सबंध में यह मजूर किया गया था कि प्रशासनिक क्षमता के आधार पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान किये जाने की बात ध्यान में रखी जायेगी। इस रिपोर्ट की मजूरी हेतु सविधान निर्मात्री सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि यह विषय अत्यन्त संवेदनशील है इसलिए ऐसे उत्तेजक तर्क प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे जो किसी तरह के विवाद को जन्म दे सकते हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए सरदार पटेल ने विधान सभाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की बात स्वीकार की थी। ऐसा बाद की वार्ता से लगता है कि उन्होंने अपनी मूलभूत धारणाओं के विपरीत इसका समर्थन किया था, पर ऐसा करना उचित नहीं था। पर उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की माँग अस्वीकार देनी चाहिए।

सरदार पटेल ने सर्वप्रथम केन्द्रीय और प्रान्तीय सदनों के लिए संयुक्त चुनाव से तो

की व्यवस्था रखे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। श्री पोकर साहब ने एक सशोधन को प्रस्तुत कर मॉग की कि केन्द्रीय और प्रादेशिक सदनों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। इसका उत्तर देते हुए सरदार पटेल ने जोरदार शब्दों में इसे अस्वीकार करने की अपील की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि—

“आज इस साम्प्रदायिक सोच के कारण देश का बँटवारा हो जाने के बाद यह कभी नहीं सोचा था कि यह प्रस्ताव गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत किया जायेगा और यदि यह गम्भीरता पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है तो उसे गम्भीरतापूर्वक किया भी जायेगा। जब पाकिस्तान की मॉग स्वीकार की गयी थी तब कम से कम यह सोचा गया था कि शेष भारत में एक ही राष्ट्र होगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात करना निरर्थक है क्योंकि इसके संघर्ष के कारण हमारे देश का विभाजन हुआ।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा “हमें अपना स्वतंत्र राज्य दीजिये तब हमने कहा अपना स्वतंत्र राज्य ले लो क्या तुम अभी भी दो राष्ट्र बनाने की इच्छा रखते हो। मैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोधी हूँ तो क्या तुम मुझे एक भी ऐसा राष्ट्र बता सकते हो जहाँ पर ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हों, यदि ऐसा होते मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।”⁹⁶ उन्होंने ऐसा चाहने वालों की देश भक्ति पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए कहा था कि—

“ऐसा जो चाह रहा है, उनके लिए पाकिस्तान में जगह है, पर भारत में नहीं है। यहाँ पर हम एक भारत राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और एक राष्ट्र की नींव रख रहे हैं और जो पुनः विभाजित होना चाहते हैं और विभाजन की इच्छा रखते हैं उनके लिए यहाँ कोई जगह, कोई क्वार्टर-खाली नहीं है। यह मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ।”⁹⁷

एंग्लो इंडियन के प्रति उदारता का परिचय देते हुए सरदार पटेल ने संविधान में व्यवस्था दी कि यदि वे सामान्य चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न कर सकें, तो संघ के राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपाल को उनके प्रतिनिधि को केन्द्र व राज्यों की व्यवस्थापिका सभाओं में मनोनीत करने का अधिकार है।’ इस संबंध में 26 मई, 1949 ई० को सरदार

९६ देसाई धीरू भाई का व्याख्यान उद्धृत सरदार साहित्य माला सम्पुट, पूर्वो, पृ० 100

९७ वही, वाल्यूम- 4, पृ० 578

पटेल द्वारा सविधान सभा में दिये गये भाषण की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।”

प्रान्तीय समिति—प्रान्तीय सविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल ने एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना पर बल दिया। सरदार पटेल की सिफारिश पर प्रान्तों के मुख्यमंत्रियों ने उन सब धाराओं को स्वीकार कर लिया जो शक्तिशाली केन्द्र को जन्म देने में सहायक बनीं। सरदार पटेल का तर्क था कि इतिहास साक्षी है कि जब-जब केन्द्र दुर्बल हुआ, उसकी अखण्डता पर आँच आयी। यद्यपि उस समय कुछ प्रान्तों में गोविन्द वल्लभ पन्त, वी०सी० राय, रविशंकर शुक्ला जैसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री थे परन्तु उन्होंने सरदार के विचारों को स्वीकार कर लिया। शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना के लिए भारतीय सविधान में अनु० 356 की व्यवस्था की गयी। जिसके अनुसार कानून और व्यवस्था भग होने की स्थिति में संघ, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करके प्रशासन स्वयं अपने हाथ में या अधीनस्थों के हाथ में सौंप देता है।

राज्यपालों के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के संबंध में भी सरदार पटेल ने एक फार्मूले की रचना की, जिसके द्वारा राज्यपाल अपनी संवैधानिक स्थिति को हानि पहुँचाये बिना रचनात्मक भाग अदा कर सकें। वे एक ओर अपने मंत्रिमंडल को सलाह दे सकें तो दूसरी ओर केन्द्र और राज्य के बीच कड़ी का कार्य कर सकें। श्री विष्णु कामथ, श्री एम०एच० मोहिनी, प० हृदय नाथ कुजरा, श्री के० सथानम् तथा प० गोविन्द वल्लभ पन्त से इस विषय पर उनका घोर वाद विवाद हुआ। क्योंकि ये प्रभावशाली नेता प्रान्तों को और स्वायत्ता देने के पक्ष में थे। राज्यपाल के चुनाव को भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने में बदले जाने का निर्णय उपरोक्त नेताओं के तर्क तथा केन्द्र राज्य संबंधों में राज्यपाल कड़ी का कार्य करे, के कारण लिया गया। प० गोविन्द वल्लभ पन्त में राज्यपाल की अनुपस्थिति में एक उपराज्यपाल का विकल्प प्रस्तुत किया था।

प० गोविन्द वल्लभ पन्त के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मूल प्रस्ताव में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपालों को दिया गया था और इसके लिए विधानमंडल के दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति लेना अनिवार्य किया गया था। बाद में यह अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान कर दिया गया जिसके अनुसार राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। सविधान निर्मात्री सभा में इस प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि पुनरावलोकित प्रस्ताव इस ढंग से तैयार किये गये हैं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से की जाय। जिससे न्यायापालिका दलगत प्रभावों से दूर रहे।

राज्यों की स्थिरता, सुदृढता व न्याय के लिए सरदार पटेल ने निष्पक्ष तथा साफ सुथरे चुनावों की आवश्यकता पर बल देते हुए सविधान सभा में निम्न सुझाव दिया।

“इस सबंध में मैं सोचता हूँ कि समिति को एक सस्तुति करनी चाहिये जिसमें निश्चिन्तापूर्ण स्वतंत्र चुनावों की आशा से सघ के राष्ट्रपति द्वारा एक चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाय ताकि समस्त राज्यों में साफ सुथरे चुनाव हो सकें।”⁹⁸

अतएव सरदार की इच्छानुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान सविधान में किया गया।

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सरदार पटेल तथा नेहरू के मध्य असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। जवाहर लाल राष्ट्रपति के चुनाव के सबंध में चाहते थे कि मतदाता केवल ससद के सदस्य हों, इस प्रकार तो वह केवल सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री का ही मनोनीत व्यक्ति बन जाता, परिणामस्वरूप सरदार पटेल की प्रान्तीय समिति ने उस पर अपील की। सरदार पटेल ने राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट करते हुए तर्क दिया कि “चूँकि राष्ट्रपति केन्द्र और राज्य दोनों की व्यवस्थापिकाओं का संरक्षक है अतएव उसका चुनाव भी उनके समस्त सदस्यों द्वारा होना चाहिये। सविधान सभा में काफी विचार विमर्श के बाद सरदार के दृष्टिकोण का समर्थन किया और इस प्रकार सरदार पटेल के प्रयासों से राष्ट्रपति ससद की कठपुतली मात्र न बन पाया और देश की एकता तथा सम्पूर्ण प्रजा का प्रतीक बना।

जम्मू काश्मीर राज्य से संबंधित विशेष अनु० 370 पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा शेख अब्दुल्ला की सलाह एवं निर्देशन से श्री गोपालास्वामी आयर ने इस अनुच्छेद की व्यवस्था का प्रावधान किया था। सिद्धान्त रूप में कांग्रेस का यह मत था कि “काश्मीर को

भी उन्ही मूलभूत व्यवस्थाओं अर्थात् शर्तों के आधार पर सविधान को स्वीकार करना चाहिये, जिन शर्तों पर अन्य राज्यों ने उसे स्वीकार किया है।'

इस अनु० के प्रस्ताव में मूलभूत सिद्धान्तों के जम्मू काश्मीर पर लागू न करने के प्रावधान का जमकर विरोध हुआ। इस विरोध के समय नेहरू विदेश प्रवास पर थे तथा गोपालास्वामी आयरगर सदस्यों को सतुष्ट नहीं कर पा रहे थे तो हताश होकर सरदार पटेल से हस्तक्षेप की माँग की। नेहरू की अनुपस्थिति में दल को सतुष्ट करने का कार्य सरदार पटेल ने अपने हाथ में लिया। यह जानकर आश्चर्य होगा कि तत्पश्चात् दल में किसी प्रावधान का कोई विरोध नहीं हुआ और न ही सविधान सभा में चर्चा ही हुई। फलतः अनु० 370 सविधान में शामिल कर लिया गया।

इसी प्रकार भाषा संबंधी विवाद में जब पुरुषोत्तम दास टंडन ने राष्ट्रभाषा के रूप में सविधान सभा में हिन्दी के पक्ष का जोरदार समर्थन किया और परिणामस्वरूप विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गयी तब सविधान में हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में सरदार ने निर्णायक भूमिका अदा की।

सरदार पटेल और नेहरू मतभेद

सरदार पटेल और नेहरू के मध्य मतभेद अधिक ठोस थे और दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मियों में लिप्त कुछ लोगों का कार्यकलाप यही था कि वे दोनों के मध्य मतभेद बढ़ाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं देना चाहते थे। डॉ० वी० के० केसकर ने नेहरू पटेल धुरी को प्रत्येक दृष्टि से एक आश्चर्यजनक सगठन बताया जो दो विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण था, जो परस्पर एक दूसरे की क्षतिपूर्ति थे।⁹⁹ यद्यपि यह सही है कि दोनों के मध्य मतभेद रहे, वैचारिक असमानता रही, किन्तु देशभक्ति, आदर्शों के प्रति आस्था और नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा के कारण दोनों ने ही अपने विचारों के इस अन्तर और असमानता को कायम रखते हुए भी आपस में टकराने की कोशिश नहीं की।¹⁰⁰ महात्मा गाँधी के प्राइवेट सेक्रेटरी प्यारे लाल ने दोनों के मध्य मतभेदों के संबंध में अपने 'महात्मा गाँधी' नामक ग्रंथ में लिखा है कि—

९९ केसकर, वी०के०, नेहरू और पटेल, पृ० 91

१०० दास, सेठ गोविन्द, सरदार पटेल, दिल्ली, 1988, पृ० 102

“मतभेद मन्त्रिमंडल में भी थे। सरदार पटेल तथा प० नेहरू में सदा ही इस प्रकार के मतभेद रहे, जिनका सबध उनकी अपनी-अपनी निजी प्रकृति से था। विभिन्न प्रश्नों के सबध में उनके दृष्टिकोण में अन्तर था। नेहरू जी के हृदय तथा उनके मस्तिष्क की अप्रतिम विशेषताओं का सरदार के हृदय में बहुत अधिक मान था किन्तु उनको यह शिकायत रहती थी कि वह सदा ही अपने को बुरे परामर्शदाताओं से घिरा हुआ रखते थे और इसलिए उन पर पर्याप्त विश्वास नहीं रखते थे और इस प्रकार के कार्यों में लग जाया करते थे जिनमें उनकी सद्भिलाषाये लुप्त हो जाती थी। इसके विरुद्ध प० नेहरू सरदार पटेल की सर्तक बुद्धि, शासन सबधी प्रतिभा तथा सघर्ष करने के अप्रतिम गुणों के प्रशंसक थे और इसलिए वह उनके अतिरिक्त और किसी के आगे नहीं झुकते थे। नेहरू जी सरदार पटेल के विभिन्न प्रश्नों को हल करने की प्रणाली से असन्तुष्ट थे तथापि वे दोनों एक दूसरे को पूर्ण सहयोग देते थे।”¹⁰¹

नेहरू और पटेल के दृष्टिकोणों का अन्तर समझने के लिए उन दोनों की विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है जिसमें दोनों की विचारधारा की विचारधाराओं का विकास हुआ।

नेहरू का जन्म एक सम्पन्न एवं बुद्धिजीवी परिवार में हुआ। प्रारम्भ से ही इंग्लैण्ड में शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त उन्हें राजनीति के शीर्ष पर पहुँचने के लिए किसी प्रकार का सघर्ष नहीं करना पड़ा क्योंकि उनको राजनीति जीवन के प्रारम्भ से ही गान्धी जी सहित तमाम बड़े नेताओं का सतत समर्थन मिलता रहा था।

इसके विपरीत सरदार पटेल का जन्म साधारण से किसान परिवार में हुआ था परिणामस्वरूप उन्हें बचपन से ही सघर्षों का सामना करना पड़ा। अतएव वे स्वभाव से कठोर हो गये और कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने की उनमें क्षमता थी और उनकी इच्छाशक्ति लौहिक थी।

इस प्रकार इन दो विभिन्न वातावरणों में दोनों महापुरुषों के राजनीतिक विचारधारा

का विकास दो विपरीत विचारधाराओं के रूप में हुआ। नेहरू प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति माने जाते थे तो सरदार पटेल रूढ़िवादी विचारधारा का नेतृत्व करते थे। इन दोनों विपरीत स्वभाव की विभूतियों की एकता के सूत्र में बाँधने का कार्य महात्मा गाँधी ने किया। दोनों ही महात्मा गाँधी के भक्त थे। नेहरू की उदारता, निष्कपट स्वभाव तथा उनके व्यक्तिगत चरित्र के कारण गाँधी जी उन्हें पुत्र के समान समझते थे तथा 1929 में सबसे कम आयु का कांग्रेस अध्यक्ष बनवाया तो दूसरी तरफ वह सरदार पटेल की कर्मठता एवं लगन से प्रभावित थे। 1931 के कराची अधिवेशन में गाँधी जी ने कहा था कि—

“जवाहर लाल विचारक हैं और सरदार पटेल कार्य करने वाले हैं।” यद्यपि देश की आजादी की लड़ाई में दोनों के मध्य मतभेद सार्वजनिक नहीं हुए किन्तु आजादी प्राप्ति के प्रारम्भिक वर्षों में ही दोनों के मध्य मतभेद सार्वजनिक रूप से उजागर होने लगे। उन दोनों के मध्य बढ़ते मतभेद से अपने अन्तिम दिनों में गाँधी भी चिन्तित रहते थे। गाँधी जी की मृत्यु के पूर्व मतभेद इतने उग्र हो गये थे कि दोनों ने त्यागपत्र देने की पेशकश की थी। पटेल और नेहरू के मध्य कुछ प्रमुख विवादित विषयों का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है।

1 नेहरू फेवियन समाजवाद एवं अन्तर्राष्ट्रीयता में विश्वास रखते थे जबकि सरदार पटेल ने अपने किसी निश्चितवाद से नहीं जोड़ा परन्तु अपने विचारों से वे पूँजीवाद को समाज के लिए आवश्यक मानते थे। अमेरिकन पत्रकार विसैट शीन के अनुसार—“सरदार पटेल की गाँधीवादी विचारधारा पूँजीवादी विकास के पक्ष में थी, जबकि नेहरू अपनी गाँधीवादी विचारधारा में सोसलिस्ट सिद्धान्तों को विकसित करना चाहते थे।”¹⁰²

2 नेहरू और सरदार पटेल के मध्य जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतों को भारत में विलय के प्रश्न को लेकर था। सरदार पटेल इन रियासतों को बहुत समझाया बुझाया पर जब ये नहीं माने तो उन्होंने राष्ट्रहित में तथा राष्ट्र की अखण्डता को सुनिश्चित करने हेतु बल प्रयोग का प्रस्ताव किया जिसका नेहरू ने विरोध किया। उनकी नजर में ऐसा करना साम्प्रदायिक कार्य होगा। इस प्रश्न को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि “सरदार ने

मन्त्रिमण्डल से त्याग पत्र देने का फैसला ले लिया था।”¹⁰³ अन्ततः बाध्य होकर भारी मन से नेहरू को सैनिक कार्यवाही के लिए सहमत होना पड़ा।

3 काश्मीर के प्रश्न पर भी दोनों नेताओं में मतभेद थे। काश्मीर सरदार पटेल के मन्त्रालय के अधीन था लेकिन नेहरू ने इस समस्या को अपने हाथ में लेकर सरदार पटेल को इसके हक से वंचित कर दिया। नेहरू इसे अन्तर्राष्ट्रीय समस्या मानकर जनवरी, 1948 ई० को संयुक्त राष्ट्र सभ में ले गये जिसका पुरजोर विरोध सरदार पटेल ने किया। साथ ही सरदार पटेल जम्मू-काश्मीर राज्य में सवैधानिक रूप से कार्य करने वाली सरकार के पक्ष में थे, अतएव अब्दुल्ला को नेहरू द्वारा आवश्यकता से अधिक महत्व देने से सतुष्ट न थे। 8 जून, 1948 ई० को नेहरू को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि

“हमें महाराणा तथा शेख अब्दुल्ला के बीच मतभेदों की खाई को पाटने का प्रयास करना चाहिये।”¹⁰⁴

4 राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के सबंध में सरदार पटेल सदैव वह सोचते थे कि व्यावहारिक कारणों से राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहना भारत के हित में होगा। दूसरी ओर कांग्रेस वर्षों से पूर्ण स्वराज्य के सकल्प से वचनबद्ध हो चुकी थी। जिसका अर्थ था राष्ट्रमण्डल से सबंध विच्छेद। नेहरू का मत था कि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता का भारत के गणतंत्र से मेल नहीं बैठता। परन्तु सरदार के प्रबल समर्थन और यथार्थवादी परामर्श से नेहरू भी इसके समर्थन बन गये।

5 चीन के साथ मित्रता को सरदार पटेल शका की दृष्टि से देखते थे। 1950 ई० में चीन ने तिब्बत के कुछ भागों में प्रवेश किया तो 7 नवम्बर, 1950 ई० को अपने एक लम्बे पत्र में सरदार पटेल ने नेहरू को चीन से गम्भीर खतरे की चेतावनी दी थी। “उन्होंने सुझाव दिया कि प्रासंगिक विचारों के प्रकाश में हमारे प्रतिरक्षा मोर्चों तथा दीर्घकालीन व्यवस्थाओं पर पुनः सोचा जाना चाहिए।”¹⁰⁵

6 धर्म निरपेक्षता को लेकर भी दोनों नेताओं में विवाद था। नेहरू की नजर में जिस कदम से मुसलमानों को कष्ट हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय बदनामी के भाव प्रकट होते हो वह धर्म

१०३ वही, पृ० 198

१०४ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार दिल्ली, 1997, पृ० 154

१०५ वही, पृ० 199

निरपेक्ष कदम नहीं है जबकि सरदार पटेल धर्म निरपेक्षता को राष्ट्रहित की दृष्टि से देखते हैं और कोई भी ऐसा कदम उठाने को धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध नहीं मानते थे जिससे कि राष्ट्र का हित हो। साथ ही पटेल नेहरू की इस बात से भी नाराज रहते थे कि वे अनावश्यक रूप से मुसलमानों को आवश्यकता से अधिक महत्व देते थे।

7 नोआखाली दंगों में सरदार पटेल, नेहरू और गाँधी की भूमिका से असंतुष्ट थे। वे सिखों और हिन्दुओं की हत्या से बहुत आहत थे अतः नेहरू तथा गाँधी द्वारा मुसलमानों के लिए अनुचित कृपा को पसन्द नहीं करते थे। गाँधी जी की नोआखाली यात्रा को भी सरदार ने उचित नहीं माना। सरदार ने एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए कहा था कि—

“जब तक मुसलमान भारत के प्रति अपनी भक्ति की घोषणा स्पष्ट शब्दों में नहीं कर देते उनका विश्वास नहीं किया जा सकता।”

8 नेहरू गृह मंत्रालय और देशी राज्य मंत्रालय में सरदार के कार्यों में दखल देते थे और शिकायत करते थे कि उन्हें राज्य में होने वाली घटनाओं से अवगत नहीं कराया जाता। इस प्रकार की शिकायतों से सरदार को कष्ट होता था।

9 भारत के प्रथम राष्ट्रपति के चयन को लेकर भी नेहरू और पटेल में मतभेद था। नेहरू राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। जबकि सरदार पटेल ने राजेन्द्र प्रसाद का प्रस्ताव रखा। इस पर नेहरू ने डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को पत्र लिखकर कहा कि राष्ट्रपति पद को लिए राजगोपालाचारी योग्य उम्मीदवार हैं अतः आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस पत्र की राजेन्द्र प्रसाद की तरफ से तीव्र प्रतिक्रिया हुई और जब नेहरू ने यह प्रश्न संविधान सभा के कांग्रेसी सदस्यों के बीच में उठाया तो उन्होंने राजेन्द्र प्रसाद का समर्थन किया। लेकिन सरदार ने उन्होंने समझाकर इस्तीफा न देने के लिए तैयार कर लिया।¹⁰⁶

10 1950 के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी पटेल और नेहरू के मध्य मतभेद हुए। नेहरू पुरुषोत्तमदास टंडन को अध्यक्ष बनाये जाने के विरुद्ध थे जबकि सरदार पटेल ने उनका समर्थन किया। नेहरू ने कहा कि “मेरा मन, इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर टंडन जी कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं तो मुझे मानना चाहिए कि कांग्रेसीजन मुझमें

विश्वास नहीं करते फलतः मैं कांग्रेस कार्यकारिणी में कार्य नहीं कर सकता यानी मैं प्रधानमंत्री नहीं रह सकता।”¹⁰⁷ अन्ततः पुरुषोत्तम दास टंडन बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिये गये।

यद्यपि नेहरू और पटेल के दृष्टिकोणों में पर्याप्त असमानता थी, परन्तु दोनों ही राष्ट्ररूपी रथ के दो विभिन्न छोर थे। आधुनिक भारत के निर्माण में दोनों का सर्वांगीण योगदान है। एक ने राष्ट्रीय प्रगति की तो दूसरे ने उसे गति प्रदान की। दूसरे शब्दों में एक ने राष्ट्र रूपी इमारत की नींव भरी, तो दूसरे ने उसे खड़ा किया। सरदार की मृत्यु पर नेहरू ने उनके योगदान को स्वीकार करते हुए कहा कि—

“सकट और विजय के समय में हम उनकी मजबूत आवाज सुनते थे। वे ऐसे मित्र और सहयोगी थे, जिन पर पूरा भरोसा किया जा सकता था, वह ऐसे शक्ति स्तम्भ थे जिससे दुर्बल हृदय भी मजबूत हो जाते थे।”¹⁰⁸

१०७ शंकर, बी० सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार, खण्ड 2 अहमदाबाद, 1976, पृ० 523-24

१०८ मेहरोत्रा एव कपूर, पूर्वो, पृ० 201

अध्याय 5

- I काश्मीर समस्या पर सरदार पटेल के विचार
 - II गोवा समस्या पर सरदार पटेल के विचार
 - III नेपाल के सम्बन्ध में विचार
 - IV मुस्लिम लीग के प्रति दृष्टिकोण
 - V राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति दृष्टिकोण
 - VI सरदार पटेल के अन्य राजनीतिक विचार
 - VII सामाजिक विचार
 - VIII आर्थिक विचार
-
-

काश्मीर समस्या पर सरदार पटेल के विचार

के०एम० मुशी ने लिखा है कि, “यदि शेख अब्दुल्ला के प्रभाव से जवाहर लाल नेहरू काश्मीर विभाग पटेल के रियासत विभाग से न लेते, तो काश्मीर कभी भी एक समस्या न बनती जैसा कि अब बन गयी है।”¹

भारत और पाकिस्तान के मध्य की काश्मीर समस्या वर्तमान समय में विश्व की सबसे विकराल समस्याओं में गिनी जाती है। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित यह राज्य भारत तथा पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। सामरिक दृष्टि से काश्मीर की सीमा अफगानिस्तान एवं चीन से मिली हुई है तथा सोवियत संघ की सीमा कुछ ही दूरी पर है। “आजादी के समय काश्मीर की बहुसंख्यक जनता लगभग 79% मुस्लिम धर्मी थी परन्तु वहाँ के अनुवांशिक शासक हिन्दू थे।”² तत्कालीन शासक हरी सिंह के खिलाफ 1946 ई० में शेख अब्दुल्ला ने “काश्मीर छोड़ कर चले जाओ का नारा बुलन्द किया।”³ परिणामस्वरूप अब्दुला को जेल में डाल दिया गया तथा उनके समर्थन में सभा करने के लिए, चेतावनी के बावजूद वहाँ गये हुए, नेहरू जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। काश्मीर समस्या पर सरदार पटेल ने विशेष रुचि लेते हुए 3 जुलाई, 1947 ई० को महाराजा को पत्र लिख कर नेहरू की गिरफ्तारी की निंदा की तथा अपना क्षोभ प्रकट किया। अपने पत्र में सरदार पटेल ने लिखा, “मैं आपकी रियासत की भौगोलिक दृष्टि से नाजुक स्थिति को समझता हूँ परन्तु एक सच्चे मित्र और शुभचिन्तक के रूप में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि काश्मीर का हित अविलम्ब भारतीय संघ तथा संविधान सभा में सम्मिलित होने में ही है।”⁴ ब्रिटिश सत्ता के स्थानान्तरण के समय काश्मीर के दीवान प० रामचन्द्र काक थे। काश्मीर नरेश हरी

१ मुशी, के०एम०, इंडियन कान्स्टीट्यूशन डाक्यूमेन्ट्स, वॉल्यूम -2, बम्बई, 1962, पृ० 175

२ मेहरोत्रा, एन० सी०, कपूर रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 152

३ पटेल, राव जी भाई, हिन्दू के सरदार, अहमदाबाद, 1972, पृ० 300

४ वही, पृ० 30

सिंह ने एक स्वतंत्र काश्मीर की कल्पना की तथा दुविधापूर्ण नीति अपनाकर भारत तथा पाकिस्तान दोनों से 'यथास्थिति समझौता' करना उचित समझा। पाकिस्तान ने यथास्थिति समझौता स्वीकार कर लिया तथा यातायात एवं डाक तार व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाये रखने का वचन दिया। इसके पूर्व की भारत से बाचतीत हो, पाकिस्तान ने काश्मीर से सबध तोड़ते हुए अनाज, पेट्रोल आदि जरूरी चीजे बन्द कर दी और काश्मीर पर कब्जा करने की नीयत से सीमा प्रान्त पर मुस्लिम दगाइयों की बहुत बड़ी सख्या को घुसपैठ करने के लिए प्रेरित किया। दगाइयों को पाकिस्तान ने यातायात तथा हाथियारों से लैस करके सीमा में प्रवेश दिला दिया। दगाई बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे साथ ही प्रजा पर अत्याचार करने लगे। "देखते ही देखते दगाई काश्मीर सीमा में वारामूला तक घुस आये और उन्होंने ऐलान किया कि वे 26 अक्टूबर 1946 ई० की ईद काश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ही मनायेगे।"

ऐसी सकटपूर्ण स्थिति में काश्मीर की राजधानी के शासक हरी सिंह ने 24 अक्टूबर, 1947 को प्रथम बार भारत सरकार से सहायता माँगी। महाराजा के विरोधी शेख अब्दुल्ला ने भी भारत से सहायता का अनुरोध किया। इसी बीच पता चला कि दगाइयों ने मुजफ्फराबाद पर भी अधिकार कर लिया है। स्थिति की वास्तविक जानकारी हेतु भारत की सुरक्षा समिति ने वी०पी० मेनन को काश्मीर भेजा। 26 अक्टूबर, 1947 ई० को महाराजा ने लार्ड माउण्ट बेटेन को लिखे पत्र में काश्मीर की विस्फोटक स्थिति पर चर्चा करते हुए लिखा-

"राज्य की वर्तमान स्थिति तथा सकट को देखते हुए मेरे सामने इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है कि मैं भारतीय अधिराज्य से सहायता माँगू। यह स्वाभाविक है कि जब तक काश्मीर भारतीय अधिराज्य में शामिल नहीं हो जाता, भारत सरकार मेरी सहायता नहीं कर सकती, अतएव मैंने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं प्रवेश पत्र आपकी सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेज रहा हूँ।"⁵ पत्र के अन्त में उन्होंने कहा कि यदि राज्य को बचाना है तो तत्काकल श्रीनगर को सहायता पहुँचायी जाय। श्री मेनन स्थिति की गम्भीरता से भलीभाँति परिचित है।"⁶

५ दास, दुर्गा, सरदार पटेल करेसपाण्डेन्स (1945-50) खण्ड 8, अहमदाबाद, 1973, पृ० 339-341

६ वही, पृ० 339-341

“श्री मेनन एकीकरण के इकरार पर महाराज के हस्ताक्षर को लेकर दिल्ली पहुँचे जहाँ सरदार पटेल हवाई अड्डे पर उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे।”⁷ वहाँ से वे सीधे सुरक्षा समिति की बैठक में गये। काफी लम्बे वाद-विवाद के उपरान्त यह निश्चय किया गया कि महाराजा की प्रार्थना को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाय कि शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद जम्मू काश्मीर में विलय पर जनमत संग्रह कराया जाये। सरदार पटेल ने कहा कि यदि आक्रमण करने में देरी की गयी तो भारत का वातावरण भी हिंसामय हो जायेगा। अतएव बगैर प्रतीक्षा किये सेना को बिना पूर्व सूचना के 26 अक्टूबर की शाम को आदेश दिया गया कि वे घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए काश्मीर पर आक्रमण करें। 27 अक्टूबर को तत्काल सेनाये हवाई जहाज द्वारा काश्मीर भेज दी गयी। भारतीय सेनाओं की कार्यवाही इतनी अचानक, इतनी तेज और इतनी प्रभावशाली थी कि श्रीनगर पहुँचते ही आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। 3 नवम्बर को सरदार पटेल रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के साथ श्रीनगर जाकर वहाँ की स्थिति की समीक्षा की तथा काश्मीर मंत्री बिग्रेडियर एल०पी० सेन से सैनिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। 18 नवम्बर को भारतीय सेनाओं ने बारामूला पर अधिकार कर लिया।

28 नवम्बर को सरदार पटेल स्वयं जम्मू गये और वहाँ की जनता को सान्त्वना देते हुए कहा—“मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम काश्मीर बचाने के लिए अपनी शक्ति भर सब कुछ करेंगे।”⁸ जनता को निडर होकर स्थिति का सामना करने की सलाह देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि “मृत्यु निश्चित है। वह शीघ्र या विलम्ब में अवश्य आयेगी। परन्तु लगातार भय में रहना प्रतिदिन मरने के समान है, अतः हमें निडर होकर रहना है।”⁹ 1 जनवरी, 1948 ई० को भारत सरकार ने काश्मीर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सभ की सुरक्षा परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया। सरदार पटेल काश्मीर मसले को सुरक्षा परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मत यह था कि “काश्मीर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सभ को न सौंपा जाय। जिस प्रकार हैदराबाद का प्रश्न हल हुआ था, उसी प्रकार काश्मीर का प्रश्न भी हल करने की उनकी दृष्टि थी।”¹⁰

७ पटेल, राव जी भाई, पूर्वो पृ० 303

८ नन्दूकर, जी०एम०, सरदार पटेल, इन दि टियुन विद दि मिलियन्स, खण्ड- 1, अहमदाबाद, 1974, पृ० 73

९ वही, पृ० 73

सरदार पटेल जम्मू काश्मीर में सवैधानिक रूप से कार्य करने वाली सरकार के पक्ष में थे। परन्तु साथ ही वे शेख अब्दुल्ला का महाराजा हरी सिंह के प्रति व्यवहार तथा नेहरू द्वारा शेख अब्दुल्ला को आवश्यकता से अधिक महत्व देने से भी सतुष्ट न थे। 8 जून, 1948 ई० को नेहरू को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि “हमें महाराजा और शेख अब्दुल्ला के बीच खाई को पाटने का कार्य करना चाहिए।”¹¹

शेख अब्दुल्ला के बारे में विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने गान्धी जी को लिखा कि “शेख अब्दुल्ला विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है।”¹² सरदार पटेल अब्दुला के प्रभाव से जम्मू काश्मीर को प्रदान की गयी विशेष स्थिति को समाप्त करने का सुझाव देते हुए कहा कि—“काश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त कर, उसे पूर्ण रूप से मिला लिया जाय तथा वहाँ जाने में अन्य भारतीयों पर लगी पाबन्दी हटा दी जाय।”¹³ सरदार पटेल, नेहरू द्वारा काश्मीर समस्या को रियासत विभाग से छीनकर अपने हाथ में ले लेने से दुःखी थे। इस सबध में उनका कथन था कि “यदि काश्मीर का मामला उनके निर्देशन में सुलझाया जाये तो वे उसका निर्णय 15 दिन में कर सकते हैं।”¹⁴

काश्मीर समस्या का समाधान

काश्मीर का मुद्दा आज एक विकट समस्या नहीं बनता अगर नेहरू के स्थान पर सरदार पटेल को इसके निराकरण का दायित्व दिया जाता। पटेल ने मीनू भसानी से यह बात कही कि अगर नेहरू बीच में न होते तो शीघ्र ही वे काश्मीर मामले का समाधान कर लेते। काश्मीर पाकिस्तान को तथा पूर्वो पाकिस्तान भारत को देकर। दोनों देशों के लिए यह लाभदायक होता।¹⁵ वी०पी० मेनन के भी यही विचार थे। पटेल इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जिन्ना उनका यह सुझाव भावात्मक व व्यावहारिक कारणों से स्वीकार कर लेंगे। काश्मीर गर्मी की तपन से राहत दिलाने के लिए, जिन्ना के लिए, उनके हृदय के अधिक करीब था तो पूर्वो पाकिस्तान हिन्दू बगाल के अधिक करीब था तथा भाषा व

१० पटेल, राव जी भाई, पूर्वो, पृ० 305

११ दास, दुर्गा, सरदार पटेल करसपोन्डेन्स, (1945-50), खण्ड एक, अहमदाबाद, 1973, पृ० 194

१२ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 155

१३ वही, पृ० 156

१४ वही, पृ० 156

१५ कृष्णा, बी०, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इण्डियाज आयरन मैन, नयी दिल्ली, 1995, पृ० 518

संस्कृति की दृष्टि से भारत के निकट था। पटेल की यह सोच ठोस तर्क पर आधारित थी। वे चाहते थे कि काश्मीर मसले का निराकरण हो ताकि बाह्य ताकतों को इस मामले में उलझाने का मौका न मिले और दोनों देशों के संबंधों में कटुता न आये। इस आदान प्रदान से दोनों देश लाभान्वित होते, उनकी विकास प्रक्रिया प्रतिरक्षा व्यय के भार से अवरुद्ध नहीं होती, उनके बीच फासले नहीं बढ़ते। पटेल की समझ यथार्थ पर आधारित थी। उनका सोचना बहुत सीमा तक व्यवहारिक था। दोनों बंगाल आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे के पूरक थे। दोनों की एकता से धर्म निरपेक्ष नीति को बल मिलता किन्तु विभाजन ने पूर्वोपाकिस्तान के रूप में भारत की पूर्वो सीमा पर भी एक विरोधी खड़ा कर दिया। 1960 ई० में नागा आन्दोलन को पूर्वोपाकिस्तान का सहयोग मिला। पटेल के निर्णय पर हम चलते तो इस प्रकार के क्षेत्रीयतावाद व अलगाववाद की मानसिकता देश पर कभी हावी नहीं होती और काश्मीर समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण न होता।

नेपाल संबंधी विचार

नेपाल के विषय में भी नेहरू और पटेल के अलग-अलग विचार थे। 1950 ई० में जब नेपाल के राजा ने भारतीय दूतावास में शरण माँगी तो नेहरू भावात्मक रूप से उनका समर्थन कर रहे थे। क्योंकि उनके अनुसार वह जनता का प्रतिनिधि था, जबकि सरदार पटेल की दृष्टि भविष्य पर टिकी थी। उनका यह निश्चित मत था कि राजा का प्रशासन स्थिरता प्रदान नहीं कर सकता है तथा दोनों देशों के बीच समान शासन प्रणालियाँ, घनिष्ठ संबंध बना सकती हैं। आज भी नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्रों का गढ़ बन गया है तथा वहाँ भारत विरोधी तत्वों का जमावड़ा हो गया है।

गोवा समस्या संबंधी विचार

गोवा की भी वही कहानी रही। नेहरू ने स्वयं स्वीकार किया कि वर्षों तक गोवा हीनता एवं उलझन का कारण बना रहा।

के पी०एस० मेनन ने गोवा पर 1950 ई० में विदेश संबंधों की समिति की चर्चा का जिक्र किया कि राज गोपालाचारी प्रेम से गोवा को जीतने के पक्ष में थे, यद्यपि प्रेम देश के विभाजन को नहीं रोक सका। इस परिचर्चा में सरदार पटेल मौन रहे। दो घंटे की बहस

के बाद सरदार पटेल ने कहा “क्या हम चले मात्र दो घंटे का कार्य है।”¹⁶ अर्थात् पटेल विवाद नहीं कार्य में विश्वास रखते थे, उनका विश्वास था कि वे दो घण्टों में गोवा पर जीत हासिल कर लेंगे। नेहरू ने इसका विरोध किया क्योंकि वह अहिंसा की नीति के खिलाफ था। इससे अन्तर्राष्ट्रीय मुश्किलें पैदा हो सकती थीं। पर नेहरू की अनिश्चितता हमेशा देश की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पायी। नेहरू जितने अनिश्चित रहे, सरदार पटेल उतने ही स्पष्ट व स्थिर-विचार वाले। वे जानते थे कि गोवा भारत का अभिन्न अंग है। मई, 1949 ई० में गोवा कांग्रेस अध्यक्ष को दिया गया अपना वचन याद था, गोवा पुन अपनी मातृभूमि से जुड़ेगा। पटेल गोवा के सबंध में अपने निर्णय को लागू नहीं कर सके क्योंकि गोवा विदेशी ताकत के अधीन था और प्रधानमंत्री नेहरू के निर्णय क्षेत्र में रहा।

पटेल ने मई, 1950 ई० में पुन गोवा पर अपनी इच्छा प्रकट की जब वे जहाज द्वारा बम्बई से कोचीन गये। जब जहाज गोवा के निकट से गुजरा तो पटेल ने जहाज के कप्तान को गोवा के निकट ले जाने को कहा। मुस्कराकर पटेल ने पूछा तुम्हारे पास कितने लोग जहाज में हैं। “कप्तान ने जब 800 लोगों के होने की सूचना दी, तो पटेल ने कहा चलो जब हम यहाँ आ गये तो गोवा को भी ले ले। जब कप्तान ने लिखित आदेश की माँग की तो पटेल मुस्कराये और कहा शायद नेहरू इसका विरोध करेगा। अतः हमें वापस चलना चाहिये।”¹⁷

मुस्लिम लीग के प्रति दृष्टिकोण

मुस्लिम लीग का जन्म कांग्रेस के विरोध में कुछ कुलीनवर्गीय मुसलमानों द्वारा 1906 ई० में ढाका में हुआ, जिसने धीरे-धीरे अपने पैर जमाते हुए 1940 ई० में भारत विभाजन की माँग रखकर पाकिस्तान नामक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव किया। 1940 की अवधि तक मुस्लिम लीग के प्रति सरदार पटेल का कोई खास दृष्टिकोण नहीं था, क्योंकि उस समय तक यह कोई विशेष प्रभाव नहीं रखती थी। 1930-40 के दशक में जिन्ना के लीग में सक्रिय होने के उपरान्त इसने देश विभाजन की भूमिका तैयार करने का कार्य किया। 1937 ई० के चुनाव में मुस्लिम लीग कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायी। लेकिन फिर भी बम्बई और

१६ मेनन, के०पी०एस०, मैनी वर्ल्ड्स, रेकोटेड, पृ० 273-74

१७ कृष्णा, बी०, इण्डियाज आयरन मैन, नयी दिल्ली, 1995, पृ०, 522

उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें जीतकर कांग्रेस के साथ मंत्रिमंडल बनाने का प्रस्ताव किया जिसे नेहरू ने अस्वीकार कर दिया। गंधी जी के सचिव प्यारेलाल ने इसे “पहले दर्जे की नीतिगत गलती बताया”¹⁸ स्वयं जिन्ना ने कहा था कि, “यदि 1937 ई० में नेहरू यू०पी० की कांग्रेस सरकार में लीग को शामिल कर लेते तो पाकिस्तान न बनता।”¹⁹

प्रारम्भ में लीग के प्रति कोई खास दृष्टिकोण न रखने वाले सरदार पटेल जिन्ना द्वारा विभाजन की मांग रखने के बाद लीग के प्रति सजग हो गये। उन्होंने गंधी जी से बार-बार आग्रह किया कि लीगी नेताओं और लीग को आवश्यकता से अधिक महत्व देने की गलती न करें। 28 दिसम्बर, 1945 ई० को महात्मा गंधी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था —

“संयुक्त अधिवेशन तथा उसके बाद जिन्ना के अभद्र व्यवहार से हमें या कांग्रेस को उसके साथ बाँचनीत करना पसन्द नहीं है और वास्तविकता यह है कि असली तौर से किसी आपसी समाधान की उसकी इच्छा ही नहीं है।”²⁰

इसके उपरान्त भी लीग के साथ वार्ताएँ जारी रही और उसके हौसले बढ़ते रहे, फलस्वरूप मुस्लिम लीग के प्रति उनका रुख और कड़ा होता गया। यहाँ तक की मुसलमानों की उचित आशकाओं के प्रति भी वे आखे मूढ़ने लगे, लेकिन कांग्रेस और लीग के मध्य चलने वाली समझौता वार्ताओं में उन्होंने कभी भी बाधा डालने का कार्य नहीं किया और न ही समझौते की किसी कार्यवाही का सार्वजनिक विरोध ही किया। वे इस बात से परेशान रहते थे कि मुस्लिम लीग के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाया जाता। उन्हें यह भी नहीं रास आता था कि मुस्लिम लीग के साथ सख्ती से पेश आने के बजाय नरमी का रुख अपनाया जा रहा है।

हिन्दुओं के खिलाफ जिन्ना और लीग के आरोपों और उनकी अडंगेबाजी से सरदार क्षुब्ध थे और मुसलमानों में लीग की बढ़ती लोकप्रियता उन्हें निराश कर ही थी। जिसके कारण सरदार की पूरी सोच ही बदल गयी। वे इस बात से भी निराश थे कि मुसलमानों के सच्चे हित चितक महात्मा गंधी पर भी मुसलमान विश्वास नहीं करते थे। भारतीय राजनीति लगातार साम्प्रदायिक रुख अपनाती जा रही थी। पटेल का विचार था कि अब लीग का

१८ जकारिया, रफीक, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान, दिल्ली, 1948, पृ० 32

१९ वही, पृ० 31

२० नन्दूरकर, जी०एम०, सरदार लेटर्स मोस्टली अननोन, अहमदाबाद 1977, पृ० 177

मुकाबला किया जाना चाहिये। सद्भाव के प्रयासों से यदि समुचित उत्तर नहीं मिल रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिये। 1946 ई० के चुनावों में मिली लीग को सफलता के बावजूद सरदार पटेल भारत को एक रखने के सकल्प से डिगे नहीं। उनका विचार था कि “मुस्लिम लीग के असवेदनशील नेताओं से बातचीत करने के बजाय कांग्रेस को सामान्य मुसलमानों के बातचीत करनी चाहिये।”²¹ उनका मानना था कि यदि कांग्रेस के लोग “राजनीति में रुचि रखने वाले और प्रभावशाली मुसलमानों से निकट संबंध रखें तो शायद वे जिन्ना के तानाशाही नेतृत्व को कुछ कमजोर कर सकें। उन्हें आशा थी कि इस दिशा में किये गये ठोस प्रयासों का अच्छा परिणाम निकल सकता है। अपने पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि लीग और जिन्ना को करिश्मे के बावजूद सिन्ध, पंजाब और बंगाल जैसे मुसलमान बाहुल क्षेत्रों में लीग बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों के बीच पैर जमाने के जिन्ना के प्रयत्नों को विफल कर दिया था, सीमांत प्रदेश खामोश बना रहा। फिर भी मनोवैज्ञानिक वातावरण कुछ ऐसा था कि पटेल के सब साथी लीग के साथ समझौता करने के पक्ष में थे। गाँधी जी हमेशा आशावादी रहे, आजाद और गफ्फार खान किसी तरह हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य आपसी समझ चाहते थे जो उन्हें बिना लीग के सम्भव नहीं लगता था। राजाजी पूरी तरह से जिन्ना के साथ समझौते के पक्ष में थे। नेहरू दुविधा में थे जिन्हें जिन्ना पसन्द नहीं करते थे, पर वे भी साम्प्रदायिक टकराव के विचार से घृणा करते थे। यानी कुल मिलाकर दिग्गजों में सिर्फ सरदार पटेल ही लीग से सीधा मुकाबला करने के पक्ष में थे। सरदार के अनुसार जिन्ना समझाने बुझाने से बदलने की सीमा पार कर चुके थे। जिन्ना और लीग के प्रति गांधी जी के प्रेम के संबंध में उन्होंने गाँधी जी को लिखे पत्र में कहा था—

“बापू आपको एक पुरानी कहावत याद दिलाऊँ—प्यार के मामले में कम प्यार करने वाले का ही पलड़ा भारी रहता है।”²² अतः दृढ़ निश्चयी सरदार पटेल अपनी बात को अपने साथियों को मनवाने में सफल हो ही गये और कांग्रेस ने लीग के साथ संपर्क जोड़ने का विचार त्याग दिया। सरदार के दबाव में कांग्रेस के व्यवहार में आये अचानक परिवर्तन से जिन्ना परेशान हो उठे। उन्होंने आगा खॉं को मध्यस्थता के लिए सरदार के पास भेजा।

२१ दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 22 अक्टूबर, 1946

२२ दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 22 अक्टूबर, 1946

आगा खॉ ने कहा कि जिन्ना अब बदल गये हैं और अब वे बेहतर मन स्थिति में हैं। इसलिए समझौता करना चाहते हैं। तब सरदार पटेल ने आगा खॉ से पूछा “क्या बिच्छू कभी अपना रंग बदलता है?” परन्तु आगा खॉ फिर भी कोशिश करते रहे पर सरदार ने स्पष्ट कर दिया कि “जिन्ना हमें अपनी जाल में फसाने की कोशिश कर रहे हैं।” अब कांग्रेस का इस बात से विश्वास उठ गया था कि लीग से बातचीत का कोई निष्कर्ष निकल सकता है। अतएव लीग से किसी भी प्रकार के समझौते से इन्कार कर दिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति दृष्टिकोण

सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी तरह से देश की एकता एवं अखण्डता के लिए समर्पित थे। अतएव देश की एकता और अखण्डता के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी भी संगठन एवं व्यक्ति के प्रति वे कड़ा कदम उठाने से कभी नहीं हिचकिचाये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की एकता एवं अखण्डता की बात करता था। उसका श्रेष्ठ संगठन था लेकिन उसके द्वारा धर्म के नाम पर किये जाने वाले ऐसे कार्यों से, जिससे कि साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की सम्भावना हो, सरदार पटेल पसन्द नहीं करते थे। जैसे, मुस्लिम सम्प्रदाय गोमांस खाता है और इसके लिए वह गायों का वध करता है, उसके इस कार्य के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रोष व्यक्त करते हुए साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का कार्य किया। एक हिन्दू होते हुए भी सरदार पटेल को यह पसन्द नहीं था। स्वतंत्रता के समय ऐसी घटनाओं के सबंध में उन्होंने कहा था, “कुछ लोग इस समय गो रक्षा की बात करने लगे हैं। अभी तो बच्चों, स्त्रियों और बूढ़ों की रक्षा नहीं होती, तो गो रक्षा की बात कहाँ से आ गयी है। जिन राष्ट्रों में गो हत्या होती है वहाँ जैसी हृष्ट पुष्ट गायें हमारे यहाँ नहीं पायी जाती, यदि सचमुच गो रक्षा करनी हो तो गाय को अच्छी तरह पालना सीखिये।”²³

सरदार पटेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वेशभूषे के साथ डण्डे को लेकर चलने की प्रथा के विरोधी थे। उनकी नजर में इस प्रकार डण्डे लेकर चलना आतंक पैदा करने के कार्य के सदृश्य है जो देश की एकता और अखण्डता में बाधक है। 6 जनवरी, 1948 ई० को लखनऊ में एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था, “आर० एस० एस० वाले जिस प्रकार आजकल कामकर रहे हैं वह रास्ता गलत है। उन्हें गलत रास्ते से ठीक रास्ते

पर लाया जाये। डण्डे से कोई काम नहीं होगा। डडा तो चोर डाकू के लिए है।” उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ से अपील करते हुए कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण देता हूँ और देश में अशान्ति न उत्पन्न करने की तथा प्रशासन को कमजोर न करने की अपील करता हूँ। मैं कहता हूँ कि उन्हें व्यक्तिगत हित की दृष्टि के काम नहीं करना चाहिए क्योंकि परिस्थितियाँ सरकार के सिर पर शान्ति स्थापना का दबाव बारम्बार डाल रही है। वे हिंसा का प्रयोग करके देश की सच्ची सेवा नहीं कर रहे हैं।²⁴

30 जनवरी, 1948 ई० को सायंकाल 5 बजकर 5 मिनट पर जब गाँधी जी प्रार्थना मंच पर चढ़ ही रहे थे तो नाथूराम गोडसे नामक एक महाराष्ट्रीय युवक ने उनके ऊपर पिस्तौल की गोलियाँ छोड़कर उनकी हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ का सदस्य था। गाँधी की हत्या के उपरान्त महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश में हिंसा का वातावरण छा गया। सरदार पटेल ने इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ की नीतियों को जिम्मेदार मानते हुए 4 फरवरी, 1948 ई० को उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा सरकार ने जब यह पाया कि उसके तमाम सदस्य हिंसा फैलाने तथा समाज विरोधी कार्यों में लगे हुए हैं तो उन्होंने तय किया कि सघ को गैर वैधानिक संस्था घोषित कर दी जाय। “इसके उपरान्त 20,000 सदस्यों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली।”²⁵ उसके प्रमुख गोवलकर भी गिरफ्तार कर लिये गये। आर०एस०एस० पर यह प्रतिबन्ध रखा गया जब तक कि मार्च 1950 ई० में सघ ने देश में शान्ति की स्थापना के साथ-साथ किसी भी प्रकार के अराजकता सबधी कार्य को न करने का वचन दिया।

इस प्रकार सरदार पटेल देश की एकता और अखण्डता के लिए कट्टरवादी मुस्लिम नेतृत्व तथा हिन्दू नेतृत्व दोनों को सावधान किया, वक्त आने पर दोनों पर नियन्त्रण लगाने का निर्णय भी लिया।

२४ भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947-50 तक) प्रकाशन विभाग दिल्ली, 1954, पृ० 75

२५ मिश्रा, डी०पी०, लिविंग एन इरा, दिल्ली, 1978, पृ० 59

सरदार पटेल के अन्य राजनीतिक विचार

(i) प्रजातंत्र एवं अनुशासन

सरदार पटेल के जीवन की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि सरदार पटेल का प्रजातंत्र में पूर्ण विश्वास था। उन्होंने सरकार तथा संगठन के पदों पर रहते हुए तथा चलाये गये विभिन्न आन्दोलनों में कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों की सीमा को पार नहीं किया। साथ ही उनका विश्वास था कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए अनुशासन अनिवार्य है। सरदार पटेल अनुशासन के अधीन सिर्फ शासितों को ही नहीं, अपितु शासकों को भी रखते हैं। उन्होंने स्वयं अपने पूरे राजनैतिक जीवन में कभी अनुशासन भंग करने का कार्य नहीं किया तथा जिसने भी अनुशासन भंग करने का कार्य किया उसके साथ वे कठोरता से पेश आये। श्री मूर्ति प्रजातंत्र में सरदार पटेल की अनुशासन की प्रतिष्ठता के सबंध में लिखते हैं कि—

“सरदार अनुशासन की उच्च विकसित वृद्धि रखते थे। उनके व्यावहारिक अनुभव ने उन्हें दिखाया था कि स्वराज्य केवल वही बनाये रखा जा सकता है, जहाँ अनुशासन जीवन का एक भाग होता है। विशेष मूलभूत मानवीय मूल्यों से समझौता नहीं हो सकता। सरदार ने अनुशासन के इन्हीं मूलभूत मूल्यों को मुख्य महत्व प्रदान किया।”¹

प्रजातंत्र के सबंध में सरदार का कथन था- “प्रजा में ताकत होगी तो जिस वस्तु की आवश्यकता उसे होगी वह मिल जायेगी। यदि प्रजा को लगेगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वह स्वशासन के भी परित्याग का मार्ग अपना सकेगी। सत्याग्रह का वही स्वरूप होगा जो उन्होंने जीवन भर अपनाया।”²

(ii) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता—सरदार पटेल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अनु० 19

१ मूर्ति, आ०के०, सरदार पटेल, दि मैन एण्ड हिज कन्टेम्पोरेरिज, दिल्ली, 1976, पृ० 13

२ पटेल, सरदार के पत्रों का उद्धरण, सरदार की सीख, अहमदाबाद, 1950, पृ० 52

मे जिन छ स्वतंत्रताओ का उल्लेख किया है उससे पहली स्वतंत्रता विचार एव अभिव्यक्ति की है। स्वतंत्रता के सबध मे उनका विचार था कि इस स्वतंत्रता को नकारात्मक आधार पर नहीं अपितु सकारात्मक आधार पर लेना चाहिए। उन्होने कहा कि—

“आजादी के समय मे समाचार पत्रो का जो धर्म था, और जो कार्य था उसमे और आज मे जमीन-आसमान का अन्तर है। एक उत्तरदायी पत्रकार की लेखनी जनता पर भरी प्रभाव डाल सकती है। वह जितनी ही भलाई पर प्रभाव डाल सकती है उतनी ही बुराई पर भी, अतएव समाचार पत्रो को चाहिए कि वे देश के निर्माण मे हाथ बँटाये और कोई ऐसा कार्य न करे जिससे की राष्ट्र को नुकसान हो।”³

(iii) **दंड व्यवस्था पर दृष्टिकोण**—सत्य एव अहिंसा का पुजारी होने के कारण सरदार पटेल ने कभी भी बदला लेने के लिए बल प्रयोग की बात नहीं की। वे आजादी की लड़ाई मे कई बार जेल गये, यातनाये सही तथा अनेक प्रकार के कष्टो को सहा लेकिन दण्डात्मक प्रतिकार कभी नहीं किया। अहिंसा के सिद्धान्त के अनुसार वे सत्याग्रह के मार्ग से ही अपने लक्ष्यो को प्राप्त करना चाहते थे। अतएव सत्ता मे आने के बाद ऐसे कानूनों की आवश्यकता पर उन्होने बल दिया जिसमे अपराधियो को दण्ड की अपेक्षा सुधरने का अधिक अवसर प्राप्त हो। अतएव उन्होने सुधारात्मक दण्ड का समर्थन किया। सरदार पटेल के अनुसार—

“मित्रता से जितना काम होता है उतना दण्ड से नहीं होता। कानून का सहारा कम से कम लेना चाहिये। हमारे पास सत्ता आयी है। इस सत्ता के अमल के कारण किसी के मन मे अरुचि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि हम इस रीति से काम नहीं करेंगे तो सत्ता को हजम नहीं कर सकेगे।”⁴

सरदार द्वारा शक्ति प्रयोग के सबध मे उनका कहना था कि सरकार को शक्ति का प्रयोग उस समय करना चाहिए जब सुधार या लोकहित के लिए आवश्यक हो, अन्यथा वह सफल नहीं होगी। राज्य को इस उत्तरदायित्व को समझना चाहिए कि तलवार का प्रयोग कमजोरो पर कदापि नहीं होना चाहिए और यदि कभी हो भी तो उनको सुरक्षित करने के लिए।

३ पटेल, मणि बहन, सरदार श्री के विशिष्ट एव अनोखे पत्र, खण्ड एक, अहमदाबाद, 1981, पृ०-326

४ वही, पृ० 254

(iv) **जनमत पर दृष्टि कोण**—सरदार पटेल ने अपने राजनीतिक जीवन में जनमत को बहुत अधिक महत्व दिया। कोई भी आन्दोलन चलाने के पूर्व वह भली भौति और जॉच परख के बाद कि जनमत इसके लिए तैयार है या नहीं, तभी चलाते थे। इस सबध में उनका विचार था कि सरकार को बिना लोक सहमति के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। “यदि हम लोक सरकार चाहते हैं तो हमें अवश्य लोक सहमति और संचालन की स्थापना करनी होगी।”⁵ इस सबध में सभी जनता की, बिना धर्म और जाति के विभेद के सुरक्षा करने का कार्य सरकार करेगी तथा इस आधार पर टकराव को रोककर समानता की नीति का अनुसरण करेगी। साथ ही सरकार को चाहिए वह अपने आप को जनता का ट्रस्टी समझे, शासक नहीं। शासक को चाहिए कि वह अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्यों को सम्पन्न करे। सरदार पटेल के शब्दों में,

“शासको को अवश्य जान लेना चाहिए कि वे जनता के ट्रस्टी हैं और राज्य के सेवक। उनके जनता के साथ सबध पिता और बच्चों की भौति के हैं। उन्हें जनता के हित में अवश्य सुरक्षा प्रदान करनी है तथा जनता का कल्याण अवश्य ही उनका आर्थिक कर्तव्य है।”⁶

(v) **नागरिकों के कर्तव्य**—स्वतंत्रता एवं समानता बनाये रखने के लिए सरदार पटेल ने नागरिकों के कर्तव्य को निश्चित करते हुए कहा कि यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो सम्भव है कि उनकी स्वतंत्रता और समानता खतरे में पड़ जाय। अतः नागरिकों में कर्तव्य पालन पर बल देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि—

“प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है कि वह महसूस करे कि देश स्वतंत्र है तथा उसे सुरक्षा प्रदान करने का उसका कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह जौति-पौति को भूल जाय और अपने आप को मात्र भारतीय समझते हुए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे।”⁷

५ भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947-50 तक), नई दिल्ली, 1982, पृ० 45

६ वही, पृ० 27

७ वही, पृ० 27

(vi) छोटे राज्य विकास में बाधक:- सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के उपरान्त देशी रियासतों का एकीकरण किया। उन्होंने अनुभव किया था कि ये छोटे-छोटे राज्य राष्ट्र के विकास में बाधक हैं तथा भाषायी और भौगोलिक आधार पर गठित ये राज्य देश की एकता और अखण्डता के लिए हानिकारक हैं। वे इस प्रकार के प्रान्तवाद के विरुद्ध थे। उन्होंने इसी कारण आन्ध्र प्रदेश से तमिलनाडु के पृथक्करण का विरोध किया था तथा सकारात्मक रूप से महाराष्ट्र से गुजरात राज्य के पृथक्करण के भी विरोधी थे।

(vii) आर्थिक स्वतंत्रता के समर्थक—सरदार पटेल राष्ट्र के विकास के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे, इसलिए कुछ लोग उन्हें पूँजीवाद समर्थक भी कहते हैं। उनकी नजरो में “राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता नहीं होगी।” उन्होंने कहा था कि मेरी केवल यही इच्छा है कि भारत को अच्छा उत्पादक राष्ट्र होना चाहिए तथा देश में कोई भूखा न रहे, भूत के लिए आँसू न बहाये। इसके लिए देश का उत्पादन बढ़ाया जाय। आयात के भारों से नहीं बैठना चाहिए। व्यक्ति आयतित वस्तुओं पर निर्भर न हो इसके लिए सरकार और जनता को मिलकर कार्य करना चाहिए। इसके लिए संविधान निर्माण के मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष के नाते उन्होंने सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया तथा व्यापार आदि को स्वतंत्रता के लिए अनु० 301 को लागू करवाने में अहम भूमिका निभायी।

सामाजिक विचार

सरदार पटेल का सामाजिक चिन्तन गाँधीवाद का पूरक है। गाँधी जी के समान सरदार पटेल ने भी अस्पृश्यता को हिन्दू धर्म का एक कलंक बताया। सरदार का कहना था, "वह धर्म के बहाने चलने वाला एक ढोंग है।"⁸ 1936 ई० में संयुक्त प्रान्त में एक किसान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में सरदार पटेल ने छुआछूत की भर्त्सना करते हुए कहा, "यह एक पाप है जिसे हम अछूत मानते हैं, अगर वह हमारा समाज छोड़कर दूसरा धर्म अपना ले, तो उसी वक्त से उसे छुआ जा सकता है। हिन्दू धर्म पर से इस कलंक को मिटा देने के लिए महात्मा गाँधी ने अनेक दुःख सहे।"⁹

सरदार पटेल स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने तथा पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के पक्षपाती थे। 1921 ई० में बिहार में किसानों की एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था, "आपको शर्म नहीं आती आप अपनी स्त्रियों को पर्दे में रखते हैं, दुख ही अर्द्धांगवायु से पीड़ित है? ये स्त्रियाँ कौन हैं ? आपकी माँ, बहन और पत्नी। उन्हें परदे में रखकर क्या आप यह मानते हैं कि क्या आप उनके सतीत्व की रक्षा कर सकेंगे? उन पर इतना अविश्वास क्यों ? क्या आप इसलिए करते हैं कि वे बाहर आकर आपकी गुलामी देख लेंगी? आपने उन्हें गुलाम पशुओं की तरह रखा है, इसलिए उनकी औलाद आप भी गुलाम पशुओं की तरह हो गये हैं- मेरी चले तो मैं बहनों से कह दूँ कि ऐसे डरपोक और नामर्दों की स्त्रिया बनने से तो उन्हें तलाक देना अच्छा है।"¹⁰

सरदार पटेल ने बाल विवाह तथा अनमेल विवाह की भी तीव्र आलोचना की तथा विधवा विवाह का समर्थन किया । समाज में बलि प्रथा जिसमें बच्चों को बलि पर चढ़ाया जाये, से सरदार पटेल अत्यन्त दुःखी थे। अपने बिहार यात्रा के दौरान इस क्रूरता पर रोष प्रकट करते हुए सरदार पटेल ने कहा, "जो ब्राह्मण गुड्डे, गुडियों का विवाह करने के लिए

८ 'पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण, अहमदाबाद, 1950, पृ० 35

९ 'वही, पृ० 312

१० 'वही, पृ० 211

स्मृतिया उद्धृत करते हैं, वे ब्राह्मण नहीं राक्षस हैं और जो माँ बाप इन ब्राह्मणों की बात मानकर बच्चों को काली माता की भेट चढ़ाते हैं, वे स्वयं पशु हैं, मेरे हाथ में कानून हो तो मैं ऐसे लोगों को गोली से उड़ा देने की सजा निश्चित करूँ।¹¹

समाज के निर्माण में सरदार ने शिक्षा पर विशेष बल दिया। 21 अक्टूबर 1950 को गुजरात विद्यापीठ के अपने दीक्षान्त भाषण में सरदार पटेल ने कहा, "जो शिक्षा पद्धति जनता तथा देश को आत्म निर्भर नहीं बनाती है, उसकी पुनर्रचना होनी चाहिये।"¹² गाँधी की भाँति सरदार पटेल स्वदेशी तकनीकी पर आधारित विशेष शिक्षा के पक्षपाती थे। साथ ही उन्होंने पुरुषों की भाँति नारी शिक्षा का भी समर्थन किया। उनका आग्रह था, "पिछड़े हुए समाज की कन्याओं को शिक्षित करने का काम महापुरुष का काम है। उसका फल बहुत समय बाद मिलेगा और जब तक फल मिलेगा, तो उसकी मिठास मिलेगी।"¹³

सरदार पटेल समानता के समर्थक थे। वे कहा करते थे "जब ईश्वर ने सबको समान बनाया है तो फिर मालिक या दास का अन्तर क्यों? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान है तो यही समानता की भावना समाज में भी व्याप्त होनी चाहिए।" संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इसी दृष्टिकोण पर बल दिया। उन्होंने बहुसंख्यक वर्ग द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार तथा उनके प्रति शका का विरोध किया। साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग से देश के प्रति पूरी वफादारी की अपील की।

सरदार पटेल एक धर्म निरपेक्ष समाज के पक्षपाती थे। उनका मत था कि ईश्वर एक है तथा सभी उसकी सन्तान हैं। धर्म ईश्वर तक पहुँचने के अलग-अलग मार्ग हैं लेकिन सबसे श्रेष्ठ मानवता है। सरदार पटेल धर्म के नाम पर सकीर्णता के विरोधी थे। वे भारतीय समाजको धर्म की सकीर्णता की भावना से मुक्त करना चाहते थे।

११ 'वही, पृ० 212

१२ 'नन्दूरकर, जी०एम०, इन दि टियुन विथ मिलियन्स, वाल्यूम- 2, अहमदाबाद, 1976, पृ० 239

१३ 'पटेल, मणिबेन, सरदार श्री के विशिष्ट एवं अनोखेपत्र, भाग-2, अहमदाबाद, 1981, पृ० 181

आर्थिक विचार

सरदार पटेल किसी विशेष सैद्धान्तिक पन्थवाद या परम्परा से जुड़े रहने के विरोधी थे। 'अत्यधिक उत्पादन तथा न्यायोचित वितरण' उनके आर्थिक चिन्तन का मुख्य आधार था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय वित्तीय संकट, आवश्यक वस्तुओं का अभाव, औद्योगिक गतिरोध, मुद्रा प्रसार आदि गम्भीर चुनौतियाँ थीं। उसी काल में पटेल के भाषण एवं पत्र व्यवहार उनके व्यवहारवादी दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। प्रान्तों के मुखमंत्रियों को लिखे पत्रों एवं भाषणों में पटेल ने सरकारी खर्च में कटौती, केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच अधिक सहयोग, वित्तीय अनुशासन, औद्योगिक उत्पादन में अधिक पूँजी नियोजन तथा मजदूरों एवं मालिकों के बीच अधिक सद्भावना पर बल दिया। नवनिर्माण काल में औद्योगिक शान्ति, औद्योगीकरण के क्षेत्र में संगठित प्रयास एवं उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग तथा नये साधनों की खोज, सरदार पटेल के चिन्तन के मुख्य आधार थे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद समय यह अनुभव किया गया कि साम्यवादी एवं समाजवादी मजदूर संगठनों को औद्योगिक अशान्ति के लिए भड़का रहे थे। 1947 ई० में सरदार पटेल की प्रेरणा से 'इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (इन्टक) की स्थापना हुई। 17 मई 1948 ई० को उसके प्रथम वार्षिक सम्मेलन में सम्बोधित करते हुए पंच फैसले द्वारा श्रम और पूँजी की समस्या को सुलझाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक शान्ति समयानुकूल है परन्तु साम्यवादी एवं समाजवादी श्रमिकों को भ्रमित कर रहे हैं।" श्रमिकों के समक्ष काल्पनिक स्वप्नलोक प्रस्तुत करके, यह आसामाजिक तत्त्व श्रमिक आन्दोलन को भ्रमित करके उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप न केवल देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर होगी, वरन् श्रमिकों को भी अधिक हानि उठानी पड़ेगी।¹⁴ सरदार पटेल तीन वर्षों के लिए औद्योगिक शान्ति के पक्ष में थे। उन्होंने हड़तालों की अपेक्षा परस्पर समझौते की और पंच फैसले की पद्धति पर अधिक बल दिया। मई 1949 ई० में इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अपने सम्बोधन में कहा, " देश में जो लोग आज के संकट

काल में ऐसी कार्य प्रणाली का आसरा लेते हैं, जो उत्पादन को रोकती है, वे मजदूरों और देश में हानि पहुँचाते हैं। झगड़ों की निपटारे का सर्वोत्तम उपाय है पंच फैसले की पद्धति, और एक बार न्याय निर्णय और पंच फैसले का तत्र चालू हुआ कि हड़तालें गैर कानूनी बन जायेगी। ऐसी परिस्थितियों में जो लोग मजदूरों को हड़तालें करने की या जारी रखने की सलाह देते हैं, वे मजदूरों के या इस देश के मित्र नहीं हैं।¹⁵

सरदार पटेल उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विरोधी थे। उनके अनुसार "वर्तमान परिस्थितियों में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण सरल कार्य नहीं है।"¹⁶ इसके लिए देश के पास न तो समुचित साधन हैं और न क्षमता है। सरदार पटेल के दृष्टिकोण से, "राष्ट्रीयकरण की चर्चा के पूर्व उद्योगों का विकास आवश्यक है।"¹⁷

सरदार पटेल गाँधीवादी समाजवाद के समर्थक थे उन्होंने कहा, "मार्क्स के आधार पर स्थित समाजवाद हिंसा के एक पथ के अलावा और कुछ नहीं है। हिंसा द्वारा सम्पत्ति का उन्मूलन कांग्रेस के आचार नियमों के विरुद्ध है, गाँधी जी नया सन्तुलन स्थापित करना चाहते हैं, पर लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ जायजाद छीनकर नहीं, बल्कि उनसे इच्छा पूर्वक आत्मत्याग करवाकर। आप कह सकते हैं कि यह अव्यवहारिक है, पर गाँधी जी ने यह दिखला दिया कि ऐसा किया जा सकता है। यह समता और स्वतन्त्रता का अहिंसात्मक मार्ग है और यही एक मात्र मार्ग है।"¹⁸

भारतीय समाज में सच्चा समाजवाद ग्रामोद्योग पर निर्भर होना चाहिये, और पाश्चात्य देशों की भारी उद्योग नीति के स्थान पर भारत में ग्राम उद्योगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन से यह सम्भव है। इससे देश की विभिन्न रोजगार जैसी समस्याएँ हल होंगी तथा देश आत्मनिर्भर बनेगा। समाज का स्वस्थ पुर्ननिर्माण होगा। यही गाँधी जी की कल्पना थी, जिसके अनुसार सरदार की स्वतन्त्र भारत के समाजिक उत्थान में इसी प्रकार की आर्थिक उन्नति से सुदृढ़ समाज की नींव रखना चाहते थे और उत्थान को आवश्यकतानुसार बनाना

१५ 'वही, वाल्यूम -2, पृ० 179

१६ 'वही, वाल्यूम -2, पृ० 193

१७ वही, वाल्यूम -2, पृ० 197

१८ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार, दिल्ली, 1997,

चाहते थे। उन्होंने कहा था कि "यहा बाहर से बहुत अनाज मगवाना पडता है, इससे देश का बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि जैसे भी बने, बाहर से अनाज मँगाना बन्द ही कर देना चाहिये और जितना जरूरी है उतना देश में उत्पादन करने का प्रयास करना चाहिये।"¹⁹ यही समाजवाद है, जिससे समाजस्थिर व आत्मनिर्भर बन सकता है। ऐसे समाजवाद की स्थापना के लिए रचनात्मक कार्यों को अधिक प्रोत्साहन देना होगा, क्योंकि इससे एक ओर हमारी आत्म निर्भरता बढ़ेगी और दूसरी ओर हमारा समाज स्वस्थ बन जाएगा। सरदार पटेल ने जीवन भर रचनात्मक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष के रूप में, सत्याग्रहों में, परिवर्तनवादी तथा अपरिवर्तनवादी विवाद के समय तथा स्वतन्त्र के उपरान्त, सरदार पटेल ने सदैव रचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता के रूप में अपनाया।" कांग्रेस दल के रचनात्मक कार्यक्रमों जैसे वस्त्र निर्माण, अन्य देशी वस्तुओं का निर्माण नशाबंदी और ग्राम सेवा आदि में अपने को प्राथमिकता से लगाया।²⁰

सरदार पटेल कुटीर उद्योग धंधों को अत्यधिक महत्व देते थे परन्तु वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि स्वतन्त्र भारत में उन्नति और सम्पन्नता की दृष्टि से औद्योगीकरण का अपना महत्व है, लेकिन यह औद्योगीकरण विशेष वस्तुओं तक ही सीमित होना चाहिए। साथ ही ऐसे औद्योगीकरण से अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण नहीं होना चाहिये फिर भी औद्योगीकरण की आवश्यकता में सरदार पटेल चाहते थे कि पूँजीवाद पर सीमा से अधिक विधायन पर रोक लगे और पूँजी पति अपनी पूँजी का प्रयोग ट्रस्टी बनकर करें, ताकि जनता को राहत मिले तथा जनता के हित से उसका सार्वजनिक उपभोग भी हो सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "हमें एक ऐसा वातावरण अवश्य तैयार करना चाहिए, जिससे हम ऐसे आधारों की उपलब्धि कर सकें- ताकि जनता के रहन-सहन का स्तर और सम्मान सुधर सके।" सरदार पटेल का दृष्टिकोण समन्वयवादी था जिसमें सीमाबद्ध पूँजीवाद रहे तथा आवश्यक औद्योगीकरण जिससे आर्थिक क्षेत्र में लाभ के साथ जनसामान्य का स्तर सुधर सके और समाज का नवनिर्माण हो।

१९ 'कुमार, रवीन्द्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार, दिल्ली, 1491,

पृ० 180

२० 'वही, पृ० 181

सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में सरदार पटेल का विचार था कि निर्धनों के रहन-सहन को ऊँचा उठाने की व्यवस्था हो अतएव वे भूमि सुधारों को बिना उचित मुआवजा करने के विरुद्ध थे। इस दृष्टिकोण से वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के किसी के द्वारा शोषण के विरुद्ध थे, लेकिन अमीर का हृदय परिवर्तन कर उसे गरीबों की ओर मोड़ने के पक्ष में थे। सरदार पटेल बल पूर्वक किसी की सम्पत्ति लिए जाने के विरुद्ध थे जिसका प्रमाण गाँधी जी का स्मारक बनवाने के लिए बलपूर्वक उसके मालिक से लिए जाने का विरोध करते हुए यह कहना है।" यदि इस तरह निजी सम्पत्ति जबरदस्ती से प्राप्त की जायेगी तो उसका अर्थ यह होगा कि किसी को अपने घर में किसी बड़े आदमी को मेहमान की तरह रखना ही नहीं चाहिये। राष्ट्र के नाम से ऐसे निजी मकान लेना मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता और यह सब बापू के नाम से करना तो गुनाह मालूम होता है, यदि सार्वजनिक मकान जिसा सम्बन्ध मालिक के अपने परिवार के निवास स्थान के रूप में न रहा हो, ऐसे मकानों को लेने में कोई हर्ज नहीं" ²¹

सरदार पटेल का आर्थिक क्षेत्र में दृष्टिकोण व्यावहारिक होने के बावजूद उनपर अनुदारवादी दाक्षिणपथी व पूँजीवादी समर्थक होने का आरोप लगाया जाता है पटेल ने स्वयं स्वीकार किया था कि, "मुझपर सदैव बिडला जैसे पूँजीपति का मित्र होने का आरोप लगाया जाता है—मैंने गाँधी जी से सीखा है, अमीर या गरीब, बड़ा या छोटा सबके प्रति सहानुभूति रखो, अतः मैं श्रमिक, उद्योगपति, राजा, किसान तथा जमींदार सभी से मित्रता रखता हूँ और उन्हें सही कार्य करने हेतु प्रेमपूर्वक प्रेरित करता हूँ।" ²²

12 नवम्बर 1949 को उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के सम्बोधित करते हुए एक कुशल व्यवहारवादी अर्थशास्त्री के रूप में सरदार पटेल ने कहा था, "अर्थशास्त्र एक व्यावहारिक विज्ञान है, अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ। कि आप समस्या के व्यावहारिक पक्ष को निकटता से देखें तथा उन उपायों की खोज करें जिनके द्वारा उपलब्ध साधनों का राष्ट्रीय विकास में उद्देश्यपूर्ण प्रयोग हो सके।" ²³ इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में पटेल उत्तरोत्तर विकास के पक्षधर रहे ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके।

२१ वही, पृ० 182

२२ नन्दूरकर, जी०एम०, पूर्वो, वाल्यूम -1, पृ० 258

२३ वही, पृ० 202

अध्याय 6

सरदार पटेल के विचारों की प्रासंगिकता

- (i) राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता
 - (ii) सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता
 - (iii) आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता
-
-

सरदार पटेल के विचारों की प्रासंगिकता

राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता

सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन व आचरण, उनके विचार, उनकी राष्ट्र के प्रति गहन निष्ठा, उनकी कर्मठता व दृढ़ता सब देश के लोगो के लिए अनुकरणीय है। राजगोपालाचारी जैसे नेता ने लिखा है कि “हमने सबसे बड़ी भूल यह की कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। यदि प्रधानमंत्री सरदार पटेल बनते और विदेश मंत्री नेहरू बनते तो बहुत अच्छा हुआ होता।”²⁴ जय प्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता ने कहा कि “सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर हमने बहुत बड़ी भूल की।”²⁵

एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण सरदार पटेल को मालूम था कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण काल में त्याग की आवश्यकता हो तो त्याग अवश्य करना चाहिये। उनके लिए व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर राष्ट्र हित था। पटेल राष्ट्रीय हित के प्रबल प्रहरी थे, राष्ट्रीयता उनके जीवन का परम लक्ष्य था, अतएव राष्ट्रहित में गाँधी जी के कहने पर प्रधानमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद जवाहर लाल नेहरू के लिए छोड़ दिया। सरदार पटेल में राष्ट्र प्रेम कूट-कूट कर भरा था एक बार गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि—“जो भारतीय है वे भारत में ही रहे क्योंकि भारत के लोगो को भारतीयों की जरूरत है चाहे वह किसी भी धर्म और जाति का हो।”²⁶

निश्चय ही इस कथन से सच्चे राष्ट्रवादी एवं धर्म निरपेक्षता का भाव झलकता है, क्योंकि राष्ट्र का सबंध किसी जाति, धर्म और सम्प्रदाय के बन्धन से आबद्ध नहीं होता, राष्ट्र केवल राष्ट्रभक्तों का होता है। उनकी कार्य पद्धति की कसौटी राष्ट्रीय हित से प्रभावित थी। भारत विभाजन को उन्होंने राष्ट्र हित की कसौटी पर परखा और उसे स्वीकार करते हुए

२४ पटेल, बाबू भाई जश भाई का व्याख्यान, उद्धृत, सरदार साहित्य माला सम्पुट, अहमदाबाद, 1986, पृ० 43

२५ वही, पृ० 44

२६ पटेल, दिलवार सिंह, जैसवार, नवेदित भारत के निर्माता सरदार पटेल, दिल्ली, 2000, पृ० 449

लोगो से कहा, “यदि एक अगूठा विषाक्त हो जाय तो उसे अलग कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा सम्पूर्ण शरीर को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ता है।”²⁷

1946 ई० में जब बम्बई में भारतीय नौ सेना ने विद्रोह किया तो सरदार ने समाजवादियों की कटु आलोचना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही की। स्वतंत्र भारत में हृदय रोग से पीड़ित होने पर भी उन्होंने वायुचालित डाकोटा विमान से सारे देश की यात्रा की और लोगों को सरकार की नीतियों से अवगत कराया, उन खतरो से सावधान किया जिनका उन्हें सामना करना था, उनके समक्ष खड़े राष्ट्र निर्माण के कार्यों पर बल दिया तथा देश की प्रगति हेतु अनिवार्य शर्तों का निर्देश दिया। सरदार पटेल के उपरोक्त कार्यों से प्रेरणा ग्रहण कर हम भविष्य में राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को सुरक्षित रख सकते हैं। तथा अनेक क्षेत्रीय समस्याओं जैसे काश्मीर समस्या, नागालैण्ड समस्या, बोडो समस्या, खालिस्तान समस्या, वनाचल समस्या आदि का समाधान कर सकते हैं।

वी०पी० मेनन ने लिखा है, कि “नेतृत्व दो प्रकार का होता है। एक नेता जैसे नेपोलियन--जो नीति का निर्माता एवं व्याख्याता दोनों था और अपनी आज्ञानुसार उस पर अमल चाहता था। ऐसे सर्वोच्च व्यक्ति रोज-रोज उत्पन्न नहीं होते। सरदार का नेतृत्व दूसरी प्रकार का था उन्होंने अपने अधिकारियों का सावधानी पूर्वक चयन किया और उन पर बिना हस्तक्षेप के नीति निर्माण का कार्य छोड़ दिया। उन्होंने कभी झूठा दावा नहीं किया कि वे विश्व में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कभी भी एक नीति का स्पष्ट रूप से अपने अधिकारियों की सलाह के बिना स्वीकार नहीं किया। विचार विमर्श अधिकारियों से उन्हें लाभ पहुंचाने वाले थे”²⁸ वास्तविकता यह है कि सरदार पटेल ने जो भी कदम उठाया वह पूर्ण विचार विमर्श तथा सतुष्टि के बाद ही उठाया। उस कदम का सबध चाहे प्रशासन में नीतिगत निर्णय से हो या सघर्ष हेतु सत्याग्रह से। बारडोली सत्याग्रह हेतु उन्होंने अन्तिम निर्णय तभी लिया जब वे अपने सहयोगियों से पूर्ण रूप से सतुष्ट हो गये तथा स्थिति को सत्याग्रह हेतु अनुकूल पाया। सरदार पटेल के निर्णय सदैव संतुलित, दृढ़ तथा देशहित में होते थे। रवीन्द्र कुमार ने सरदार पटेल की तुलना लेनिन तथा माओत्सेतुंग से करते हुए लिखा है कि “लेनिन ने भावी पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन भर सघर्ष किया, कष्ट

२७ वही, पृ० 449

२८ कुमार, रवीन्द्र, सरदार वल्लभ भाई के सामाजिक एवं राजनीति विचार, दिल्ली, 1991, पृ० 186

उठाये और स्वयंकीनता स्वीकार की। उनका भी अमर सन्देश सरदार पटेल की भांति यही था—दुःख सहन करके, अस्तित्व के खातिर जूझो। लेनिन एक विचारक तथा जन्मजात नेतृत्वकारी थे और सरदार पटेल एक सुदृढ़ सघर्षकर्ता व नेतृत्वकारी। सिद्धान्तों में दोनों में मतभेद थे, परन्तु जीवन के कर्म को दोनों बराबर महत्त्व देते थे।²⁹

साम्यवादी चीन के निर्माता माओत्सेतुंग के नेतृत्व की श्रेणी सरदार पटेल से इस रूप में मिलती है कि दोनों नेतृत्वकारी किसानों के संगठन को समान महत्त्व देने वाले थे। यद्यपि माओ ने चीनी साम्यवादी दल को मजबूत संगठन दिया और जिससे चीन की क्रान्ति भी समाप्त हुई, उसी की भांति सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अधिकतर गतिशील संगठन बनाया जिसने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया। “इस प्रकार सरदार पटेल के नेतृत्व का वर्गीय चरित्र एकपक्षीय नहीं बहुपक्षीय था। वे बिस्मार्क से श्रेष्ठ लौह पुरुष, नेपोलियन से श्रेष्ठ कार्य पद्धति वाले, लेनिन जैसे कर्मप्रिय तथा माओत्से तुंग जैसे कृषक नेतृत्वकारी नेता थे।”³⁰ वर्तमान अविश्वास की राजनीति में राजनेताओं के लिए सरदार का सुदृढ़ नेतृत्व अनुकरणीय है। जिसके माध्यम से वे संगठन को गतिशील बना सकते हैं और विश्वास की राजनीति पैदा कर सकते हैं।

सरदार पटेल मानते थे कि राजनीति को जब भी व्यवहार में उतरना हो तब ससार के अपूर्ण मनुष्यों की आवश्यक मर्यादाओं को ध्यान में रखना चाहिये। मर्यादाएँ भी सभी आवश्यक नहीं होती। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से एव दक्षता से गुजरात के भीरु किसानों को निर्भीक बनाया था फिर भी देश या काल की दृष्टि से जो मर्यादाएँ अनिवार्य हों उसे लक्ष्य में लेना चाहिये। अन्यथा हमें ही बनवास लेना पड़ेगा और हमारी खाली जगह निर्बल आदमी आ बैठेंगे अतएव अपवित्र कहकर राजनीति को छोड़ देने से राजनीति का प्रश्न समाप्त नहीं हो जायेगा। प्रकृति में कुछ भी खाली नहीं रहता अर्थात् अयोग्य व्यक्ति उस रिक्त स्थान पर अधिकार कर लेंगे सिर्फ मैकियावेली को गुरु मानकर राजनीति नहीं कर सकते। “सरदार ने राजनीति के लिए केवल आनेस्टी (प्रमाणिकता) शब्द का प्रयोग न करके ‘पॉलिटिकल आनेस्टी’ शब्द का प्रयोग किया है।”³¹ उनका कहना था कि इसका

२९ वही, पृ० 187

३० वही, 188

३१ पटेल, बाबू भाई जश भाई, पूर्वो, पृ० 60

सर्वत्र पालन उचित होगा, यदि ऐसा न हो तो कम से कम राजनीति में इसका पालन तो करे ही। पेन्शन अदा करने के बारे में ससद के समक्ष वृत्तांत रखते हुए उन्होंने कहा कि—“इसमें छोटे बड़े सुधार या सुझाव हो सकते हैं। जो निश्चय किया गया है वह सर्वांग संपूर्ण है, ऐसा भी मैं नहीं कहा लेकिन वर्तमान संयोगों में इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हिन्दुस्तान का एकीकरण। यही सबसे प्रथम करने लायक कार्य है। इसे पूर्ण करने में यदि दूसरे प्रश्न बाकी रह जाते हैं तो रहे, उनका फैसला बाद में करेंगे।”³² इस प्रकार की दृष्टि में राष्ट्रहित सर्वोपरि महत्व का था। एम० एन० राय के पटेल की मृत्यु के दो दिन पहले लिखा कि वे भारत भाग्य के निर्माता थे। “जब भविष्य निराश जनक हो तो, भूत से प्रेरणा लेना होगा, सरदार पटेल इस भूत के गौरव थे।”³³

सरदार पटेल को अप्रमाणिकता का भय था पर उद्दामवादी गिने जाने का मोह न था। राजाओं को दिये गये सालियाना के बारे में उद्दामवादियों ने विरोध किया श्री वी०पी० मेनन के कथानुसार “अकेले ग्वालियर राज्य की गंगा जली निधि में इतनी रकम थी कि उसके ब्याज से सारे मध्य भारत के राजाओं का सालियाना चुकाया जा सकता था। निजाम ने जो जाययाद सौपी थी उसके ब्याज की ही आय सवा करोड़ रुपये थी। राजाओं ने भारत सरकार को एकास्सी करोड़ रुपये दिये थे, इतना ही नहीं बल्कि बारह हजार मील की लम्बी रेलवे दी थी। प्रतिवर्ष अपनी निजी खर्च के लिए 20-25 करोड़ खर्च करने वाले राजाओं को कुल मिलाकर पाँच करोड़ देने थे फिर भी सरदार पटेल ने राजाओं को दिये जाने वाला सालियाना नये राजा की नियुक्ति के समय क्रमशः घटता जाय ऐसी व्यवस्था करायी थी।”³⁴ उद्दामवादियों ने जब सालियाना का करार रद्द करने या बदलने का आग्रह किया तब सरदार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि “स्वराज्य का आरम्भ मैं अप्रमाणिकता से नहीं करना चाहता हूँ।”³⁵ उन्होंने आगे कहा कि “यदि सलाह सम्मति से समाधान न हुआ होता तो आज की अपेक्षा उस समय संघर्ष करने की शक्ति राजाओं में अधिक थी, उन्हें न्याय देना उचित है, उनकी जगह अपने आप को रखें और तब अपने त्याग का मूल्यांकन करें। राजाओं ने अपने कर्तव्य का पालन किया है, उन्होंने अपनी सत्ता एवं अधिकार छोड़ दिये हैं और राज्यों के

३२ वही, पृ० 60

३३ कृष्णा, बी० सरदार वल्लभ भाई पटेल इण्डियाज आयरनमैन, नयी दिल्ली, 1995, पृ० 516

३४ वही, पृ० 14

३५ वही, पृ० 14

विलीनीकरण में सम्मति दी है। करार के अनुसार हमने जो उत्तरदायित्व लिया है तथा उन्हें जो विश्वास दिलाया है उसे पेन्शन अदा करके पूरा करना है। इसे पूरा न करने में हमारी निष्फलता और विश्वास भग गिना जायेगा।”³⁶ यह पेन्शन जो क्रमशः घटने वाली थी लेकिन अनेकों करोड़ खर्च करने वाले शासन ने बाद में पेन्शन बन्द करके इसे प्रगतिशील कदम कहकर अभिवादित किया लेकिन सरदार पटेल तो वो यह विश्वास भग ही लगा होता इस प्रकार सच्चाई, विश्वास और ईमानदारी की सरदार पटेल की राजनीति एक आदर्श है जिससे वर्तमान राज्य की विकृतियाँ दूर की जा सकती हैं।

शुद्ध सोने से गहने नहीं बनते उसमें तौबे का मिश्रण करना पड़ता है। यह ताबों यानी दूरदर्शी व्यवहार। इसी व्यवहार के कारण सरदार पटेल ने तत्कालीन तमाम प्रशासनिक सेवा को विश्वास दिलाया था कि तुम्हारे वाजिब अधिकारों को हम छीनने वाले नहीं हैं और न ही तुम्हारे साथ शत्रुभाव रखने वाले हैं। यदि देश की चिन्ता है तो परिस्थितियों को लक्ष्य में रखकर तुम्हें सब कुछ करना चाहिए। नेहरू अधिकारियों पर अंग्रेज समर्थक होने के कारण भरोसा रखने के पक्ष में नहीं थे। सरदार ने उन्हें समझाते हुए कहा “अगर आप उन्हें भरोसा नहीं देंगे तो यह देश नहीं बचेगा और देश ही न रहेगा तो लोकतंत्र और समाजवाद कहा से रहेगा?”³⁷ इनके अलावा सरदार ने सभी को समझाया कि पराधीन होने का कारण वे सब मजबूर थे अब परिस्थिति बदली है इसलिए हम जैसा चाहेंगे, वैसा वे करेंगे। उन पर भरोसा रखकर उन्हें मौका दिया जाना चाहिये। सरदार कहते थे कि “नौकर वर्ग तुम्हारा न माने तो इसमें उसका दोष नहीं है तुम्हारा है। घोड़ा अपने सवार को खूब पहचानता है। सवार ढीला होने पर घोड़ा शरारत करे तो इसमें क्या आश्चर्य?”³⁸ सरदार की इस बात का अनुभव सभी मंत्रियों को हुआ होगा। सरदार ने मेहनत से काम लिया, कृष्णमाचारी से काम लिया प्रत्येक व्यक्ति से काम लेते समय वे केवल इतना देखते थे कि उसमें सज्जनता है या नहीं। मनुष्य की योग्यता जैसे-जैसे बढ़ती जाय उसी अनुपात में इसका अमल अधिक होना चाहिये। इसी योग्यता को बढ़ाने का कार्यक्रम ही रचनात्मक कार्यक्रम है रचनात्मक कार्य चलता रहे, राज्य को इसमें अवरोधक नहीं बनना चाहिये और

३६ वही, पृ० 14

३७ वही, पृ० 64

३८ वही, पृ० 64

राजनीति में परिस्थिति में मुताबिक सज्जनता का संगठन करके समयानुसार सर्वाधिक शक्य मार्ग निकालते हुए आगे बढ़ना चाहिये।

सरदार पटेल बेहद अनुशासन प्रिय तथा दल के प्रति उनकी अटूट निष्ठा थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ० खरे सीधे गवर्नर जनरल से मिलकर कांग्रेस के लिए अपमान जनक आचरण किया था। सरदार ने उनसे पूछा कि “आपको कांग्रेस को अन्धेरे में रखकर विदेशी शासन के प्रतिनिधि गवर्नर से गुप्त चुप तरीके से मिलने का अधिकार किसने दिया। आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, जिसने आपको कुछ शर्तों के साथ मुख्यमंत्री पद पर बिठाया है। अच्छा व्यवहार रखिये नहीं हो हट जाइये।” खरे को जाना पड़ा, उनकी और गवर्नर की चालबाजी कारगर न हुई। उसी मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री थे। जिसने एक हरिजन बालिका पर अत्याचार करने वाले सजा प्राप्त कैदी को माफी दिलवायी। सरदार ने इसका स्पष्टीकरण माँगते हुए कहा, ऐसे अपराधी को आपने माफी कैसे दिलायी? कांग्रेसी मंत्री होकर अपने यह काम अच्छा नहीं किया। इस स्थान पर आप नहीं रह सकते। उन्होंने आगे कहा कि अपने इस कृत्य के लिए मैं न्यायाधीश नहीं बनूँगा लेकिन निवृत्त न्यायाधीश मन्मथनाथ से आपके मामले की जाँच कराऊंगा। वे जो कहे उसे मानना पड़ेगा। मन्मथनाथ ने जाँच के उपरान्त मंत्री को अधिकार के दुरुपयोग का दोषी पाया फलतः मंत्री को जाना पड़ा। मुस्लिम होने के कारण मुस्लिम लीग ने विरोध किया, उत्पात मचाया पर सरदार दृढ़ रहे सरदार पटेल ने स्पष्ट करते हुए कहा “वह मंत्री हिन्दू है या मुसलमान, मेरे सामने यह प्रश्न है ही नहीं। सवाल है कि अधिकार के दुरुपयोग का।”

अनुशासनहीनता की वजह से सरदार पटेल ने नरीमान जैसे कुशल और प्रगतिशील अल्पसंख्यक जाति के नेता नरीमान को भी दल से निष्कासित करने जैसा कठोर निर्णय लिया। सरदार पटेल ने कहा कि, “मेरा निर्णय गलत या अन्यायी हो, तो मुझे निकाल दीजिये, मुझे एतराज नहीं लेकिन योग्य व्यक्ति उसकी जाँच करे।”³⁹ गाँधी जी प्रसिद्ध वकील बहादुर जी को अपने साथ रखकर नरीमान एवं उनके समर्थकों को एक सप्ताह तक सुना, उन्होंने फैसला दिया कि सरदार पटेल के विरुद्ध शिकायत निराधार है। यह प्रकरण बड़ा दुःखदायी रहा। लेकिन यह भी स्मरणीय है कि जब तक इसका फैसला न आया तब

तक सरदार सेवाग्राम नहीं गये। गॉंधी जी ने कहला भेजा पर सरदार गये ही नहीं। महादेव भाई ने बुलावा भेजा तो सरदार ने कहा कि “मुझे नहीं आना है, यदि मैं आऊँ तो लोग इसका गलत अर्थ निकालेंगे। मुझे तो बम्बई भी नहीं जाना है मेरे मामले की जाँच कराइये। ससदीय बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से यदि नरीमान के साथ अन्याय किया हूँ तो मैं अयोग्य हूँ।”⁴⁰ 1946 ई० के चुनावों में भी अनुशासन एव दल के प्रति निष्ठा के गुण को प्रत्याशियों के लिए योग्यता के रूप में रखा।⁴¹ इस प्रकार उच्च जीवन मूल्यों की रक्षा करना ही सरदार का अटल लक्ष्य था जिसके आधार पर ही आज देश की राजनीति को स्थिर बनाया जा सकता है।

भारत की एकता और अखण्डता के साथ-साथ धर्म निरपेक्षता के प्रति भी सरदार पटेल सदैव प्रयत्नशील रहे। वे स्पष्ट वक्ता थे इसलिए कुछ लोगो ने प्रचार किया कि सरदार पटेल मुस्लिम विरोधी है पर यह निराधार है, वे मानते थे कि—“भारत और पाकिस्तान में हिन्दू और मुस्लिम भाईचारे से रह सके ऐसी हवा खड़ी करने की आवश्यकता है। बहुमत के लोगो को अल्पमत के हितों के पहरेगीर बनना है, अल्पमत के हितों की रक्षा का कर्तव्य बहुमत वर्ग के लोगो का है। हिन्दु भारत में मुसलमानों से अधिक है इसलिए हिन्दुओं को मुसलमानों का रक्षण करना है।” जब स्पेशल ट्रेन हिन्दुस्तान से पाकिस्तान जाने लगी, तब अमृतसर के उन सिक्खों ने जो पाकिस्तान से घायल होकर आये थे और जिनके कुटुम्ब के लोगो की वहाँ हत्या कर दी गयी थी, स्पेशल ट्रेन में जाने वालों को काट डालने का निर्णय लिया। उस समय सरदार पटेल जान हथेली पर रखकर अमृतसर पहुँचे और सिक्खों को समझा बुझाकर ट्रेनों को जाने का मार्ग प्रशस्त किया। सरदार ने धर्म निरपेक्षता को राष्ट्र की अखण्डता को ध्यान में रखकर साफ शब्दों में यह कहा कि “जिसे पाकिस्तान से लगाव हो वह पाकिस्तान चला जाय, पर जिसे भारत में रहना है उसे भारतीय बनकर रहना होगा। पर जो भारत के प्रति वफादार नहीं है वह पाकिस्तान चला जाय।”⁴² यह देश का दुर्भाग्य

४० वही, पृ० 57

४१ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार दिल्ली, 1997, पृ० 117

४२ पटेल, बाबू भाई जशभाई, का व्याख्यान उद्धृत सरदार साहित्य माला सम्पुट, अहमदाबाद, 1986, पृ० 47

है कि वह आज सरदार के विचारों को भूल रहा है परिणाम स्वरूप साम्प्रदायिकता हिलोरे मार रही है। यदि राष्ट्र को साम्प्रदायिकता के चुगल से निकालना है तो सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर ही लोगो में राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत करके तुष्टीकरण की नीति का त्याग कर, ही इस समस्या का समाधान सम्भव है।

सरदार लोकतंत्र के बड़े पुरस्कर्ता थे। लिये हुए निर्णय को अमल में लाने की क्षमता उनमें थी पर सभी निर्णय वे लोकतंत्रीय ढंग से लेने के हिमायती थे। उदाहरणार्थ कांग्रेस प्रमुख पद के लिए टडन जी ने उम्मीदवारी की थी वे चुने भी जाते ऐसी परिस्थितियाँ थी। किन्तु जवाहर लाल को यह पसन्द नहीं था, उनकी मान्यता थी की टडन जी का झुकाव हिन्दुओं की ओर है जवाहर लाल नेहरू ने लिखा कि “मैं जिसे प्रतिक्रियावादी झुकाव कहता हूँ वैसे टडन है।” सरदार पटेल ने नेहरू जी को समझाते हुए कहा कि कांग्रेस का सविधान और कांग्रेस सर्वेसर्वा है। नासिक अधिवेशन में जो प्रस्ताव कांग्रेस मजूर करेगी वे प्रमुख के लिए बन्धनकारी होंगे यदि वे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। जो अधिकार कांग्रेस अधिवेशन का है उसे आप क्यों ले रहे हैं। आखिरकार टडन ही अध्यक्ष चुने गये।

मद्रास के मुख्यमंत्री की पसन्दगी के बारे में सरदार पटेल ने लोकमत का सम्मान किया। पंडित जवाहर लाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद एवं सरदार पटेल तीनों लोग चाहते थे कि मद्रास का उत्तरदायित्व राजाजी सम्भाले, उनकी नजर में राजाजी से योग्य और कुशल कोई दूसरा नहीं था, परन्तु मद्रास कांग्रेस ने टी० प्रकाशम् को अपना नेता चुना। सरदार पटेल ने लोकतंत्र का सम्मान करते हुए कहा कि—“मैं मानता हूँ कि कांग्रेस और विधान सभा का हित इसी में है कि आप लोग राजाजी को पसन्द करें फिर भी आप टी० प्रकाशम् को पसन्द करते हैं तो मैं राजाजी को आपके ऊपर थोपने वाला नहीं हूँ।”⁴³ इसके अलावा कई अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिसमें उन्होंने लोकतन्त्र में विश्वास व्यक्त किया। लोकतंत्र के प्रति सरदार पटेल की अटूट निष्ठा से प्रेरणा लेकर वर्तमान समय में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

४३ पचोली, मनु भाई का व्याख्यान, उद्धृत सरदार साहित्य माला सम्पुट , अहमदाबाद, 1982, पृ०-68

सरदार पटेल छोटे-छोटे राज्यों के गठन के खिलाफ थे। दिसम्बर 1949 ई० में कांग्रेस द्वारा आन्ध्र प्रदेश को भाषायी आधार पर विभाज्य करने सबधी, पारित प्रस्ताव का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, “कुछ लोग भाषायी आधार पर आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के गठन की बात करते हैं परन्तु यह नहीं सोचते कि इसका उत्तर और पश्चिम के प्रदेशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें विभिन्न राज्यों के बजाय भारत की एकता और अखण्डता के बारे में सोचना चाहिये। हमें यह सोचना चाहिये की हम भारतीय हैं।”⁴⁴ उनका विचार था कि, “यदि किसी कारण किसी प्रदेश के बड़े आकार में काट-छाट करना जरूरी हो जाय, तो भौगोलिक स्थिति को सम्मुख रखते हुए प्रशासनिक सुविधा और लाभों को ही ध्यान में रखकर किसी प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहिए।”⁴⁵ दुर्भाग्य से सरदार पटेल के विचारों के विरुद्ध अगले कुछ ही वर्षों में भाषायी आधार पर राज्यों का पुर्नगठन कर क्षेत्रीयवाद को प्रोत्साहन दिया गया। क्षेत्रीयवाद का जो विष देश की एकता में अवरोध बना है उसे निकालने के लिए सरदार पटेल के बताये मार्ग पर ही चलना जरूरी है।

सरदार पटेल ने हमेशा नैतिकता और ईमानदारी की राजनीति की। वे जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे। सरदार पटेल की नैतिकता का सबसे बड़ा प्रमाण नेहरू के सबध में गाँधी को दिया गया जिसके कारण उन्होंने नेहरू को जीवन भर अपना नेता माना। उनकी ईमानदारी का प्रमाण अपने पुत्र डाह्या भाई को अपने सरकारी निवास में रहने की अनुमति नहीं प्रदान करना तथा अपने पुत्र या पुत्री को राजनैतिक उत्तराधिकारी न घोषित करना है। आर्थिक रूप से कितने ईमानदार थे ‘इसका प्रमाण उनकी मृत्यु के पश्चात् घर से मात्र 287 रु० की नकद राशि व दो धोती और एक कुर्ता निजी सम्पत्ति के रूप में थी।”⁴⁶ वे कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहते हुए “प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को निरन्तर टेलीफोन करते थे लेकिन बिल अपनी जेब से भरते थे। जिसमें उनकी आधे से अधिक आय व्यय हो जाती थी।”⁴⁷ भ्रष्टाचार की आँधी से अस्थिर राजनीति को नयी राह सरदार के जीवन से मिल सकती है।

४४ पटेल, दिलवार सिंह, जैसवार, पूर्वो, पृ० 346

४५ वही, पृ० 330

४६ वही, पृ० 330

४७ कुमार, रवीन्द्र, पूर्वो, पृ० 13

राष्ट्रमंडल के प्रति पटेल के दृष्टिकोण की प्रासंगिकता

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य के सकल्प के अनुसार भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बनाना चाहते थे लेकिन सरदार पटेल का विचार था कि "व्यवहारिक कारणों से राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना भारत के हित में होगा।"⁴⁸ उनके प्रबल समर्थन और यथार्थवादी परामर्श से 27-28 अप्रैल, 1949 ई० को लंदन में राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भारत ने प्रभुता सम्पन्न गणराज्य बने रहने के साथ ही अपने व्यापारिक तथा आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया। राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने से भारत को न केवल आर्थिक क्षेत्रों में लाभ मिला अपितु विश्व मंच पर भारत अपनी व अफ्रीकी देशों की बात प्रभाव शाली ढंग से रखने में सफल रहा। वर्तमान समय में भारत राष्ट्रमंडल का एक प्रमुख राष्ट्र है। वर्तमान नेतृत्व सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रमंडल का प्रयोग अपने हितों के लिए कर सकता है।

चीन संबंधी विचार की प्रासंगिकता

चीन के बारे में पटेल की दूर दृष्टि और समझ नेहरू से कहीं अधिक परिपक्व व सही थी। नेहरू हिन्दी चीनी भाई-भाई के भ्रम में खोये रहे जब तक कि चीन ने 1962 ई० में आक्रमण करके उनका भ्रम नहीं तोड़ दिया। जबकि सरदार पटेल ने हमेशा से चीन को एक सम्भावित शत्रु व सीमा पर एक चुनौती के रूप में देखा। 1949 ई० में जब चीन एक शक्तिशाली एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा तो सरदार पटेल ने बार-बार नेहरू को सजग किया, भारत को उत्तर पूर्वी सीमा के खतरे के प्रति सावधान होना आवश्यक है।

सरदार पटेल की सूक्ष्म दृष्टि ने चीन की साम्राज्यवादी नीतियों को पहचान लिया। "जून 1949 ई० में उन्होंने नेहरू को स्पष्ट लिखा कि तिब्बत में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी, साम्यवादी शक्तियों से दूर रहना होगा। चीन तिब्बत की स्वायत्ता को अवश्य भंग करेगा।"⁴⁹ पटेल ने हमेशा चीन के प्रति सावधान रहने की बात की। उन्होंने सड़क, रेल,

४८ मेहरोत्रा, एन०सी०, पूर्वो, पृ० 199

४९ दास, दुर्गा, सरदार पटेल और कांग्रेसपॉन्डेन्स, वाल्यूम VIII, अहमदाबाद, 1977, पृ० 139

वायु सेना, संचार, यातायात द्वारा तिब्बत, भूटान, सिक्किम, दार्जिलिंग व आसाम से सबधों को और निकट लाने की सलाह दी थी। सरदार पटेल भारत और चीन के बीच सम्भावित तनाव के बारे में आशंकित रहे तथा, बार-बार नेहरू को सतर्क किया, अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले 7 नवम्बर, 1950 ई० को नेहरू को पत्र लिख कर चीन से सावधान रहने की बात कही। पर यहाँ भी नेहरू ने उनकी सलाह की उपेक्षा की जिसका खाजियामा देश को 1962 ई० में भरना पड़ा।

चीन के बारे में सरदार पटेल के विचार आज की प्रासंगिक हैं, चीन के प्रति सतर्क रहना होगा। एक तरफ तो वह भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दिल्ली, मास्को, पेकिंग धुरी बनाने की बात करता है तो दूसरी तरफ भारत की सीमा पर सैनिक जमावड़ा कर देता है। साथ ही भारत के शत्रु पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध सैनिक साजो सामान की दिष्ट से मजबूत बनाने का कार्य करता है।

लार्ड माउण्टबेटेन ने 1966 ई० में लिखा कि मैं पटेल को हमेशा एक ऐसे पुरुष के रूप में याद करूँगा जिनमें लौह इच्छा, स्पष्ट दृष्टि, दृढ़ प्रतिज्ञा थी पर हृदय से कोमल, विनम्र और भावनाशील रहे।'

सरदार पटेल के सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता

सरदार पटेल भारतीय एकता के शिल्पी थे। उनके पास ऐसी अद्भुत दृष्टि थी जिसके द्वारा वे सशक्त और अखण्ड भारत का निर्माण करना चाहते थे। सरदार पटेल अपनी गुटनिरपेक्ष नीतियों, नैतिक गुणों एवं अपनी व्यापक प्रशासनिक क्षमता के कारण ही भारतीयों में एकता और अखण्डता के आदर्शों का सूत्रपात कर सके जिसके कारण ही उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा का पितामह कहा जाता है। यह उनकी नेतृत्व क्षमता ही थी, जिसके बल पर वे तत्कालीन नौकरशाहों को इस प्रकार निर्देशित कर सके और उनके अंदर देशभक्ति की भावना इस कदर कूट-कूट कर भर दी कि वे लोग भारत को एक सम्पूर्ण विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिये कटिबद्ध हो गये और इस कार्य में वह पटेल के साथ-साथ जी जान से जुट गये। अच्छे समाज के लिए आधारभूत मान्यताएँ हैं—शांति और सहअस्तित्व, वस्तुनिष्ठता की उच्चतम दर, लोगों में न्याय और समानता की भावना तथा समुदायिक जीवन के प्रति आकर्षण एवं जीवन के हर पहलू में तर्कसंगत दृष्टिकोण। यही वे धारणानाएँ हैं जिनको सरदार पटेल भारत के विकास में अग्रणी और निर्णायक मानते थे।

12 अक्टूबर 1948 ई० को गुजरात और महाराष्ट्र समाज के अभिनन्दनोत्सव के अवसर पर दिये गये व्याख्यान में सरदार पटेल ने शान्ति एवं सह अस्तित्व पर बल देते हुए कहा कि “हिन्दुस्तान में विभिन्न धर्म, जाति तथा भाषा के मानने वाले लोग रहते हैं लेकिन उनकी संस्कृति एक है और वह है हिन्दुस्तानी संस्कृति, हम सभी अनुभव करते हैं कि हम हिन्दूस्तानी हैं, तो हमें मिल जुल कर परस्पर सौहार्द, प्रेम, एवं बन्धुत्व के आधार पर एक स्वच्छ एवं सबल समाज का निर्माण करना है।”¹

जनवरी 1948 ई० को कलकत्ता क्लब में दिये व्याख्यान में सरदार पटेल न्याय और समानता को एक स्वच्छ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक मानते हुए कहा कि ‘पहले उत्पादन करो और फिर समानता के आधार पर बाँटो’। सरदार का विचार था कि यदि बटवारा समानता और न्याय के आधार पर नहीं होगा तो समाज में वर्गीय विभाजन के

१ भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947 से 50), प्रकाशन विभाग दिल्ली, 1970, पृ० 196

फलस्वरूप असन्तोष की भावना का तीव्र गति से विकास होगा जो राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता में बाधक होगी ही राष्ट्र की आर्थिक विकास में भी अवरोधक होगी।²

सामुदायिकता के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव जीवन का आधार ही सामुदायिकता की भावना है। सामुदायिकता की भावना सकुचित न होकर वृहद होनी चाहिये जिसके अन्दर विभिन्न सकल्पनाओं को समाहित करने की क्षमता हो सरदार पटेल के अनुसार खुशहाल जीवन के लिए समुदाय नहीं अपितु सामुदायिकता की भावना जरूरी है जिसके द्वारा ही हम विभिन्न समुदायों में सहआसत्तित्व की सकल्पना कर सकते हैं।

सरदार पटेल जातिवाद (नस्लवाद), साम्राज्यवाद, सम्प्रदायवाद तथा अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सतत् संघर्ष किया। वे “अस्पृश्यता को हिन्दू धर्म पर एक कलक मानते थे।”³ एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने सामाजिक अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न का घोर विरोध किया। सामाजिक न्याय के आदर्शों के साथ उनका गहरा लगाव था किन्तु उनका प्रथम कार्य भारत के अन्यापूर्ण आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण का अन्त करना था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भर्त्सना इसलिए की कि उसके कारण भारत का आर्थिक एवं राजनीतिक पतन गर्त में जा रहा था। सरदार पटेल ने सामाजिक कुरीतियों बाल विवाह का विरोध करते हुए कहा, “बचपन में लड़के लड़कियों की शादी कर के कच्ची उम्र में उठा कर ग्रहस्थी का सारा बोझ लादना अपने बच्चों की हत्या करने जैसा है, अगर मेरे हाथ में सत्ता होती तो बारह तेरह वर्ष की लड़कियों का विवाह करने वालों को फासी पर चढ़ा देने या गोली मारने की सजा देता।”⁴ अनमेल विवाह का भी विरोध सरदार पटेल ने किया। दहेज प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया इस सम्बन्ध में उनका कहना था कि, “ये सब झड़ट छोड़ कर इस लड़के को बाजार में क्यों नहीं खड़ा कर देते साड़ को पाँच हजार रुपये आये या सात हजार”⁵। समाज में प्रचलित बलि प्रथा के वे प्रबल विरोधी थे। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, “विधवा के लिए लगाये गये समाज के बन्धन और विधवा के साथ समाज का व्यवहार इतना क्रूर और कठोर होता है कि उसका जीवन

२ वही, पृ० 101

३ पारीख, नरिहर सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947), अहमदाबाद, 1950, पृ० 35

४ पारीख, नरिहर, सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947), अहमदाबाद, 1950, पृ० 212

५ पटेल, दिलावर, सिंह जैसवार, नवेदित भारत के निर्माता सरदार पटेल, दिल्ली, 2000, पृ० 477

तपस्या बन जाता है”⁶ सरदार पटेल अर्न्तजातीय विवाह के समर्थन में कहते थे। “बालिग लड़के लड़कियाँ अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करें इसमें माता-पिता या सगे सम्बन्धियों को रुकावट नहीं डालनी चाहिये।⁷ वे पर्दा प्रथा के विरोधी थे तथा उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा को उचित माध्यम बताते हुए स्त्री और पुरुषों के लिए समाज शिक्षा पर बल दिया।

वर्तमान समय में भारत एक ऐसे सक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है, जिसमें एकता, अखण्डता, सामाजिक समरसता जैसी विचारधाराएँ गौण होती जा रही हैं और उनके स्थान पर क्षेत्रीयता, जातीयता और धार्मिक कट्टरता जैसी विचार धाराएँ हावी होती जा रही हैं। दहेज वर्तमान समस्या में एक विकराल सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लिया है।

सरदार पटेल एक सबल एवं सुदृढ राष्ट्र के स्वप्न दृष्टा रहे जो सामाजिक न्याय पर आधारित तथा सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होगा। जातीयता, क्षेत्रीयता और धार्मिक कट्टरता के साथ-साथ लोलुपता जैसी सामाजिक बुराइयों सरदार पटेल के बताये हुए मार्ग का अनुसरण करके समाप्त की जा सकती हैं और शान्ति तथा सहआसत्तित्व को स्वीकार करते हुए न्याय और समानता की भावना के आधार पर सामुदायिक जीवन की भावना विकसित करके स्वच्छ समाज का निर्माण किया जा सकता है।

६ वही, पृ० 477

७ वही, पृ० 477

आर्थिक विचारों की प्रसांगिकता

आज तीसरी दुनिया से भूख और गरीबी को हटाने के लिए सम्पूर्ण विश्व, संयुक्त राष्ट्रसंघ और विश्व बैंक सहित कई अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भरकस प्रयास कर रहे हैं। बहुत से सकल्प लिये गये, बहुत सी नीतियां बनायी गयी ताकि उपरोक्त को क्रियान्वित किया जा सके। परन्तु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी सफल नहीं हुए हैं।

स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद सरदार पटेल ने राज्यों के विलीनीकरण का विशालकाय कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त, आर्थिक विकास की दिशा में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि—राज्यों को जोड़ने के बाद अपनी ऊर्जा और समय को अपने देश के आर्थिक विकास को प्राप्त करने में लगाये। आर्थिक विकास के सम्बन्ध में सरदार पटेल का अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रहा। सन्तुलित आर्थिक विकास और न्यायपूर्ण वितरण, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा स्वावलम्बिता उनके आर्थिक विचारों का लक्ष्य था। खाना, कपड़ा और आवास नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं अतः इनके उत्पादन बढ़ाने के लिए पटेल ने “उद्योगपतियों, व्यापारी वर्ग तथा मजदूरों के अनुरोध किया सब के लिए उनका एक ही मूल मंत्र था। अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाओ”⁸ 26 जनवरी 1948 ई० को पटना में नागरिकों से अपने भाषण में राजनीतिज्ञ, पूँजीपति, किसान, मजदूर, सबसे अनुरोध किया कि अपने धर्म का अनुपालन करे उत्पादन बढ़ाये और सकीर्ण हितों को राष्ट्रीय हितों के लिए त्याग दे तभी राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर होगा और स्वावलम्बी बन सकेगा।”⁹ 20 फरवरी 1948 ई० को बम्बई में एक सभा को सम्बोधित करते हुए सरदार पटेल ने लोगों से अधिकतम उत्पादन की अपील की। उन्होंने इस बात की भी वकालत की कि सरकार, मजदूर और उद्योगपति सभी को मिलकर कार्य करना चाहिये।

सरदार पटेल ने औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ कृषि उत्पादन पर भी बल दिया,

८ नन्दरकर, जी०एम०, सरदार पटेल बर्थ सेण्टरी वाल्यूम -2, अहमदाबाद, 1975, पृ० 26-27

९ भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल के भाषण (1947-1950), प्रकाशन विभाग, दिल्ली, 1970, पृ० 126

वे सदैव कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर देते थे, उनके दृष्टिकोण में कृषि को प्रधानता दी जानी चाहिये और उपयुक्त साधनों को उपलब्ध कराया जाना चाहिये। सरदार पटेल ने किसानों से अपील की थी कि वे मेहनत करें ताकि अपनी परेशानियों से अपना उत्तम प्राप्त कर सकें और सरकार को अपनी न्यूनतम आवश्यकता से अधिक दे सकें। उन्होंने किसानों की सुझाव दिया था कि सरकार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सहयोग करें ताकि खाद्य आपूर्ति एवं मॉंग में सामाज्यस्थ स्थापित किया जा सके।

सरदार पटेल ने उद्योगपतियों व्यवसायियों, व्यापारियों और मजदूरों से अपील करते हुए कहा कि "मुझे यह कहने की जरूरत नहीं कि वर्तमान आर्थिक संकट से निपटने और बढ़े हुए उत्पादन का क्या महत्व है। यही वह श्रेष्ठ तरीका है जिससे मॉंग और आपूर्ति के बीच सन्तुलन स्थापित किया जा सकता है। अतएव सरकार, उद्योगपतियों और मजदूरों सभी को राष्ट्र सेवाभाव से कार्य करना चाहिये।

उद्योगपतियों का कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक उत्पादन करें। मजदूरों को भी चाहिये कि वे औद्योगिकों की मदद करें ताकि राष्ट्र को फायदा हो सके। सरकार का कर्तव्य है कि वह भाई भतीजावाद तथा लालफीताशाही से बचे। व्यापारियों का कर्तव्य है कि उत्पादित किया हुआ माल बिना किसी या कम से कम व्यवधान के उपभोक्ता तक पहुँचाये।

"उत्पादन करो या फिर मिट जाओ"¹⁰ यह एक कटु सत्य है इस समय इसलिए आप सबको परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें जो आजादी मिली है हमें, चाहिए कि हम उसे सभाल सकें। हमारी मिट्टी में हमारे देश में प्राकृतिक साधनों का भण्डार है क्यों न उसका उत्तम ढंग से इस्तेमाल किया जाय? क्यों न कपड़े, स्टील, सीमेन्ट आदि क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाकर अपनी गृहस्थी जरूरतों का समाधान किया जाय? क्यों न और कोयला और जरूरत के समानों का उत्पादन किया जाय ताकि भारत एक विशाल और मजबूत राष्ट्र बन सके और कोई भी उसकी सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न न लगा सके इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि अगर आप ज्यादा वेतन चाहते तो उत्पादन को बढ़ाईये। देश दो चीजों की मॉंग करता है पहली हिन्दु-मुस्लिम एकता, दूसरी मजबूती राज्यों के मिलने से।

१० भट्ट, एम०सी०, प्र०, सरदार पटेल्स, आइडियाज आन एकोनामिक पोलसी - दियर रेलीवेन्सी, अहमदाबाद, 1998, पृ० 10

11 नवम्बर 1949 ई० को व्यापारियों, उद्योगपतियों और मजदूर, नेताओं की बैठक में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु कहा, "हमारे आर्थिक विकास की कुंजी बड़े हुए उत्पादन में है।¹¹ उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए दो दृष्टिकोणों को अपनाया जाना चाहिये। प्रथम अपनी औद्योगिक क्षमताओं का भरपूर उपयोग करना चाहिये और द्वितीय हम अपने औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा पूँजी निवेश की आवश्यकता होगी। बड़े हुए पूँजी निवेश से जहाँ हम एक ओर उपभोक्ता की माँगों से निपट सकते हैं वही दूसरी ओर हम अपने आयातों पर भी रोक लगा सकते हैं, जो कि न हमारी विदेशी मुद्रा को बचाने में सहायक होगा बल्कि नयी औद्योगिक ईकाई के लिए आवश्यक कच्चेमाल की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।

सरदार पटेल भारत आर्थिक कठिनाइयों के प्रति सजग थे। वे बराबर इस बात का चिन्तन करते कैसे नागरिकों की मूल भूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाये उनके जीवन को सुखद बनाया जाये तथा देश को आत्म निर्भर बनाया जाये। आर्थिक, पुर्ननिर्माण तथा महगाई नियन्त्रण पर विशेष बल देते थे। अधिक उत्पादन तथा उचित वितरण उनकी आर्थिक नीति की आधार शिला रही उनके अनुसार सरकारी तंत्र उद्योग मजदूर को एकजुट होकर राष्ट्र के सन्तुलित विकास में सक्रिय होना होगा।

अपने कार्यक्रमों को विस्तार देते हुए हमारा लक्ष्य अपने साधनों का परीक्षण होना चाहिये और उसे इस तरह योजनाबद्ध होना चाहिये कि हम भविष्य के प्रति आशान्वित रहे कि उत्पादन एक लम्बा रास्ता तय करेगा। जिससे कि हमारी करेसी पर निर्भरता कम हो।

सरदार पटेल ने खाद्य सामग्री के आयात और अधिक दामों के बारे में कहा था कि यदि हमारे पास वो पूँजी होती, जो हमने पिछले तीन सालों में खाद्य सामग्री के आयात पर खर्च कर दी है, तो पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को अच्छी जिन्दगी प्रदान कर सकते थे। हम हमेशा भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, पर क्या हमने कभी भी इस बात पर विचार किया कि गरीबों की सहायता करना, पड़ोसियों की मदद करना तथा दीनहीन लोगों के प्रति दया करना ही सभ्यता एवं संस्कृति के चमकते हुए रत्न हैं। यदि हम ईमानदार हैं तो हमें उन लोगों का कड़ा विरोध करना चाहिये जो कि सरकार को दिये

हुए एक-एक दाने की कीमत माँगते हैं या फिर भूखे पड़ोसियों को देखता हुआ अपने गेहूँ का भण्डारण करते हैं या अपनी मिट्टी की एक-एक इंच भूमि का भी सही ढंग से इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं करते साथ ही उन लोगों का भी विरोध होना चाहिये जो लोग खाद्य सामग्री को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं।

सरदार पटेल ने पूँजीवादियों से विशेष तौर पर बचत की अपील की थी उन्होंने बचत को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा। उनका कहना था कि कृषक, मजदूर, व्यापारी, वकील, सरकारी कर्मचारी सबको बचत करनी चाहिये जिससे की राष्ट्र निर्माण में सरकार की मदद हो सके। हमारे पास विकास की बहुत सी योजनाएँ हैं पर जब हम अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो पाते हैं कि यदि हम अपने साधनों के भीतर जीना हैं, तो हम अपने विकास कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ेगी। जबतक हम राष्ट्रीय आर्थिक नीति में भारी बदलाव करके इन कार्यक्रमों को लागू करने योग्य स्थिति नहीं प्राप्त कर लेते तब तक इनको लागू नहीं किया जा सकता। ये कार्यक्रम ही वर्तमान के साथ-साथ बढ़ती हुई जनसंख्या का भरणपोषण कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूँजी की आवश्यकता है जिसे अपने देश में आना चाहिये। हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से भी उधार लेना चाहिये पर स्वाभाविक है कि हम अपनी रोजमर्रा की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए विदेशी उधार पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके लिए मेरे पास एक ऐसी योजना है जिसमें हमने घोषणा की है कि ऊँचे वेतन और अनिवार्य बचत में स्वैच्छिक कटौती की जाय। जिसमें की सरकारी कर्मचारियों ने व्यापारियों और दूसरे आय व्यवसायियों को मात दी है। मैं यही अपील प्रान्तीय सरकारों से भी करता हूँ।

ये सभी सहयोगात्मक कदम न सिर्फ सहयोगी को भविष्य की बचत से लाभान्वित करते हैं बल्कि सरकारों की भी सहायता करते हैं ताकि वे अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। “कम खर्च, ज्यादा बचत और जितना निवेश कर सको यही एक नागरिक जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिये।”¹²

सरदार पटेल औद्योगिक विकास के लिए मजदूरों के महत्वपूर्ण सहयोग को पहचानते थे, इसलिए उनके भाषणों में हमेशा ही इस बात पर जोर होता था कि आगे बढ़े हुए कामों को पूरा करने के लिए पूँजीपति और मजदूरों का साथ जरूरी है, और अगर हम ऐसा नहीं

१२ भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947-50), प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, 1970, पृ० 100

कर पाते हैं तो ने सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी बल्कि मुझे इसमें भी कोई दो राय नहीं दिखती अगर मजदूर और पूँजीपति के बीच का द्वन्द्व खत्म न हो तो सरकार भी अपने देश के लिए एक अभिशाप साबित होगी" और मैं पूर्व तरह से सहमत हूँ कि अगर इस द्वन्द्व को किसी तरह का बढ़ावा दिया गया तो भारत के औद्योगिक भविष्य के लिए यह एक करारा झटका होगा।

इंग्लैंड में मजदूरों, पूँजी और सरकार के आपसी सहयोग से उत्पादन को बढ़ावा जा सका था, वही दूसरे स्थान पर भारत में हम जादू पर विश्वास करते दिखाई पड़ते कि मजदूर कम उत्पादन करेगा और ज्यादा कीमत पा लेगा और इसका नतीजा होता है हड़ताल जो कि उत्पादन को कम करती है, और कम उत्पादन मतलब और गरीबी और भूखमरी, हमें इस चक्र को तोड़ना होगा।

मजदूर आज दोराहे पर खड़ा है, अगर वह सही राह पकड़ता है, और अपनी सारी ऊर्जा को राष्ट्र को मजबूत करने के लक्ष्य पर लगा देता है, तो भारत के पास एक उज्ज्वल भविष्य है पर यदि वह गलत राह चुनता है तो सबको बरबादी पर ले जायेगा।

मजदूरों को ये समझाना चाहिए कि वे केवल खुद को व्यवस्थित रखने के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि उनको अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य बनता है उसको महसूस करना चाहिए, मजदूरों को हमेशा करोड़ों देशवासियों की आशाओं को सामने रखना चाहिए और तोड़-फोड़ वाली नेतागिरी को छोड़कर देश के हित के बारे में सोचना चाहिए।

पिछले दो वर्षों में हमने बहुत से ऐसे भयंकर खतरों का सामना किया है, जिनका कि किसी भी देश ने इतिहास में भी सामना नहीं किया होगा। उन सब खतरों के बावजूद हमने उस एकता और सीमायी मजबूती को प्राप्त किया है जिसका अदाजा हमें पिछले दो हजार सालों से नहीं था हमें उन प्राप्ति को यूँ ही नहीं खो देना चाहिए बल्कि उनको एक खुशहाल और सफल राष्ट्र के निर्माण में लगाना चाहिए, मैं खुद जो इस प्राप्ति के कारणों में से एक था इसको बताना चाहता हूँ पर इसके लिए मुझे सहयोग और सहायता प्रत्येक नागरिक की चाहिये।

जो भी विदेशी निवेश के विषय में पूरी जानकारी रखते हैं जानते हैं, कि भारत की विशालतम ताकत है उसकी विदेश निवेश नीति जहाँ पर अगर एक बार निवेश लागू हो जाता तो लाभ और पूँजी दोनों आने लगता है। भारत का बहुत सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

बैढको ने इस पर बहुत ही साफ रिकार्ड रहा है और इसी से उसने निवेशकर्ताओं का विश्वास जीता है।

नवम्बर 1948 सरदार पटेल ने आवश्यक वस्तु के मूल्यों पर रोक की बात कही क्योंकि महगाई हमारी आजादी का सीधा प्रहार करती है।¹³ हम सभी मूल्यों के बढ़े हुए रूप से परेशान हैं और जब वो कुछ उचित कीमत पर आते हो एक सुखद अहसास होता है। सरदार पटेल इन बातों से कितना प्रभावित थे ये इस बात से ही पता चल जाता है जो उन्होंने 11 नवम्बर 1949 को कही, हम इतने ऊँचे मूल्यों को नहीं झेल सकते इसलिए मूल्यों को नीचे आना ही चाहिये अपनी सिकुडती हुयी आय और भविष्य के सिकुडन को देखते हुए हम जब तक खुद को उबार न पाये तब तक हमें उन साधनों को उन विदेशी मुद्राओं में बनाना होगा जिनसे कि हम औद्योगिक जगत को बचा सके और इसके लिए हमें अपने आयातों में कटौती करनी पड़ेगी।

सरदार ने हमेशा ही सेवाओं को एक ऊँचा स्थान दिया है और कहा कि एक बुरा काम करने वाला वह है जो अपने औजारों से लडता है। किसी ने भी सेवाओं के अर्थ को नहीं समझा है, इसलिए मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूँ कि इस बारे में लोगों को जागरूक बनाऊ इसलिए सभी को यकीनन सरकारी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और अगर सरकार और विधायिका ने उन्हें यह जिम्मेदारी भरा काम सौंपा है तो उन्हें उसे निभाना चाहिए और अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो न ही वे अपने साथ अन्याय कर रहे हैं बल्कि वे इस सरकार, उस विधायिका, उस देश के साथ विश्वासघात कर रहे जिन्होंने उन पर विश्वास करके अपना ये काम उन पर छोड़ा था। इसलिए मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि वे अपने में सुधार करें ताकि उनकी हर कार्यवाही देश को बिना नुकसान पहुँचाये उसका हर सम्भव फायदा कर सके। अगर वो ऐसा कर पाये तो वे घृणा को चाहत में बदल सकेगे, अन्धकार को प्रकाशवान कर सकेगे।

तो ये देखा जा सकता है सरदार पटेल एक देशभक्ति का सदेश देते थे, उनकी एक पैनी नजर थी मानव व्यवहार पर अपने देश की आर्थिक दिशा को सवारने के लिए एक मजबूत इच्छा थी ताकि वो अपने देश से गरीबी हटा सके, ताकि इस देश के लोगो

को अपनी जरूरत के अनुसार, खाना, कपड़ा और आवास मिल सके। राष्ट्र के आर्थिक विकास के सरदार पटेल के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इस सम्बन्ध में 1986 ई० में जे० आर० डी० टाटा का कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है, "अगर विधाता ने पटेल को जवाहर लाल से उमर में छोटा बनाया होता तो शायद भारत का पटेल निर्धारित विकास अलग मार्ग पर चलता और उसकी आर्थिक व्यवस्था कहीं बेहतर होती।"¹⁴

अध्याय - 7

निष्कर्ष

निष्कर्ष

राष्ट्रनिर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर्मयोगी एवं राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के प्रबल समर्थक थे। देश भक्ति के मूर्त स्वरूप थे स्वतन्त्रता संग्राम के महासेनानी, अविश्रान्त राष्ट्रकर्मी परम नैष्ठिक देशभक्त, दूरदर्शी राजपुरुष, दृढ़ प्रशासक एवं संवेदनशील मानव थे। भारत की पावन मिट्टी से जुड़े सरल किसान परिवार में जन्म हुआ उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए वे बड़े हुए, अन्याय का सदा विरोध किया, निर्भयता और आत्मविश्वास से भरपूर उनका तेजस्वी व्यक्तित्व रहा। त्याग, श्रम, साधना और साहस का अद्भुत सङ्गम था उनका जीवन। यही कारण था कि धरती का यह लाल भारतीय राजनीति रूपी हिमालय के उत्तुंग शिखर पर समासीन हुए। स्कूल की परीक्षापास कर, अर्थान्ध्रता के कारण वल्लभ भाई कालेज और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाये। अतएव तीन वर्षों के उपरान्त प्लीडर की परीक्षा पासकर वकालत शुरू की। शीघ्र ही वे अपने व्यवसाय में ख्याति प्राप्त कर एक सफल वकील की श्रेणी में आ गये। तद्उपरान्त कुछ धनसङ्ग्रह करके विलायत गये और बेरिस्टरी की उपाधि धारण कर भारत वापस आये और अहमदाबाद में वकालत करने लगे। इसी दौरान महात्माँ गान्धी के सम्पर्क में आने के उपरान्त भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में जुड़ गये। त्याग अध्यायवास और सङ्गठनात्मक कला से शीघ्र ही वे शीर्षस्थ नेता बन गये। उनकी आन्तरिक प्रतिभा और निर्मल गुण ही उनमें उत्साह और साहस का प्रवाह करते रहे। लोकमान्य तिलक की भाँति भारतीय राष्ट्र को सङ्गठित, सशक्त, परमदृढ़ बनाना ही उनके जीवन का महामन्त्र था। 1917-18 के खेड़ा सत्याग्रह, 1922 के नागपुर झण्डा सत्याग्रह 1924 के बोरसद सत्याग्रह, 1927 का गुजरातत बाढ़ सकट तथा 1935 ई० के बोरसद प्लेग, अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष पद आदि ने इस महापुरुष की निर्भयता, वेजोड व्यवस्था शक्ति, सेवा परायण, ध्येयनिष्ठा, निश्चय बल और असामान्यशक्ति का गुजरात और राष्ट्र को परिचय कराया। 1928 ई० के बारदोली आन्दोलन का कुशल नेतृत्व करके सरदार पटेल ने किसानों के बीच अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। उनके नये तुले शब्दों में, किसानों को उनके अधिकारों का चैतन्य कराने वाले छोटे व्याख्यानो में गजब की शक्ति थी। कांग्रेस

संगठन में गुजरात प्रान्तीय अध्यक्ष के रूप में, 1931 ई० के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में, प्रान्तीय स्वशासन के वक्त पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में देश के प्रान्तीय प्रधानमण्डलों के सूत्रधार के रूप में उन्होंने अपनी गहरी सूझ-बूझ, दूर दृष्टि, अनुशासन, प्रियता विषय की पकड़, व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता आदि का परिचय दिया। सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुए 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार विषयक प्रस्ताव पारित हुआ। अपने सक्षिप्त व्याख्यान में उन्होंने भगतसिंह और उनके साथियों के मृत्युदण्ड को कारावास में नहीं बदलने पर वायसराय की कड़ी आलोचना की। 1941 ई० में वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में जेल गये। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान भी उन्हें जेल में रखा गया। स्वतन्त्रता आन्दोलन में सरदार पटेल गाँधी जी के सच्चे अनुयायी के रूप में भाग लिया तथा उनके बताये हुए मार्ग का अनुसरण किया 1939 ई० में त्रिपुरी कांग्रेस में उनकी सुभाष चन्द्र बोस से जोरदार टक्कर भी हुई।

स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में सरदार पटेल एक परमदृढ़ नायक की भूमिका निभाई उसी प्रकार जब शासन की बागडोर सम्भालने की जिम्मेदारी आयी तो उच्चतम शासकीय अधिकारियों को भी अपनी गहन सूझ-बूझ और योग्यता से मन्त्रमुग्ध किया। 2 सितम्बर 1946 ई० को गठित आन्तरिम सरकार में सरदार पटेल गृह विभाग तथा सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के मंत्री बने। 12 मई 1947 ई० को कैबिनेट मिशन ने देशी राज्यों के सम्बन्ध में कहा था कि ब्रिटिश शासन का अन्त होने पर देशी राज्यों ने जो सार्वभौमिक अधिकार सम्राट को सौंपे थे, उन्हें वापस मिलेंगे। 3 जून 1947 ई० को ब्रिटिश सरकार ने इस विज्ञप्ति का समर्थन किया परिणाम 15 अगस्त 1947 ई० को भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में आस्तित्व में आया। सरदार पटेल भारत विभाजन के विरोधी थे लेकिन अन्ततः उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ एक वर्ष शासन चलाने के अनुभव के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि साम्प्रदायिकता की आग से देश को बचाने के लिए तथा उसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए विभाजन अनिवार्य है और उनको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 5 जुलाई 1947 ई० को सरदार पटेल देशी रियासतों के मंत्री के साथ उप प्रधान मंत्री भी बने। अपनी मान्त्रिमण्डलीय जिम्मेदारी को सरदार ने बड़ी योग्यता, दक्षता और निष्ठा से चलाया। 1948 ई० में हृदयरोग से अक्रान्त होने पर भी वे सर्वदा कार्यरत रहे। प्रशासनिक कार्यों में उनका व्यक्तित्व मुखरित होता रहा। सरदार पटेल का अविस्मरणीय कार्य देशी रियासतों का भारत में विलयन कराना है। राजनीतिक सूझ-बूझ, व्यवहार कुशलता और राजनयिक कुशलता

से 554 से भी अधिक छोटे-बड़े देशी नरेशों का भारत सघ में विलय करने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार अखण्डता की उन्होंने रक्षा की। उनकी तुलना जर्मनी के लौह पुरुष विस्मार्क से की जाती है। जो कार्य विस्मार्क ने "रक्त और अयस" से किया वल्लभ भाई पटेल ने यह कार्य राजनय से किया। हैदराबाद का भारत में विलयन उनका चिरस्मरणीय राष्ट्रीय योगदान है।

गृहमन्त्री के रूप में स्वतन्त्रता उपरान्त अंग्रेज प्रशासकीय अधिकारियों के इंग्लैण्ड वापसी से उत्पन्न प्रशासकों की समस्या का समाधान करने हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का गठन कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाने कार्य सरदार पटेल ने किया।

भारत के संविधान और संवैधानिक परम्परा के निर्माण और दृढीकरण में भी सरदार का स्थान है। वे संविधान निर्मात्री सभा की तीन उपसमितियों के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अल्प संख्यकों के लिए आरक्षण का विरोध किया और सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग अस्वीकार कर दी गयी। प्रान्तीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रपति द्वारा सकटकालीन परिस्थितियों में राज्यों का शासन अपने हाथ में लेना सरदार पटेल के विचारों से ही समविष्ट हुआ। राज्यों द्वारा सम्पत्ति ग्रहण करने पर, राज्य सम्बद्ध व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की राशि देगा यह बात भी उन्हीं के विचार और सुझाव पर स्वीकृत की गयी। नेहरू राष्ट्रपति का चुनाव मात्र ससद द्वारा करवाना चाहते थे जबकि पटेल जिस समिति के अध्यक्ष थे उनका सुझाव था कि ससद के बाहर उसका निर्वाचन हो अन्त में निर्णय हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव ससद और राज्य विधान मण्डलों द्वारा होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति के गरिमामय पद को केवल ससद के ऊपर आश्रित नहीं किया गया। सघ इकाइयों को भी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में शामिल कर राष्ट्रपति को सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि का सम्मान प्राप्त हुआ।

काश्मीर समस्या को देशी रियासतों के विभाग से अलग किये जाने से सरदार पटेल खुश नहीं थे उन्होंने इस पर विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यदि यह समस्या मुझे दे दी जाय तो मैं 15 दिनों में इसे हल कर सकता हूँ इसके अलावा काश्मीर प्रश्न की सयुक्त राष्ट्र सघ में ली ले जाने के विरोधी थे। मुस्लिम लीग को वह राष्ट्र की एकता और अखण्डता

मे बाधक समझते थे तथा अन्य हिन्दू सगठनों को भी वे किसी प्रकार की समाज में अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं देते। कुछ लोग सरदार पटेल को मुस्लिम विरोधी बताते हैं लेकिन वास्तव में वे तटस्थ थे। मुस्लिमों के प्रति उनका विचार अन्य विषयक विचारों की भाँति राष्ट्रीयता से ओत प्रेत था। विदेश नीति के सम्बन्ध में वे दूरदर्शी थे। राष्ट्र मण्डल की सदस्यता प्राप्त करने के समर्थक थे तथा नेहरू को चीन के सम्भावित खतरो से बार-बार आगाह किया।

सरदार पटेल का सामाजिक विचार गोंधी जी का अनुपूरक है उन्होंने जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद, अस्पृश्यता, बाल विवाह, अनमेल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया तथा अन्तर्जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। साथ ही शान्ति एवं सह आस्तित्व, सहनशीलता, न्याय एवं समानता तथा सामुदायिकता के आधार पर एक स्वच्छ समाज की स्थापना पर बल दिया तथा वे आर्थिक रूप से गोंधीवादी समाजवाद के समर्थक थे। सरदार पटेल के राजनीतिक जीवन के प्रायः चार दशक अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ने में लग गये और उस युग के समस्त दलों और राष्ट्रकर्मियों का साम्राज्यवाद विरोधी जग जीतना उद्देश्य था। उस वक्त वर्ग संघर्ष को समर्थन देना स्वतन्त्रता आन्दोलन को कमजोर करना होता अतएव पटेल ने अपने ढंग से दरिद्रता की समस्या से लड़ने का कार्य किया। सहयोग समितियाँ, लघुउद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रश्रय देना उनका लक्ष्य था।

सरदार पटेल ने आर्थिक विषमता, सामाजिक वैमनस्य और दूरियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार को उन्मूलन का सतत प्रयास किया। क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद, सामुदायिकतावाद जैसे सकीर्ण प्रवृत्तियों का विरोध कर अखण्ड और राष्ट्रीय मनोवृत्ति तथा संस्कृति उजागर करने में सदा अग्रणी रहे।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सरदार पटेल भविष्य द्रष्टा थे। भारत की राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के उनके अपने मौलिक विचार थे। व्यापक दृष्टिकोण, दूरदर्शिता समन्वय एवं सन्तुलन और व्यवहारिकता उनके विचारों की मुख्य विशेषता थी। उनकी विचार धारा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता से बंधी थी, जिसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि था।

सरदार पटेल बहुमुखी क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ थे। अन्याय का प्रतिकार उनके कर्मों व सिद्धान्तों की बुनियाद रही। वे कर्मयोगी, व्यवहारिक - राजनीतिज्ञ एवं स्पष्टवादी थे।

उनमें न केवल राष्ट्र की जटिल समस्याओं को समझने की अपूर्व क्षमता थी वरन राष्ट्र को सही नेतृत्व देने की अपूर्व क्षमता थी। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की उनमें गहरी समझ थी और उनके समाधान के बारे में स्पष्ट योजना थी। निष्काम कर्मयोगी, परम राष्ट्रभक्त, निष्ठावान प्रशासक एवं दूरदर्शी राजनेता के रूप में सरदार पटेल ने भारत के नवनिर्माण में अभूतपूर्व योगदान किया। उनका जीवन दर्शन, उनका चरित्र एवं व्यवहार, उनके निर्णय, उनके सुझाव देश के भावी विकास में आज भी उतने ही प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय हित पटेल के लिये सदैव सर्वोपरि रहा। पद या सत्ता का लोभ उनको लेशमात्र विचलित नहीं कर सका। उन्होंने समर्पित, साहसी, सत्याग्रही के रूप में राजनीति में प्रवेश किया तथा एक सक्षम सगठनकर्ता एवं कुशल प्रशासक के रूप में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को सफल नेतृत्व प्रदान किया। अपने निष्पक्ष, भेदभावपूर्णरहित व्यवहार द्वारा एक स्वच्छ, सबल एवं सुदृढ़ प्रशासन की नींव रखी। अन्याय, अनाचार और भ्रष्टाचार का प्रबल विरोध ही नहीं अपितु उन्मूलन करने का सतत् प्रयास किया। उनकी कार्यप्रणाली, जो कि कार्यकर्ताओं पर विश्वास व सद्भाव पर आधारित थी, आज भी राजनीतिज्ञों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के गिरते मनोबल को ऊपर उठाने की दिशा में अनुकरणीय है।

वे समाज को सद्भावना के नींव पर खड़ा करने में तत्परता से लगे रहे। उन्होंने सामाजिक कुशितियों की पूर्ण आलोचना की। वे महिलाओं की शिक्षा, बराबर का सम्मान तथा भागीदारी के पक्षधर थे। उन्होंने एक सहिष्णु समाज का लक्ष्य सबके सामने रखा। हिन्दू-मुस्लिम में सद्भाव और एकता के विस्तार के लिए प्रयास किया। सबको जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय जैसी सकीर्ण परिधियों से ऊपर उठ कर राष्ट्रीय हित के आधार पर एकजुट होने की सदैव प्रेरणा दी। वे भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व समृद्धशाली बनाना चाहते थे। उन्होंने सबको एक ही मूलमंत्र दिया- “अपने धर्म का पालन करो और श्रम करो।” परिश्रम और निष्ठा से ही देश का विकास संभव है। आपस के सारे लड़ाई-झगड़े भूलकर सबको उत्पादन बढ़ाने, बचत करने की सलाह दी। अनावश्यक खर्चों में कटौती और मेंहगाई पर नियन्त्रण की बात की। देशी रियासतों का भारतीय संघ में सम्मिलन सरदार पटेल के सुदृढ़ नेतृत्व और निर्णायक क्षमता द्वारा संभव हुआ। भारत के गृहमंत्री के रूप में प्रशासनिक सेवाओं का सगठन और लोकतंत्रीकरण उनकी ही देन है।

निष्पक्ष एव स्वच्छ चुनाव के संचालन के लिये स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग का गठन तथा हिन्दी को राष्ट्र भाषा का गौरव दिलाने में भी सरदार पटेल की ही निर्णायक भूमिका रही। उनमें अद्भुत दूरदर्शिता थी। 1948-49 में काश्मीर, चीन, नेपाल, गोवा आदि के मामलों पर उनके विचार व सुझाव आज भी कितने उचित प्रतीत होते हैं।

सरदार पटेल ने देश, समाज और राजनीति को स्वस्थ, उन्नत, सर्वहितकारी बनाने का सतत प्रयास किया। त्याग एव सेवा, सदाचार, स्पष्टवादिता, सत्यभाषण, नैतिकता, आत्म-सम्मान, समदृष्टि, सादगी, कर्तव्यपालन आदि के उदात्त जीवन-मूल्यों को अपने आचरण में उतारा और वे सम्पूर्ण देशवासियों के लिये एक अद्वितीय आदर्श बने। अनुशासन और विश्वास का अनुपम समन्वय कर स्वच्छ और सुदृढ़ प्रशासन की परम्परा स्थापित की। वे दूरदर्शी राजनेता थे। समय की आवश्यकता के अनुरूप उचित निर्णय लेते तथा एक बार निश्चय कर लेने पर उसे दृढ़ता से लागू करते। राष्ट्रवादी, व्यवहारकुशल राजनेता सरदार पटेल का व्यक्तित्व एव कृतित्व देशवासियों के लिये सर्वदा ज्योति स्तम्भ बने रहेंगे।

ग्रन्थ-सूची

- 1- आजाद, अब्दुल कलाम, आजादी की कहानी, ओरियेन्ट लोगमेस, कलकत्ता, 1965
- 2- कुमार, रवीन्द्र, सरदार पटेल का सत्याग्रही जीवन, राजीव प्रकाशन मन्दिर, मुजफ्फरपुर, 1987
- 3- कुमार, रवीन्द्र, सरदार पटेल के राजनीतिक एवं सामाजिक विचार, मित्तल पब्लिकेशन, नयी दिल्ली, 1991
- 4- कुमार, सुरेन्द्र, सरदार पटेल, जनवाणी प्रकाशन, दिल्ली 1998
- 5- गिरिकर, देव, सरदार पटेल, चरित्र और काल, भारत ग्रन्थ माला, पुणे, 1971
- 6- जकारिया, रफीक, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1998
- 7- तारा चन्द्र, भारतीय स्वतन्त्रता का इतिहास, भाग-१, प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, 1982
- 8- तारा चन्द्र, भारतीय स्वतन्त्रता का इतिहास, भाग-२, प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, 1982
- 9- दास, सेठ गोविन्द, सरदार पटेल, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 1969
- 10- दास, दुर्गा, (सम्पादित), सरदार पटेल का पत्र व्यवहार, (1945-1950), (सम्बन्धित खण्ड), नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1973
- 11- देसाई, महादेव, बीर, वल्लभ भाई, सरदार पटेल युनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, 1970
- 12- देसाई, नारायण, सरदार और गोंधी जी, सरदार वल्लभ भाई, पटेल राष्ट्रीय स्मारक, अहमदाबाद, 1982
- 13- देसाई, महादेव, बारदोली सत्याग्रह, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1957

- 14- पटेल, ईश्वर भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चरोत्तर बुक्स, आजन्द, 1974
- 15- पटेल, दिलावर सिंह जैसवार, नवेदित भारत के निर्माता सरदार पटेल, गीताजलि प्रकाशन दिल्ली, 2000
- 16- पटेल, बाबू भाई, स्वतन्त्र भारत का निर्माण, सरदार वल्लभ भाई, पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन अहमदाबाद, 1983
- 17- पटेल, मणि बहन, सरदार श्री के विशिष्ट एव अनोखे पत्र, भाग-एक, सरदार वल्लभ भाई, पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन, अमदाबाद 1981
- 18- पटेल, मणि बहन, सरदार श्री के विशिष्ट एव अनोखे पत्र, भाग-दो, सरदार पटेल स्मारक भवन, अहमदाबाद, 1981
- 19- पटेल मणिबहन, बापू के पत्र सरदार वल्लभ भाई के नाम, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद 1952
- 20- पटेल, गगुभाई, युग पुरुष सरदार वल्लभ भाई, पाटीदार सशोधन एव प्रकाशन ट्रस्ट अमहदाबाद 1990
- 21- पटेल, राव जी भाई, मणि भाई, हिन्द के सरदार, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1972
- 22- पटेल, एच० एम०, सरदार पटेल की सर्वोन्मुखी राष्ट्र सेवा, सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय स्मारक भवन, अहमदाबाद, 1948
- 23- परमार रजन, बारदोली के सरदार राष्ट्र भाषा प्रचार, समिति, वर्धा, 1972
- 24- पाठक, देवव्रत, सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय स्मारक भवन, अहमदाबाद, 1981
- 25- प्रभाकर, विष्णु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली, 1982
- 26- पारीख, नरहरि सरदार वल्लभ भाई पटेल, खण्ड-एक, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1950
- 27- पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खण्ड-दो, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अमदाबाद, 1954

- 28- पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918-1947) तक, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1950
- 29- बापू के पत्र सरदार वल्लभ भाई के नाम, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद 1956
- 30- भारत की एकता का निर्माण, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण (1949 से 1950 तक) प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, 1970
- 31- मिश्र, ज्योति प्रसाद (सम्पादक), पटेल अभिनन्दन ग्रन्थ लखनऊ, 1948
- 32- मेहता, चन्द्र बहन, अनन्य देशभक्त - महावीर या धर्मवीर वल्लभ भाई, सरदार पटेल स्मारक भवन अहमदाबाद, 1981
- 33- मेहरोत्रा, एन०सी०, एव कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, आत्माराम एण्ड सन्स काश्मीरीगेट, दिल्ली 1997
- 34- रणजीत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शालिनी प्रकाशन, इलाहाबाद, 2000
- 35- सरदार की सीख, सरदार पटेल के पत्रों का उद्धरण, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद, 1958
- 36- सरदार पटेल - सत्याग्रही से राजनीतिज्ञ, निर्देशक, भारतीय अभिलेखागार नयी दिल्ली, स्टेट्स मैन प्रेस नयी दिल्ली,
- 37- सरदार साहित्य माला सम्पुट, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन, अहमदाबाद
- 38- सरदार शताब्दी स्मारक ग्रन्थ, कुल सचिव, सरदार पटेल युनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, 1978
- 39- शकर, बी०, सरदार पटेल- चुना हुआ पत्र व्यवहार, भाग-एक, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद 1976
- 40- शकर, वी०, सरदार पटेल- चुना हुआ पत्र व्यवहार, भाग-दो, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1976

- 41- शंकर, वी, सरदार के सपनों का भारत और वास्तविकतायें, सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय स्मारक भवन, अहदाबाद, 1982
- 42- शर्मा, धर्मपाल, राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत, युगवार्ता प्रसंग लेख सेवा, नयी दिल्ली 1982
- 43- शरण, गिरिराज, पटेल ने कहा था, प्रभात प्रतिष्ठान नयी दिल्ली, 1982
- 44- शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, सोसाइटी फार पार्लिया मेण्टरी स्टडीज, नय दिल्ली, 1963

अंग्रेजी ग्रन्थ

- 1- अली, युसुफ, लीडर्स आफ इण्डिया, पदमा पब्लिकेशन, बम्बई 1947
- 2- आजाद, अब्दुल कलाम, इण्डिया विन्स फ्रीडम, आरियेन्ट लोगेस, कलकत्ता, 1959
- 3- अहलू वालिया, बी०के०, फैक्ट्स आफ सरदार, कल्यानी पब्लिकेशन, लुधियाना, 1974
- 4- कान्स्टीट्यून्ट असेम्बली डिवेट्स, वाल्यूम-III, प्रिन्टेड बाई गर्वमेन्ट आफ इण्डिया प्रेस, फरीदाबाद, 1966
- 5- कान्स्टीट्यून्ट असेम्बली डिवेट्स, वाल्यूम -IV, प्रिन्टेड बाई गर्वमेन्ट आफ इण्डिया, प्रेस, फरीदाबाद 1966
- 6- कान्स्टीट्यून्ट असेम्बली डिवेट्स, वाल्यूम -V, प्रिन्टेड बाई गर्वमेन्ट आफ इण्डिया, प्रेस, फरीदाबाद 1966
- 7- दास, दुर्गा (सम्पादित), सरदार पटेल कोरेस पोण्डेन्स (1945-50), वाल्यूम-1 से 10 तक, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1973
- 8- दास, एम० एम०, पार्टीशन एण्ड इण्डिपेण्डेन्स ऑफ इण्डिया, विजन बुक्स, दिल्ली, 1982
- 9- देसाई, महादेव, दि स्टोरी ऑफ बारदोली, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1957
- 10- देसाई, महादेव, डे टू डे विथ गॉंधी, वाल्यूम 1 से 8, सर्व सेवा सघ वाराणसी
- 11- देसाई, महादेव, महादेव भाई की डायरी, वाल्यूम 7 से 10, सर्व सेवा सघ वाराणसी
- 12- देसाई, महादेव, महादेवभाई की डायरी, वाल्यूम 12 से 15, सावरमती आश्रम ट्रस्ट, अहमदाबाद,

- 13- देसाई, महादेव, दि डायरी ऑफ महादेव देसाई, वाल्यूम- 1 नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1953
- 14- देसाई, महादेव, महादेव भाई की डायरी, वाल्यूम -2, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1949
- 15- देसाई, महादेव, दि स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैकमिलन, न्यू देल्ही, 1974
- 16- फार ए यूनाइटेड इण्डिया, स्पीक्स ऑफ सरदार पटेल (1947-1950), पब्लिकेशन डिवीजन, न्यू देल्ही, 1982
- 17- गुहा, ए०सी०, नेशनल (इण्डियाज) स्ट्रगल क्वार्टर ऑफ एव सेन्चुरी, पब्लिकेशन डिवीजन, न्यू देल्ही, 1982
- 18- गोंधी, एम० के०, लेटर्स टू सरदार पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1957
- 19- गोंधी, राजमोहन, पटेल ए लाइफ, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1973
- 20- कृष्णा, बी०, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इण्डियाज आइरन मैन, नयी दिल्ली, 1985
- 21- लिमये, मधु, प्राइम मूवर्स, रेडियेन्ट, दिल्ली , 1985
- 22- लोहिया, राम मनोहर, गिल्टीमैन ऑफ इण्डियाज, पार्टीशन, किताबिस्तान, इलाहाबाद, 1960
- 23- मेहता, अशोक, इकोनामिक कान्सेन्सेज ऑफ सरदार पटेल, चेतना, हैदराबाद, 1949
- 24- मेनन, वी०पी०, दि स्टोरी ऑफ दि इन्ट्रीग्रेशन ऑफ दि इण्डियन स्टेट्स, बम्बई, 1961
- 25- मेनन, वी०पी०, दि ट्रान्सफर ऑफ पावर इन इण्डिया, ओरियेन्ट लोगमेस, कलकत्ता, 1957
- 26- मिश्रा, डी०पी०, लिवग इन इरा, वाल्यूम -2, विकास पब्लिसिंग हाउस, न्यू देल्ही, 1978

- 27- मुन्शी, के० एम०, इण्डियन कान्स्टीट्यूशनल डाकूमेण्ट्स, वाल्यूम-1 मुन्शी पेपर्स बम्बई, 1967
- 28- मुन्शी, के० एम०, इण्डियन कान्स्टीट्यूशनल डाकूमेण्ट्स, वाल्यूम-2 मुन्शी पेपर्स बम्बई, 1967
- 29- नन्दूरकर, जी० एम०, सरदारस लेटर्स मोस्टली अननोन (1945-48), वाल्यूम - 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक भवन, अहमदाबाद, 1975
- 30- नन्दूरकर, जी०एम०, सरदारस लेटर्स मोस्टली अननोन, वाल्यूम-2, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन अहमदाबाद, 1975
- 31- नन्दूरकर, जी०एम०, सरदारस लेटर्स मोस्टली अननोन, वाल्यूम - 445, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन अहमदाबाद, 1977-78
- 32- नन्दूरकर, जी०एम०, इन दि ट्यून विद द मिलियन्स, वाल्यूम-1 अहमदाबाद, 1974
- 33- नन्दूरकर, जी०एम० इन दि ट्यून विद दि मिलियन्स, वाल्यूम - 2 अहमदाबाद,, 1976

समाचार पत्र और पत्रिकाये :-

- I- बाम्बे क्रानिकल
- II- हिन्दूस्तान टाइम्स
- III- हरिजन
- IV- नवजीवन
- V- टाइम्स ऑफ इण्डिया
- VI- यग इण्डिया

सारणी

देशी रियासतों का विलीनीकरण

(1) सघ में मिले हुए राज्य				
क्रम संख्या	मिलने की तारीख	राज्यों के नाम	राज्यों की संख्या	क्षेत्र का नाम
1	15-2-1948	सौराष्ट्र के विभिन्न राज्य	222	सौराष्ट्र
2	7-4-48	जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर करौली, वासबाड़ा, उदयपुर, अलवर आदि	18	राजस्थान
3	15-6-48	देवास, ग्वालियर, इन्दौर आदि	25	मध्य भारत
4	30-8-48	पाटियाला, कपूर थला, नाभा, मालेर कोटला, फरीद कोट, जिन्द, नालागढ़ और कलसिया	8	पटियाला तथा पूर्वी पंजाब सघ
5	5-1-49	सिरोही	1	राजस्थान
6	1-7-49	ट्रावनकोर और कोचीन	2	ट्रावनकोर कोचीन
योग :			276	

2. केन्द्र द्वारा शासित राज्य

क्रम संख्या	मिलने की तारीख	राज्यों के नाम	राज्यों की संख्या	क्षेत्र का नाम
1	15-4-48	पंजाब के पहाड़ी राज्य	21	हिमाचल प्रदेश
2	1-6-48	कच्छ	1	कच्छ
3	12-10-48	बिलासपुर	1	बिलासपुर
4	1-6-49	भोपाल	1	भोपाल
5	1-10-49	त्रिपुरा	1	त्रिपुरा
6	15-10-49	मणिपुर	1	मणिपुर
7	1-1-50	अजयगढ़, ओरछा, पन्ना आदि	35	विध्य प्रदेश
योग -			61	

प्रान्तों के साथ मिलने वाले राज्य

क्रम संख्या	मिलने की तारीख	राज्यों का नाम	राज्यों की संख्या	किस प्रान्त में मिले
1	1-1-48	अजयगढ़ आदि	23	उड़ीसा
2	1-1-48	बस्तर, चगभाकर आदि	14	मध्य प्रान्त
3	1-2-48	ममरई	1	मध्य प्रान्त
4	23-2-48	लोहा	1	पूर्वी पंजाब
5	23-2-48	बगना पल्ले	1	मद्रास
6	3-3-48	पुदुक्कोट्टा	1	मद्रास
7	3-3-48	दुजाना	1	पूर्वी पंजाब
8	8-3-48	अलकोट, औछ आदि	17	बम्बई
9	7-4-48	पटौदी	1	पूर्वी पंजाब
10	10-6-48	गुजरात के विभिन्न राज्य	144	बम्बई
11	18-7-48	सरायवेला, खारसवान	2	बिहार
12	6-11-48	दाता	1	बम्बई
13	1-1-49	मयूरक्षेत्र	1	उड़ीसा
14	1-3-49	कोल्हापुर	1	उड़ीसा
15	11-4-49	सदूर	1	मद्रास
16	1-5-49	बडौदा	1	मद्रास
17	1-8-49	टिहरी गढ़वाल	1	उत्तर प्रदेश
18	5-10-49	बनारस	1	उत्तर प्रदेश
19	1-12-49	रामपुर	1	उत्तर प्रदेश
20	1-1-50	कूच बिहार	1	पश्चिमी बंगाल
योग		216		

राज्यो की संख्या		क्षेत्रफल वर्ग मील मे	जनसंख्या हजारो मे	
1	सघ से मिले हुए राज्य	275	2,15,450	34,699
2	केन्द्र शासित राज्य	61	64,604	16,925
3	प्रान्तो से मिले हुए राज्य	216	1,08,739	19,158
योग		552	3,87,893	60,783